हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 2013

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

बुधवार, 6 मार्च, 2013

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(8)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)2
वाक आउट	(8)11
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(8)11
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)26
अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा– अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(8)32
गुड़गांव में राजीव गांधी चैरीटेबल ट्रस्ट को भूमि के आवंटन सम्बन्धी मामला उठाना/वाकआउट	(8)32
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव– हरियाणा में स्वाइन फ्लू मामलों की तीव्रता से उमड़ने सम्बन्धी	(8)38
वक्तव्य– स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(8)40

मूल्य :

548

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)50

बैठक का समय बढ़ाना (8)90

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)90

सदन का स्थगन (8)93

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)93

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन (8)96

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)96

बैठक का समय बढ़ाना (8)98

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)98

बैठक का समय बढ़ाना (8)113

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)113

बैठक का समय बढ़ाना (8)120

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)120

वाक आउट (8)126

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)126

बैठक का समय बढ़ाना (8)128

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)129

वैयक्तिक स्पष्टीकरण– (8)134
उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) द्वारा

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)134

बैठक का समय बढ़ाना (8)137

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण) (8)137

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुदानों पर चर्चा तथा मतदान (8)141

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 6 मार्च, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will make the obituary references.

श्री हरि सिंह, स्वतन्त्रता सेनानी

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन महान् स्वतन्त्रता सेनानी श्री हरि सिंह के 5 मार्च, 2013 को हुए दुःखद् निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पानीपत जिले के गांव पट्टी कल्याणा में सन् 1927 में हुआ। देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लेने के साथ-साथ द्वितीय विश्वयुद्ध में भी भाग लिया।

श्री हरि सिंह एक वर्ष तक बर्मा जेल में भी रहे। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हमें ऐसे देशभक्त तथा समाजसेवक पर गर्व है। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

यह सदन महान् स्वतन्त्रता सेनानी को शत्-शत् नमन करता है तथा इनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जसवंत सिंह, हवलदार

यह सदन हवलदार श्री जसवंत सिंह के 3 मार्च, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 सितम्बर, 1976 को गांव अटवाण, जिला कुरुक्षेत्र में हुआ। वे मातृभूमि की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर 8 फरवरी, 1994 को भारतीय सेना की 8 ग्रेनेडियरस यूनिट में भर्ती हुए। उन्होंने बहादुरी और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू

कश्मीर के कूपवाड़ा पंचगांव में आतंकवादियों को मार गिराया था। उन्हें इस बहादुरी के लिए वर्ष 2010 में सेना मैडल (गैलेन्ट्री अवार्ड) देकर सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश एक वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो शोक प्रस्ताव स्वतंत्रता सेनानी श्री हरी सिंह और हवलदार श्री जसवंत सिंह के दुःखद निधन पर सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हम भी अपनी पार्टी की तरफ से उनके दुःखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिवार को दुःख की इस घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी श्री हरी सिंह के मार्च, 2013 और हवलदार श्री जसवंत सिंह के दिनांक 3 मार्च, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary References made by the Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other Members of the House. I feel grieved on the sad demise of Shri Hari Singh, Freedom Fighter of village Patti Kalyana, District Panipat yesterday. He was a great freedom fighter. He actively participated during the freedom struggle of India. I also feel grieved on the sad demise of Shri Jaswant Singh, Havildar of village Atwan in district Kurukshetra on 3rd March, 2013. He was honoured with gallantry award for bravery in 2010. I pray Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now I will request all of you to kindly stand up for two minutes to pay homage to the departed souls.

(At this Stage, the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now the Questions Hour.

National Law University

***1394. Shri B.B. Batra :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) Whether any building/structure has been raised to start the National Law University in Rajiv Gandhi Education City at Sonepat as per announcement of the Government for setting up the Law University; and

(b) the time by which the admissions are likely to be started and from which academic year?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :

(a) No, Sir.

(b) The admissions will be started from the academic year 2015-16.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, I would like to know whether any budget has been allocated for this purpose and specific date when the construction is going to be started.

Mr. Speaker : Hon'ble Member is asking about specific date for starting the construction.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है it is a State funded University and the Government will raise grant approximately Rs. 119 Crores for this purpose. 119 करोड़ रुपये की यह राशि जो अब बजट पेश किया है उसमें ऐलोकेट भी की है। उसमें से करीबन 5 करोड़ रुपये की राशि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए ऐलोकेट की गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि नॉर्दरन इण्डिया में दिल्ली और जोधपुर में ही केवल दो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। लीगल एजुकेशनल सिस्टम को ठीक बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल सब्जैक्टस को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सरकार ने इसी निर्णय के साथ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 25 एकड़ लैंड दी है और उसका पोजैशन लेने के बाद उसका प्रोपर ले-आऊट प्लान और आर्कीटैक्चर ड्राईंग से रिलेटिड जो भी बिल्डिंग की रिक्वायरमैंट हैं उसकी इस समय प्लान तैयार कर ली गई हैं और इस बिल्डिंग की ड्राईंग एप्रूवल के लिए एस्टेट आफिस, हुडा, सोनीपत के कार्यालय में भेज दी गई हैं। जहां तक इस लॉ यूनिवर्सिटी को शुरू करने की बात है तो वर्ष 2015-16 में हम इस यूनिवर्सिटी में क्लासिज शुरू कर देंगे।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, I am asking simple question when the construction is going to be started?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, स्पेसिफिक डेट की जहां तक बात है तो आर्कीटैक्चर ड्राईंग इस समय तैयार हो चुकी हैं और एस्टेट आफिस, हुडा, सोनीपत के कार्यालय में भेजी जा चुकी हैं। इसलिए करीबन एक जून, 2013 को इस लॉ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की कन्स्ट्रक्शन शुरू हो जायेगी।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, पंचकूला सिटी के लिए लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में वर्क आऊट किया गया था जो कि बीच में रह गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचकूला सिटी के लिए लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में सरकार के पास कोई मामला विचाराधीन है अगर है तो यह कब तक बननी शुरू हो जायेगी?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने पंचकूला में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रश्न किया है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि पहले एक बार पंचकूला के सरकारी कालेज में लॉ की क्लासिज लगाने के बारे में विचार किया गया था और इस बारे में केस भी सबमिट किया गया था। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ने लॉ क्लासिज शुरू करने के लिए परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि देश में अलग से लॉ यूनिवर्सिटी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए पंचकूला में कोई लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का सरकार का विचार नहीं है। हां, जो नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में खुलने जा रही है उसमें एडमिशन के लिए जो हरियाणा डौमिसाइल के बच्चे होंगे, उनको सीटों में 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

Up-gradation of Schools

***1505. Shri Rameshwar Dayal Rajoria :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government School of Jarthal, Rajgarh, Basdudha Villages of Bawal Constituency from 10th Class to 10+2 Class; if so, the time by which these Schools are likely to be upgraded?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No Sir.

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, जिन स्कूलों के मैंने अपने प्रश्न में नाम दिए हैं वे बहुत पुराने स्कूल हैं और उनके आस-पास 8 से 10 किलोमीटर की दूरी के गांवों में कोई स्कूल नहीं हैं। राजगढ़ के स्कूल को अपग्रेड करने के लिए विभाग से डी.ई.ओ. के पास एक पत्र भी आया था लेकिन उस स्कूल में 10+2 कक्षा की क्लास नहीं बैठ सकी और उस स्कूल को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। मेरी आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट है और मेरी यह डिमाण्ड भी है कि इन गांवों की दूरी को देखते हुए इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जड़थल, राजगढ़, बसदूधा गांवों के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए यह प्रश्न किया है और इनका कहना है कि ये स्कूल नार्म्स पूरे करते हैं। जारथल स्कूल को इसलिए अपग्रेड नहीं किया गया क्योंकि किसी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए बच्चों की संख्या 150 होनी चाहिए जबकि इस स्कूल में केवल 135 बच्चे हैं तथा एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल एवेलेबल है इसलिए इस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। जहां तक राजगढ़ के स्कूल की बात है तो वहां भी 150 बच्चों के अगेन्स्ट 135 बच्चे हैं, नार्म्स फिजीबल हैं लेकिन due to less enrollment यह स्कूल अपग्रेड नहीं किया जा सकता। बसदूधा स्कूल में भी 150 बच्चे चाहिएं जबकि बच्चे केवल 63 हैं, किलोमीटर जरूर दूर हैं लेकिन वहां बच्चों की

संख्या कम होने के कारण यह स्कूल अपग्रेड नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि इनकी कांस्टीच्युंसी बावल में गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल आसलवास को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड किया गया है, गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल बलखेड़ी को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड किया गया, गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल खिजौरी को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड किया गया है, गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल बूढला को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड किया गया है, गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल कसौली को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड किया गया है, गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल यबान गुर्जर को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड किया है और पाढला और कमालपुर के प्राइमरी स्कूल को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इनके यहां और भी बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया गया है जिनमें पिथरवास के हाई स्कूल को सीनियर सैकेंडरी स्कूल में, सेकी और पंचोर के हाई स्कूल को सीनियर सैकेंडरी स्कूल में और माजरा मुस्तिल के हाई स्कूल को भी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया गया है। इस प्रकार करीबन 20 से ज्यादा स्कूल इनकी कांस्टीच्युंसी में अपग्रेड किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे रिवाड़ी में 96 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया गया है।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : अध्यक्ष महोदय, बहुत से स्कूलों को डिग्रेड भी किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों को तोड़ा जा रहा है। जहां सरकार प्रदेश को एजूकेशन हब बनाने की बात करती है, भट्ठों पर स्कूल खोलने की बात करती है तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि स्कूलों को तोड़ा क्यों जा रहा है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी सदन के सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं, ये सभी चुनकर आए हुए विधायक हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि किसी भी जगह पर स्कूल खोलने के लिए मिनीमम बच्चों की संख्या 25 होनी चाहिए। जहां पर भी बच्चों की संख्या 25 थी वहां हमने स्कूल खोल दिया लेकिन अगर किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 25 नहीं होगी तो उस स्कूल को बंद ही किया जाएगा तथा एडज्वायनिंग एरिया के एक किलोमीटर में जहां भी स्कूल होगा वहां इन बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि जिस इलाके से लोकदल के विधायक हैं वहां चाहे मॉडल स्कूल खोल दिए जाएं या कोई और स्कूल खोल दिए जाएं पता नहीं क्या कारण है कि उन स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते और बच्चे भाग जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मोरखी गांव है और वहीं से मैं एम.एल.ए. हूं, मेरे गांव में सरकारी स्कूल में 2000 बच्चे हैं। इसके अलावा इसके इलाके में कहीं किसी स्कूल में 2000 बच्चे हों तो ये इस्तीफा दे दें या मैं इस्तीफा दे दूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question disallowed, need not answer this question.

Shri Randeep Singh Surjewala : The Hon'ble Member has to apologize. He has to apologize and withdraw his words. He cannot disrespect a colleague woman Member in this fashion. He should be taught sense and discipline.

Mr. Speaker : Mr. Patwari withdraw your words, आप मंत्री महोदया से माफी मांगिए। What do you mean by "Iska"? क्या यह कोई बात करने का तरीका है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हम इनको सम्मानित सदस्य कह कर थकते नहीं और ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। This kind of misbehaviour will not be permitted.

Mr. Speaker : Mr. Patwari, withdraw your words.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रही थी कि जहां जहां से लोकदल के एम.एल.ए. चुनकर आते हैं वहां बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदया कह रही थी कि जहां जहां से लोकदल के एम.एल.ए. हैं वहां बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। यह सरकार की भी जिम्मेवारी बनती होगी कि इस बात का पता लगाए कि वहां के बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं जाते। उसके कोई कारण तो होंगे। हो सकता है कि आपने वहां पूरी फैसिलिटीज न दी हों इस वजह से बच्चे न आते हों, या आपने उनको प्रोत्साहन न दिया हो। सरकार की भी यह जिम्मेवारी है इसलिए केवल यह कहकर टालना अच्छी परम्परा नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं आते। अध्यक्ष महोदय, ये मिनिस्टर हैं, इनकी सरकार है इसलिए इनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि पता लगाएं कि बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं आते और ये अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं।

Mr. Speaker : Mr. Kali Ram Patwari, please stand up in your seat. You are hereby reprimanded for using these words.

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को इस बारे में बताना चाहूंगी।

Mr. Speaker : No need to answer this question. He has felt sorry, that is all.

New Stadium in Narnaund

***1290. Smt. Saroj Mor :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new stadium in Narnaund Constituency?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : नहीं, श्रीमान जी।

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरे हल्के नारनौंद के खिलाड़ियों ने अकेले इतने मैडल जीते हैं जितने की सारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं फिर भी मंत्री जी ने वहां स्टेडियम बनाने का जवाब 'नहीं' में दिया है। इसके क्या नार्म्ज हैं?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि

नारनौंद हल्के में पहले से ही पांच स्टेडियम बने हुए हैं फिर भी माननीय सदस्या चाहती हैं कि नारनौंद हल्के में कोई और स्टेडियम बनाया जाये तो ये जहां स्टेडियम बनवाना चाहती हैं उस गांव से या नारनौंद से प्रोपर रैजोल्यूशन पास करवाकर भिजवा दें। हम फिजिबिलिटी चैक करवा लेंगे और यदि नार्म्ज पूरे होंगे तो वहां स्टेडियम बनवा देंगे।

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को नम्बर एक कहा जा रहा है और जितने मैडल पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं उतने मैडल अकेले नारनौंद के खिलाड़ियों ने जीते हैं फिर भी नारनौंद हल्के में स्टेडियम बनाने के बारे में मंत्री जी ने 'नहीं' में जवाब दिया है, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने 'नहीं' में कहां जवाब दिया है?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा प्रदेश नम्बर एक है और खेल के क्षेत्र में विशेषकर नम्बर एक पर है। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने कॉमन वैल्थ, एशियाड और ओलम्पिक में सबसे ज्यादा मैडल जीते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में स्टेडियम बनवाये हैं ताकि खिलाड़ियों को निश्चित रूप से अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल सके और हमारे खिलाड़ी अच्छी परफॉरमैंस दे सकें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो इस बात को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सरकार हरियाणा प्रदेश में 275 स्टेडियम बनाने जा रही है। दूसरी तरफ कस्बे में स्टेडियम बनाने के लिए मंत्री जी ने 'नहीं' में जवाब दिया है। सरकार गांवों में स्टेडियम बनाने की बात कर रही है दूसरी तरफ बड़े कस्बे में स्टेडियम की जरूरत है और वहां लोगों का स्पोर्ट्स में इन्ट्रस्ट है। वहां पर स्टेडियम बनाने के लिए अगर मंत्री जी यह कहकर टालना चाहें कि नार्म्ज पूरे करेगा तो बनायेंगे, यह गलत बात है। सरकार जब गांव में जमीन ले सकती है तो उस कस्बे में जमीन लेने में क्या दिक्कत है? वहां पर स्टेडियम की जरूरत है और सरकार को बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाता है कि हरियाणा स्पोर्ट्स में नम्बर एक है। यह ठीक बात है कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं लेकिन उनके साथ-साथ ऐसे बच्चों को भी खेलों के नाम पर प्रोत्साहित किया जाता है जो हमारी स्टेट के नहीं हैं, दूसरी स्टेट्स के रहने वाले हैं। उनको यहां बुलाकर प्रोत्साहित किया जाता है और अपनी पीठ थप-थपाई जाती है कि वे बच्चे हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे दूसरे प्रदेशों के बच्चे हैं अगर उनको प्रोत्साहित करना था तो ओलम्पिक में 6 पदक आये थे, 6 के 6 बच्चों को प्रोत्साहित करना था जबकि इन्होंने केवल चार को किया था।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है? It's a suggestion.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी का इशारा सुशील कुमार की ओर है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हरियाणा की धरती पर जन्म लिया और वे हरियाणा की माटी से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने एक निवास दिल्ली में भी बना लिया है, क्या हम हरियाणा की माटी में जन्में स्पोर्ट्सपर्सन को इस तरह से हरियाणा की विधान सभा में तिरस्कृत कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी को धन्यवाद करना चाहिए कि

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की माटी में जन्में, हरियाणा की संस्कृति जिनकी जड़ों के अंदर है और उनकी रगों में दौड़ती है व जिनका परिवार आज भी हरियाणा के अंदर रहता है, का सम्मान किया है। हरियाणा के गांव में जिन्होंने जन्म लिया और आज भी जो हरियाणा की माटी को सिर से लगाकर फिर देश का तिरंगा पकड़कर आगे बढ़ते हैं उनका यदि इस प्रकार से अपमान करेंगे तो यह अशोभनीय है। सदन के सीनियर साथियों को कम से कम इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इनकी खुद भी स्पोर्ट्स में रुचि है। इनको हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा की माटी से जुड़े खिलाड़ियों को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि पूरे देश में आज हरियाणा का उदाहरण दिया जाता है कि हरियाणा की खेल नीति बहुत बेहतर है। जिस प्रकार की हमारी खेल नीति है यदि इसी तरह से अन्य प्रांत भी अपनी खेल नीति बनायें तो यह देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बन सकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने हरियाणा के बच्चों को सम्मानित किया है मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत दफा धन्यवाद कर चुका हूं कि उन्होंने हरियाणा के बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया लेकिन मंत्री जी भी हाऊस को गुमराह कर रहे हैं ये भी यह गलत कह रहे हैं कि जो और तीन बच्चे हैं जो कि ओलम्पिक में मैडल जीतकर आये हैं इन तीनों को सरकार ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री उन चार की बजाय जो 6 बच्चे मैडल जीतकर आये उन सभी 6 के 6 को ही सम्मानित करते तो मैं आज फिर उनको इस बात की बधाई देता। वास्तव में यह बात मैं कहना चाहता हूं। ये जो तीन बच्चे हैं इनके बारे में यहां कहा जा रहा है कि वे हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए हैं यह फिर से गलत कहा जा रहा है। उनमें एक बच्चा दिल्ली का रहने वाला है और दो बच्चे हैदराबाद के रहने वाले हैं। सर, आप उनका रिकार्ड मंगवाकर देख लें और अगर ये तीनों बच्चे बाहर के न हों तो फिर इसके लिए ये बधाई देने की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी के घर आकर गुलदस्ता दे जाऊंगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि गगन नारंग, सुशील कुमार और सायना नेहवाल अगर इनकी जड़ें भी हरियाणा में नहीं हैं तो माननीय साथी अभय जी मुझे इस बात के लिए माफ करें कि ये भी राजस्थान से आकर हरियाणा में बसे हैं फिर तो किसी की भी जड़ें हरियाणा में नहीं हैं। मैं श्री अभय जी की बात को आगे बढ़ाता हूं मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि हर वो हिन्दुस्तानी जो तिरंगा पकड़कर मैडल लेकर आता है हमें उन सब पर फख्र है। हरियाणा के लोगों को हर हिन्दुस्तानी पर फख्र है। सर, इन्होंने सुझाव दिया है। जिन व्यक्तियों की जड़ें हरियाणा की माटी के अंदर हैं अगर उनको हरियाणा की सरकार ने पुरस्कृत किया और उनका हौंसला बढ़ाया तो इसमें गलत क्या है? मेरे साथी को इस पर खुशी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो बाकी हिन्दुस्तानी हैं जो हिन्दुस्तान के लिए अवार्ड लेकर आये हैं हमें उन पर भी अभिमान है। मैं चाहता हूं कि हम सबको उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यू.पी.ए. की केन्द्र सरकार ने भिन्न-भिन्न विभागों में जहां पर वे काम

करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : स्पीकर सर, *****

श्री अध्यक्ष : राजौरिया जी, आपकी कोई सप्लीमैंट्री नहीं है इसलिए आप कृपया करके बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) Not to be recorded. अब जो श्री राजौरिया जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) सुमिता सिंह जी आप अपनी सप्लीमैंट्री पुट कीजिए।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कोई नया स्टेडियम नहीं मांग रही हूं। मैं तो यह जानना चाहती हूं कि करनाल हल्के के अंदर पुण्डरक गांव के अंदर पिछले चार साल पहले एक स्टेडियम बना था। यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था लेकिन पिछले चार साल से वहां पर न तो बिजली का कनैक्शन है और न ही पानी का कनैक्शन है। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इस स्टेडियम में बिजली और पानी का कनैक्शन देने का काम अण्डर प्रोग्रैस है जो कि जल्दी ही पूरा कर दिया जायेगा।

Construction of Solid Waste Treatment Plant

***1332. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that solid waste treatment plant was installed in Ambala without obtaining EIA clearance certificate from Ministry of Environment & Forest, Government of India; and

(b) if so, the reasons thereof and the action taken, if any, for not obtaining the above mentioned certificate in time and causing delay in the functioning of the plant?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda) : Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Notification mandating enviroment impact assessment (EIA) clearance was issued on 14.9.2006 whereas the foundation stone for the solid waste management plant at Patvi was laid on 10.4.2006.

(b) A provisional 'No Objection Certificate' from the Haryana State Pollution Control Board was obtained on 02.08.2005 for setting up solid waste management plant at Village Dabkora at Jatwar in Tehsil Naraingarh but the site of the plant was later shifted to village Patvi due to non finalization of land deal from the farmers at village Dabkora. The plant was commissioned in July 2008 but due to the objections raised by the Haryana

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[Shri Bhupinder Singh Hooda]

State Pollution Control Board, the plant was shut down in April, 2010.

A presentation was made on 18.02.2013 in the Ministry of Environment and Forest, Government of India for issuance of terms of reference for EIA clearance, which is expected to be issued shortly.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला में करोड़ों रुपये की लागत से एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट लगाया गया था। यह प्लांट पांच साल पहले बनकर तैयार हो चुका है लेकिन फिर भी आज तक यह चालू नहीं हो सका है। उसके न चलने का कभी कोई कारण बताया जाता है तो कभी कोई कारण बताया जाता है। इस प्लांट की सारी की सारी मशीनरी को जंग लग चुका है जिससे सारी की सारी मशीनरी खराब हो चुकी है। अब यह दलील दी जा रही है कि उसका Environment Impact Assessment Clearance Certificate नहीं लिया गया है। सर, इस रिप्लाई में यह कहा गया है कि Environment Impact Assessment Clearance की जो नोटिफिकेशन थी वह 14.09.2006 को इश्यू हुई थी लेकिन इस प्लांट का फाऊंडेशन स्टोन पहले रख दिया गया था जो कि 10.4.2006 को रख दिया गया था। सर, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे फाऊंडेशन स्टोन पहले रख दिया हो लेकिन 14.09.2006 को जब क्लीयरैंस नोटिफिकेशन जारी हो गई तभी से हमें इसकी क्लीरैंस लेने के लिए मूव करना चाहिए था। यह प्लांट वर्ष 2008 में कम्पलीट हो गया था और वर्ष 2010 में बंद हो गया था उसके बाद भी इन्होंने उनकी क्लीयरैंस के लिए कोई मूवमैंट नहीं की। इन्होंने 18.2.2013 को यानि 7 साल बाद फाईल मूव की है। इसका शिलान्यास कुमारी सैलजा ने किया था तो इसकी सजा अम्बाला की जनता क्यों भुगते?

Mr. Speaker : It is not a question, it is a speech.

श्री अनिल विज : सर, 5 साल हो गये हैं उस प्लांट को चालू नहीं किया जा रहा है। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह लैप्स क्यों हुआ? जब 14.9.2006 को नोटिफिकेशन जारी हो गई थी तो सरकार को तभी इसकी क्लियरेंस के लिए मूव करना चाहिए था। 7 साल तक सरकार क्यों सोती रही, सरकार ने इसकी क्लियरेंस के लिए मूव क्यों नहीं किया? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी क्लियरेंस कब तक जारी हो जायेगी और यह प्लांट कब तक चालू किया जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त को शायद पूरे तथ्य मालूम नहीं हैं। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस समय जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट अम्बाला के बारे में चर्चा चल रही है, इसके जवाब में लिखा है कि ओरिजनली यह प्लांट डबकोरा गांव में बनना था। नारायणगढ़ तहसील में डबकोरा व जटवाड़ में इसका निर्माण होना था लेकिन वहां के ग्रामीण साथियों ने इसका विरोध किया कि यह यहां पर नहीं बनना चाहिए। उसके बाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने पटवी गांव में 17 एकड़ 14 मरले जमीन खरीदी जो कि विज साहब के साथ लगता गांव है। विज साहब का यह कहना कि यह प्लांट कभी चला

नहीं, ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2008 से अप्रैल, 2010 तक यह प्लांट चला भी है और कुमारी सैलजा जी, जो कि हमारी माननीय केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका पत्थर रखा था तथा हमें इस बात का फख्र भी है कि भारत सरकार ने हमें इसके लिए ग्रांट भी दी है। मैं मेरे आदरणीय साथी विज साहब को कहना चाहता हूं कि बात को तोड़-मरोड़ कर पेश न करें। सम्मानित मंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र से हैं, इसलिए उनका और अम्बाला के लोगों का अपमान न करें। दूसरी बात इन्होंने एन.ओ.सी. के बारे में कही है। अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमैंट एण्ड फोरैस्ट ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है उसके मुताबिक, अगर हम 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाते हैं तो दोबारा से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। नॉर्मली इसकी एन.ओ.सी. हरियाणा स्टेट पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा, इसलिए इसको चालू कर लिया गया था। इस प्लांट की लोकेशन पटवी गांव में शिफ्ट की गई है। जहां भी इन्टर स्टेट बॉर्डर में आप 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर हैं तो 2006 के नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सरकार का नॉर्म अब यह है कि हमें दोबारा से भारत सरकार के पास परमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा जो उनके नोटिफिकेशन के अनुसार ही 276 दिन की प्रक्रिया है। वह हमने इनिशिएट कर दी है, प्रैज़ैन्टेशन दे दी है। वह प्लांट इसलिए बंद किया था क्योंकि वह उन मापदंडों को पूरा नहीं करता था। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत सरकार से वह क्लियरेंस आ जायेगी और हम इस प्लांट को दोबारा चालू कर देंगे।

वाक आउट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सर, मंत्री जी को सवालों की जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है।

श्री अध्यक्ष : अब आप जलेबी बनाने लग गये हैं। अब श्री नरेन्द्र सांगवान जी आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी सप्लीमैंट्री तो पूछने दें?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, विज साहब अब आप बैठें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे अपनी सप्लीमैंट्री नहीं पूछने दे रहे हैं तो इसके विरोध में मैं सदन से वाकआऊट करता हूं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी.एल.) की एकमात्र सदस्या, श्री अनिल विज को उनके प्रश्न पर सप्लीमैंट्री न पूछने देने के विरोध में सदन से वाक-आऊट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि करनाल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट आज तक कितने घंटे चला है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक-दो दिन पहले इस बारे में माननीय सदस्य का स्पेसिफिक प्रश्न लगा हुआ था और मैंने इनके प्रश्न का जवाब दे दिया था। अम्बाला के सोलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट से इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है।

On Line Display of Registries

***1340. Smt. Sumita Singh :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for online display of all Registries of both Government and non-Government land being registered in Tehsils to prevent Corruption?

Revenue Minister (Sh. Mahendra Pratap Singh) : No, Sir.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि रेवैन्यू डिपार्टमैंट में जो रजिस्ट्रियां होती हैं ईट्स ऐन ओपन सिक्रैट क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर आप ओनलाईन रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो और क्या उपाय करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप वाक आउट करके फिर सदन में वापिस आ गए। "शायद मुझे निकाल कर पछता रहे थे आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गए आप।"

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब 'नो सर' कह कर दिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि काफी समय से सुनने में आ रहा है कि जो रजिस्ट्रीज हैं उनको ओनलाईन किया जाएगा। ईट्स ऐन ओपन सिक्रैट क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस डिपार्टमैंट के अन्दर जब कोई आम आदमी रजिस्ट्री कराने जाता है तो वहां पर बगैर पैसे लिए कोई रजिस्ट्री नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की बात कर रही हूं। अगर सरकार रजिस्ट्री ओनलाईन करना शुरू नहीं कर रही है तो फिर मंत्री जी इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करना चाह रहे हैं?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह एक बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें उन्होंने चिन्ता भी प्रकट की है और माननीय साथियों ने उस पर मेजें भी थपथपाई हैं। जहां तक भ्रष्टाचार उन्मूलन का विषय है उसके ऊपर मेरे ख्याल में सभी व्यक्तियों का खुश होना स्वभाविक है। (विघ्न) इससे पहले विपक्ष के साथी थोड़ा सा सुनना भी सीखें। पहले उस मैम्बर की सैटिसफैक्शन की जरूरत है जिनका ये सवाल है।

Mr. Speaker : Why should you respond to the sitting commentaries? आप अपना जवाब दो। You have to ignore any commentary being made while sitting. Ignore it.

श्री महेन्द्र प्रताप : जहां तक माननीय सदस्या का इस सवाल से ताल्लुक है वह ये है कि विभाग में पारदर्शिता अपनाते हुए स्वच्छता के तौर पर भ्रष्टाचार व भ्रष्ट आचरण को रोकते हुए रजिस्ट्रीज को ओनलाईन करने की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। इस विषय पर इनकी चिन्ता करना जायज भी है क्योंकि भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचारिक व्यवस्था का ऐसा दोष है जो हर जगह मौजूद है इसलिए रजिस्ट्रीज को ओनलाईन करने की व्यवस्था को लागू करने के लिए हर व्यक्ति के विचार और सभी के सामुहिक प्रयास की आवश्यकता है। इतना ही नहीं रोजमर्रा के सवेरे से शाम तक हर काम व्यक्ति को खुद भी देखने और सोचने की आवश्यकता है। जहां तक रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है और जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल भी किया है तो इसके संबंध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार

ने यह व्यवस्था पिछले काफी समय से शुरू की हुई है कि रजिस्ट्री और जमाबंदी के सारे रिकार्ड का कम्प्यूटराईजेशन किया जाये ताकि लोगों को कोई असुविधा पेश न आये और काम भी सुचारू रूप से चल सके। अध्यक्ष महोदय, इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु रिवेन्यु रिकॉर्ड का पूर्णतः कम्पयूटराईजेशन किया जा रहा है। इस समय तकरीबन 7085 के करीब टोटल जमाबंदियां हैं जिनमें से 6990 जमाबंदियों को वैबसाईट पर डाल दिया गया है और इनमें से 5400 जमाबंदियों को आज ऑनलाईन कर दिया गया है। अभी मैंने जो बात की है वह केवल मात्र जमाबंदी के ही बारे में ही है। रजिस्ट्रेशन का काम इससे आगे का है। इसके लिए क्या सिस्टम एडॉप्ट किया जा रहा है इसके बारे में भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि एन.आई.सी. सैंटर के द्वारा दो प्रकार के सॉफ्टवेयर संचालित किये जा रहे हैं। एक तो हैरिस के नाम से जाना जाता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की इंफॉरमेशन को डाला गया है और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर लैंड रिकॉर्ड इंफॉरमेशन को डाला गया है लेकिन इसके अन्दर जमाबंदी और नक्शों को डालने का काम अभी बाकी है। इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री का डाटा सब-तहसील या तहसील केन्द्र से इंटरनेट के माध्यम से चण्डीगढ़ हैडक्वॉटर में स्थित डाटा केन्द्र पर भेज दिया जाता है। इसमें कलैक्टर रेट वगैरह भी सारे फीड होते हैं। इस तकनीक के काफी फायदे देखने को मिले हैं और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आगे भी इसके फायदे हमें देखने को मिलेंगे। नक्शे वगैरह और जमाबंदियों के पूरे विवरण को इस सॉफ्टवेयर में डालकर ऑनलाईन करना अभी शेष है, जैसे ही हम यह कंप्लीट करेंगे तो अगला जो चरण होगा उस चरण में इस सॉफ्टवेयर में हम रजिस्ट्रेशन को भी अवश्य लायेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने सारा रिकॉर्ड ऑनलाईन करने की जो सदन में अभी अपनी बात रखी है। बात करते-करते रिवेन्यू में भ्रष्टाचार का भी जिक्र आया। हम सब जानते हैं कि रिवेन्यू में आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रजिस्ट्रियों पर पिछले काफी दिनों से पाबंदी लगी हुई है जो भ्रष्टाचार बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण रहा है। जब रजिस्ट्रियों पर बैन लगा दिया जाता है तब जो लोग मिलीभगत कर लेते हैं उनकी तो रजिस्ट्री हो जाती है और जो नहीं कर पाते उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि क्या रजिस्ट्रियों पर से पाबंदी हटेगी और दूसरा यह कि पाबंदी के दौरान जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं क्या उनकी इन्क्वॉयरी करवायेंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि कानून और नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रियां की जाती हैं अगर कहीं पर ऐसी रजिस्ट्रियां हुई हैं तो क्या उनकी इन्क्वायरी करवायेंगे? इस सम्बन्ध में मैं मेरे माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यदि जहां कहीं से भी करप्शन के इस तरह के मामलों की शिकायत मिलती है तो तुरन्त बिना समय गवाएं ईन्क्वायरी की जाती है और तुरन्त कार्यवाही करते हुए सजा के रूप में कई बार दोषियों को सस्पैंड किया जाता है या उनको नौकरी से हटा भी दिया जाता है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की पाबंदी का सवाल है तो इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि कानूनन रजिस्ट्रियों पर कोई पाबंदी नहीं है।

:
:

[श्री महेन्द्र प्रताप]
रजिस्ट्रियों पर पाबंदी कानून की दृष्टि से नहीं लगाई जा सकती है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : ठीक है, यह तो सभी जानते हैं (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप : अरोड़ा जी, पहले सुन तो लो कि क्या और कैसी पाबंदी है? हाईकोर्ट का एक आदेश भी है। हाईकोर्ट ने प्राईवेट पार्टीज के केसिज में और अनऑथोराईज्ड कॉलोनीज के केसिज में स्टे लगा दिया और साथ ही रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को डायरैक्शन भी दे दी और जनता को जागरूक करने के लिए भी कह दिया कि जो अनअथोराइज्ड कालोनीज में अनअथोराइज्ड तरीके से जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उनको हतोत्साहित किया जाए। अब उसके कुछ भी मायने निकाले जा सकते हैं। सरकार द्वारा निर्देश उन आदेश के संदर्भ में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के लैवल पर दिये गये। (विघ्न) जहां तक नगर विकास अधिनियम के मुताबिक एक हैक्टेयर से कम की जमीन के लिए अगर रजिस्ट्री करनी है तो उसमें यह व्यवस्था है कि एन.ओ.सी. लेनी होगी और संबंधित विभाग से एन.ओ.सी. लेने के बाद ही रजिस्ट्री की जाए, यह कानून सम्मत है। उसके ऊपर ये नहीं है कि हमने कोई पाबंदी लगा रखी है। कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष्य में ये है। अरोड़ा जी जो कह रहे हैं वह भी सही है कि जितनी पाबंदियां लगेंगी उसकी आड़ में करप्शन भी जागेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी रिकार्ड की बात है कि इन आदेशों के बाद अनअथोराइज्ड और गलत तरीके से हो रही रजिस्ट्रियों पर अंकुश भी लगा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से अनअथोराइज्ड कालोनीज में रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। मेरा मंत्री महोदय से दूसरा क्वेशचन यह था कि यदि पाबंदी के बावजूद भी जिन कालोनियों में रजिस्ट्रियां हुई हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां जहां इस तरह से रजिस्ट्रियां हो रही हैं वहां वहां हम कार्रवाई करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसा कोई केस है तो बताएं हम इंक्वायरी करवा लेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप पिछले दो महीनों की रिपोर्ट इस बारे में मांग लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी समझदार हैं। मैंने इनको जवाब दे दिया है कि जहां से भी शिकायत मिलती है या शिकायत मिले बिना भी हमने 3-3 महीनों के रिकार्ड मंगाए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत कर रहा हूं कि अम्बाला छावनी में ऐसी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, you do not respond to everybody who is speaking without my permission.

श्री महेन्द्र प्रताप : सर, हम जहां समस्याओं के उन्मूलन के प्रयास करते हैं वहां उससे

कई और भी दिक्कतें भी पैदा होती हैं । कानून के मुताबिक तो रजिस्ट्रियां खुली हुई हैं परन्तु हाईकोर्ट के जो अनअथोराइज्ड कालोनीज के बारे में आदेश हैं, इंस्ट्रक्शंज हैं उन पर भी ध्यान दिया जाये, उनकी भी सरकार को पालना करनी होगी । फिर भी 2-2, 3-3 महीने में हम रिकार्ड की जांच करते हैं । यह जो रजिस्ट्रेशन का रिकार्ड डाटा स्टेट का डेली आ रहा है, ये सिस्टम जो शुरू हुआ है, इससे इस चीज के ऊपर रोक लगेगी । मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हम 2-3 महीने में रिकार्ड या रिपोर्ट्स प्राप्त करते रहते हैं ।

Flyover at Bahalgarh

***1266. Sh. Jai Tirath Dahiya :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether the construction work of flyover at Bahalgarh (NH-1) Sonepat has been started; if not, the time by which it is likely to be started and completed?

Industries Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : No, Sir. No time frame can be given at this stage.

श्री जयतीर्थ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि लगभग दो साल का समय हो गया है । मेरे हल्के में माननीय मुख्यमंत्री जी तीन फ्लाईओवर्ज की घोषणा करके आए थे जिनमें से दो फ्लाईओवर्ज पर आज के दिन काम चल रहा है लेकिन जो यह तीसरे फ्लाईओवर का काम है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सबसे जयादा दिक्कत है वह बागपत से दिल्ली रोड़ पर है वहां इतना हैवी ट्रैफिक है कि दो घंटे लगाए बगैर और पुलिस की सहायता लिए बगैर सड़क क्रॉस नहीं कर सकते हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस नेशनल हाई-वे पर काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे काबिल दोस्त को यह बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो राई हल्के की घोषणाएं थी, वे रेलवे ओवर ब्रिजिज के बारे में थी । वे हमने चालू कर दिए हैं यह माननीय सदस्य ने माना भी है । इस फ्लाईओवर के बारे में चीफ मिनिस्टर की एनाउंसमैंट नहीं थी । फिर भी हमने इस फ्लाईओवर के लिए यह कहा था कि इसके लिए हम कोशिश करेंगे क्योंकि यह नेशनल हाईवे दिल्ली से चण्डीगढ़ को कनैक्ट करता है । मैं मेरे काबिल साथी को बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमने इसके बनाने के बारे में भारत सरकार को केस मूव किया था और पत्राचार के अलावा तीन बार मैं पर्सनली और दो बार मुख्यमंत्री जी यूनियन सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर डॉ. सी.पी. जोशी से इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए मीटिंग करके आये हैं और डॉ. सी.पी. जोशी जो हमारे सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने डी.पी.आर. के आर्डर कर दिए हैं । डी.पी.आर. का कन्सलटैण्ट 16.12.2011 को लगा दिया है और भारत सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग अथोरिटी द्वारा डी.पी.आर. कन्सलटैण्ट के लिए एग्रीमैंट कर लिया है । जब डी.पी.आर. कन्सलटैण्ट अपनी डी.पी.आर. की रिपोर्ट दे देगा उसके बाद गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया इसको अपनी प्लान में शामिल करेगी । इसलिए मैंने यह कहा है कि No time schedule can be given as yet because the case of this Fly-over

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

is already under contemplation of Government of India. I also agree with the Hon'ble member कि यह फ्लाईओवर बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है। इसके बारे में हमने भारत सरकार से यह इश्यू टेक अप किया है और आदरणीय मंत्री जी ने इसके बारे में प्राथमिक सहमति जताई है। भारत सरकार ने एन.एच.ए.आई. को आर्डर किया है इसलिए एन.एच.ए.आई. ने डी.पी.आर. कन्सलटैण्ट एप्वायंट किया है। आपको भी इस बारे में मालूम है कि there is a procedure that the Government follows. Once the DPR consultants Report comes then the matter would go for tendering and after that necessary funds will be allocated by the Government of India. That is why I said that it is not possible for me on behalf of the Government of India today to specify the time limit.

श्री जयतीर्थ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए जितना भी समय लगता है चाहे एक साल लगे या दो साल लगें तब तक वहां कोई सर्विस लेन या दूसरी व्यवस्था करके वहां से जाम हटाया जाए क्योंकि वहां पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है लगातार जाम लगा रहता है इसलिए सरकार कोई एक्सट्रा सर्विस लेन बनाकर ऐसा कोई तरीका निकाले ताकि वहां की ट्रैफिक जाम की समस्या का हल हो सके।

Sh. Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, the suggestion is valid and I have noted it. Speaker Sir, we have deputed as far as possible extra police staff as well as traffic police so that there is no problem of traffic Jam. सर, वहां पर एक प्रॉब्लम यह भी है, आपने भी देखा है कि वहां उस चौराहे के दोनों तरफ कोई न कोई छोटे और बड़े ईंटरीज हैं वे सब अपनी गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर खड़ा करेंगे तो जाम की स्थिति प्राकृतिक तौर से बनेगी। उस चौराहे के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें भी हैं। इसके अलावा फल, सब्जी वालों की भी बहुत सारी दुकानें हैं। जिस कारण से बहुत सारा ट्रैफिक वहां खड़ा रहता है। हम यह कोशिश करेंगे कि बगैर किसी को असुविधा किए, बगैर किसी की आजीविका छीने, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस के माध्यम से ट्रैफिक का प्रोपर नियंत्रण किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रान्त सर्विस रोड नहीं बना सकता। यह आपको मालूम ही है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने ठीक सवाल किया है बहालगढ़ क्षेत्र में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। इसी प्रकार से नेशनल हाई-वे पर पानीपत से अम्बाला तक कई जगह पर जो फ्लाईओवर्ज बन रहे हैं जिनका काम शुरू हो गया था लेकिन अब उनका काम बन्द हो गया है। क्या हाई कोर्ट ने भी उनको इन फ्लाईओवर को बनाने के लिए पाबन्द किया है? क्या सरकार उस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी कि वे इतने लम्बे समय तक इनको क्यों नहीं बना रहे हैं?

Mr. Speaker : Haryana Government has no jurisdiction and control over these companies.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात दुरुस्त है कि उस कम्पनी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यह भारत सरकार का प्रोजैक्ट है फिर भी हमने भारत सरकार को लिखा है कि यह रोड हमारे प्रान्त की ज्युरिसडिक्शन के अन्दर से जा रही है और इसको बनाने में डिले हो रहा है। इसके बारे में हमने हाईकोर्ट को भी कहा और हमारे इन्सटान्स पर ही हाई कोर्ट ने उस कम्पनी पर जुर्माना भी लगाया है और उनको यह भी कहा है कि आपके कन्सेशनल पीरियड से यह समय काट लिया जायेगा। इसकी वजह से करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, समालखा और नीलोखेड़ी के इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा थी इसलिए भारत सरकार को अनुरोध करके हमने सिक्स लेनिंग का और 28 नए फ्लाईओवर का प्रोजैक्ट बनाया है। हम भारत सरकार को अनुरोध करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वे अधिकतम जुर्माना कंट्रैक्ट के मुताबिक उन पर इम्पोज करें।

To Open Boys College in Bhoda Kalan

***1512. Sh. Ganga Ram :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Boys College in village Bhoda Kalan of Pataudi Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened; and

(b) if the reply to part (a) above is in negative, the reasons thereof?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) इसका कारण यह है कि गुड़गांव जिले में पांच राजकीय महाविद्यालय एवं दो सरकार से सहायता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय पहले से ही चल रहे हैं।

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का सवाल नहीं है, दूरी का भी सवाल नहीं है। भौंडा कलां अकेले गांव से 550 बच्चे 10+2 करके निकलते हैं। 5 किलोमीटर के रेडियस में शायद ही इससे भी ज्यादा बच्चे निकलते होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि इन हालातों को देखते हुए क्या यह कालेज खोला जाना जरूरी नहीं है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, भौंडा कलां जो इनकी पटौदी कंस्टीच्युंसी में है उसमें इन्होंने गवर्नमैंट कालेज खोलने की मांग की है। द्रोण गवर्नमैंट कालेज, गुड़गांव इनके यहां से 32 किलोमीटर पर है। गवर्नमैंट कालेज सिधरावली इनके एरिया से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है जो इस समय चल रहा है। गवर्नमैंट कालेज जटौली हेली मंडी इनके एरिया से केवल 11 किलोमीटर पर है। गवर्नमैंट कालेज सैक्टर 9 और 14 हैं। इसके इलावा एक ओर ऐडिड कालेज निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह, सुहाना जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आर.एल.एस. कालेज, सिधरावली जो केवल 8

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

किलोमीटर पर है। सरकार ने 2005 के बाद 28 नए कालेज बनाए हैं और पिछले साल 8 कालेज और बनाए गए हैं। पटौदी के आसपास के कालेजिज की संख्या वहां के बच्चों की रिक्वायरमैंट को मीट आउट करती है इसलिए पटौदी कांस्टीच्युंसी में यह कालेज खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

To check Pollution in Gurgaon Canal

***1347. Sh. Aftab Ahmed :** Will the Enviornment Minister be pleased to state—

(a) the steps being taken by the Government to check the Pollution in the water flowing in Gurgaon Canal;

(b) whether the Government has undertaken any study to gauge the ill-effects of these Pollutants to farming; and

(c) the kind of pollutants present in the water flowing in Gurgaon Canal togetherwith the date on which last inspection was carried out?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Pollution of water flowing in Gurgaon Canal is mainly due to discharge of untreated/partially treated effluents of 26 drains of Delhi and Uttar Pradesh into river Yamuna in Delhi Territory. The matter has been taken up by the State Government with the Ministry of Enviornment & Forests, Government of India, the Central Pollution Control Board, Government of NCT of Delhi & Government of Uttar Pradesh at various levels, being an interstate pollution problem.

(b) No such study to gauge the ill-effects of these Pollutants to farming has been undertaken by the Haryana State Pollution Control Board.

(c) The kind of pollutants present in the water flowing in Gurgaon Canal are mainly Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), suspended Solids, PH value, Phosphate, Oil & Grease etc. The Haryana State Pollution Control Board is continuously monitoring the quality of water of Gurgaon Canal near Badarpur and the last inspection was carried out on 13th February, 2013.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव कैनाल एकमात्र यहां सिंचाई का साधन है परन्तु उसकी पानी की जो क्वालिटी है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा।

दिल्ली और यू.पी. के बारे में तो रिप्लाई में लिखा हुआ है। सारा इंडिस्ट्रियल वेस्टेज इस योग्य भी नहीं है कि वह सिंचाई के काम आए। इस कैनाल के पानी को पशु भी पीते हैं। इस अलाके में इरीगेशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस गुड़गांव कैनाल को इस लायक तो किया जाए कि इसका पानी कम से कम कृषि के काम तो आ सके। इस कैनाल से फायदे की बजाय हानि हो रही है। इससे खेतों और पशुओं को हानि हो रही है। दूसरे स्टेट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि ये पर्याप्त कदम होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी कदम नहीं उठाया गया तो हमारे इलाके को बहुत नुकसान हो जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सही है। यह जो गुड़गांव कैनाल है यह वैस्टर्न में ओखला के पास निकलती है और करीबन 26 नाले ऐसे हैं जिनमें दिल्ली का एनट्रीटिड सीवरेज का पानी गिरता है। बदरपुर के पास जाकर गुड़गांव कैनाल निकलती है। यह जो पानी है यह पानी पशुओं के पीने के तो लायक नहीं है परन्तु इरीगेशन के लायक अवश्य है। पल्ला में जहां यमुना एंटर करती है वहां इसका बी.ओ.डी. लेवल मात्र 1.2 से लेकर 2.85 है लेकिन जब बदरपुर की तरफ एंटर करती है वहां बी.ओ.डी. लेवल 12 से 38 मिलीग्राम पर लीटर है जो हानिकारक है। इसके बारे में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सैंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से टेक अप किया है। एक फरवरी, 2011 को हमने मिनिस्ट्री आफ इन्वायर्नमैंट को लैटर लिखा है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरैक्शन दी जाए कि इस पर नियंत्रण करे। मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी 8 फरवरी, 2012 को लैटर लिखा था कि इस बारे में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को एप्रोप्रिएट डायरैक्शन दी जाए। दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड को भी कहा कि वे जो एफ्यूलैंट डाल रहे हैं उसके पैरामीटर्ज पर नियंत्रण करें। उसके अलावा इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने 31.12.2010 को चिट्ठी लिखी है। उससे पहले 23.2.2009 को मैंने चिट्ठी लिखी और 29.9.2009 को चेयरमैन, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने चिट्ठी लिखी थी। इसके अतिरिक्त एक चिट्ठी मैंने सितम्बर के महीने में भी लिखी थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लोक अधिकार संगठन ने याचिका No. 533 of 2012 डाली हुई है। एक और याचिका रिट पैटीशन No. 725 of 1994 titled as News Item Published in Hindustan Times Vs. Titled 'And Quit Flow Maily Yamuna' ये दो पैटीशन डल चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में इस पर कार्यवाही हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि एक मास्टर ड्रेन इसके पैरलल बनाई जाये ताकि जो एफ्यूलैंट है उसको मास्टर ड्रेन में डाला जा सके और किसी प्रकार से यमुना में न डले। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जिसके चेयरमैन भारत सरकार के मिनिस्टरी ऑफ एन्वायर्नमैंट के सक्रेटरी हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली जल बोर्ड के मैंबर सक्रेटरी इस कमेटी के मैंबर हैं। इसी तरह से आई.आई.टी. डायरैक्टर दिल्ली, हरियाणा और यू.पी. के चीफ सक्रेटरी और सीनियर रिप्रजैनटेटिवज भी इसमें मैंबर हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक टैक्नीकल ग्रुप भी स्थापित किया गया है जिसमें हरियाणा,

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
दिल्ली और सैंटर तीनों के अधिकारी शामिल किए गए हैं। जो इस मास्टर ड्रेन की कार्यवाही कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से बात रखी गई कि इस मास्टर ड्रेन को आगरा कैनाल में मिला देंगे। हमने आब्जैक्ट किया कि नहीं आप इसका पानी ट्रीट करके मिलावोगे ताकि वह पानी सिंचाई और पीने के काम आ सके। अध्यक्ष महोदय, इसकी मानिटरिंग समय-समय पर करते रहते हैं। अभी बदरपुर में 13 फरवरी को इसकी इन्सपैक्शन की गई थी। यह बड़ा ही चिंता का विषय है और सरकार इस पर सजग है।

Development of Park in Ratia

***1413. Shri Jarnail Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Hon'ble Chief Minister has made an announcement to develop a beautiful park in Ratia; if so, the time by which the work of said Park is likely to be started?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. The work has started on 1.2.2013.

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रतिया में पार्क बनाने का वादा किया था। वहां पर पार्क बनाने के लिए काम भी शुरू हो चुका है लेकिन वह बड़ा धीरे चल रहा है इस तरफ ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि इस पार्क पर टोटल कितना पैसा खर्च किया जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि नगर पालिका रतिया में सुजनहार डेरे के पास पार्क बनाने के लिए जमीन ली गई है। यहां पर पार्क बनाने के लिए 80 लाख रुपये की राशि भेज दी गई है। इसके टैण्डर ईशू कर दिए गए हैं और फरवरी, 2013 से कार्य आरम्भ हो चुका है। चूंकि हाल ही में कार्य अलोट हुआ है इसको हम कंट्रैक्ट की सीमा के अंदर ही निर्माण करवाएंगे। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसका निर्माण जल्द से जल्द करवायेंगे और इसके लिए जरूरी हिदायतें विभाग को दे दी गई हैं।

Replacement of Obsolete Wires

***1355. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the time by which the obsolete electricity wires are likely to be replaced in district Jind; and

(b) whether any public interest scheme is being formulated by the Government and Bijli Corporation to release the new electricity

connections for the tubewells of the farmers; if so, the proposed draft thereof together with the time by which the said scheme is likely to be implemented?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir,

(a) In district Jind, 191 kms. obsolete wires were identified to be replaced as on 01.06.2011 and the same has been replaced by new wires.

(b) The new electricity connections for the tubewells of the farmers are being released as per the instructions of the Nigam duly approved by the Government.

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे जिले में 305 गांव हैं जिनमें से अभी भी 170 गांवों के अंदर बिजली की तारों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। जिसकी वजह से बराबर एक्सीडैंट्स होते रहते हैं जिससे सरकारी मुलाजिमों को खर्चा भरना पड़ता है। इनमें से 40 गांव तो मेरे अपने हल्के के हैं। ये हमने बार-बार इनके एस.ई. को आईडैंटीफाई भी करवाये हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की कोई स्कीम आ रही है जिसके तहत इन तारों को बदला जायेगा लेकिन अभी भी वे तारें नहीं बदली गई हैं। हमें बार-बार यही कहा जाता है कि कई स्कीम आ रही हैं जिसके तहत इनको पी.वी.सी. वॉयर से रिप्लेस किया जायेगा लेकिन इसके बावजूद भी 170 गांवों की बहुत बुरी कंडीशन है। पार्ट बी में इन्होंने ट्यूबवैल कनैक्शन के बारे में बताया है। सर, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि मेरे अपने जिले में जिन लोगों ने इसके लिए पूरी पेमैंट कर रखी है उनके भी ये कनैक्शन पैंडिंग हैं जिनकी संख्या 1600 है। ये कनैक्शन वर्ष 2008, 2009 और 2010 से पैंडिंग हैं। इसके लिए जो 20-20 हजार रुपये निगम वाले लेते हैं वे भी अभी 615 केसिज बकाया हैं। यह संख्या बहुत पुरानी चली आ रही है। मंत्री जी ने मेरे सवाल का एक लाइन का जवाब दे दिया कि बिजली कनैक्शन विधिवत नियमों के अनुसार दिये जा रहे हैं। जिन किसानों का पिछले कई सालों से बिजली विभाग के पास पैसा जमा है उनको आप कनैक्शन नहीं दे पा रहे हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ये उनको उनका पैसा जमा होने का कोई बेनिफिट देंगे और जो आज की डेट में 1600+615 कनैक्शन पैंडिंग हैं ये कनैक्शन मंत्री जी कब तक दे देंगे?

11.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है कि कई जगह गांवों में बिजली की जो तारें हैं वे काफी पुरानी हो चुकी हैं। इसके बारे में हमने बाकायदा एक स्कीम बनाई है और इसके लिए हमने एक सर्वे करवाया था। जीन्द में हमने 1.6.2011 तक की 191 किलोमीटर लम्बी लाइन बदल दी थी लेकिन अभी तक जिन गांवों के अंदर अभी भी एफुलैंट वॉयर है उसके बारे में ये हमें लिखित में दे दें। इस प्रकार के केसिज के लिए हमने यह फैसला किया है कि इन पुरानी तारों को एक्स.एल. पी.वी.सी. केबल के द्वारा रिप्लेस किया

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

जाये। ऐसा हमने गांव सिंघान, जिला हिसार के अंदर किया है। हम यह चाहते हैं कि मीटर भी बाहर लगाये जाने चाहिएं। अगर मीटर सब बाहर लगवा देंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में पुरानी तारों को एक्स.एल. पी.वी.सी. केबल के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। इस बारे में बोर्ड गहनता से विचार-विमर्श कर रहा है। इस योजना पर एक हजार करोड़ रुपये के करीब खर्च आने की संभावना है। इस बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसा होने से कुण्डी सिस्टम से बोर्ड को छुटकारा मिल जायेगा। इस योजना पर बहुत ज्यादा धनराशि खर्च होगी इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना चाहूंगा कि इनकी नॉलिज में जहां पर भी मल्टीपल ज्वायंट्स हों और बहुत खराब हो उसके बारे में ये मुझे लिखकर भेज दें उनको हम जरूर ठीक करवायेंगे। इसके बारे में हम दोबारा से सर्वे करवा रहे हैं कि जहां-जहां इस प्रकार की परेशानी है वहां-वहां यह योजना लागू की जाये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने एक विलेज इम्प्रूवमैंट प्रोग्राम भी चलाया है जिसके तहत हम प्रदेश में जहां-जहां बिजली की तारें लटक रही हैं उनको भी हम आने वाले 6 महीने में खिंचवा देंगे। इस प्रकार से हमने प्रदेश के 1374 गांवों की लटकी हुई बिजली की तारों को खिंचवा दिया है। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 859 गांव हैं और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के 515 गांव हैं। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 1.6.2011 तक पूरे प्रदेश में 10557.83 किलोमीटर बिजली की लाइनें खराब थी जिसमें से 3473.39 किलोमीटर लम्बी लाइनों को हमने रिप्लेस कर दिया है और जो बाकी 7084 किलोमीटर हैं इनको ठीक करने का हमारा टारगेट मार्च, 2013 था लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें और भी समय लगेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम इनको ठीक कर देंगे। एक माननीय सदस्य ने ट्यूबवैल कनैक्शन के पैंडिंग होने की बात कही है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उनके जिले में 1600 बिजली कनैक्शन पैंडिंग हैं अर्थात् जो 31.1.2013 तक जो पैंडिंग कनैक्शन हैं उन पैंडिंग ट्यूबवैल कनैक्शन को हम अगले एक साल के अंदर हम इन सब उपभोक्ताओं को कनैक्शन रिलीज कर देंगे। स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999 से 2005 तक जिस समय माननीय सदस्य की पार्टी की सरकार थी उस समय टोटल 37633 ट्यूबवैल कनैक्शन रिलीज हुये थे और हमारी सरकार के समय में वर्ष 2005 से लेकर अब तक जो कनैक्शन रिलीज हुए हैं उनकी संख्या 160310 है।

Constitution of Sanitation Staff Commission

***1420. Smt. Kavita Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute a Sanitation Staff Commission for the welfare of sanitation employees working in the Municipal Corporations, Municipal Councils and

Municipal Committees in the State?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda) : No, Sir.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, आजकल जो सफाई कर्मचारी हैं वे ज्यादातर ठेकेदारों के माध्यम से रखे जाते हैं। ठेकेदारों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है न तो उन्हें मिनीमम वेजिज एक्ट के तहत मिनीमम वेजिज मिलती है, न ही प्रोविडैंट फण्ड दिया जाता है और न ही उनके इंश्योरेंस की कोई स्कीम है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा फोरम है जिसके अंदर सफाई कर्मचारी अपने उत्पीड़न की शिकायत कर सकें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। सर, मैं यह और पूछना चाहूंगी कि कई वर्षों पहले प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से 100-100 गज के प्लॉट्स देने की घोषणा की गई थी जो कि अब तक नहीं दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि ये प्लॉट्स उनको कब तक दिये जायेंगे?

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

New Bus Route

***1437. Shri Phool Singh Kheri :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is only single route of bus service to Kamheri, Sogalpur, Kasoli, Paprala, Vopur villages via Harnauli village; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to start another route of bus service for the said villages togetherwith the time by which it is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान् जी। तथापि, वहां कोई अन्य रूट शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

Release of Water in Minors

***1480. Col. Raghbir Singh:** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) the number of times water has been released in Hadodi distributary, Chillar Balkra minor, Makrana minor, Chiria Sub-minor and Tokha minor during the year 2012-13 and if water has not been released the reasons thereof;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to release water into the aforesaid minors; if so,

[Shri Randeep Singh Surjewala]

the time by which the said proposal is likely to be implemented; and

(c) as per schedule, the number of days in a month, water is being released in Satnali feeder and Bhiwani canal?

वित्त मंत्री (श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) :

(क) तथा (ख) वर्ष 2012-2013 के दौरान हदोदी रजवाहे (रहरोदी रजबाहा) में 61 दिनों के लिए, तोखा माइनर (कारी तोखा माइनर) में 41 दिनों के लिए और चिड़िया सब माइनर (चिड़िया रजवाहा) में 88 दिनों के लिए पानी छोड़ा गया है। वर्ष 2012-2013 के दौरान मकराना सब माईनर की लाइनिंग के टूटने और पंपों की पानी उठाने की कम क्षमता के कारण मकराना माइनर (मकराना सब माइनर) और चिल्लर बलकरा माइनर (दाढ़ी चिल्लर माइनर) जो कि मकराना सब माइनर से निकलती है में पानी नहीं छोड़ा गया है। नाबार्ड XVIII के तहत 31.8.2013 तक मकराना सब माइनर की लाइनिंग की मरम्मत और 31.12.2013 तक पंपों की पानी उठाने की क्षमता बढ़ाने के बाद इन माइनरों में पानी छोड़ा जायेगा।

(ग) सतनाली फीडर और भिवानी रजबाहे में 32 दिनों की रोटेशन में 8 दिन के लिए पानी छोड़ा जा रहा है।

Widening of Under Cut

***1445. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to solve the problem of traffic jams being faced by the commuters while passing the way from Sector 12-12A to Sector-20 in Panchkula by widening the under cut/underpass?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान जी।

Budget Allocated for Drinking Water Facilities

***1284. Master Dharampal Obra:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the budget allocated by the department at present in regard to the extension of drinking water pipe lines, construction of boundary walls and repair of water works in Mandoli Kalan, Surpura Kalan, Surpura Khurd, Chaiher Khurd and Hariawas villages of Behal Sub-division falling in Loharu Constituency and whether there is any proposal under consideration of the Government to allocate any budget for the above said works in these villages in near future?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, गांव हरियावास में पाइप लाइनों के विस्तार के लिए 15.10 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। हरियावास में जलघर की मरम्मत की जरूरत नहीं है। गांव हरियावास में चारदीवारी का निर्माण करने के प्रस्ताव पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा और अनुमान के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद बजट आबंटित किया जाएगा। गांव मंडोली कलां, सुरपुरा कलां, सुरपुरा खुर्द और चैहड़ खुर्द में पीने के पानी की पाइप लाइनों के विस्तार, चारदीवारी बनाने और जल घरों की मरम्मत के लिए अनुमानों के प्रशासकीय अनुमोदन तथा बजट आवश्यकता अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में आबंटित किया जाएगा।

Details of Science Classes

***1373. Shri Naseem Ahmed:** Will the Education Minister be pleased to state the details of the Government Senior Secondary Schools in District Mewat in which science classes are availabe and schools in which science classes are not available alongwith the reasons?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फिरोजपुर झिरका, घासेड़ा, पुनहाना, तावड़ू तथा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरोली के पांच विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त पांच आरोही आदर्श विद्यालयों तथा पांच आदर्श विद्यालयों में भी विज्ञान संकाय उपलब्ध है। शेष 24 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय उपलब्ध नहीं है। विज्ञान संकाय वहीं दिया जाता है जिनकी समुदाय से मांग हो और विद्यालय विज्ञान संकाय आरम्भ करने के सभी मानदण्डों को पूर्ण करता हो जैसे कि कक्षा 10वीं में कम से कम 60 विद्यार्थी पढ़ते हों।

Establishment of Toll Barrier

***1448. Shri Bishan Lal Saini :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state —

(a) the name of the department that has established the Toll Barrier in village Damla of District Yamunanagar togetherwith the amount being collected by it in a month; and

(b) whether a Toll Barrier has also been established on Khajuri road in Shadipur; if so, whether approval has been given by the Government for its establishment?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग ने जिला यमुनानगर के गांव दामला में टोल बैरियर स्थापित किया हुआ है। वर्तमान में 63,50,000/- रुपये की राशि प्रति मास ठेकेदार के माध्यम से एकत्रित की जा रही है।

(ख) हां, श्रीमान जी।

Repair of Choupals

***1458. Shri Krishan Kamboj :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair Choupals constructed in villages Kariwala, Manalian, Gindra, Kharia, Rania City and Sant Nagar etc. of Rania constituency; if so, the time by which grant is likely to be released for maintenance of the said Choupals as these are in a dilapidated condition?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान जी, रानियां शहर को छोड़कर उपरोक्त चौपालों की मुरम्मत के एस्टीमेट तैयार किये जा रहे हैं और चौपालों की मुरम्मत के लिए राशि शीघ्र जारी कर दी जायेगी।

Widening of Roads

***1366. Shri Narender Sangwan:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the following roads:—

(a) Nagla Mega chowk Meerut road to Gharaunda *via* Vill. Amritpur Kalan; and

(b) Railway crossing Gharaunda to Uplimod Gharaunda?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : (i) तथा (ii) नहीं, श्रीमान् जी।

Replacement of Electricity Wires

***1430. Shri Jagdish Nayar :** Will the Power Minister be pleased to state the time by which the obsolete electricity wires are likely to be replaced in the villages of Hodal Constituency?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, ग्रामीण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में पुरानी व जर्जर तारों को बदलने का कार्य चलाया गया है। होडल निर्वाचन क्षेत्र के गांवों सहित समस्त राज्य में कार्य धन की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए जून, 2013 के अंत तक पूरा होना संभावित है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Theft of Vehicles

330. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of vehicles lifted by thieves in calender year 2009, 2010, 2011 and 2012 in Haryana togetherwith the number of such vehicles recovered and handed over to owners; and

(b) the number of vehicles lying Haryana Police Station unclaimed togetherwith the number vehicles disposed off by way of auction?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क)

वर्ष	चोरी हुए वाहनों की संख्या	चोरों से बरामद किये गये वाहनों की संख्या	मालिकों को सौंपे गये वाहनों की संख्या
2009	8555	3033	2984
2010	11381	3408	3328
2011	12585	3731	3667
2012	13055	3468	3171

(ख)

थानों में खड़े लावारिस वाहनों की संख्या	बोली के माध्यम द्वारा निपटारा किए गये वाहनों की संख्या
5731	9112

Exports of Carpets

331. Shri Sampat Singh : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state the total amount of export of carpets from Panipat in 2005 together with the amount of export from Panipat in the latest year alongwith the reasons of decrease in exports?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी, वर्ष 2005-06 में पानीपत से गलीचों के निर्यात की मात्रा की राशि 110.50 करोड़ रुपये थी। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान पानीपत से गलीचों का निर्यात 524.50 करोड़ रुपये था। अतः इस क्षेत्र से वर्ष 2011-12 के दौरान गलीचों के निर्यात की मात्रा में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। पानीपत से गलीचों के निर्यात की मात्रा वर्ष दर वर्ष के आधार पर निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	निर्यात वर्ष	निर्यात की मात्रा (रु. करोड़ में)
1.	2005-06	110.50
2.	2006-07	144.34
3.	2007-08	236.91
4.	2008-09	272.64
5.	2009-10	287.95
6.	2010-11	349.41
7.	2011-12	524.50

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

ऊनी गलीचा उद्योग पानीपत में लगभग 32 वर्ष पुराना है। वर्तमान में, इस उद्योग में इकाइयां भारी मात्रा में कार्यरत हैं, जिनमें 4228 मजदूरों को रोजगार प्राप्त है। निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा हाथ से बने हुये गलीचों के उच्चतम निर्यात के कारण पानीपत को गोल्ड ट्राफी प्रदान की गई है।

Amount sanctioned for Police Welfare and Sports

332. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount sanctioned for Police Welfare and Sports in the State during the financial year 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13;

(b) whether there is any society for this purpose; if so the name of the society together with the norms of the society for distributing this fund among the headquarters, battalions and district etc.;

(c) the total amount in the aforesaid period actually spent at the headquarter, battalions and the districts etc. in the aforesaid period;

(d) the total pending amount of TA and DA for the Police Force?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(अ) वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 व 2012-13 में निम्नलिखित धनराशि पुलिस कल्याण व खेल कोष के लिये स्वीकृत की गई :-

वर्ष	हरियाणा पुलिस कल्याण कोष	हरियाणा पुलिस खेल कोष
2009-10	1,25,00,000/- रुपये	शून्य
2010-11	शून्य	शून्य
2011-12	2,00,00,000/- रुपये	शून्य
2012-13	2,00,00,000/- रुपये	शून्य

(ब) इस समिति का नाम हरियाणा पुलिस कल्याण एवं खेल समिति है जिसके मानदण्ड निम्न प्रकार से हैं :-

हरियाणा पुलिस कल्याण एवं खेल समिति दिनांक 2.06.2003 से पंजीकृत है। इस समिति के नियम सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इसके नियमित सदस्य होंगे चाहे वो कहीं भी तैनात हों।

मुख्यालय :

इस समिति का मुख्यालय अध्यक्ष के कार्यालय में स्थित होगा।

समिति के सदस्य

1.	अध्यक्ष	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।
2.	उपाध्यक्ष (3)	1. अतिरिक्त महानिदेशक, मुख्यालय, या पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा वरिष्ठ मनोनित वरिष्ठ अधिकारी। 2. पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था। 3. राज्य गुप्तचर विभाग के चीफ/प्रमुख।
3.	महासचिव	पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक कल्याण शाखा, या पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा मनोनित सदस्य।
4.	संयुक्त सचिव	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कल्याण।
5.	सदस्य	आदेशक चतुर्थ वाहिनी ह.स.पु. मधुबन।

1. **समिति के लक्ष्य एवं उद्देश्य**

   1. हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सम्बन्धित सुविधा, पुलिस पब्लिक स्कूलों का प्रबन्धन, भलाई केन्द्र सुविधा, कैंटीन, सेवानिवृत्ति-लाभ, ऋण, छात्रवृत्ति तथा अचानक मृत्यु होने पर सहायता राशि देना, इत्यादि।
   2. हरियाणा पुलिस में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने बारे।
      - हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों को खेलों में रूचि बढ़ाने बारे।
      - राज्य पुलिस के खेलों के संचालन व प्रदर्शन हेतु।

2. **समायोजित राशि प्रदान करना**

हरियाणा सरकार पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जमा की गई पुलिस कल्याण कोष की राशि के बराबर अनुदान प्रदान कर रही है।

3. **समायोजित राशि के खर्च का विवरण**

राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता एवं पुलिस कर्मचारियों से की गई मासिक कटौती पुलिस कर्मचारियों के कल्याण हेतु खर्च की जाती है जो निम्न प्रकार है।

1. ऋण।
2. पुलिस कर्मचारियों के उत्कृष्ट बच्चों को छात्रवृत्ति लाभ।
3. मृतक के परिवार को दी जाने वाली सहायता।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

4. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर दिये जाने वाला लाभ।

5. सेवानिवृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जाने वाली विदाई पार्टी।

4. हरियाणा पुलिस कल्याण कोष के अंशदान की मासिक दरें

हरियाणा पुलिस कल्याण कोष की मासिक अंशदान की राशि दिनांक 1.4.2010 से बढ़ाई गई है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र. नं.	पद	मासिक कटौती
1	पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	200/- रुपये
2	पुलिस महानिरीक्षक	200/- रुपये
3	पुलिस उप महानिरीक्षक	200/- रुपये
4	पुलिस अधीक्षक	100/- रुपये
5	अन्य राजपत्रित अधिकारी/अधीक्षक कार्यालय	100/- रुपये
6	निरीक्षक/उप अधीक्षक कार्यालय	50/- रुपये
7	सहायक, निजी सहायक, सीनियर स्केल स्टैनो, एस.एस.ए./एफ.एस.एल.	50/- रुपये
8	उप निरीक्षक एवं जूनियर स्केल स्टैनो	50/- रुपये
9	सहायक उप निरीक्षक, आशुलिपिक, सहायक प्रयोगशाला/एफ.एस.एल.	50/- रुपये
10	प्रधान सिपाही/सिपाही/लिपिक	30/- रुपये
11	चतुर्थ श्रेणी	10/- रुपये

5. हरियाणा पुलिस खेल कोष के अंशदान की मासिक दरें

हरियाणा पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए हरियाणा पुलिस खेल कोष की स्थापना की गई है ताकि हरियाणा पुलिस विभाग में खेलों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी राशि स्वीकृत या प्रदान नहीं की जाती है।

हरियाणा पुलिस खेल कोष की मासिक अंशदान की राशि दिनांक 1.4.2010 से बढ़ाई गई है, जो निम्न प्रकार से है :-

क्र. नं.	पद	मासिक कटौती
1	पुलिस महानिदेशक	500/- रुपये
2	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	500/- रुपये
3	पुलिस महानिरीक्षक	400/- रुपये
4	पुलिस उप महानिरीक्षक	400/- रुपये
5	पुलिस अधीक्षक/आदेशक	400/- रुपये
6	उप पुलिस अधीक्षक	100/- रुपये
7	निरीक्षक	50/- रुपये
8	उप निरीक्षक	40/- रुपये
9	सहायक उप निरीक्षक	30/- रुपये
10	प्रधान सिपाही	20/- रुपये
11	सिपाही	10/- रुपये

(स) इस अवधि के दौरान कुल राशि जो वास्तव में मुख्यालय, वाहिनियों और जिलों आदि द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	हरियाणा पुलिस कल्याण कोष	हरियाणा पुलिस खेल कोष
2009-10	1,37,09,965/- रुपये	15,00,000/- रुपये
2010-11	1,70,12,646/- रुपये	12,65,754/- रुपये
2011-12	1,19,16,886/- रुपये	68,10,883/- रुपये
2012-13	1,21,79,775/- रुपये	87,26,304/- रुपये

(ड) पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के यात्रा खर्च की देनदारी के लिये 33.94 करोड़ रुपये के बिल लम्बित हैं।

Foundation Stone of Lala Lajpat Rai Veterinary University

333. Shri Sampat Singh : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state—

(a) when was the foundation stone of Lala Lajpat Rai Veterinary University, Hisar laid down by Hon'ble Governor and the Chief Minister;

(b) the details of the works done together with the amount spent after the foundation stone was laid; and

(c) the time by which the building is likely to be completed?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 15 अगस्त, 2011 को लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार का शिलान्यास किया गया था।

(ख) वस्तुतः विश्वविद्यालय के नए परिसर के भवन का निर्माण कार्य अभी आरम्भ किया जाना है।

(ग) इस समय, जब वास्तुकार के चयन एवं वास्तु नक्शे को अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया जारी है, भवन निर्माण कार्य के पूर्ण होने की निश्चित अवधि दिया जाना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker : I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Om Parkash Jain, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House for today, the 6th March, 2013 due to his ill-health. (Interruption)

गुड़गांव में राजीव गांधी चैरीटेबल ट्रस्ट को भूमि के आबंटन संबंधी मामला उठाना/वाक आउट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 18 from Shri Ram Pal Majra, MLA and Col. Raghbir Singh, MLA regarding upsurge of Swine Flue Cases in Haryana. (Interruption)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि ..

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, जो ये मामला उठा रहे हैं उसका हाई कोर्ट से निर्धारण हो चुका है तथा हाईकोर्ट ने उस पैटीशन को खारिज कर दिया है। कम से कम इनको पहले अपने तथ्यों की जांच तो करनी चाहिए। क्या कैग की रिपोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी होती है? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, केवल अनर्गल बातें उठाना, केवल एक ऐसी बात उठाना जिसके कोई मायने नहीं हैं, सस्ती राजनीति करना व जो मामला हाई कोर्ट से रिजैक्ट हो चुका है, उसको उठाने का इनका क्या औचित्य है? इनकी आदत है केवल व्यवधान डालना, इनकी आदत है बाहर जाना, बहिर्गमन करना इनकी आदत हो गई है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट में गुड़गांव में राजीव गांधी ट्रस्ट में धांधली का आरोप लगा है। कैग की रिपोर्ट छिपा कर रखी गई है। उस पर बहस होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सच केवल यह है कि इन्होंने पूरे हरियाणा की जमीन चौ. देवी लाल ट्रस्ट व अन्य ट्रस्टों के माध्यम से हड़प रखी हैं। अपने आप को जमीनें अलॉट कर रखी हैं। ये राजीव गांधी ट्रस्ट का नाम कैसे ले सकते हैं? हाई कोर्ट से इस मामले का निर्धारण हो चुका, हाई कोर्ट ने पैटीशंज डिसमिस कर दिये हैं। इनको शर्म आनी चाहिए किस इस प्रकार की अशोभनीय बातें करते हैं। इनको यह बात उठाने का कोई अधिकार नहीं है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Everbody please sit down. (Interruption) Please sit down. (Interruption) Everybody please sit down. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विज साहब को पूरी बात के बारे में पता ही नहीं होता। इनकी मंशा केवल एक ही होती है, इन्हें बेकार में व्यवधान डालना है, इन्हें इस सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना, शोर करना इनका मकसद है। केवल बहिर्गमन करना इनका मकसद है, केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना इनका मकसद है। देवी लाल जी के ट्रस्ट के नाम से कितनी जमीनें इन्होंने ली हैं क्या इनको इस बात की जानकारी है। श्री राजीव गांधी ट्रस्ट के मामले का पूरा निर्धारण हाई कोर्ट में हो चुका है, ये केवल खबर बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह भी हुआ कि एक पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कुर्सी पर रहते खुद जमीन अपने नाम कर ली। इस बारे में मेरे पास कागजात हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं वे कागज सदन के पटल पर रखूंगा। इन्होंने इसी तरह के अनैतिक काम किये हुये हैं। हरियाणा की भोली-भाली जनता की हजारों एकड़ जमीन देवी लाल ट्रस्ट के नाम, माता हरकी देवी ट्रस्ट के नाम और न जाने कितने और ट्रस्टों के नाम लोक दल की सरकार ने कर रखी है। इस संबंध में मेरे पास सभी कागजात हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं। वह मामला जिसका उच्च न्यायालय में पटाक्षेप हो चुका है उस मामले को उठाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Everbody please sit down. (Interruption)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

Mr. Speaker : Please sit down. (Interruption) Everbody please sit down. आप प्लीज बैठिये। (विघ्न) Shri Ram Pal Majra, please read your Calling Attention Motion.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, पहले उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आपके मैंबर का कालिंग अटैंशन मोशन है उनको बोलने दो। प्लीज, उनको बोलने दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे कालिंग अटैंशन मोशन को टेक अप करने से पहले राजीव गांधी चैरीटेबल ट्रस्ट गुड़गांव को जो उल्हावास की 5 एकड़ 3 मरला जमीन दी गई है पहले उस पर चर्चा करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं रामपाल जी, मैंने आपको कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ने के लिए कहा है आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन ही पढ़ो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्या ये अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, he is not reading his motion. (Interruption) They can't speak like this. (Interruption) The petition has already been dismissed and rejected by the Hon'ble High Court.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं आप केवल अपना कालिंग अटैंशन मोशन ही पढ़ें।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यदि आप कालिंग अटैंशन मोशन से पहले गुड़गांव में राजीव गांधी चैरीटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं तो इसके विरोध में हम सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य तथा शिरोमणि अकाली दल का एकमात्र सदस्य और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी.एल.) की एक मात्र सदस्या श्रीमती रेणुका बिश्नोई गुड़गांव में राजीव गांधी चैरीटेबल ट्रस्ट को जमीन अलॉट किए जाने का मामला सदन में स्पीकर साहब द्वारा सदन में न उठाने दिए जाने के विरोध में सदन से वाक आऊट कर गए।)

Mr. Speaker : Alright, the Calling Attention Motion which was called out early, has been lapsed as the Member has walked out.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, केवल व्यवधान डालना ही इनका लक्ष्य है, केवल शोर डालना ही इनका लक्ष्य है। इन्होंने कोई सार्थक बात नहीं करनी। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the General Discussion on the Budget Estimates for the year 2013-2014 will be resumed. I will call upon Shri Rajpal Bhukhri. (Interruption)

श्री राजपाल भुखड़ी (सढ़ौरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामपाल जी, आप वाक आऊट करने के बाद भी यहां खड़े हैं। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, इण्डियन नैशनल लोकदल के साथियों को कभी मालूम नहीं होता कि वे कर क्या रहे हैं? न इनका वाक आऊट पूरा होता है और न ये सदन के अन्दर पूरे होते हैं एवं न ये सदन से बाहर पूरे होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल मुखड़ी : सर, इस सदन की गरिमा में रहकर चर्चा करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, विपक्ष के नेताओं की समस्या यह है कि ये न पूरे सदन के अन्दर हैं न पूरे सदन से बाहर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामपाल जी, आप क्या कर रहे हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ रहा हूं।

Mr. Speaker : That Calling Attention Motion has lapsed. Although that was very important he should have carried on with that but he walked out. Without reading his motion he walked out.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, रामपाल माजरा जी को कभी ये मालूम नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं? इनको केवल ये मालूम है कि इनको क्या पढ़ाया गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामपाल जी, आप तो वाक आऊट कर गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : सर, उसी टाइम वाक आऊट करके आने के बाद मैंने अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ना शुरू कर दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, काश इन्हें यह मालूम होता कि वह पढ़ क्या रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपने इनको अलाऊ किया तो ये पढ़ने लग गए। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he does not want to read his motion. You have already permitted discussion on Budget and that may now continue. (Interruption)

Mr. Speaker : Rampal Ji, it was very important issue but you walked away.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, स्वाइन फ्लयू का मामला बहुत महत्वपूर्ण है उस पर बोलने के लिए आपने मुझे अलाऊ किया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It was very important but you walked away. I have already ruled that it has lapsed. As the very initiator you walked away.

:

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, अगर आप कालिंग अटैंशन मोशन पर बोलने की परमीशन दे दो तो क्या हो जाएगा? (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, you have already called upon Shri Rajpal Bhukhri to speak and he has started his speach. When Shri Majra was speaking yesterday, we have heard him patiently and we did not interrupt him. he should also let the Member speak.

Mr. Speaker : Shri Bhukhri, you may start General Discussion on Budget Estimates now.

श्री राजपाल भुखड़ी : ठीक है सर, इस सदन की गरिमा में रहकर चर्चा करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय संसाधन जुटाने में देश के मुख्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Rampal Ji, you had walked out. I also announce in the House that their initiator is not available and your calling attention notice has lapsed. आप वाक आऊट कर गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he is not serious. They have walked out on every motion that they have moved. (Interruption)

श्री राजपाल भुखड़ी : सर, वर्ष 2012-13 और 2014 के दौरान 27780.33 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है जोकि संशोधित अनुमान 2012 और 2013 से 15.75% प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हमारा राजस्व खर्च 28784.34 करोड़ रुपये है जो संशोधित अनुमान से अनुमान 2012 और 2013 से 18.50% की वृद्धि दर्शाता है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Arora ji, Please sit down. Others also have to speak. Let the pandemonium die. Let it die please. (Interruption)

श्री राजपाल भुखड़ी : सर, हमारा राजस्व खर्च 12.70% की वृद्धि के साथ 46223.56 करोड़ रुपये होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज के कमजोर वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताई गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, यह क्या तरीका है? क्या इस प्रकार से संसदीय मर्यादाएं चलेंगी? क्या इस प्रकार से हाऊस चलेगा? अरोड़ा जी आप भी विधान सभा के स्पीकर रहे हैं, क्या आप इस प्रकार इस सदन की कार्यवाही को चलाएंगे। कल भी आप बोले हमने कुछ नहीं कहा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Ashok ji, I called Rampal Majra but he walked out. आप सभी तो वाक आऊट कर गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, पहले कालिंग अटैंशन मोशन मूव करके रामपाल जी ने पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद ही हम सब ने वाक आऊट किया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : He walked out. I saw him walking out and then I have said that the motion has lapsed. (Interruption) I have taken up the next agenda. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, इतने सीरियस इशू पर भी सरकार सीरियस नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You are not serious yourself. (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, you permitted Opposition to speak for two hours. You permitted Mr. Majra to speak for an hour. He did not utter a word on Swine Flue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, ये कोई तरीका नहीं है, ये तो बिल्कुल धक्काशाही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, माजरा जी का जो कालिंग अटैंशन मोशन मंजूर किया गया है उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल मात्र माजरा जी की बात ही नहीं है बल्कि यह तो पूरे प्रदेश का इशू है। स्वाईन फ्लयू एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अनेक लोग मरे हैं। इस वक्त भी यह बीमारी लगातार बढ़ती जी जा रही है। माजरा जी तो केवल मात्र प्रदेश के अन्दर जो हैल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में ही कहना चाहते हैं, तो इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? जब आपने मंजूर कर ही लिया है, अगर यह पढ़ देंगे तो क्या हो जायेगा?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यदि आप माजरा जी को नहीं बोलने देना चाहते तो यह तो आपकी मर्जी ही है।

Mr. Speaker : No, no. I had allowed him. (Interruption)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, अगर माजरा जी पढ़ देंगे तो क्या हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) मान लो माजरा जी वाक-आऊट करके चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे जो दूसरे साथी हैं कर्नल रघुबीर सिंह जी, आप उनको पढ़ने दें, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या आप सारे ही वाक-आऊट कर जाएंगे?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, my friend wants a suggestion. Let me give him a suggestion. (interruption)

Mr. Speaker : O.K. You can proceed.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं भी सदन में मौजूद हूं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये... (शोर एवं व्यवधान)

:
:
:

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : विज साहब, आप तो ऑमनी प्रजैंट हो, भला आपका कोई मुकाबला हो सकता है? (शोर एवं व्यवधान) आप तो हर जगह मौजूद हैं, आप हर दल में मौजूद हैं, आप तो हर दल की भावना और विचारधारा में मौजूद हो। (विघ्न) आपका क्या मुकाबला? स्पीकर सर, अपोजीशन बैंचिज से एक सुजैशन आया है। Although the motion has left yet a suggestion has come, Government is ready with the reply. My request would be to you that the discussion may be permitted and we will request Sh. Rajpal Bukheri to speak after that.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा में स्वाइन फ्लू मामलों की तीव्रता से उमड़ने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 18 from Shri Ram Pal Majra, MLA and Col. Raghbir Singh, MLA regarding upsurge of Swine Flue cases in Haryana. I admit it. Shri Sampat Singh, MLA and Shri Anil Vij, MLA have also given Calling Attention Notice Nos. 17 & 40 respectively on the similar subject. They are also allowed to raise supplementary. Shri Ram Pal Majra, MLA being the first signatory may read the notice. (Interruption).

@श्री रामपाल माजरा
कर्नल रघबीर सिंह] : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में स्वाइन फ्लू की बीमारी दिनों-दिन तेजी से फैल रही है। सरकार द्वारा आम आदमी के लिए उचित चिकित्सा प्रबन्धों में लापरवाही बरती जा रही है। इस बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। हरियाणा में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं तथा कई दर्जन मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं। स्वाइन फ्लू से पीड़ित प्रदेशवासियों के प्रति सरकार के ऐसे बेरूखे व्यवहार की वजह से मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। न तो प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू की बीमारी को गंभीरता से ले रही है और न ही स्वास्थ्य विभाग इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सरकार के इस ढुलमुल रवैये के कारण स्वाइन फ्लू के मामलों में हर रोज वृद्धि हो रही है। देश में अब तक स्वाइन फ्लू के कारण 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर हो चुकी है। हरियाणा के 23 प्रतिशत गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं और 17.7 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। 58 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रहने के लिए भवन नहीं हैं, 70 प्रतिशत में महिला चिकित्सक नहीं है तथा 37 प्रतिशत में मरीजों के लिए बिस्तरों का प्रबन्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रचार की कमी के कारण लोग स्वाइन फ्लू

@ Read by Shri Ram Pal Majra M.L.A.

की बीमारी के बारे में जागरूक नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में न ही तो स्वाइन फ्लू पीड़ितों के लिए अलग से वार्ड बनाये गए हैं और न ही इन मरीजों के लिए दवाओं का उचित प्रबंध किया गया है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-17

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-18 के साथ ब्रैकटिड की गई

प्रो. सम्पत सिंह : इस महान सदन का ध्यान हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों से संबंधित एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। हरियाणा में स्वाइन फ्लू (एच1 एन1) के कारण दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जब इसकी तीव्रता के पीछे के कारण की जांच की जा रही है, तो विशेषज्ञ कहते हैं कि उत्तर में लम्बी सर्दी की इसमें भूमिका हो सकती है। गत् मास या इसके बाद उत्तर भारत में तापमान इस रेंज में रहा कि इस वायु-वाहित बीमारी का अधिकतम फैलाव एक ही समय प्रवृत्त हुआ। वातावरण में विषाणु हमेशा मौजूदा था तथा अनुकूल मौसम परिस्थितियों ने इसे उत्पन्न होने का अवसर प्रदान किया।

ये विषाणु अवधि के साथ सक्रीय प्रवृत्ति के हैं जब संक्रमण थोड़े-थोड़े समय में तेजी से बढ़ता है तब मामले कम रहते हैं। क्योंकि विषाणु अपेक्षाकृत नया है, अधिक लोग अतिसंवेदनशील हैं। पूरे हरियाणा में 100 से अधिक मामले विषाणु संक्रमण के दर्ज किए गए हैं।

लोगों को उच्च स्तर के बुखार, श्वास समस्या, छाती का दर्द तथा बलगम में खून के लक्षण की गंभीरता के बारे में ज्ञान नहीं है, जो उन्हें स्वाइन फ्लू तक ले जाते हैं। लोगों को बताना चाहिए कि यदि उन्हें उपरोक्त लक्षण हों, तो उन्हें 48 घण्टे के भीतर अस्पताल में जाना चाहिए। केवल मामले में देरी संकीर्णता विकसित करती है।

ये बीमारी मधुमेह के रोगियों सहित छाती एवं फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अति संवेदनशील है। इसलिए लोगों को बीमारी के बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वस्थता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए कहना चाहिए।

हरियाणा सरकार को क्षतिपूर्ति करनी ही होगी। राज्य में स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिएं तथा सरकारी अस्पतालों को इस के उपचार के लिए गोलियों की आपूर्ति करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार की और अधिक गोलियां प्राप्त करनी चाहिएं।

क्या राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों, जहां पर वैंटीलेटर की सुविधा

उपलब्ध नहीं थी, मरीजों के लाभ के लिए, निजी अस्पतालों की सूची (पैनल) बनाने के लिए कहा है।

क्या स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश जारी किया गया है कि (एच1 एन1) विषाणु के कारणात्मक जीन में बदलाव के कारण बढ़ रहे स्वाइन फ्ल्यू के प्रकोप के बारे में लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए जोकि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उच्च मृत्यु दर के कारण भयभीत हो रहे थे?

स्वाइन फ्ल्यू के कारण लोग बहुत भयभीत हैं। अभी तक स्वाइन फ्ल्यू रोगियों के उपचार के लिए अस्पतालों द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किये गए हैं तथा इन्हें अन्य रोगियों से दूर रखने के लिए कोई पृथक स्थान नहीं है। वार्डों के पृथकरण के नाम पर केवल कोई कमरा या बरामदे में कुछ परदे लगाकर पृथक कर दिये गये हैं।

वह सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-40

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 18 के साथ ब्रेकटिड की गई

श्री अनिल विज, एम.एल.ए. इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि स्वाईन फ्ल्यू का कहर गम्भीर चिंता का विषय है और सरकार गहरी निंद्रा में काम कर रही प्रतीत होती है। बहुत से लोग इसकी चपेट में आ गये हैं और स्वाइन फ्ल्यू से मरने वालों की संख्या भी अत्यधिक बढ़ गई है। अस्पतालों में इससे निपटने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं। स्वाइन फ्ल्यू का कहर लगभग हर साल अपना रौद्र रूप दिखाता है परन्तु प्रश्न यह है कि राज्य सरकार समय पर इस सन्दर्भ में आवश्यक पग क्यों नहीं उठाती? स्वास्थ्य विभाग के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान होने के बावजूद सरकार के बेरुखे व्यवहार के कारण अस्पतालों में कोई पुख्ता प्रबंध नहीं हैं। स्वाइन फ्ल्यू ने बहुत से लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकार द्वारा उक्त बीमारी से बचाव के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं? यह सब के लिए बहुत चिंता का विषय है।

वह सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करते हैं।

Mr. Speaker : Now, the concerned Minister will make a statement.

वक्तव्य-

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा स्वाईन फ्ल्यू के विषय में व्यक्त की गई चिन्ता की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं

यह कहना चाहता हूं कि सरकार भी राज्य में हो रहे स्वाईन फ्ल्यू के बढ़ते मामलों के प्रति उतनी ही संवेदनशील है। यद्यपि ये मामले हरियाणा तक ही सीमित नहीं हैं। वर्ष 2013 में, 24 फरवरी, 2013 तक पूरे भारत में स्वाईन फ्ल्यू के कुल 2267 मामले थे जिनमें से 254 की मौत हो गई है। मैं सदन के सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2009 में जब भारत में स्वाईन फ्ल्यू रिपोर्ट किया गया था, उस वर्ष हरियाणा में स्वाईन फ्ल्यू के 1968 मामले सामने आये थे।

एच.वन.एन.वन. तुलनात्मक रूप से एक नया इनफ्लूएंजा वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसी जुकाम तथा नजदीकी सम्पर्क से होता है। यह वायरस पहली बार अमेरिका में अप्रैल, 2009 में प्रकाश में आया। एच.वन.एन. वन. मुख्यतः श्वास की तकलीफ करता है। चूंकि यह वायरस एक उत्परिवर्तित प्रकार का वायरस है, इसलिए विश्व में किसी भी व्यक्ति में इस से बचने की प्रतिरक्षण शक्ति नहीं है तथा इसकी इसी क्षमता के कारण ही यह इतना अधिक फैलने वाला संक्रमण है। भारत सरकार के दिनांक 7.2.2013 के पत्र के अनुसार यह वायरस मौसमी खांसी, जुकाम के वायरस की तरह व्यवहार करेगा तथा आने वाले कुछ वर्षो तक संचरण करता रहेगा। इसलिए पेनडेमिक अवधि के पश्चात एच.वन.एन.वन. संचरण के विशेष स्तर के साथ स्थानीयकृत फैलने की उम्मीद कर रहे हैं। चूंकि सर्दी के मौसम में प्रतिरक्षण शक्ति कम होने तथा वायरस के इस मौसम में अधिक संचरण होने के कारण स्वाईन फ्ल्यू फैलने के लिए अनुकूल वातावरण होता है, इसका प्रमाण यह है कि पूरा उत्तर भारत स्वाईन फ्ल्यू के चपेट में है।

हरियाणा में, 1 जनवरी, 2013 से 1 मार्च, 2013 तक स्वाईन फ्ल्यू के 360 मामले दर्ज हो चुके हैं। इन 360 पॉजिटिव मामलों में से 92 को छुट्टी दे दी गई, 141 मरीजों का घर पर क्वारेंटिन से उपचार किया गया तथा 38 मौतें दर्ज की गई तथा 89 मरीज 1 मार्च, 2013 तक भर्ती थे। यह उल्लेखनीय है कि 360 मामलों में से 197 मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानि गुड़गांव तथा फरीदाबाद में से दर्ज हुये हैं, जिसका कारण है कि दिल्ली में स्वाईन फ्ल्यू के मामले काफी संख्या में हैं। केवल दिल्ली में ही स्वाईन फ्ल्यू के लगभग 764 मामले दर्ज किये गये हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वाईन फ्ल्यू से होने वाली मौतें गंभीर निमोनिया तथा श्वास सम्बन्धी जटिलताओं के कारण होती है। अधिकतर मौतें सहवर्गी रोगों तथा उच्च जोखिम समूह से सम्बन्धित रोगियों की हुई हैं। यद्यपि हरियाणा में केवल 10.55 प्रतिशत स्वाईन फ्ल्यू पॉजिटिव रोगियों की ही मौतें हुई हैं, जबकि पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात में क्रमशः 19 प्रतिशत, 18.88 प्रतिशत तथा 17.94 प्रतिशत स्वाईन फ्ल्यू पॉजिटिव रोगियों की मौतें हुई हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा उच्च सतर्कता दर्शाई गई तथा तत्काल कार्यवाही की गई है। स्वाईन फ्ल्यू मामलों के प्रबन्धन, दवाएं, आई.ई.सी. गतिविधियों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश 11.1.2013 को पुनः निर्देशित कर दिये गये थे। उपचार प्रोटोकाल का पालन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ताई से

[राव नरेन्द्र सिंह]

किया जा रहा है तथा स्वाईन फ्ल्यू के मामलों को लक्षणों तथा रोगी के स्वास्थ्य के आधार पर ए.,बी. तथा सी. वर्गो में बांटा गया है। जिन रोगियों को मामूली बुखार, खांसी, बदन दर्द अथवा बदन दर्द के बिना गला पका होना, सिर दर्द तथा उल्टियां लगी हों, उन्हें 'ए' वर्ग में रखा गया है। ऐसे रोगियों को आसेल्टेमीवीर (टेमीफ्लू) दवा की जरूरत नहीं होती तथा 24 से 48 घण्टे तक निगरानी में रखा जाता है तथा एच.वन.एन.वन. परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। ए. वर्ग के चिन्हों एवं लक्षणों के अतिरिक्त उच्च जोखिम समूह के रोगियों जैसे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के रोगी, फेफड़ों के रोग से पीड़ित रोगी, हृदय रोग, जिगर रोग, गुर्दे के रोग, रक्त डिसार्डर, मधुमेह, स्नायु रोग, कैंसर, एच. आई.वी./एड्स तथा दीर्घकालिक कॉटीसॉन की थैरेपी पर निर्भर रोगी बी-वर्ग में सम्मिलित हैं। इन रोगियों को घर में अलग रखने तथा ओसेल्टेमीवीर द्वारा उपचार करने की आवश्यकता होती है। इन रोगियों का एच.वन.एन.वन. परीक्षण आवश्यक नहीं है। वर्ग 'सी' में वे रोगी आते हैं जिन्हें सांस फूलने, सीने में दर्द, उनींदापन, थूक में खून आना, नाखूनों का रंग नीला होना तथा पुरानी बीमारी के और बिगड़ने की समस्या हो। वर्ग-सी के सभी रोगियों को एच.वन.एन.वन. परीक्षण और तत्काल अस्पताल में भर्ती करके उपचार की आवश्यकता होती है।

हरियाणा राज्य में एच.वन.एन.वन. जांच के लिए चार अधिकृत प्रयोगशालाएं जोकि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अन्वेषण संस्थान (PGIMER) चण्डीगढ़, डा. लाल पैथ प्रयोगशाला (गुड़गांव) तथा रैलीगेयर (गुड़गांव) हैं। निजी चिकित्सकों को रिपोर्ट करने वाले रोगियों सहित सभी रोगियों को ट्रैक किया जाता है और लाईन सूचीबद्ध करके उचित उपचार एवं अनुवर्ती सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनके संबंधियों/सम्पर्कों को बचाव के लिए उपचार दिया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वाईन फ्लू समाज में न फैले 830 परिवारों के सदस्यों का तत्काल बचाव संबंधी उपचार किया गया जब कि वर्ष 2009 में ऐसे 200 पारिवारिक मित्रों/सम्पर्कों का उपचार किया गया था।

यह कहना गलत है कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सूचित करने के लिए उचित मापदंड नहीं अपनाएं बल्कि लोगों को लक्षणों तथा सावधानियों के बारे में जागरुक करने हेतु सक्रिय एवं सामयिक कदम उठाए गए हैं। लोगों को रोग के लक्षणों तथा उपचार संबंधी जागरुकता लाने तथा लोगों में इस रोग के फैलने के भय को रोकने के उद्देश्य से राज्य मुख्यालय पर एक सघन अभियान चलाया गया। स्वाईन फ्ल्यू पर नियंत्रण पाने हेतु क्या करना चाहिए व क्या न करना चाहिए सहित आवश्यक सावधानियों के बारे में लोगों का मार्ग दर्शन करने बारे समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनके प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर दिये गये। सभी जिलों में जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठकों, प्रिन्ट मीडिया

तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सूचना तथा प्रसारण गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

सभी 21 जिलों की सर्वेक्षण यूनिटों से दैनिक रिपोर्ट प्राप्त हो रही है तथा इसका मूल्यांकन एवं निगरानी राज्य सर्वेक्षण यूनिट द्वारा किया जा रहा है। राज्य यूनिट सुनिश्चित करती है कि जिलों द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा प्रत्येक जिले में दवाओं का नियमित भण्डार बनाए रखा जाता है। 13 तथा 14 फरवरी, 2013 को आयोजित सिविल सर्जनों के सम्मेलन में सभी जिलों द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई।

चूंकि बहुत से रोगी निजी चिकित्सकों से उपचार प्राप्त करते हैं, इसलिए निजी चिकित्सकों का भारतीय चिकित्सा संगठन के माध्यम से संवेदीकरण करने तथा सूचना का प्रसार करने का कार्य किया गया है। विभिन्न जिलों में निजी चिकित्सकों को स्वाईन फ्लू के बारे में संवेदीकरण के लिए भारतीय चिकित्सा संगठन के साथ कुल 40 बैठकें आयोजित की गई।

राज्य के प्रत्येक जिला अस्पताल में स्वाईन फ्लू के रोगियों के लिए पृथक ओ.पी.डी. आरम्भ की जा चुकी है तथा कुल 10000 से अधिक रोगियों की जांच की जा चुकी है। इन रोगियों की वर्ग के अनुसार सूची तैयार की जा चुकी है। इन रोगियों की स्थिति पर नजर बनाए रखने हेतु उनके दूरभाष नंबर सामान्य रूप से रिकार्ड किये जा रहे हैं। 'ए' वर्ग का कोई रोगी वर्ग 'बी' तथा 'सी' में रूपांतरित न हो जाए, इसके भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सर्वेक्षण यूनिट द्वारा दूरभाष तथा ई-मेल के माध्यम से स्वाईन फ्लू की स्थिति की दैनिक निगरानी तथा समीक्षा की जा रही है। राज्य के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को जिलों के 'सी' वर्ग के रोगियों का उपचार करने हेतु चौकस रहने के लिए संवेदित किया गया है।

सभी जिलों को किसी आपातकालीन आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं और सिविल सर्जनों को यूजर राशि से खर्च करने की शक्तियां प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत सरकार से 1200 व्यक्तिगत सुरक्षा किट (PPE), 5500 ट्रिपल लेयर मास्क, 400 एन 95 मास्क, कैप ऑसलटैमीवीर 104000, तथा 450 वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम (VTM) वायल्स प्राप्त हुई हैं जिन्हें अनुपातिक रूप से सभी जिलों को वितरित किया जा चुका है।

राज्य के सभी जिले, सरकारी और निजी संस्थानों में आवश्यकता पड़ने पर वेंटीलेटर सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक जिले में निजी सेवा प्रदाताओं की पहचान हो चुकी है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में कुल 32 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। 90 वेंटीलेटरों की निजी संस्थाओं में पहचान हो चुकी है। सिविल सर्जनों को आवश्यकता पड़ने पर सरकारी संस्थानों में भर्ती रोगियों के लिए निजी संस्थानों से उपलब्ध वेंटीलेटरों का प्रयोग करने के निर्देश जारी किये गए हैं और इस पर आने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[राव नरेन्द्र सिंह]

प्रत्येक जिला अस्पताल में आइसोलेशन सुविधा उपलब्ध है जिसमें 214 बिस्तरों की क्षमता है। पता लगाए गए कुल 360 मामलों में से 56 रोगी सरकारी जिला अस्पतालों में भर्ती किये गये थे।

मैं यह भी सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि विश्व के सभी भागों में लगभग 45 करोड़ लोग निमोनिया से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं तथा यह सभी आयु वर्गों में मौत का प्रमुख कारण है जिससे प्रतिवर्ष 40 लाख लोगों की मौत होती है। (विश्व में प्रतिवर्ष होने वाली कुल मौतों का 7%)

माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा द्वारा मूलभूत संरचना के संबंध में उठाए गए मुद्दे के प्रत्युत्तर में कहना चाहूंगा कि सरकार ने मूलभूत स्वास्थ्य संरचना को सशक्त करने का निरन्तर प्रयास किया है। भवनों के निर्माण पर प्रतिवर्ष लगभग 70-80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती है। उप स्वास्थ्य केन्द्र जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार 5000 जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है इसलिए प्रत्येक गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। वर्ष 2005 की तुलना में इस समय राज्य में 2630 उप-स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, जबकि 2005 में 2433 उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत थे। इसी प्रकार मानदण्डों के अनुसार 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है तथा प्रत्येक गांव में नहीं है। इस समय राज्य में 466 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जबकि वर्ष 2005 में 294 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत थे। सरकार मूलभूत स्वास्थ्य संरचना में सुधार लाने तथा अन्तराल को चरणबद्ध रूप से भरने के लिए कृत संकल्प है। नए उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय जरूरतों, पंचायत भूमि की उपलब्धता तथा धन की उपलब्धता के मद्देनजर खोले जा रहे हैं। इस समय 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 286 उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं। 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 2 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रशासनिक अनुमोदना वर्ष 2012-13 में प्रदान की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2008 में एक नई मानक ड्राईंग को अंतिम रूप दिया गया जिसमें चिकित्सकों तथा अन्य अमले के लिए आवासों का प्रावधान किया गया है।

महिला चिकित्सकों की कमी के मुद्दे के सम्बन्ध में कथन है कि सामान्य रूप से देश में महिला चिकित्सकों सहित चिकित्सकों की कमी है। नये चिकित्सकों तथा महिला चिकित्सकों की नियमित भर्ती के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से सतर्क है तथा विभाग द्वारा महामारी जांच, पर्याप्त मात्रा में दवाओं का प्रावधान, आइसोलेशन सुविधा, निजी चिकित्सकों की भागीदारी तथा आम जनता में जागृति द्वारा स्वाईन फ्ल्यू पर नियंत्रण पाने के सभी कदम उठाए गए हैं।

इस प्रयास में मैं सदन के सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का भी और आपका भी धन्यवाद करता हूं। जो स्वाईन फ्ल्यू टैस्टिंग लैब्स हैं यह पूरे प्रदेश में नहीं हैं। सिर्फ पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में है और यह एच1 वन1 की जो रिपोर्ट आती है यह 4-5 दिन में आती है, तब तक स्वाईन फ्ल्यू का मरीज संकटमय स्थिति में चला जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या शीघ्रातिशीघ्र लैब की रिपोर्ट आ सके, इसके लिए कोई कदम उठाएंगे?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा के लिए 4 लैब्स रजिस्टर की गई हैं कि हरियाणा के सारे टैस्ट इन्हीं लैब्स में जाएंगे। दो सरकारी लैब्स जिनमें से एक एन.सी.डी.सी. दिल्ली में है और दूसरी पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में है। दो प्राइवेट लैब्स गुड़गांव में हैं जिनमें से एक रैलीगेयर और दूसरी लाल पैथ लैब्स। इन चार लैब्स को अथोराइज किया गया है और जो भी सैम्पल लिए जाते हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर रिपोर्ट आती है। जहां तक आइसोलेशन वार्ड का सम्बन्ध है पूरे प्रदेश में लगभग 214 ऐसे वार्ड मुकर्रर किए गए हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल्ज हैं उनमें अलग से ओ.पी.डी. की व्यवस्था पेशेंट्स को चैक करने के लिए होगी। जो भी इस तरह के केसिज आते हैं, उनको सैपरेट रखते हैं और उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है।

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह लैब पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में है तो पी.जी.आई. रोहतक में क्यों नहीं बनाई जा सकती है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जितने भी जिला मुख्यालय में बड़े-बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर इस तरह की लैब्स का बंदोबस्त क्यों नहीं किया जा सकता है और इसके अलावा तीसरा मेरा प्रश्न है कि प्रदेश में डाक्टर्ज की जो कमी है उसके लिए क्या मंत्री महोदय शिविर लगाकर डाक्टर्ज को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे ताकि डाक्टर्ज को इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो और वे अच्छी दवाइयां पेशेन्ट्स को दे सकें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो तीन प्रश्न किए हैं। उनका पहला प्रश्न रोहतक में लैब बनाने के बारे में है। मैं पहले भी सदन की जानकारी के लिए बता चुका हूं और पुनः बताना चाहता हूं कि ये लैब्स भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। सिर्फ हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल सभी स्टेट्स के लिए भी भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित की गई हैं। ये लैब्स डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लैवल पर नहीं हैं और सिर्फ हमारी स्टेट नहीं बल्कि किसी भी स्टेट में इस तरह की लैब्स नहीं हैं। जो माननीय सदस्य का सुझाव है इसके लिए हम भारत सरकार को लिखेंगे कि पी.जी.आई. रोहतक में लैब खोलने की परमिशन मिल जाए और यह भी चाहेंगे कि भविष्य में हरियाणा प्रदेश के लिए ऐक्स्ट्रा लैब्स और मिल जाएं। इस समय दो सरकारी लैब्स जिनमें से एक एन.सी.डी.सी. दिल्ली में है और दूसरी पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में है। दो प्राईवेट लैब्स गुड़गांव में हैं जिनमें से एक रैलीगेयर और दूसरी लाल पैथ लैब्स हैं।

⋮

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वाईन फ्ल्यू एक ऐसी भयंकर बीमारी आई है कि यदि किसी आदमी को थोड़ा बहुत बुखार भी हो तो आदमी यह सोचने लगता है कि कहीं स्वाईन फ्ल्यू न हो। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि टैस्टिंग लैब्स के लिए तो इनको सिर्फ भारत सरकार से मंजूरी ही लेनी होती होगी। फंड लेना कोई जरूरी नहीं है फंड तो हरियाणा सरकार भी खर्च कर सकती है। लैब खोलने का आप समय रहते प्रयास कर लें क्योंकि दो-तीन महीने इस बीमारी को फैले हुए हो चुके हैं। मैंने इस बारे में 11 मार्च, 2013 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था लेकिन रामपाल माजरा जी ने 13 मार्च, 2013 को दिया था। मुझे खुशी है कि रामपाल जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये भी मेरे कुलीग हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां तक लैब का सवाल है आप चाहे इसे एडहोक तौर पर मन्जूरी लेकर सिस्टम को जरूर शुरू करें। दूसरी बात वेन्टीलेटर और आईसोलेशन के बारे में कही गई है। क्या मंत्री जी ने कभी डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल में जाकर कोई आईसोलेशन वार्ड चैक किया है? मंत्री जी आपके डिस्ट्रिक्ट के कई होस्पिटल्ज मेरे नोटिस में हैं जिनमें केवल मात्र दो कमरों के आगे पर्दा लगाकर आईसोलेशन वार्ड बनाये हुए हैं और उन्हीं को आपने आईसोलेशन वार्ड मान लिया। अगर पर्दे से आईसोलेशन वार्ड बन जाता है तो that is very horrible. आप यह देखेंगे कि आईसोलेशन वार्ड के क्या नार्म्स हैं, उसके लिए क्या-क्या चीजें चाहिए, What would you require for it? उसके बाद आप एक भी होस्पिटल को चैक कर लें और वहां पर आईसोलेशन वार्ड के क्या नार्म्स हैं उनके बारे में पता कर लें। आपको अभी तक तो नार्म्स के बारे में पता लग गया होगा क्योंकि यह तो काफी सीरियस बीमारी है। आपको पता लग जायेगा। आप एजूकेटिड और पढ़े लिखे और जागरूक मंत्री हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप टैस्ट चैक के तौर पर देखेंगे कि इस बारे में कोई फायदा नहीं हो रहा है। जहां तक वेन्टीलेटर की बात है अभी तक आप इस बारे में इन्स्ट्रूमैंट और ऑपरेटर का तालमेल नहीं बैठा पाये हैं क्योंकि इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट नहीं हैं। बहुत जगह आपने इक्विपमैंट भेज रखे हैं लेकिन वहां पर इक्विपमैंट ऑपरेटर नहीं हैं। जहां तक मेरी जानकारी है हिसार से आपके दो इक्विपमैंट्स उठ गये हैं। इसके अलावा जो वहां पर अवेलेबल हैं वे काम कर रहे हैं या नहीं इसके बारे में पता नहीं। ऐसी स्थिति में मंत्री जी एक तो आपके इक्विपमैंट भी काम नहीं कर रहे हो और दूसरे आईसोलेशन वार्ड भी न हों, ऐसे में क्या होगा कि बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। दिनांक 11.2.2013 को जब मैंने यह कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था उस समय हरियाणा में स्वाईन फ्ल्यू से 24 आदमी मरे थे। उसके बाद अब तक आज की तारीख में प्रदेश में 40 स्वाईन फ्ल्यू के केसिज हो चुके हैं। आपने जो रिप्लाई में 38 की संख्या दी है यह शायद 2 दिन पहले के आंकड़े हैं। इतनी सीरियस बीमारी प्रदेश में फैल रही है। इन चीजों के बारे में you should be more serious being a young, energetic and educated minister.

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रोफैसर साहब ने जो प्रश्न किया है वह वेन्टीलेटर के बारे में है। वेन्टीलेटर को चलाने के लिए एक्सपर्ट टीम की जरूरत पड़ती है।

एक्सपर्ट की उपलब्धता न होने की वजह से ये वेन्टीलेटर काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी मेडिकल कालेज रोहतक में 13 तथा 6 रिजर्व कुल 19 वेन्टीलैटर्ज मुकर्र किए हुए हैं, भगत फूल सिंह मेडिकल कालेज में 6, मेडिकल कालेज अग्रोहा में 2 और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर जैसे गुड़गांव और रोहतक में 5, इस प्रकार कुल 32 वेन्टीलेटर्ज जहां पर सरकारी होस्पिटल्ज हैं वहां पर दिए हुए हैं। इसके अलावा 19 वेन्टीलेटर्ज प्राईवेट इन्स्टीट्यूट्स में भी मुकर्र किए हुए हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो वहां से हम मंगवा लेते हैं। हमने सभी सी.एम.ओज. को कह रखा है कि वे अपने यूजर्स फण्ड से इनकी मदद ले सकते हैं। जहां तक आईसोलेशन वार्ड की बात है इस बारे में सरकार ने स्टेट लेवल की एक सर्विलैंस कमेटी बनाई हुई है और डायरेक्टर हैल्थ को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के सी.एम.ओ. को अपने डिस्ट्रिक्ट का इन्चार्ज बनाया हुआ है। प्रोफैसर साहब के इस बारे में जो भी सुझाव आये हैं हम उनके बारे में चैक करवा लेंगे। इस समय स्टेट में 214 आईसोलेशन वार्ड की संख्या हमारे पास उपलब्ध है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये बिल्कुल नार्म्स के हिसाब से काम करें।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि वेन्टीलेटर ऑपरेटर ही उपलब्ध नहीं हैं। आप ये बतायें कि वेन्टीलेटर कितने हैं और चलने की पोजीशन में कितने हैं? पिछली बार सुमिता सिंह जी ने कहा था कि करनाल में दो वेन्टीलेटर्ज हैं वे अनयूज्ड पड़े हैं। इन पर सात लाख रुपये से ज्यादा खर्चा हो गया लेकिन उनको चलाने वाला वहां पर कोई नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि हिसार में भी दो तो वेन्टीलेटर वहां से उठ गये थे और मेरे आने के बाद हो सकता है और भी उठ गये होंगे।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रो. साहब को बताना चाहूंगा कि वेन्टीलेटर को चलाने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए स्पेशलिस्ट स्टाफ की जरूरत होती है जो 24 घण्टे के कान्टीन्यूस प्रोसैस में काम कर सके। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल में हमारे पास प्रोपर स्टाफ नहीं है जो इनके लिए काम कर सके। स्पीकर सर, वेन्टीलेटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर के अन्दर नलकी डालकर इस्तेमाल किया जाता है और एक बॉडी के बाहर से ही जिस भी मरीज को सांस की तकलीफ होती है उसके जांचने में काम आता है। इसलिए इसकी दूसरी सुविधा के लिए जो अपने सरकारी मेडिकल कालेज हैं उनमें ये वेन्टीलेटर्ज यूज करने के लिए दिए हैं। जैसे ही एक्सपर्ट उपलब्ध हो जायेंगे तो हम हर जगह डिप्यूट कर देंगे। हम चाहते हैं कि यह सुविधा हर डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल में उपलब्ध हो।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, सरकार के पास जो डाक्टर्ज उपलब्ध हैं उन्हीं को कोई इन्सैन्टिव दिया जाये ताकि वे ही इन वेन्टीलेटर्ज पर काम कर सकें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार जो इन्सैन्टिव दे सकती है वह दे रही है। इसके अलावा जो भी प्रयास सरकार कर सकती है वह करेगी।

:
:
:

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल वेन्टीलेटर्ज का नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी आपने देखा होगा कि जो आपके इक्विपमैंट हैं उनमें से काफी एक्विपमैंट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास स्टाफ नहीं है। पैरामैडीकल स्टाफ के बिना डाक्टर्ज अधूरे हो जाते हैं और सारे काम डाक्टर्ज को करने पड़ते हैं। डाक्टर्ज को ही बुखार, बी.पी. और शूगर वगैरह चैक करने पड़ते हैं। पैरामैडीकल स्टाफ पूरा हो तो हमें इतने ज्यादा डाक्टर्ज की जरूरत ही न पड़े। भारत सरकार ने जो पिछले दिनों पैरामीटर्ज निकाले हैं उसके हिसाब से हरियाणा में कम से कम डेढ़ लाख पैरामैडीकल स्टाफ की जरूरत है। इस समय कितना पैरामैडीकल स्टाफ है इस बारे में मुझे पता नहीं है। शकुंतला खटक जी इस सर्विस में रही है इसलिए उनको इस बारे में ज्यादा पता है। अध्यक्ष महोदय, पैरामैडीकल स्टाफ की आज बहुत जरूरत है। हिन्दुस्तान में यह आंकड़ा 56 लाख का था और अपने यहां डेढ़ लाख पैरामैडीकल स्टाफ की रिक्वायरमैंट है। अगर आप पैरामैडीकल स्टाफ नहीं लगाएंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर्ज आज मिल नहीं रहे और पैरामैडीकल स्टाफ आप भर्ती नहीं कर रहे। पैरामैडीकल स्टाफ की भर्ती करें और उनको ट्रेनिंग दिलवाकर भर्ती करें। केवल सर्टिफिकेट के आधार पर पैरामैडीकल स्टाफ की भर्ती नहीं होनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग दिलवाकर ही भर्ती किया जाए। ऐसे बहुत से इंस्टीच्यूट खुले हुए हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस बारे में मैं डिमांड के समय डिसकस करूंगा। जो मशीनें पड़ी हैं चाहे एक्सरे मशीन हैं वहां रेडियोलोजिस्ट नहीं है तो एक्सरे मशीन किस काम आएगी। इसी तरह जो दूसरी मशीनें हैं अगर उनको हैंडल करने वाले नहीं होंगे तो इन मशीनों का कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे महकमे में मीटिंग करके पता करें कि किस-किस हॉस्पिटल में क्या-क्या और कितने-कितने इक्यूपमैंट्स हैं और कितने रिक्वायर्ड हैं? डाक्टर्ज की बात आप छोड़िए क्योंकि भर्ती करने में टाइम लगता है। डाक्टर्ज को भरने में तेजी लाईए और इनको इन्सैंटिव दीजिए ताकि डाक्टर्ज हमारे होस्पिटल्ज के अंदर अट्रैक्ट होकर आएं और यह जरूरी भी है। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर्ज से ज्यादा पैरामैडीकल स्टाफ, स्पोर्टिंग स्टाफ और टैक्नीशियन वगैरह की आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग आज बाहर के अस्पतालों में लूटे जा रहे हैं। प्राइवेट होस्पिटल्ज वाले लोगों की जेबें काट रहे हैं। फ्री या नार्मल रेट पर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों को मिलनी चाहिएं वे सुविधाएं हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये प्राइवेट होस्पिटल्ज पनप रहे हैं, लैबोरेट्रीज पनप रही हैं। सिविल अस्पताल के बाहर जिसने भी कोई एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीन लगा रखी है आज के दिन वह सबसे ज्यादा कामयाब है। मेरा निवेदन है कि सरकार इन चीजों की तरफ विशेष ध्यान दे।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने पैरामैडीकल स्टाफ का जिक्र किया है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज पैरामैडीकल स्टाफ की कमी है इसलिए इनकी भर्ती करने के लिए हम सर्विस कमीशन को लिख चुके हैं और उनकी संख्या

इन्क्रीज करने के लिए भी प्रोसैस चलाया हुआ है। प्रो. सम्पत सिंह जी ने वाजिब सुझाव दिया है। हमने उसको नोट कर लिया है और हम उस पर अमल करेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, स्वाईन फ्ल्यू तकरीबन हर साल आता है। यह सूअर की जो रैस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें इंफैक्शन से जनरेट होता है उसके बाद इंसान के छींकने से और हाथ लगाने से फैलता है। आइसोलेशन न रहने से फैलता है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I just want to intervene and to correct my learned friend that it is a form of influenza and it has spread to many States over the years. It has been noted acess the world, and it has effected 9 crores people in various countries. Due to this influenza 45 lacs deaths happened across the world, as per the WHO data that we saw. But to say that it is only a form of influenza and sometime, it takes different contagious shapes. (Interruption)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, it is not a point of discussion. I am not talking about that. It is not a point of discussion. The minister is just elaborating over it. मैं यह कह रहा हूं कि यह बीमारी लगभग हर साल आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी इस बीमारी से 38 मौतें हुई हैं। ये एक तरह से ओर्डिनरी इंफ्ल्यूंजा ही होता है, खांसी जुकाम होता है, जब तक इसमें एच-1 और एन-1 में अंतर न कर लिया जाए, टैस्ट न किया जाये या इलाज न किया जाए तो यह इतनी तेजी से फैलता है कि फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। मरीज की आक्सीजन लेने की क्रिया रूक जाती है और उसकी डैथ हो जाती है। स्वाईन फ्ल्यू के मरीज को बचाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है।

Mr. Speaker : I do not want to be taught on this issue. Please ask your supplementary.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड ही कर रहा हूं। मेरी डिमांड यह है कि इस बीमारी के ईलाज के लिए टैमीफलू दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सभी हस्पतालों में इस दवाई को उपलब्ध करवाया जाये। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सारे अस्पतालों में नहीं हो सकता तो कम से कम जिला अस्पताल में वैंटीलेटर, एक टैस्टिंग लैब और टैमीफलू दवाई अवश्य उपलब्ध करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, मैडीकल और हैल्थ के लिए बहुत बजट सरकार के पास होता है और केन्द्र सरकार से भी बहुत सहायता मिलती है। इस भयानक बीमारी पर रोक लगानी चाहिए और लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए। स्वाइन फ्ल्यू से मरीज के बहुत जल्दी फेफड़े खराब हो जाते हैं और उसको सांस लेने के लिए वैंटीलेटर की आवश्यकता होती है। जब तक उसे पी.जी.आई. रोहतक पहुंचाते हैं उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। इसलिए हर जिला अस्पताल में एक वैंटीलेटर, एक टैस्टिंग लैब और टैमीफलू दवाई उपलब्ध अवश्य करवाई जाये ताकि प्रदेश के लोगों को इस भयंकर बीमारी से बचाया जा सके।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, you have already replied on this.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

Rao Narender Singh : Yes Sir.

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरराम्भण)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the Budget Estimates for the year 2013-14 will be resumed.

श्री राजपाल भूखड़ी (सढ़ौरा, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर चर्चा करने के लिए समय दिया है। इस गरिमामय सदन में चर्चा करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय संसाधन जुटाने में हमने देश के दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 के दौरान 43780.33 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है जोकि संशोधित अनुमान 2012-13 से 15.75% प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह से हमारा राजस्व कर 28784.34 करोड़ रुपये है जो संशोधित अनुमान 2012-13 से 18.50% की वृद्धि दर्शाता है। हमारा राजस्व खर्च 12.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 46223.56 करोड़ रुपये होगा इसके लिए मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताई गई है जो कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरह से प्रिय दर्शनी आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2013-14 के बजट में 'प्रियदर्शनी आवास योजना' के नाम से एक महत्त्वकांक्षी आवास योजना को शुरू किया है। इसी तरह से जिनके पास मकान नहीं हैं या कच्चे मकान हैं उनके लिए भी वर्ष 2013-14 व 2014-15 की अवधि की परियोजना में 2 लाख परिवारों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत मैं मानता हूं कि जो लोग अपने घर का सपना देखते हैं उनका सपना पूरा हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी इससे पहले सरकार बनी थी उस समय वर्ष 2009 में 100-100 गज के प्लाट गरीब आदमियों को देने का निर्णय लिया था जिसमें सरकार ने काफी कामयाबी भी हासिल की है लेकिन उस समय जिन लोगों को ग्राम पंचायत के पास जमीन न होने के कारण या किसी दूसरे कारण से प्लाट नहीं मिल सके उन लोगों को प्राथमिकता देकर प्लाट अलॉट किए जायें। उस समय कुछ जगह लोगों को प्लॉट तो मिल गये लेकिन कब्जा नहीं मिला। उन गरीब लोगों को कब्जा भी दिलवाया जाये ताकि गरीब आदमी को फायदा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गरीब लोगों की मदद करने के लिए हमारी सरकार मकान बनाने के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत गरीब आदमियों को 50 हजार से बढ़ाकर 81 हजार रुपये कर दिया है व शौचालय बनाने के लिए अलग से 9100 रुपये दिए जायेंगे। मैं इस कार्य की सराहना करता हूं क्योंकि इससे जो मैटीरियल की महंगाई हुई है और जो ईंटें महंगी हुई हैं उससे गरीब आदमी अच्छे

तरीके से अपना मकान बना सकेगा क्योंकि 50 हजार रुपये की राशि से उसके लिए अपना मकान बनाना मुश्किल है। डिप्टी स्पीकर सर, इस योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने नये आयाम स्थापित किये हैं। जैसे कि वर्ष 2010-11 के लिए गेहूं की पूरे देश में कृषि की उत्पादकता का लक्ष्य हासिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को कर्मण अवार्ड प्रदान किया है और वर्ष 2012-13 का भी कृषि कर्मण अवार्ड हमारे राज्य को मिले। मैं इसके लिए भी अपने सरकार के प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश के किसानों ने कृषि की उपज बढ़ाने के लिए जो मेहनत की है मैं उनको भी इसका श्रेय देते हुए बधाई देना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रयासों से हमारे प्रदेश के किसान निरंतर इस मामले में आगे बढ़ते रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय जी, अगर ग्रामीण विकास की बात की जाये तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ऐलान किया था कि हम सभी गांवों को 10 लाख रुपये की राशि विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए देंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत बड़े गांव हैं उनको 25 लाख रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए दी जायेगी और सभी गांवों को अच्छा बनाया जायेगा। इसमें भी हमारी सरकार काफी आगे बढ़ी है और इस सम्बन्ध में काफी अच्छे कार्य हुए हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। मेरे हल्के में 264 गांव हैं और 200 पंचायतें हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि मुझे अपने क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद दी जाये। डिप्टी स्पीकर सर, मेरे हल्के में जो घाड़ का क्षेत्र है उसके बारे में आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वहां के लोगों को क्या-क्या दिक्कतें हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस घाड़ के क्षेत्र की ओवरऑल डिवैल्पमैंट के लिए कम से कम मुझे पांच करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया जाये ताकि इस घाड़ क्षेत्र के जो गांव हैं उनका समुचित विकास जल्दी से जल्दी हो सके और वहां के निवासी भी समतल क्षेत्र वालों के बराबर खड़े हो सकें। डिप्टी स्पीकर सर, आपको भी इस बारे में बहुत ज्यादा पता है क्योंकि आप भी वहां आते-जाते रहते हैं कि वहां पर जो घाड़ का क्षेत्र है वहां पर ऊंचा-नीचा ऐरिया है। वहां पर न तो पानी के इतने अच्छे साधन हैं और न ही वहां पर आमदन के बहुत अच्छे साधन हैं। इस प्रकार से वहां पर जो लोग रहते हैं वे बहुत ज्यादा गरीब हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनली मिलकर भी इस बारे में प्रार्थना की थी और मेरे हल्के के इस घाड़ के क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए पांच करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की डिमाण्ड की थी जिसको पूरा करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको हामी भी भरी है। (विघ्न)

डॉ. बिशन लाल सैनी : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : सैनी जी, आप किस बात का प्वायंट ऑफ आर्डर मांग रहे हैं? कृपया आप बैठ जाइये और हाऊस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान)

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Deputy Speaker Sir, they spoke for two and half hours yesterday, but we did'nt disturb them. Today when a Hon'ble Member is raising demands for his area, why they are disturbing him?

श्री राजपाल भूखड़ी : डिप्टी स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, आप आई.एन.एल.डी. के माननीय साथियों की स्पैशल क्लास लगवाकर इनको हाऊस में व्यवहार करने की तहजीब सिखाईये। (विघ्न) इनको इतना भी नहीं मालूम कि हाऊस की एक महिला सदस्य से किस प्रकार से बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजपाल जी, आप बोलिए।

श्री मोहम्मद इलियास : डिप्टी स्पीकर सर, ******

श्री उपाध्यक्ष : इलियस जी, आपको भी बोलने के लिए मौका दिया जायेगा उस समय आप बोल लेना। अब आप कृपया करके बैठ जाइये और हाऊस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब मत कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) Not to be recorded. मोहम्मद इलियास जी, चेयर के आदेश के बिना बोल रहे हैं इसलिए ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : राजपाल जी, आप बोलिए।

श्री राजपाल भूखड़ी : डिप्टी स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, मैं सिर्फ एक मिनट ही लूंगा। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह श्री इलियास जी के लिए बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इनकी पार्टी ने बजट पर बोलने के लिए जो list of Members दी है उसमें इनका नाम ही नहीं है यानि इनकी पार्टी इनको इस लायक भी नहीं समझती कि ये बजट पर कुछ बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं लेकिन इलियास जी को इससे ऐतराज क्यों हो रहा है? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : इलियास जी, आप बार-बार डिस्टर्ब न करें। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात रख रहे हैं, ये उसको डिक्टेट कैसे कर सकते हैं कि उसको क्या कहना है और क्या नहीं? (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इलियास जी, आप बैठिये। एक सदस्य अपने हल्के की बात रख रहा है, आप उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, कल विपक्ष अढ़ाई घण्टे तक बोला है लेकिन हमने उनको बिल्कुल नहीं टोका। पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर साहब बोले, फिर रामपाल माजरा जी लगभग डेढ़ घण्टा बोले हमने कुछ नहीं कहा। क्या इस प्रकार से संसदीय प्रणाली की मर्यादाओं को निभाया जा सकता है? एक माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं और विपक्ष के साथी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए। मेरे काबिल साथी का तो उनकी पार्टी ने बोलने वालों की लिस्ट में नाम भी नहीं दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं फिर भी मैं अनुरोध करूंगा, वे हमारे बड़े भाई हैं, वे तीसरी बार चुनकर आये हैं, उन्हें बोलने का मौका जरूर दीजिए। सैनी साहब, ये आपके जिले की ही मांग उठा रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छी बात होगी, इसलिए आप इनको अपनी बात कहने दें।

श्री राजपाल भूखड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे खाड़ के क्षेत्र के बारे में कहा है कि आपके खाड़ क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये और देंगे, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, हमारा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है। हमारे इलाके में गन्ना ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। यह रिकार्ड की बात है और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को गन्ने के 45/- रुपये प्रति क्विंटल के दाम बढ़ा दिया हैं। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक रिकार्ड की बात और बताता हूं, 1982 में किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किये थे। उस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था मुझे उसका पता नहीं है क्योंकि उस समय तो मैं बच्चा होता था और वैसे भी मैं किसी का नाम नहीं लेता। किसानों ने यमुनानगर में गन्ने के रेट में 50 पैसे बढ़वाने के लिए प्रदर्शन किया था लेकिन हमारे किसानों पर घोड़े चढ़वा दिये थे, लाठियां भांजी गई और पानी की बौछारें मारी गई। आज के हमारे मुख्यमंत्री ने किसी के ऊपर कोई लाठी या गोली नहीं चलवाई और 45 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के दाम बढ़ा दिये।

डॉ. बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, केवल लाठियों और पानी की बौछारों से ही काम नहीं चला था बल्कि घोड़ों की टापों से भी मरवाया गया था लेकिन 50 पैसे गन्ने के दाम नहीं बढ़ाये गये थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैनी साहब को कुछ नई जानकारी देना चाहता हूं। नारायणगढ़ और यमुनानगर के किसानों पर 1999 से 2005 के बीच में ओमप्रकाश चौटाला की सरकार के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, लाठियां चलवाई गई और मुकदमे दर्ज किये गये थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने वे मुकदमे वापस लिये हैं और उन किसानों को रिहा करवाया था। इसी प्रकार से कंडेला में जो किसान उनके द्वारा किये गये वायदे को पूरा करने की मांग कर रहे थे, 12 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। नारायणगढ़ और यमुनानगर में भी किसानों पर इसी प्रकार से गोलियां और लाठियां चली थी। उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
डॉ. बिशन लाल सैनी जी को तो शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि ये उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य नहीं थे। ये तो उस समय विरोध करने वालों में थे, ये उस समय बहुजन समाज पार्टी के सदस्य होते थे और ये भी लाठियां खाने वालों में शामिल थे।

श्री राजपाल भूखड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि किसानों को जो गन्ने का भाव 45 रुपये बढ़कर मिला है यह एक ऐतिहासिक बात है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह भी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि अगले वर्ष हरियाणा के किसानों को जो गन्ने का मूल्य दिया जाये वह दूसरे राज्यों से ज्यादा दिया जाए। सर, अगर मैं पॉपुलर के रेट की बात करूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शोर न करें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्हें बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : सर, मैं अपने हल्के के बारे में भी बात करना चाहूंगा। मैं सदन में एक बात कहना चाहता हूं कि सन् 1999 से 2005 के दौरान हमारे क्षेत्र के किसानों ने गन्ने की फसल को अपने खेतों से उखाड़ दिया था। जिसके कारण गन्ने की कमी के कारण शुगर मिल की तीन यूनिटों में से केवल एक ही यूनिट चलती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अबकी बार गन्ने की बिजाई के लिए विशेष सब्सिडी दी जाए, ताकि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ने की फसल बीज सकें तभी हमारी शुगर मिल की गन्ने की पिराई की जो क्षमता है वह पूरी हो सकेगी और उसकी तीनों यूनिटें चल सकेंगी तभी हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा चीनी का उत्पादन हो सकेगा। सर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सन् 1999 से 2005 के बीच किसानों ने गन्ने की फसल को इसलिए उखाड़ा था क्योंकि किसानों को समय पर गन्ने की पैदावार का शुगर मिल द्वारा भुगतान नहीं किया जाता था। हमारी सरकार ने सन् 2005 के बाद 32 करोड़ रुपया किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान किया है। सर, अब मैं पॉपुलर की खेती के बारे में कहना चाहूंगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसमें किसी को कोई दिक्कत हो। (शोर एवं व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष, यमुनानगर का इलाका आपके हल्के और मेरे हल्के का इलाका है। इस इलाके के किसानों ने पॉपुलर की खेती की वजह से ही इतनी तरक्की की है। इसके अलावा इस इलाके के पास कोई ज्यादा साधन नहीं हैं। आज हमारी सरकार ने पॉपुलर का मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। लेकिन सन् 1999 से 2005 के बीच जब इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी उस समय किसानों ने पॉपुलर की खेती को उखाड़ दिया था। आज अगर आप देखें तो 80% जमीन में हमारे किसान पॉपुलर की खेती की पैदावार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शोर न करें, भूखड़ी जी आप जल्दी से वाईंड अप कीजिए।

श्री राजपाल भूखड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसी हमारी सरकार की नीतियां हैं, उसके कारण ही हमारे किसानों ने पॉपुलर की खेती से तरक्की की है और आगे भी तरक्की करेगा। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश से हमारे राज्य में घुसेगा और अगर हमारे राज्य का सड़क तंत्र मजबूत होगा तो उससे यह लगेगा कि हमारा राज्य बहुत आगे है। हमारे राज्य में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सर, जो दिक्कत है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। सर, कोर्ट के आदेशानुसार हमारे प्रदेश में खनन बंद है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जोकि यहां बैठे हैं, उनको भी आपके माध्यम से यह रिक्वैस्ट कहना चाहूंगा कि वह भी खनन पर लगे बैन को खुलवाने पर पूरा विचार करें। सर, यमुनानगर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। हमारा एरिया फ्लड इफैक्टिड है। सर, जब ऊपर पहाड़ी से पानी आता है तो उससे सड़कें टूट जाती हैं। (विघ्न) दिलबाग जी, जिस बात के लिए मैं बोलता हूं, आप तो उस बात पर बोलते भी नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्ष : दिलबाग जी, आप भूखड़ी जी को बोलने दीजिए, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दिलबाग सिंह : भूखड़ी जी, हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) का जो बजट अब की बार दिया गया है उस बजट को बढ़ाया जाये अन्यथा पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक नहीं हो पायेंगी। ये टूटी सड़कें तभी ठीक होंगी जब पी. डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) के बजट को बढ़ाया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश में बहुत सारे विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोले हैं और काफी पर काम जारी है जिनको पूरा होने में स्वाभाविक ही है कि समय लगेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सढ़ौरा क्षेत्र जोकि मेरे इलाके में पड़ता है, वहां पर ढाई-तीन लाख की आबादी है और पौने दो लाख वोटर हैं, बावजूद इसके वहां पर कोई भी कॉलेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक सरकारी कॉलेज दिया जाये ताकि हमारी बच्चियां जो खाड़ क्षेत्र से जगाधरी नहीं जा सकती क्योंकि यहां पर बसों के साधन पूरी संख्या में नहीं हैं, उनकी भी आगे की पढ़ाई करने की इच्छा पूरी हो सके। इसके अतिरिक्त हमारी क्षेत्र की और भी कई दिक्कतें हैं। एक तो बिलासपुर के अन्दर मिनी सैक्रेटरिएट बनाने की हमारी मांग है। वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री जी ने इसको सब-डिविजन का दर्जा दिया था जिससे डिप्टी स्पीकर सर आपके इलाके के साथ-साथ मेरे इलाके को भी फायदा हुआ है। जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन यहां पर लघु सचिवालय नहीं है। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर दिया है और मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हां भी भरी है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाया जाये। इसके अतिरिक्त हमारे इलाके में जो

[श्री राजपाल भूखड़ी]

जगाधरी से लेकर चण्डीगढ़ तक रेलवे लाईन को रेल बजट में मंजूरी मिली है उसके लिए मैं रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल जी का तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के साथ-साथ बहन कुमारी सैलजा जी जो हमारी सांसद भी हैं, का भी धन्यवाद करना चाहूंगा (इस समय मेजें थपथपाई गई) और प्रार्थना करूंगा कि इस रेलवे लाईन पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाया जाये जिससे हमारे इलाके में एक नई तरक्की आयेगी। अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने बिजली की विशेष क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक विशेष कार्य भी किये हैं। बिजली प्रदेश की समृद्धि और विकास के आधार के रूप में उभरी है। चालू वित्त वर्ष में दैनिक आधार पर औसतन 1078 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है जबकि वर्ष 2005 में 578 लाख प्रति यूनिट बिजली की आपूर्ति की जाती थी। हरियाणा में बिजली की 724.4 मैगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार ने आठ वर्ष के शासनकाल में 3712.80 मैगावाट बिजली की क्षमता और बढ़ाई है। सर, माननीय चौधरी बंसी लाल जी ने अपने पूरे कार्यकाल में बिजली का केवल एक ही कारखाना लगाया था जबकि हमारी सरकार ने 4 से लेकर 5 तक बिजली के कारखाने लगाये हैं। आज तक इस तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। अगर इस तरफ ध्यान दिया होता तो जिस जगह आज हम खड़े हैं उसके आगे हम खड़े नजर आते। इसके साथ-साथ मैं माननीय बिजली मंत्री जी से भी एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे इलाके में सढौरा, बिलासपुर, तलाकौर और मुस्तफाबाद चार सब-स्टेशंज हैं। इन चारों सब-स्टेशंज में 16 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर लगाये हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि चारों ट्रांस्फोर्मरों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और जिनकी मंजूरी भी हमारे बिजली विभाग ने दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : भूखड़ी जी, आप प्लीज जल्दी कीजिए, आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो यह चार सब स्टेशंज हैं उनमें जल्दी से जल्दी अलग से जो ट्रांसफार्मर मंजूर किये गये हैं, उनको भेजा जाये ताकि मेरे इलाके में बिजली सुचारू रूप से चल सके। सर, मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर श्री सुरजेवाला जी से जोकि एक कर्मठ और हमारे काबिल मंत्री भी हैं, एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे हल्के की जो सड़कें हैं, जो मेन रोड हैं वे तो लगभग ठीक हैं लेकिन जो लिंक रोड हैं वह

12.00 बजे

कहीं आधा किलोमीटर और कोई एक किलोमीटर का छोटा-मोटा टुकड़ा है, उनकी मैंने लिस्ट सौंपी हुई है, उन सड़कों की स्पेशल रिपेयर करवाई जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में मेरे हल्के में 10 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से मार्किटिंग बोर्ड की 45 सड़कें मंजूर हुई थी जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उनके लिए सरकार की तरफ से राशि भी जारी हो चुकी है लेकिन इन दो साल की अवधि में उनमें से सिर्फ 12 सड़कों की ही रिपेयर हो पाई है और बाकी की सड़कें

यूं की यूं पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन सड़कों की रिपेयर जल्द से जल्द कराई जाए। एक मामला मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि मेरे जिले में पिछले सप्ताह एक घटना हुई। वैसे तो खनन पर बैन है लेकिन कुछ लोग फिर भी खनन करते हैं। उसमें हम उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन लोगों के साथ जो ट्रक भरकर ले जा रहा था वह सढ़ौरा में पकड़ा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहां की पुलिस के आला अधिकारियों ने उनको सी.आई.ए. में बंद किया और छह लोगों को चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग गलत काम करें उनके लिए संबंधित धारा के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। जो कुछ उन छह लोगों के साथ हुआ है वह मामला मीडिया में भी आया है। जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ है इसलिए सरकार की तरफ से उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी को इस बात का हक नहीं है कि कानून को तोड़कर, मानवीय हिदायतों को और मानवता को छोड़कर किसी की जान ही ले लेगा, किसी के हाथ पैर ही तोड़ देगा। कोई भी आदमी अगर अधिकारी बन जाता है तो वह परमात्मा की वजह से बनता है। इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता के प्रति मानवता को ही छोड़ दे। हमारे संस्कार और मानवीय कोर्ट भी इस बात की इजाजत नहीं देते कि किसी को डंडे-सोटे से पीटा जाए और वह भी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसको आई.पी.एस. की फीती लगी हो। हमें किसी पद पर भेजा गया है तो हमें लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है, दुख दर्द दूर करने के लिए भेजा है। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने बिजली के बिल माफ किए, कर्ज माफ किए, किसानों के कर्ज माफ किए लेकिन हमारी सरकार ने उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग थे, जो खेती नहीं करने वाले लोग थे, उनका बिल भी माफ कर दिया गया लेकिन उनका पूरा भुगतान बैंक में नहीं गया है जिसकी वजह से उनको आगे लोन लेने में दिक्कत होती है। उन गरीब लोगों का जो बकाया सरकार ने बैंकों को देना है, वह दे दिया जाए, ताकि वे गरीब लोग अपने छोटे-मोटे कार्य के लिए कोई कर्ज लेना चाहें तो वह ले सकें। सर, बी.पी.एल. में क्या होता है कि नंबर लगे हुए हैं जैसे उदाहरण के तौर पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। ठीक है कि उससे हर किसी का नंबर सीरियलवाइज पड़ेगा लेकिन यदि किसी गरीब आदमी का मकान गिर जाता है और उसका नंबर सीरियल में 6 नंबर पर लग गया और नंबर चल रहा है 3 या 4 तो ऐसे में उसकी मदद मिलनी चाहिए क्योंकि उस आदमी के मकान की स्थिति अगर अच्छी नहीं हैं तो अधिकारियों को ऐसे आदेश दिए जाने

....

[श्री राजपाल भूखड़ी]
चाहिए कि उस आदमी की मदद के लिए कोई रास्ता निकालें। इसके लिए उस आदमी को चक्कर काटने पड़ते हैं। सर, इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि :-

एक पल भी जिए जो किसी के लिए,
है सफल जिन्दगी आदमी के लिए,
जो तरसते रहे रोशनी के लिए,
हम जलाएं दिए उन्हीं के लिए।

सर, मैं एक छोटी सी बात और कहना चहूंगा कि सन्तुलित व्यक्ति दूसरे के विचारों को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें सदन में संतुलन रखना चाहिए। सन्तुलित व्यक्ति दूसरे के गुणों और विचारों को स्वीकर करते हैं परन्तु वे अपने महत्व को भी कम नहीं करते। इसलिए आदमी को अपना महत्व कम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री कृष्णलाल पंवार (इसराना) : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा, वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 का जो बजट सदन में पेश किया है, उस बजट को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि इस बजट में हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए, हरिजन के लिए, कारीगरों के लिए, कर्मचारियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए कहीं कोई ऐसी चीज नहीं दर्शायी गयी है जिससे प्रदेश के लोग इस बजट में खुश हों। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश वर्ष 1966 में बना था। वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2005 तक हरियाणा सरकार पर 23000 करोड़ रुपये का कर्ज था। लेकिन वर्ष 2005 में मौजूदा सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर आज 67732 करोड़ रुपये हो गया है। इसके बाद सरकार की मन्शा यह है कि दस हजार करोड़ रुपये का कर्ज और लेने जा रही है। डिप्टी स्पीकर सर, इस बजट का जो आकार है, वर्ष 2013-14 के बजट के जो आंकड़े हैं उसमें दर्शाया गया है कि कुल रकम का लगभग 66000 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होंगी, इसके आगे यह बताया गया है कि उपरोक्त में से लगभग 44000 करोड़ रुपये विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होंगे और लगभग 22000 करोड़ रुपये विभिन्न कर्जों से प्राप्त होंगे। बजट के आंकड़े देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले कर्ज और उसके ब्याज के भुगतान करने के लिए भी सरकार और कर्ज लेगी। डिप्टी स्पीकर सर, इस बजट के माध्यम से सरकार ने बड़े बलंग दावे करने का प्रयास किया है कि हम प्रदेश में किसानों और उद्योगपतियों को डोमैस्टिक में और सी.एस. में पूर्ण रूप से बिजली देंगे। जबकि आंकड़े यह बताते हैं कि वर्ष 2012-13 में जो बजट पेश किया गया था उसमें 9.60 प्रतिशत बिजली के लिए बजट दिया गया था जबकि वर्ष 2013-14 के बजट में केवल 7.91 प्रतिशत बजट बिजली के लिए दिया गया है जो कि पिछले वर्ष से 1.69 प्रतिशत बजट बिजली के लिए कम दिया गया है। सरकार कहती है कि बिजली का बहुत बड़ा उत्पादन करेंगे। बजट और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी दिखाया गया है कि वर्ष 1999 से वर्ष 2005 तक के समय में प्रदेश में

केवल 724.4 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया गया। जबकि जब चौधरी देवीलाल जी वर्ष 1987 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे पानीपत की पांचवीं यूनिट 210 मैगावाट की, छठी यूनिट 210 मैगावाट की 1989 में इन दोनों यूनिट्स का पाईलिंग वर्क शत-प्रतिशत हो चुका था। इनको बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का सामान पानीपत रेलवे स्टेशन पर आ चुका था। उसके बाद वर्ष 1991 में पांच साल तक प्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार रही, उसके बाद वर्ष 1996 से लेकर साढ़े तीन साल तक चौधरी बंसीलाल की सरकार रही यानी साढ़े आठ साल तक उस सामान को पानीपत रेलवे स्टेशन से किसी ने उठाया ही नहीं। उसके बाद 24 जुलाई, 1999 को चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो पानीपत का पांचवां यूनिट 28.3.2000 को चालू हो जाता है और इसी प्रकार से पानीपत थर्मल प्लांट का छठा यूनिट 31.3.2001 को चालू हो जाता है, पानीपत थर्मल प्लांट का सातवां यूनिट 250 मैगावाट का 28.9.2004 को चालू हो जाता है और पानीपत थर्मल प्लांट का आठवां यूनिट 250 मैगावाट का 28.1.2005 को चालू हो जाता है। डिप्टी स्पीकर सर, इसी प्रकार से आपके यमुनानगर में जो हाईड्रोलिक बिजली का प्रोजैक्ट है जो 7.2 मैगावाट का है, उसकी सातवीं यूनिट 16.4.2004 को चालू हुई है और 8वां यूनिट 7.2 मेगावाट का 12.5.2005 को चालू हुआ जिससे 934.4 मेगावाट बिजली बनती है और सरकार कहती है कि 724.4 मेगावाट बिजली बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, झाड़ली जहां 500-500 मेगावाट के 3 यूनिट हैं। सरकार इसके बारे में दावा करती है कि इस प्लांट से पूरे प्रदेश को 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है जबकि असलियत यह है और मैंने कल भी प्वायंट ऑफ आर्डर पर मुख्यमंत्री महोदय से कहा था कि इस प्लांट में 50 परसैंट हिस्सा एन.टी.पी.सी. का है, 25 परसैंट पैसा हिस्सा इसमें दिल्ली गवर्नमैंट का है और हरियाणा का सिर्फ 25 परसैंट हिस्सा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। मैं अपने साथी की बात को करैक्ट करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट में 25 परसैंट हिस्सा देकर उसमें से हमें आधी बिजली मिलेगी। इसमें भी इनको ऐतराज है। If I pay fifty rupees and get electricity of 100 rupees, इसमें तो इनको दिल्ली की यू.पी.ए. सरकार की तारीफ और धन्यवाद करना चाहिए। इस प्लांट की आधी बिजली यानि 750 मैगावाट दिल्ली को मिलेगी और आधी हमारी होगी। हमारे काबिल पावर मिनिस्टर कैप्टन साहब जो पहले हाउस में नहीं बैठे थे लेकिन अब आ गए हैं वे पूरी बात बता देंगे। यमुनानगर के अंदर 600 मेगावाट का पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़, हिसार में 1200 मेगावाट, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, झाड़ली-2-1320 मेगावाट का और इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली-1-1500 मेगावाट का ये 4 नए बिजली उत्पादन के प्लांट्स हमने लगाए हैं। इसके अलावा जी.एम.आर. कम्पनी से और अडानी पावर से केस इवीडिंग के माध्यम से जो बिजली खरीदी गई है वह लगभग 1700 मेगावाट से अधिक है। यह हरियाणा बनने के बाद अपने आप में पहली बार एक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

रिकार्ड है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इनकी तरह थर्मल पावर प्लांट पर केवल हरा रंग करके उसको ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, 1424 मेगावाट बिजली अडानी पावर से लौंग टर्म परचेज हमने कर रखी है और वह बिजली हमें मिल रही है और जहां तक इन्होंने कहा कि हमारे प्लांट्स बन्द हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्लांट्स बन्द नहीं हैं। इस समय डिमांड कम है इसलिए हम उनकी सर्विस करा रहे हैं। इस समय खेदड़ के 600-600 मेगावाट के दोनों यूनिट सर्विस के लिए बन्द हैं और उनकी मैंटीनैंस चल रही है ताकि गर्मी के मौसम में ये ठीक तरह से काम कर सकें। यमुनानगर के 300-300 मेगावाट के दोनों यूनिट वर्किंग कंडीशन में है। जैसा मैंने बताया था कि हमने पूरा चैनल भेजा और हमने इनको ठीक करवाया है और आज के दिन सभी पावर प्लांट्स वर्किंग कंडीशन में हैं। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट में 600-600 मेगावाट के दो यूनिट लगे हैं। उनमें से एक इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि कोयले की कमी है और यह सी.एल.पी. यूनिट है तथा दूसरी यूनिट चालू स्थिति में है। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट में 500-500 मेगावाट के तीन यूनिट हैं और तीनों वर्किंग कंडीशन में हैं। आज के दिन प्रदेश में बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। आज तकरीबन जहां 9600 मेगावाट बिजली की गर्मियों के दिनों डिमांड रहती है वहां आज के दिन हमारे पास 3800 मेगावाट बिजली एवेलेबल है। किसी भी गांव के फीडर पर यदि 25 परसैंट लाइन लोसिज हैं तो वहां हम 4 घण्टे बिजली फालतू देने का निर्णय ले चुके हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मै आगे की बात बाद में बताऊंगा लेकिन पहले मैं मंत्री जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये गलत कह रहे हैं। कल मैंने इस बारे में बताया था और आज की डेट की पावर समरी मेरे पास है। आज के दिन पानीपत थर्मल पावर प्लांट के 110-110 मेगावाट के 4 यूनिट बंद हैं। झज्जर के इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट के 500-500 मेगवाट के दो यूनिट बंद हैं। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट में भी 500 मेगावाट का एक यूनिट बंद है। यमुनानगर के हाईडल पावर प्लांट के 300-300 मेगावाट के दोनों यूनिट आज बंद हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा हमारे पावर प्लांट्स खराब नहीं हैं। (विघ्न) ये कह रहे हैं कि हमने शट डाउन कर रखे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे चार यूनिट शट डाउन हैं लेकिन इनमें कोई खराबी नहीं है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत बात न करें क्योंकि मैं बता रहा हूं कि चार यूनिट शट डाउन जरूर हैं लेकिन उनकी मैंटीनैंस चल रही है। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट के 500-500 मेगावाट के तीनों यूनिट वर्किंग कंडीशन में हैं और प्रदेश में आज के दिन कोई पलांट खराब नहीं है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खेदड़ के 600-600 मेगावाट के दो यूनिट तीन महीने के लिए बंद किए गए हैं। मंत्री जी बात को छिपा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि मैंने कुछ छिपाया नहीं है। मैंने कहा है कि मैंटीनैंस का काम चल रहा है इसलिए यूनिट बंद किए गए हैं और यूनिट वर्किंग कंडीशन में हैं। समय-समय पर मैंटीनैंस की रिक्वायरमैंट हर मशीनरी को होती है। इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है इसलिए हम यूनिट्स की मैंटीनैंस करवा रहे हैं, किसी तरह की खराबी नहीं है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं जो प्रदेश के हित में हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि केवल अधिकारियों के लिख देने से बात नहीं बनेगी। मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि सैशन खत्म होने के बाद तुरंत मंत्री जी खेदड़ प्लांट में जायें और देखें कि वहां की फाउंडेशन 10 से 12 मिलीमीटर धंस चुकी है। मंत्री जी, आप वहां तुरंत दौरा कीजिए, हो सकता है अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हों। यह प्रदेश के हित की बात है इसको आप जल्दी से जल्दी चैक करवायें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा झाड़ली के जो इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दो सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें देसी कोल के अलावा इण्डोनेशिया से इम्पोर्टिड कोल मंगवाकर यूज किया जाता है। इस रिगार्डिंग मंत्री जी की दिल्ली में मीटिंग हुई थी जिसमें स्वयं मंत्री जी ने माना था। मेरे पास उस मीटिंग की मिनट्स की फोटो कापी है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहें तो मैं दिखा देता हूं। इसमें देसी कोल के साथ इण्डोनेशिया से इम्पोर्टिड कोल मंगवाकर यूज किया जा रहा है और इन दोनों यूनिट्स के लिए 25 साल का एम.ओ.यू. इण्डोनेशिया के साथ साईन किया गया है। वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि किस रेट पर बिजली लेने की बात की गई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इम्पोर्टिड कोल का संबंध है इस बारे में रैगुलेटरी कमीशन की डायरैक्शंज आई थी ताकि पी.एफ.एल. लोड अच्छा हो सके। इसमें देसी कोल के साथ 15 से 20 प्रतिशत इम्पोर्टिड कोल यूज किया जाता है। 20 प्रतिशत कोल केवल पानीपत की चौथी यूनिट में यूज होता है ज्यादातर जगह 15 प्रतिशत ही इम्पोर्टिड कोल यूज किया जाता है। यह भी इसलिए ताकि पी.एफ.एल. लोड बढ़ सके। जो डोमैस्टिक कोल है वह अच्छा नहीं है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि जो इण्डोनेशिया से कोल मंगवाया जा रहा है उसकी क्लोरीफाई वैल्यू 5800 की जगह 4800 आ रही है और जो हमारे डोमैस्टिक कोल हैं उसकी क्लोरीफाई वैल्यू 4800 की जगह 3600 आ रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर सर, इनके समय में भी डोंग फैंग कम्पनी थी वह भी चाईनीज थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये यहां पर गलत बात न करें। यह बात सही है कि रिलायंस कम्पनी को यह काम दिया गया था।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, हम तीन साल से सुन रहे हैं कि श्री कृष्ण लाल पंवार जी चाईनीज मशीनरी का ही जिक्र कर रहे हैं। अगर कोई खराब मशीनरी आ गई है तो वह चेंज हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर सर, वहां पर कोई मशीन खराब नहीं है। जो संघाई कारपोरेशन लिमिटिड कम्पनी है वह भी टॉप क्लास कम्पनी है। उसका बहुत अच्छा टर्न ओवर है। यह डौंग फैंग कम्पनी हाई कोर्ट में गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गई। जहां पर जाकर ये हार गये। उसके बाद हमने यह काम संघाई कंपनी को दिया क्योंकि रिलायंस का जो लिंक था वह संघाई कंपनी के साथ था। डौंग फैंग से उनकी आपस में बात नहीं बनी और इसकी वजह से वह संघाई कम्पनी के साथ हो गया। जो पहले दो बार एग्रीमैंट हुआ था वह दोनों बार ही चाईनीज कम्पनी के साथ हुआ था। चौटाला जी के समय में भी चाईनीज कम्पनी के साथ एग्रीमैंट हुआ था और हमारे समय में भी संघाई कम्पनी के साथ हुआ है जो कि चाईनीज है। ये बिना मतलब के ही बार-बार चाईनीज की बात करते हैं। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि यह प्लांट बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसकी सारी की सारी मशीनरी बिल्कुल बढ़िया है। ये यह कहकर हाऊस को गुमराह करते हैं कि चाईनीज के कल पुर्जे खराब हैं। यह इनकी बात बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्ण लाल जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं इसलिए आप जल्दी वाईंड-अप कीजिए।

श्री कृष्ण लाल पंवार : डिप्टी स्पीकर सर, उसके बाद टरबाईन में वाईब्रेशन हुई और रूटर खराब हुआ। 25 सितम्बर, 2011 को यह प्लांट बंद हुआ। चाईना से रूटर मंगवाना था लेकिन सरकार एक साल तक चाईना से रूटर नहीं मंगवा सकी। फिर इन्होंने यहां पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च करके उसको चालू करवाया। इस बारे में वास्तविक स्थिति से माननीय मंत्री जी अवगत करवा देंगे लेकिन अब ये दोनों बंद पड़े हैं। डिप्टी स्पीकर सर, इससे 12 करोड़ रुपये का प्रतिदिन का जैनरेशन लॉस हुआ है। इसमें एक साल से भी ज्यादा समय इस काम में लगा है। इसी प्रकार से मैं खेदड़ थर्मल पावर प्लांट की बात करना चाहूंगा। वहां पर जो कोल क्रैश होता है वहां पर दो गियर बक्से खराब हो गये और उनकी परचेज के लिए एक देसी कम्पनी से एच.पी.जी.सी.एल. ने बात कर ली। इस पर दूसरी कंपनियों ने कहा कि ये आपको घटिया उपकरण दे रहे हैं इसलिए इनसे ये उपकरण न लिये जायें। इस पर तीसरी कम्पनी ने कहा कि हम इन दोनों कम्पनियों से 15 परसैंट रेट कम करके मैं ये उपकरण दूंगा लेकिन जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो वह भी चाईनीज कम्पनी थी। इसके लिए श्री एम.एल. सहगल जो कि हिसार के निवासी थे उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में पी.आई.एल. डाली कि खेदड़ पावर प्लांट के अंदर जो गियर बक्सों की खरीद की गई है उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है इसलिए इसकी पेमैंट रुकवाई जाये। इस प्रकार 23 अगस्त, 2012 को माननीय हाई कोर्ट ने डायरैक्शन दी कि इन कम्पनियों की पेमैंट को रोक दिया जाये। ये हालत हैं। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां पर लाखों रुपये का तेल का घोटाला हुआ जिसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई लेकिन इस मामले में आज तक किसी की भी रिस्पांसीबिलिटी फिक्स नहीं करवाई गई। डिप्टी स्पीकर सर, पानीपत में थर्मल प्लांट है वहां पर ऐस डैक है जहां पर हमारा राख और पानी मिक्स होकर

जाता है उसकी अभी 16 करोड़ रुपये की लागत से 6 मीटर की ऊंचाई बढ़ाई है। अगर पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ऊंचा ऐस डैक कहीं है तो वह पानीपत थर्मल प्लांट में है। यह भी ओवरफ्लो हो चुका है लेकिन सरकार के पास आगे के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार को चाहिए था कि अलग से ऐस डैक बनाया जाता लेकिन बार-बार कमीशन खाने के लिए बार-बार उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। उसकी वजह से सुताना गांव है जिसकी ऐस डैक में 700 एकड़ जमीन गई है। वहां पर सेम आ गई जिसकी वजह से वहां के किसान अपनी 300-400 एकड़ जमीन हर वर्ष बीजने से वंचित रह जाते हैं। माननीय मंत्री जी हमारी ग्रिवैंसिज कमेटी के चेयरमैन हैं। मैंने जब इनके सामने वहां पर इसका जिक्र किया तो उस समय इन्होंने अधिकारियों से बात की और इन्होंने कहा कि हम वहां पर सेम की समस्या को समाप्त करने के लिए डीप ट्यूबवैल लगायेंगे लेकिन आज तक वे डीप ट्यूबवैल नहीं लगाये गये हैं। डिप्टी स्पीकर सर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस गांव के लोगों ने इसके लिए अपनी पूरी जमीन दे रखी है मैंने मंत्री जी से ग्रिवैंसिज कमेटी की बैठक में भी अनुरोध किया था उस गांव को जाने वाली सड़क का केवल एक से सवा किलोमीटर का टुकड़ा है जिसके ऊपर थर्मल पावर प्लांट ने कोयले में आने वाले स्टोन को भी डाल दिया है। मैंने उनके ऊपर ब्लॉक्स लगाने के लिए कहा था और मंत्री जी इस बारे में आदेश भी देकर आये थे लेकिन आज तक वह कार्य भी नहीं हुआ। सर, जिस प्रकार से यह सरकार कहती है कि हम बिजली के रेट नहीं बढ़ाते। इस सरकार ने एक अप्रैल, 2012 को 1795 करोड़ रुपये के बिजली के बिल बढ़ाये हैं। इसी प्रकार से 1 जुलाई, 2012 से फ्यूअल सरचार्ज के नाम पर 1086 करोड़ रुपये का बोझ जनता पर डाल दिया गया तथा अब फिर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा रैगूलेटरी कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि हमें 5700 करोड़ रुपये और बढ़ाने की अनुमति दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बोलना चाहता हूं। शिक्षा का स्तर हरियाणा में बहुत नीचे जा चुका है। पिछली बार मैंने विधान सभा में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था कि प्राइमरी से मिडल क्लास तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं तथा उसमें एस.सी./बी.सी. के कितने बच्चे हैं? उस प्रश्न के जवाब में बताया गया कि इन स्कूलों में पढ़ने वालों की संख्या 25 लाख है और 25 लाख में से 17 लाख बच्चे एस.सी./बी.सी. के थे। जिस प्रकार कल दांगी साहब कह रहे थे कि इन सरकारी स्कूलों में तो सिर्फ बी.पी.एल. परिवार वालों के ही बच्चे पढ़ते हैं, हालांकि गरीब आदमी भी चाहता है कि उसके बच्चे भी कॉन्वैंट स्कूलों में पढ़ें लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं और वे सोचते हैं कि कॉपी-किताबें और कपड़े मिल जायेंगे तथा सरकार की तरफ से जो इन्सैन्टिव दिया जाता है वह मिल जायेगा। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने एक स्कीम बनाई थी जिसके तहत प्रदेश में पहली क्लास से ही अंग्रेजी अनिवार्य की गई थी लेकिन आज सरकार ने उसको हैल्डअप कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतनी ओलावृष्टि हुई कि 20 घण्टे बाद तक ओले मैल्ट नहीं हुये। जिन

[श्री कृष्ण लाल पंवार]
गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें कैत, शाहपुर, बिजावा, इसराना, मांडी कुराना, बवाना लाखु और आसन खुर्द आदि हैं जहां पर किसानों की लगभग 600 एकड़ गेहूँ की फसल बर्बाद हो गई है। इसी प्रकार से मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी बताना चाहता हूं। आज सरकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश में वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके वेतनमान केन्द्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाये जायें तथा पुलिस मुलाजिमों के वेतनमान पंजाब की तर्ज पर बढ़ाये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम मामला है। प्रदेश सरकार कहती है कि हम अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लासिज के हितैषी हैं। ****

ऊर्जा मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रकार से जाति संबंधी शब्द कह रहे हैं यह हाउस की कार्यवाही से निकाले जायें। हरियाणा सरकार 36 बिरादरी की सरकार है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर 2010 तक सिंचाई विभाग में मकैनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर की ज्वाइंट सिनियोरिटी होती थी लेकिन 2010 में विधान सभा में रैजोल्यूशन ला कर मकैनिकल और सिविल के काडर अलग-अलग कर दिये।

वित्त मंत्री (हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : उपाध्यक्ष महोदय, नहर महकमें में मकैनिकल का, इलैक्ट्रिकल का बहुत कम काम है। 90% सिविल इंजीनियरिंग के काम कर दिए। Then the Engineers went to High Court. केस हाई कोर्ट में पैंडिंग है उस पर जो फैसला होगा बाद में देखा जाएगा। केस सबज्यूडिस है।

श्री उपाध्यक्ष : पंवार साहब, जल्दी खत्म करिये, आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गए हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, मैं केवल दो मिनट में हल्के की बात करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पंवार साहब, आप अपनी बात को दो मिनट में खत्म करिये।

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, एक एच.के. गुप्ता सुपरिटैंडैंट इंजीनियर हैं जिनको एक साल की एक्सटैंशन दी गई जबकि 58 साल में आदमी सर्विस से रिटायर्ड हो जाता है लेकिन इनकी आयु 59 वर्ष हो गई उस दौरान उनको प्रमोट किया गया। क्या एक्सटैंशन पीरियड में उनकी प्रमोशन कर सकते हैं? सर, इसके अलावा मैं अपने हल्के की दो चार बातें भी कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप जल्दी करिये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट की तरफ से नौलथा गांव में सी.एच.सी. बनाने के लिए ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन आज तक एक डेढ़ साल हो गया वहां पर सी.एच.सी. नहीं बनी। दूसरा मेरा मुख्यमंत्री जी से प्रश्न था कि इसराना के लिए सी.एच.सी. बनवा दें तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सर्वे कराएंगे यदि वहां पर जरूरत होगी तो वहां सी.एच.सी. बनवा देंगे। सर, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने वहां पर सी.एच.सी. की आधारशिला रखी थी, पैसा भी दिया गया था लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद उस पैसे को विदड्रा कर लिया गया। इसी प्रकार से सन् 2010 में हाऊस में एश्योरैंश आया था कि सींख गांव में 132 के.वी. का पॉवर हाऊस एक साल के अंदर बना दिया जाएगा जो अब तक नहीं बना। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो किसान सैल्फ फाईनैंश स्कीम के तहत अपना ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वह चोरी हो जाता है तथा वह यदि सरकार की तरफ से लगाया जाता है तो 20% चार्ज किसान से लिया जाता है जो गलत है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की सड़कों के बारे में मैंने सवाल भी दिया था लेकिन उसका नम्बर नहीं आ पाया था। मतलौढ़ा से कलरा, लुहारी से कालखा, मादड़ से ब्राह्मण माजरा जो श्री ओमप्रकाश जैन के विधान सभा क्षेत्र में आता है और मादड़ मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। यहां पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं इसके सर्वे के लिए अगर आप कमेटी बना दें तो आप देखेंगे कि उन पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है और जब झोटा-बुग्गी और पशु उस पर से जाते हैं तो उनके खुरों में पत्थर लगते हैं। वहां की सड़कें इतनी बुरी तरह से टूटी पड़ी हैं। इसके अलावा मेरे हल्के में मार्केटिंग बोर्ड की सन् 1999 में एक सड़क बनी थी लेकिन आज तक उसकी रिपेयर नहीं हुई। कवी गांव से लेकर मोर माजरा, शैरा से बाल जाटान गांव तक जाने वाली सड़क का तो नामोनिशान ही नहीं है। सन् 1999 के बाद इन सड़कों से आना जाना बिल्कुल बंद है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इनको जल्दी बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी मेरे विधान सभा क्षेत्र के सौदापुर गांव में गए थे तो उस गांव में टोटली एस.सीज/बी.सीज कटैगरी के लोग रहते हैं, मजदूर लोग हैं, वहां पर दीपेन्द्र हुड्डा जी मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करने की घोषणा करके आए थे कि एक हफ्ते के अन्दर इसके ऑर्डर आ जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी को बताना चाहूंगा कि वह स्कूल अब तक अपग्रेड नहीं हुआ। सर, 26 जनवरी को अच्छे स्कूल के लिए सौंदापुर गांव के सरपंच को भी सम्मानित किया है। सर, एक सिवाना गांव के मिडल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के लिए मैं माननीया मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वह इस स्कूल को अपग्रेड करें। सर, मेरे पास कहने के लिए बातें तो बहुत हैं अगर समय दो तो मैं बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने हल्के की सारी डिमांड लिख कर दे देना। अब श्री तेवतिया जी बोलेंगे।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया (पृथला) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विधान सभा में आज सन् 2013-14 का बजट एक बार फिर आम आदमी के लिए पुण्य शब्द हो गया है। कांग्रेस

[श्री रघुबीर सिंह तेवतिया]

पार्टी वास्तव में एक आम आदमी की पार्टी है। इसकी नीतियां हमेशा ही जनहितैषी रही हैं। एक कर्मक बजट ने प्रदेश के लोगों को राहत की सांस दी है। इस जनहितैषी बजट की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। चाहे बी.पी.एल. गरीब वर्गों के आवास का निर्णय लिया है चाहे वह कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए पहले से ज्यादा बजट दिया है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के लिए बजट दिया है, चाहे उच्चतर शिक्षा के लिए बजट दिया है, चाहे वह तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास एवं ग्रामीण विकास हो सभी मदों में पहले से ज्यादा बजट बढ़ाया गया है। आज किसी भी क्षेत्र में चाहे सड़कों और पुलों की बात हो, चाहे बिजली क्षेत्र की बात हो, बी.पी.एल. परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख आवास बनाने की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्र में डेढ़ लाख आवास बनाने की योजना हो, चाहे वह खेलों की बात है इन सभी पर जो इस बार के बजट में ध्यान रखा गया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में बगैर भेदभाव के और बगैर बदले की भावना से काम शुरू किया है। जो यह विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि क्षेत्रवाद के हिसाब से काम होता है केवल मिथ्या बातें हैं। मेरे अपने क्षेत्र में अब तक जो काम हुए हैं पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं तथा उसके बाद में जो मेरी कुछ अतिरिक्त मांगें हैं उनको भी सदन में रखना चाहूंगा। 19 मार्च, 2011 को पृथला क्षेत्र के गांव धनौली में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जब रैली में भाग लेने आये तो हमने उनके सामने अपने क्षेत्र की अनेक समस्याएं रखीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हृदय की विशालता का परिचय देते उन सभी मांगों को मान लिया है और ये मांगें अब पूरी भी होती जा रही हैं। हमारे विपक्ष के अनेक साथी रोजाना क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हैं जो सरासर गलत है। (शोर एवं व्यवधान) पिछले 50 सालों से पृथला क्षेत्र के लोगों की और इसके साथ लगते 50 गांवों की आर.ओ.बी. बनाने की एक पुरानी मांग थी क्योंकि इसके बनने से ये सभी गांव आपस में जुड़ जाते हैं। आज अलावलपुर फाटक पर लगभग 45 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा है और उस पर लगभग 24 घंटे काम चल रहा है। यह हमारी एक पुरानी मांग थी जिसको मुख्यमंत्री जी ने माना है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। वर्ष 1999 में जब आदरणीय चौटाला साहब की सरकार आई तो उन्होंने मोहना में उपतहसील की घोषणा की थी लेकिन वह घोषणा झूठी साबित हुई क्योंकि उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया था। (शोर एवं व्यवधान) वर्ष 2011 में जब यह मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी तो मोहाना को उपतहसील का दर्जा दिया गया। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) आज उसका उद्घाटन हुआ है। हमारा पलवल ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता था। इसके अन्दर 124 गांव आते थे। आज पृथला क्षेत्र में पलवल जिले के 38 गांव हैं। इसमें हथीन क्षेत्र के दो गांव और भी जोड़े गये हैं उन्हें अलग ब्लॉक का दर्जा दिया गया है, इसका भी उद्घाटन कर दिया गया है। अब वहां पर अधिकारी बैठते हैं तथा काम भी चालू है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) इसी तरह मेरे क्षेत्र के पांच गांवों मच्छगर, चंदावली, सौतई, मुजैदी और नवादा को आई.एम.टी. दी गई है। यहां के लोग धरने पर बैठे थे उनको 16 लाख रुपये मुआवजा दिया गया था लेकिन वे ज्यादा मुआवजे की डिमांड

कर रहे थे। मैंने मध्यस्थता करके उन किसानों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाया। अवॉर्ड सुनाने के बाद दोबारा पैसा नहीं दिया जा सकता यानी कि अवॉर्ड को दोबारा नहीं सुनाया जा सकता लेकिन यह हरियाणा की पहली मिशाल बनी जब मुख्यमंत्री जी ने एक ही कलम से उन पांचों गांवों के किसानों के लिए तीन अरब 85 करोड़ का फायदा पहुंचाया। जो 16 लाख की मांग थी उसके बदले उनको 46 लाख तथा 20 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया और वह किसान आज पूरी तरह से संतुष्ट भी है। इसी तरह जब सड़कों की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक सड़क पर 17-17 करोड़ की लागत आई है। बल्लभगढ़ से मोहाना, बल्लभगढ़ से चंदावली, मच्छगर, दयालपुर अट्टाली वाया झायसा होते हुए मोहना तक एक बहुत बड़ी सड़क है जिसको लगभग 17 करोड़ की लागत से चौड़ा करके दोबारा बनाया गया है। यह पौने 20 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसी तरह से हमारा पृथला से वाया दुधौला होते हुए जो सड़क पलवल को भी जोड़ती है उसे मेरी मांग पर घतीर तक जो कि पलवल क्षेत्र का गांव है, तक बढ़ाया गया है। (विघ्न) हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि पलवल में काम नहीं हो रहे हैं। घतीर तक 6 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से यह सड़क बनाई गई है। (शोर एवं व्यवधान) यह सड़क मेरी रिकमंडेशन पर बनाई गई है। इसी तरह से पृथला से छपरोला सहराला तक होते हुए 5 करोड़ रुपये की लागत से एक और सड़क बनाई गई है। इन बड़ी-बड़ी सड़कों को बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से और भी कई सड़कें हैं जैसे बघोला, देवली, जलोला से लेकर नये गांव तक 7 करोड़ रुपये की लागत से सड़क बनाई गई है। इसी तरह से पृथला असावती ततारपुर तक सड़क 5 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से बनाई गई है। एक बहुत बड़ी सड़क अभी मंजूर की गई है वह है बल्लभगढ़ से साहूपुरा डीघ, फतेहपुर बिल्लौच होते हुए सदरपुर तक 9 करोड़ 59 लाख 38 हजार रुपये की लागत से मंजूर की है और कितनी ही ऐसी सड़कें हैं जैसे बल्लभगढ़ से मुन्जेड़ी तक सड़क बनाई गई है। इसी तरह से मार्किटिंग बोर्ड की सड़के जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं, मंजूर की हैं जिनमें से कई सड़कें बन चुकी हैं और कई सड़कों पर काम चालू है, चाहे वह करनेरा से मनकरपुर हो, खलावती से मनकपुर हो, गरखेड़ा से पुनेराखुर्द की हो, चाहे कक्ड़ीपुर से मनकोला हो, जवा से घाघोट हो, पनेराखुर्द से महमदपुर और महमदपुर से नरियाला हो, चाहे मोहना से गोपीखेड़ा हो, चाहे सुनहरी से नगला और नगला से पंचायती झुग्गी खादर के पास छांयसा हो, जड़ोली से नगला लक्की हो, ऐसी काफी सड़कें मेरे हल्के की बनाई गई हैं। इसके साथ-साथ मेरी मांग भी है कि अभी भी कई सड़कें खराब हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से मांग करता हूं कि जी.टी. रोड से जादरू, जी.टी. रोड से उरावली, जी.टी. रोड से शाहपुर खुर्द, जी.टी. रोड से ब्याला, जी.टी. रोड से मोहला, जी.टी. रोड से हरफली छपरोला तक, अलावलपुर से बदराम, अलावलपुर से सदरपुर ऐसी कई सड़कें बनाई हैं। इसके अलावा और भी कई सड़कें बनाई हैं इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा एक प्रश्न भी लगा था उसमें यह था कि आई.टी.आई. की फतेहपुर बिल्लौच में 52% बिल्डिंग बन चुकी है। बीच में ठेकेदार गांव छोड़कर चला गया था, उसके टैंडर अब छोड़ दिए हैं और अगले 27.1.2014 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : तेवतिया जी, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : सर, इसी सैशन में इसकी क्लासें चलाने की मेरी मांग है। इसी तरह से जनौली में एक कैंट मंजूर हुई है जब तक उसमें बिल्डिंग बने तब तक इसकी नये सैशन से क्लासें वहां लगा दी जाएं, यह भी मैं मांग करता हूं। खेलों के क्षेत्र में मैंने अपने हल्के में तीन स्टेडियम्स की मांग की थी मैं उसमें नवादा और सीकरी के स्टेडियम का काम चल रहा है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, परन्तु यह भी मांग करता हूं कि जनौली में इसका काम जल्दी शुरू किया जाए। इस प्रकार मेरे हल्के की जो-जो मांगें थी वह धीरे-धीरे पूरी हो रही हैं। विपक्ष जो बदले की भावना और भेदभाव के आरोप लगाता है, वे आधारहीन हैं। विपक्ष के साथी कहते हैं कि सिर्फ रोहतक के काम होते हैं। तो मेरा हल्का उनके सामने है, उसमें इतने काम हुए हैं जितने 1999 से 2005 तक पूरे फरीदाबाद क्षेत्र में काम हुए थे, उतने काम पिछले साढ़े तीन साल और अब डेढ़ साल की अवधि को मिलाकर अकेले मेरे हल्के में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे कर दिये हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : धन्यवाद डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में जो बजट पेश किया है उसके लिए पूरे प्रदेश के लोग एक साल से इन्तजार में रहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का बजट आयेगा और उसमें हमें कोई राहत देने का काम वित्त मंत्री जी करेंगे। डिप्टी स्पीकर सर, बजट पढ़कर यह लगा कि न तो प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, न प्रदेश के व्यापारियों के लिए, न ही प्रदेश के किसानों के लिए और न ही किसी वर्ग के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। डिप्टी स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके अन्दर लगभग 76 प्रतिशत पैसा या तो रिपेमैंट ऑफ लोन में जायेगा, या जो कर्ज ले रखा है उसका इन्ट्रस्ट देने में जायेगा और या फिर पैंशन और सेलरी में जायेगा। बजट के अन्दर जो प्रावधान किया गया है उसका 24 प्रतिशत हिस्सा केवल विकास कार्यों के लिए रखा गया है। अब इस बात से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार हरियाणा नम्बर वन बनाने की बात करती है। 16000 करोड़ रुपए हर हैड में रखा है। 22000 करोड़ रुपए आगे कर्ज लेने के लिए प्रावधान किया है। अगर कर्जे की किस्त नहीं आयेगी तो एक महीने की तनख्वाह नहीं दे पायेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश को कर्ज में डुबाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार की एक बात कहना चाहता हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता हूं। अरोड़ा साहब ने ये सारी बातें गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए रखी हैं आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें। माननीय वित्त मंत्री जी ने आलरेडी बजट भाषण में बताया है कि प्रदेश का कर्ज प्रदेश की जी.एस.डी.पी. के 16 प्रतिशत से कम है और यह प्लानिंग कमीशन की नार्म्स के मुताबिक यह 23 प्रतिशत तक हो सकता है। माननीय अरोड़ा साहब, स्पीकर भी रहे हैं और एक सीनियर पार्लियामैंटेरियन भी हैं। He knows all the norms fixed by the Planning Commission.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि जो बजट के अन्दर कहा गया है कि पैसा कहां जायेगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ज्यादा पैसा जो बजट का है वह कर्जे का ब्याज देने में जायेगा। यही कारण है कि वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए यह तो बता दिया कि प्रत्येक महकमे के लिए इतना पैसा रखा गया है। परन्तु डिप्टी स्पीकर सर, जो अहम महकमे हैं उन सब के अन्दर प्रसैंटेज के हिसाब से बजट बहुत घटा है। इसका कारण यह है कि हम जो कर्ज लेते जा रहे हैं। आगे भी यही होगा कि हम इतना कर्ज बढ़ा लेंगे तो इतना पैसा कहां से आयेगा और कहां पर जायेगा। आप देखिए सिंचाई के लिए पहले 6.31 प्रतिशत बजट था जो अब 6.19 प्रतिशत रह गया है यानी घटा है, इसी तरह से बिजली के लिए 9.60 प्रतिशत था जो अब 7.91 प्रतिशत रह गया है, इसी प्रकार से शिक्षा के लिए हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने की बात सरकार करती है परन्तु शिक्षा के अन्दर भी 15.39 प्रतिशत बजट था जो अब 14.77 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार से सड़क और भवन एवं निर्माण के लिए जो 4.71 प्रतिशत था वह अब 4.28 प्रतिशत रह गया है। जन स्वास्थ्य विभाग जो पीने के पानी की व्यवस्था करता है उसके लिए 4.6 प्रतिशत था जो कि अब 3.49 प्रतिशत रह गया है यानि 0.57 कम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लॉ एण्ड आर्डर की बात करूंगा तो ये कहेंगे कि आप इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति आज प्रदेश में बहुत खराब है। हमें पुलिस बल को मजबूत करने के लिए इस पर पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए परन्तु इस पर भी बजट कम किया गया है जिसका कारण एक ही है कि हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी हाउस चलता है सबसे पहले कैग की रिपोर्ट आती है परंतु बजट आ गया और उस पर चर्चा चल रही है और आज के बाद एक दिन का और बजट बकाया है परंतु कैग की रिपोर्ट अभी तक हाउस में नहीं रखी गई। इसका क्या कारण है इस बारे में वित्त मंत्री महोदय अपने जवाब में बताएं। इसका कारण एक ही है कि इन्होंने सभी कायदे कानूनों को तोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने बिल्डर्ज को, राजीव गांधी ट्रस्ट को और दूसरे लोगों को फायदे पहुंचाने का काम किया। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल साथी मिथ्या और झूठी बात कर रहे हैं। राजीव गांधी ट्रस्ट का मामला पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट तक जा चुका है और वहां यह याचिका खारिज कर दी गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि श्री बी.बी. बतरा जी की कमेटी ताऊ देवीलाल ट्रस्ट और अन्य ट्रस्टों के बारे में रिपोर्ट लेकर आएगी इसलिए ये विचलित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में तो यह भी हुआ कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद के ट्रस्ट को खुद के दस्तखतों से जमीन दी हुई है। सारे आंकड़े और तथ्य सामने आने वाले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैग की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था। (विघ्न) राजीव गांधी के नाम पर मंत्री जी को पता नहीं क्यों दिक्कत आ गई? जो इनके नेता रहे हैं हम उनका नाम ही तो ले रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं बड़े आदर के साथ उनका नाम ले रहा हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये तथ्यों के विपरीत बात न करें।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़े तजुर्बेकार व्यक्ति हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो कैग की रिपोर्ट रखने की बात कही है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, जब कैग की रिपोर्ट आई ही नहीं, क्या कैग लिखने से पहले आपसे राय करते हैं? (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ये सीनियर मंत्री हैं, ये एम.एल.ए. रहे हैं, ये हमारे साथ विपक्ष में भी रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाउस खत्म होने वाला है लेकिन कैग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इसका क्या कारण है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हिन्दुस्तान से बाहर थे। अरोड़ा जी ने शायद पता नहीं किया। नार्मली तो ये पता करके आते हैं। (विघ्न) He was out of the country. I have already found out and that's why he could not sign the 4th Report.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, वे बाहर से आएंगें नहीं तो इसका मतलब क्या हाउस में कैग की रिपोर्ट नहीं आएगी। (विघ्न) कैग की रिपोर्ट लाने के लिए आप यहां हैं और आपको इसे हाउस में ले करना है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको क्लैरीफाई कर देना चाहता हूं। अरोड़ा जी ने एतराज किया कि कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं लेकर आए। Let me clarify one thing. Comptroller and Auditor General of India is not subservient to Government of Haryana. C.A.G. was travelling outside the country as per my knowledge. Therefore, he could not approve his Fourth Report. His Report has only been received by the Government on 4th March. What is the date of today, if I may ask you ? When we receive the Report, we will place the Report before the House. He has not approved his 4th Report because he was travelling outside the country. I am saying on record and the said report has been received only on 4th March. If you want to make an issue, then go to the Office of the C.A.G. and make an issue there.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में टैक्स फ्री का बहुत जिक्र आता है और इस बारे में मेजें थपथपाई जाती हैं कि हमने टैक्स फ्री बजट पेश किया। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जब वे जवाब देंगे तो कम से कम यह तो क्लीयर कर दें कि ये न तो बिजली के रेट बढ़ाएंगे, न बसिज का किराया बढ़ाएंगे, न रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाएंगे, न कलैक्टर रेट बढ़ाएंगे और न वैट बढ़ाएंगे। क्या मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे कि इसके बाद प्रदेश को टैक्स फ्री रखा जाएगा या पिछले साल की तरह ये टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर वित्त मंत्री जी के अपने निवास पर पिछले लगभग 108 दिन से सचिवालय स्टाफ

धरने पर बैठा है और उनकी एक ही मांग है कि आप हरियाणा को नम्बर-1 कहते हो, हमें देश में नम्बर-1 स्केल नहीं बल्कि कम से कम पड़ोसी राज्य के बराबर कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारा विधान सभा का स्टाफ है। पंजाब और हरियाणा का स्टाफ एक ही बिल्डिंग में बैठा है और पंजाब ज्यादा सैलरी दे रहा है और हम कम दे रहे हैं फिर किस प्रकार की नम्बर वन स्टेट की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो पुलिस का स्टाफ है उनको कई बार महीनों-महीनों छुट्टी भी नहीं मिलती और उन्हें लगातार एक-एक महीने तक काम करना पड़ता है। उनकी भी यही मांग है कि उनके पे-स्केल पंजाब के बराबर कर दिए जायें। इनको इसमें दिक्कत कहां है। यदि आज काम करने वाले लोग धरने पर बैठेंगे तो काम कैसे होगा? उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खर्चा बढ़ाने की बात है मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो जो लोग मांग करते हैं उनको दिया नहीं जाता और दूसरी तरफ ए.जी. ऑफिस के अंदर 166 वकील लगा रखे हैं। जिनमें 1 ए.जी., 2 सीनियर ए.ए.जी., 55 एडीशनल ए.जी., 15 सीनियर डिप्टी ए.जी., 46 डिप्टी ए.जी. और 48 ए.ए.जी. यानि टोटल 166 लोग वहां लगा रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी फिर कहेंगे कि हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं। इन 166 में से आधे अकेले रोहतक के हैं जो यहां आते भी नहीं, सिर्फ तनख्वाह ले जाते हैं। इस बारे में चाहे पता करवा लेना।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी को आंकड़े कंफर्म किए बिना ऐसी बात कहना अशोभनीय बात है। इनको तथ्य पर बात करनी चाहिए। इनके पास न आंकड़े हैं, न तथ्य हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में रामपाल माजरा जी ने अनस्टार्ड क्वैश्चन पूछा है उसका जवाब आया हुआ है। उसके जवाब में इन्होंने खुद माना है कि 166 लगे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अनस्टार्ड क्वैश्चन का रिप्लाई आया हुआ है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या उस जवाब में एड्रैस भी दिए हुए हैं कि ये लोग कहां के रैजीडैंट हैं। I know that. I have read the reply given to the unstarred question of Shri Ram Pal Majra. Do you know the residence of each one of the law officers ? And Sir, can the matter of the Law Officers which relates to the Government, be debated in the Vidhan Sabha ?

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि इन्होंने जो टीचर्स लगा रखे हैं उन्होंने आगे अपने असिस्टैंट लगा रखे हैं। वे कभी स्कूल नहीं जाते, केवल तनख्वाह लेने जाते हैं। उनमें ज्यादातर रोहतक के हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये अपने समय की बात भूल गये हैं। इन्होंने एम.आई.टी.सी. के 9000 कर्मचारियों को घर बिठा दिया था। इन्होंने उनकी रोजी-रोटी छीनने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस की सरकार ने कमेटी बनाकर दोबारा उनको नौकरी पर लगाया था।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि जो ए.जी. आफिस में इन्होंने 166 वकील लगा रखे हैं इनमें से ज्यादातर तो केस की पैरवी भी नहीं करते। इसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। इसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप वाईंड अप करें। आपने गवर्नर एड्रैस पर भी बोला था।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो गवर्नर एड्रैस से अब तक खड़ा हूं, पांच दिन हो गये खड़ा हुआ हूं। मैं बोल रहा था और उस टाईम सदन एडजर्न कर दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अरोड़ा जी मेरे बड़े भाई हैं और सच की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब भी मेरे बड़े भाई या इनकी पार्टी के सदस्य कहीं भाषण दे रहे हों और वहां मंच पर कोई इनके कान में रोहतक का नाम ले दे तो ये एकदम से बैठ जायेंगे। पता नहीं ये रोहतक के नाम से इतना डरते क्यों हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि रोहतक भी हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। ये लोग तो यू.पी. और राजस्थान से लोगों को लाकर यहां नौकरियां लगाते थे। अब ये लोग उस समय को भूल गये हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारे दोस्त हैं और पूजनीय भी हैं क्योंकि ब्राह्मण हैं। रोहतक से हमें कोई दिक्कत नहीं है चाहे वहां आप नौकरियां लगायें और पैसा लगायें, हमें कोई एतराज नहीं है। डिप्टी स्पीकर सर, हमें तकलीफ तब होती है जब हमारे नहीं लगते। अब ये सत्तापक्ष के साथी खुद इस बारे में कह रहे हैं। सर, सारे आंकड़े यही बता रहे हैं। पिछले 8 साल में एच.आर. डी.एफ. का पैसा रोहतक में लगा है 229 करोड़ रुपये और यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे जिले कुरुक्षेत्र से वित्त मंत्री हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुरुक्षेत्र में लगा है सिर्फ 41 करोड़ रुपये। मैं यह कहना चाहता हूं कि रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री चाहे 229 करोड़ रुपये के 529 करोड़ रुपये कर दें लेकिन हमारे 41 करोड़ रुपये के कम से कम 241 तो होने ही चाहिएं। हमें रोहतक में विकास कार्यों पर बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च करने का कोई दुख नहीं माननीय मुख्यमंत्री वहां पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दें। सर, सत्तापक्ष के मेरे साथी गवर्नर एड्रैस पर बोल रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं (विघ्न) उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है। (विघ्न)

13.00 बजे

श्री आनंद सिंह दांगी : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जो माननीय सदस्य नौकरियों की बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी नौकरियां एक ही जिले के लोगों को दी गई हैं। इस बारे में कहना चाहता हूं कि जो केस अभी हाल ही में सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसके बारे में तरह-तरह की बातें सारे देश व प्रदेश में हो रही हैं और जिसमें कुछ लोग जेल में भी गये हैं, जे.बी.टी. की उस लिस्ट में रोहतक जिले के सिर्फ 29 बच्चों का ही सिलैक्शन हुआ है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि (विघ्न)।

Shri Randeep Singh Surjewala : Deputy Speaker Sir, on a point of order. मैं भी इस बारे में अपने को श्री दांगी जी की बात के साथ जोड़ते हुए यह कहना चाहता हूं कि अरोड़ा साहब उस सरकार में मंत्री थे उस समय कुरुक्षेत्र जिले के हिस्से में जे.बी.टी. की 150 पोस्टें थी लेकिन उन पर वहां से काटा मारकर इन 150 पोस्टों पर किसी और जिले के लोगों को लगा दिया गया।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे सभी भाई चौटाला साहब के जेल जाने की बातें कर रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि जे.बी.टी. की पोस्टें पर वहां से इतने लगे और वहां से उतने लगे। सर, यह बात आप भी जानते हैं और ये जो सारे लोग जो मेरे सामने बैठे हैं ये भी वास्तविकता जानते हैं। यह बात हरियाणा प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है। अगर नौकरियों की बात आती है तो इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 1966 में हरियाणा बना उसके बाद से चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो अगर नौकरियों के मामले में जेल जायें तो हर सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जेल जाने चाहिएं। ये भाई जो मेरे सामने बैठें हैं जो कि सरकार के अंदर हैं मैं आज भी देखता हूं कि ये लोग सभी प्रकार की नौकरियों में अपने-अपने हल्के के लोगों की लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री के पास कम जाते हैं लेकिन उनके ओ.एस.डी. के पास ज्यादा जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू से यह एक सिस्टम बना हुआ है। यह बात मैं कहना नहीं चाहता था (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, आदरणीय अरोड़ा जी वरिष्ठ साथी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। मैं इनको केवल दो बातें याद दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि ये सारे घटनाक्रम के कई वर्षों से चश्मदीद गवाह रहे हैं। सर, हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन जिसको हम एस.एस.एस. बोर्ड कहते हैं उसके सदस्य जेल में गये। यह 1989 से 1991 के बीच में जो इनका स्टाफ सिलैक्शन कमीशन था उसके सदस्यों को जेल जाना पड़ा। (विघ्न) सर, इनको हमारी बात सुनने का माद्दा तो रखना चाहिए। सर, मैं यह कह रहा था कि इनके द्वारा नियुक्त किये गये स्टाफ सिलैक्शन कमीशन के सदस्यों को सारी नौकरियों में उनके द्वारा बरती गई हेरा-फेरी के कारण जेल जाना पड़ा और बाकायदा उनको सजा हुई। डिप्टी स्पीकर सर, यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, अगर अरोड़ा साहब सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाने वाली कोई बात कहेंगे तो इनको उसके ऊपर सरकार के क्लेरिफिकेशन की बात को तो सुनना ही पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि ऐसा पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस बारे में भारतवर्ष के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय खण्डपीठ ने आर्टिकल 317 के तहत इनके द्वारा नियुक्त हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को दोषी पाया और महामहिम राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप में उनको हटाना पड़ा। डिप्टी स्पीकर सर, यह इनके लिए बड़े शर्म की बात है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं भी इसमें अपने को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि यह बड़े शर्म की बात है कि पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे दोस्त हैं, मैं इनको एक राय देना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी इनको एक राय है। अगर ये मेरी राय को मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे अन्यथा ये इतने भी नहीं रहेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब एक साथी कह रहे थे कि जो जन-प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी अनदेखी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डी-प्लान को दोबारा से शुरू किया है। जिला परिषद् के मैम्बर को 10 लाख रुपये दिये गये। ब्लॉक समिति के चेयरमैन, नगर पालिका और नगर निगम के चेयरमैन को 50-50 लाख रुपये दिये गये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। हमने ब्लॉक समिति के चेयरमैन को नहीं दिये बल्कि ब्लॉक समिति और जिला परिषदों को दिये हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् और ब्लॉक समिति को तो 50 लाख रुपये दिये गये और एम.एल.एज. को कोई पैसा नहीं दिया गया। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव है, एक मांग है। (विघ्न)

श्री नरेश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब यह तो बता दें कि यह स्कीम किसने शुरू की थी और किसने बंद की है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सुझाव दे रहे हैं, जो ये कहने जा रहे हैं, वह मैं समझ गया हूं। हम लिफाफा देख कर मजमून भांप लेते हैं। जो सुझाव अरोड़ा साहब देना चाहते हैं वह मैं समझ गया हूं। आप भी शायद उस समय सदस्य होंगे जब एम.पी. डिवैल्पमैंट फंड का केन्द्र में प्रावधान हुआ था उस समय मैं भी एम.पी. था। यह सुझाव हरियाणा विधान सभा में भी आया था तब श्री ओमप्रकाश चौटाला ने कहा था कि एम.एल.ए. के लिए डी-प्लान में पैसा नहीं होना चाहिए और हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यह रिकॉर्ड की बात है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इसको शुरू कर सकते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्योंकि वे मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी बात मानता हूं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : एक दोस्त की बात ही मान लो। भाईचारा तो फिर भी घर की बात है, लेकिन दोस्ती लम्बी चलती है। हम भी मुख्यमंत्री जी पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं और दूसरे सदस्य भी लगाते हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी को राय है कि कर्ज तो वैसे भी लिया जा रहा है 450 करोड़ रुपये का कर्ज और ले लिया जाये तथा सभी विधायकों को डी-प्लान के नाम से 5-5 करोड़ रुपये दे दो, कोई भी नहीं बोलेगा, सारे आपके गीत गायेंगे। (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र अरोड़ा साहब भेदभाव

का आरोप लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है लेकिन ये ईमानदारी से यह बता दें कि इन्होंने अपने हलके के बारे में काम कहा हो और मैंने नहीं किया हो और मैं तो सभी साथियों को कह रहा हूं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हलके की हालत तो बहुत खराब है। (विघ्न)

ऊर्जा मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, डी-प्लान में मैंने श्री कृष्ण लाल पंवार से लिस्ट मांग कर काम किये हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस डी-प्लान की मीटिंग की ये बात कर रहे हैं उस मीटिंग की प्रोसीडिंग पर उपायुक्त महोदय ने आज तक साईन नहीं किये हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बतायें कि इनसे पूछा या नहीं पूछा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी बहन सुमिता सिंह ने रजिस्ट्रियों का जिक्र किया था। आज शहरों की आबादी बढ़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी एक शहर की बात नहीं है। आज हर शहर में हजारों की संख्या में शहर के भी और गांव के भी बच्चे प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लगे हुए हैं। आज बेरोजगारी बढ़ रही है और जमीन घट रही है। सर, एक तो सरकार ने प्लाटों और मकानों की रजिस्ट्रियां बंद करके बेरोजगार बच्चों का रोजगार खत्म कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े बिल्डर्ज को तो 55 एकड़ जमीन पर सरकार ने लाईसैंस दिया है जिससे वह टाऊनशिप बना लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे मांग है कि जिन बच्चों की रोजी रोटी खत्म होती जा रही है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बिल्डर्ज लाईसैंस की शर्त को 55 एकड़ जमीन की बजाए 5 एकड़ जमीन कर दिया जाए, क्योंकि सरकार बिल्डर्ज को बड़े शहरों में कॉलोनी बनाने का जो लाईसैंस देती है उसके लिए मिनीमम शर्त 55 एकड़ जमीन है। कोई भी बेरोजगार युवक चाहे वह शहर का हो या गांव का हो इस शर्त को पूरा नहीं कर पाता और वह कॉलोनी नहीं काट पाता। यही कारण है कि फिर वे अनअथोराईज कॉलोनियां काटते हैं। टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट वाले पैसे लेकर उनकी कॉलोनियां कटवा देते हैं जिसमें आम आदमी प्लॉट लेकर फंस जाता है। वे लोग जब मकान बनाते हैं तो उनके मकान के नाम नोटिस इश्यू हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि सरकार अपने नियम तय करे और बिल्डर्ज लाईसैंस की शर्त 55 एकड़ की बजाए 5 एकड़ या 7 एकड़ जमीन कर दें ताकि अपने शहर के बच्चे व गांवों के बच्चे जो बेरोजगार फिर रहे हैं उनको भी काम मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ बजट में सड़कों के बारे में काफी कुछ कहा गया है कि सड़क तंत्र को हम बहुत मजबूत कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिपली गांव से लेकर थर्ड गेट कुरुक्षेत्र तक जिस पर आपका रैजीडैंस भी है कृपा करके उस सड़क का ही हाल देख लें कि उस सड़क का कितना बुरा हाल है। वित्त मंत्री जी, आप तो लग्जरी कार में चलते हो इसलिए शायद आपको कोई झटका नहीं लगता होगा

:
:
:

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

और लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। मैं आम पब्लिक की हालत के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि जो लोग थ्री व्हीलर द्वारा पिपली से कुरुक्षेत्र जाते हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक रिश्तेदार सुल्तान सिंह यहां विधान सभा में बैठा है जब वह अपनी ससुराल में जाते हैं तो उसकी ससुराल वाले उनको कहते हैं कि हमारे गांव वाली सड़क तो बनवा दो हमारा रिश्तेदार सुल्तान सिंह कई बार मंत्री जी को अमीन रोड से फदुपुर तक की सड़क बनवाने के लिए कह कर भी आए हैं। सुल्तान सिंह को अपनी ससुराल में जाने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर फालतू काटकर जाना पड़ता है, इसलिए वह अपनी ससुराल जाते ही नहीं हैं और इस वजह से उनकी रिश्तेदारी खराब हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आज आम आदमी के लिए मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। रेत के, बजरी के, ईंट के, सीमेंट के, सरिये के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी एक सदस्य यहां कह रहे थे कि आपके समय में 5 करोड़ रुपये माइनिंग का आता था लेकिन अब हम उस माईनिंग के रिवैन्यू को 35 करोड़ रुपये तक ले गए। हमारे समय में रेत 5 रुपये फुट मिलता था। लेकिन आज 30 रुपये फुट हो गया है, कोरसैंट आज 40 रुपये फुट लेना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस महंगाई को रोकने का कोई इन्तजाम करें। सर, कोर्ट में और स्टेटों के भी मामले थे परन्तु उन स्टेटों का स्टे तो टूट गया परन्तु हरियाणा पर ही स्टे क्यों लगा हुआ है? उसको भी तुड़वाने का काम करें। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आज पूरे सदन के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने एक गऊ कमीशन बनाया है जोकि एक अच्छी बात है क्योंकि गऊएं हमारी माता हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसके आदेशानुसार हरियाणा प्रदेश की हर गऊशाला में, प्रत्येक गऊ के चारे पर 15 रुपये खर्च किये जायेंगे। सरकार गऊओं के प्रति कितना आदर रखती है उसका पता इस बात से लग जाता है कि हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। इसलिए सबसे पहली मेरी प्रार्थना है कि गऊओं का सम्मान करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका डाली गई है उसको वापस लिया जाये। दूसरी मेरी प्रार्थना है कि बॉर्डर के ऊपर जो नाके लगे हुए हैं उन नाकों को मजबूत किया जाये जिससे गऊओं की तस्करी को मजबूती से रोका जा सकेगा और साथ ही जो अपराधी लोग दूसरे प्रदेशों से हरियाणा के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं वह भी नहीं आ सकेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि थोड़ी देर पहले हमारे साथी अरोड़ा साहब ने डी-प्लान के पैसे के बारे में बात की थी तो उस संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि डी-प्लान के पैसे के यूज करने के बारे में तो हर विधायक और हर सांसद की राय ली जाती है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : डिप्टी स्पीकर सर, हमारी तो कभी इस पर राय नहीं ली गई? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, इसके बारे में तो कृष्ण पाल गुर्जर जी भी बता सकते हैं जो डी-प्लान के सदस्य भी हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप लोग

डी-प्लान की मीटिंग्ज में नहीं जायेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा... (शोर एवं व्यवधान) अगर मीटिंग में जाओगे तो यह पैसा आप लोगों को जरूर मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : डिप्टी स्पीकर सर, हम तो मंत्री जी से कई बार रिक्वैस्ट भी कर चुके हैं कि मंत्री जी हमारे हलके का भी ध्यान रखो लेकिन बावजूद इसके हमारी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अरोड़ा जी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताओ? (शोर एवं व्यवधान) अगर आपके किसी साथी ने हमसे कोई डिमांड की है तो आप उनसे पूछ लो, जो हमने उनको कभी ना कही हो। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी, आप माजरा साहब से पूछ लो जो उनको कभी किसी चीज की ना कही हो। माजरा जी भी कई बार अपने गांव के विकास के बारे में हमको कहते हैं तो हम उन कामों को भी पूरा करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपके किसी भी साथी ने अगर कोई डिमांड की है तो हमने उसको पूरा ही किया है (शोर एवं व्यवधान) किसी सदस्य की अगर कोई वाजिब डिमांड है तो उसे पूरा करना हमारा काम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैंने कई बार पर्सनली सुरजेवाला जी को कहा कि भाई दो लाख रुपये किसी वाल्मिकी चौपाल पर या हरिजन चौपाल पर तो जाने दो। एक ब्लॉक के 19 गांव कैथल में पड़ते थे लेकिन सुरजेवाला जी ने एक पैसा भी डी-प्लान का इस क्षेत्र में नहीं जाने दिया। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, माजरा जी पूर्णतः मिथ्या बोल रहे हैं...(शोर एवं व्यवधान) 10 करोड़ रुपये इनके विधान सभा क्षेत्र में इस समय खर्च होने लग रहे हैं (मेजें थपथपाई गईं।) जिसे आप अगर चाहे तो हाउस की कमेटी बनवाकर चैक करवा सकते हैं। मैं इनकी बात को चैलेंज करता हूं। आप हाउस की कमेटी बनाईये और जिसकी बात झूठ निकले उसको यह हाउस दंडित करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिसका मैं विधायक हूं वहां पर मेरे कहने से एक ईंट तक भी नहीं लगी है और आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, इस समय माजरा जी के विधान सभा क्षेत्र में एच.आर.डी.एफ. के माध्यम से दस करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो रहे हैं। मैं ऑफर करता हूं कि इस विषय पर एक हाउस की कमेटी बना दी जाये और जो झूठा हो उसको इस वैल के अन्दर सज़ा दी जाये। Are you agreeing? If you agree, we will get the facts out? (Interruption) आप सहमत तो हो (शोर एवं व्यवधान) मैं कलायत विधान सभा क्षेत्र की ही बात कह रहा हूं और किसी विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

:
:
:

श्री अनिल विज : सर, हमारा अम्बाला छावनी का डी-प्लान का पैसा नहीं मिलता है और पूछते हैं तो बताया जाता है ऊपर से रोका हुआ। यह पैसा पिछले साल भी लैप्स हो गया था इस साल भी तीन महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिल पाया है। सर, ये ऊपर से डी-प्लान का पैसा कौन रोकता है? सर, इस ऊपर वाले को तो चैक करवाओ? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। बजट किसी भी प्रदेश के विकास का आईना होता है लेकिन हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस खूबसूरती के साथ आंकड़ों के जाल में फंसाकर जो विकास की तस्वीर पेश की है अगर उस आंकड़ों के जाल को हटा दिया जाये तो विकास की जो वास्तविक तस्वीर है यह प्रदेश की जनता के सामने आ जायेगी। प्रदेश की जनता जो पहले से ही महंगाई और भ्रष्टाचार की मार से जूझ रही है इस बजट के माध्यम से उन्हें कोई भी राहत देने का कार्य नहीं किया गया है। स्पीकर सर, अगर बजट ऐट ए ग्लांस का पेज नंबर 1 का अवलोकन किया जाये तो पाएंगे कि सरकार की वित्तीय स्थिति किस तरह की है। अगर रेवेन्यू डैफिसिट की बात की जाये तो वर्ष 2011-12 में वह 1457 करोड़ का था और 2012-13 में संशोधित अनुमान के अनुसार 3163.38 करोड़ रुपये हो गया है। इसका मतलब यह है कि पिछले वर्ष सरकार ने जो रोजमर्रा के खर्च किए थे जैसे वेतन, पेंशन, बिजली के बिलों के भुगतान आदि उनके लिए 1700 करोड़ रुपये का सरकार को ऋण लेना पड़ा। 2004 में फिस्कल रिसीट्स एण्ड बजट मैनेजमैंट एक्ट के अनुसार यह कहा गया था कि जो रेवेन्यू डैफिसिट है उसे जीरो पर लाया जाये तभी केन्द्र सरकार ग्रांट जारी करेगी। इसी तरह से जहां तक वित्तीय घाटे की बात की जाये तो यह 2012-13 में 8132 करोड़ था जो कि 2013-14 में 8975 करोड़ होने का अनुमान है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है। (विघ्न) स्पीकर सर, बजट के अंदर प्लान ऐक्सपैंडीचर है, नॉन प्लान ऐक्सपैंडीचर है उसको देखा जाये तो प्लान जो है उस पर खर्च किया जा रहा है 20532 करोड़ और नॉन प्लान में 32720 करोड़ का प्रावधान है। इससे साफ पता चलता है कि विकास की गति धीमी होगी। स्पीकर सर, मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहती हूं।

Mr. Speaker : Kavita Ji, what is the difference between plan and non-plan?

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, प्लान यह है कि किस-किस सैक्टर में आलरेडी प्लानिंग हो चुकी है और जो नॉन प्लान में होगा वह अपनी मर्जी से जैसे गवर्नमैंट डिसाइड करेगी और खर्च कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र के दौरान यह बात भी कई माननीय सदस्यों ने उठाई कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस बारे में पूरे सदन में चिंता दिखाई गई और पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने जिस तरह से अपनी संजीदगी दिखाई और बताया था तो हमें लगा था कि सरकार इस दिशा में कोई प्रभावशाली कदम उठाएगी लेकिन प्लान बजट के अंदर उसके बारे में कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि जब आप महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में इतने संजीदा

हैं तो उसके लिए आपको कुछ राशि अपने प्लान बजट में रखनी चाहिए थी। कैग रिपोर्ट जो पार्लियामैंट में रखी गई है उसमें कहा गया है कि हरियाणा में महिलाओं और बाल कल्याण के पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार की तरफ से 57.87 करोड़ रुपये का फंड महिलाओं और बाल कल्याण के लिए दिया गया था, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ तो किस तरह से महिलाओं और बच्चों को उत्पीड़न से मुक्ति सरकार दिलाएगी? स्पीकर सर, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए भी पॉवर सैक्टर के बारे में बात कही थी अब भी यह कहना चाहूंगी कि पावर सैक्टर के लिए वर्ष 2012-13 में 5805 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी और अब 2013-14 में 600 करोड़ समथिंग घटाकर 5232 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। जब पिछले साल ही बिजली की प्रदेश में इतनी बुरी हालत थी तो इस बार क्या हालात होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। आज प्रदेश में बिजली, तारों और खंभों की क्या स्थिति है, कनैक्शंज की क्या स्थिति है और बजट पहले से भी कम कर दिया गया है इससे बिजली महकमे की हालत वर्स्ट से भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह से कोऑपरेटिव सैक्टर में भी पिछली बार जो बजट रखा था, उससे भी कम कर दिया गया दिखाया है। कुल रिसीट्स 65785 करोड़ की है लेकिन स्पीकर सर, सरकार ने विभिन्न संस्थाओं से उस लोन की रीपेमेंट के लिए लोन लिया है और उसे चुकाने के लिए 19500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि कुल प्राप्तियों का 25 से 30 प्रतिशत लोन की रिपेमेंट में ही चला जाएगा। और इससे भी ज्यादा जो बजट की परसैंटेज है वह रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको देने में निकल जायेगा। स्पीकर सर, विकास के लिए सरकार के पास पैसा कहां से बचेगा? स्पीकर सर, अब मैं बुढ़ापा पैंशन के बारे में कहना चाहूंगी। सरकार ने बुढ़ापा पैंशन के बारे में दोबारा से जाँच करवाई और उसमें पाया गया कि इसमें काफी अनियमितताएं बरती गई हैं। पूरे प्रदेश में 13477 व्यक्ति ऐसे पाये गये जो गलत पैंशन ले रहे थे। सरकार की तरफ से उन व्यक्तियों को तो नोटिस जारी कर दिए गये कि उनकी पैंशन वापस जमा कराई जाए। उन अधिकारियों के प्रति अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है जिनकी वजह से उन व्यक्तियों को पैंशन दी गई है। स्पीकर सर, इसी तरह से बी.पी.एल. के कार्ड बनाने में जो अनियमितताएं बरती गई हैं उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है जोकि असल में दोषी थे। स्पीकर सर, पिछले चार साल से अब की बार चौथा बजट मैं इस सदन में सुन रही हूं बजट पेश करते हुए हर बार यह कहा जाता है कि इस साल टैक्स फ्री बजट होगा लेकिन यह बिल्कुल सच साबित हो चुका है कि पहले या बाद में लेवी टैक्स इम्पोज कर दिए जाते हैं। हाउस टैक्स पहले माफ करके फिर लगा दिया गया। स्पीकर सर, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहती हूं कि जो अनएथोराईज्ड कॉलोनिज हैं उन कॉलोनिज में सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा मुहैय्या नहीं कराई जाती तो फिर उन कॉलोनिज पर जो मकान बन गये हैं या जो खाली प्लॉट हैं उन पर हाउस टैक्स लगाने का सरकार का कोई हक नहीं बनता। इसके लिए मेरा सुझाव है और मेरी यह डिमाण्ड भी है कि जो खाली प्लॉट हैं और जो अनएथोराईज्ड मकान हैं उन पर हाउस टैक्स न लगाया जाए। स्पीकर सर, पिछले सैशन में मैंने एक मांग की थी कि जो अनएथोराईज्ड कॉलोनिज में जो लोग रहते हैं उनसे सभी पार्टियां वोट लेती हैं हम भी उन लोगों से वोट मांगते हैं। उन लोगों को भी मानवता की तरह जीने का हक

[श्रीमती कविता जैन]

है। मैंने पिछले सैशन में उन कॉलोनिज में एक स्टैण्ड पोस्ट नल लगाने की मांग की थी और माननीय पार्लियामैंट्री एफेयर्स मिनिस्टर ने वहां पर स्टैण्ड पोस्ट नल लगाने के लिए एग्री भी किया था लेकिन वह मांग आज तक पूरी नहीं की गई है। अब मैं सोनीपत में टाऊन पार्क के बारे में कहना चाहती हूं। आपको पता है कि सोनीपत शहर में कोई भी बड़ा टाऊन पार्क नहीं है। मैंने सोनीपत में टाऊन पार्क बनाने के लिए एक क्वैश्चन भी लगाया था लेकिन उसका जवाब "नहीं" में आया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि सोनीपत के सैक्टर 12, 13, 14, 15 का जो एरिया है वहां कोई बड़ा पार्क नहीं है। सैक्टर 16 में एक पार्क की ले-आऊट की गई थी और 15.76 एकड़ जमीन में पार्क बनाने का एक प्रोपोजल था लेकिन उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया और उस एरिया में प्लॉट काटने की घोषणा कर दी गई। मैं यह कहना चाहूंगी कि मानव की जो जरूरतें हैं उनको मूल्यों के आगे नहीं तोलना चाहिए और जनता की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः विचार करना चाहिए। सरकार हमेशा बात करती है कि गरीबों को मुफ्त प्लॉट दिए जायेंगे और मकान बनाकर दिए जायेंगे। इसके बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे सोनीपत में सैक्टर 23 के पास एक अम्बेडकर कॉलोनी है वहां पर गरीब लोगों के 30-35 मकान बने हुए हैं। स्पीकर सर, यह तो उस एरिया की जमीन है उस जमीन का 30 वर्ष पहले अधिग्रहण कभी किया गया था उसके बाद शायद कोई कोर्ट केस के कारण उस अधिग्रहण पर स्टे ले लिया गया। इस दौरान गरीब लोगों ने वहां पर जमीन खरीदी और उस जमीन पर अपने मकान बना लिए हैं। आज उनको नोटिस जारी किए गये हैं कि उनके मकान या तो एक्वायर किए जायेंगे या तोड़ दिए जायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूं और इसके बारे में मेरा एक सुझाव भी है कि सरकार जब मकान बनाने के लिए गरीबों को पैसा देती है और जमीन देती है तो उन गरीबों के मकानों को छोड़ दिया जाए ताकि इन गरीब लोगों को बहुत राहत मिल सके। इस बार हाउस में एक अजीब सी बात देखने में आई है कि जब क्वैश्चन आवर के दौरान किसी भी विधायक के सड़कों को बनाने के लिए कोई प्रश्न नहीं लगे। या तो प्रदेश की सारी सड़कें सही सलामत हैं या फिर सभी साथी विधायक इस बात से खुश हैं कि उनके हलके की कोई भी सड़क टूटी ही नहीं है। लेकिन स्पीकर सर, आप भी सोनीपत शहर की उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं और आपको पता है कि सोनीपत की सड़कों का क्या हाल है। इसलिए मैं आपके नोटिस में सोनीपत की सड़कों के बारे में जरूर लाना चाहूंगी। स्पीकर सर, आप तो कभी गन्नौर निकल जाते हैं और कभी करनाल और जनता की पकड़ में हम लोग आते हैं। सर, मैं सोनीपत शहर की कुछ सड़कों के नाम सदन में बताना चाहूंगी। मिशन चौक से कालीपुर चुंगी तक ककरोई रोड वाली सड़क, ओल्ड डी.सी. रोड, राठधना वाली सड़क, पुराना बाई पास गोहाना रोड, श्मशानघाट से पुलिस लाइन तक, मुरथल अड्डा से जटवाड़ा तक तथा जिन सड़कों का मैंने राज्यपाल अभिभाषण के दौरान जिक्र किया था उन सभी सड़कों के नाम भी ले लिए जाएं। जो हुड्डा डिपार्टमैंट की सड़कें सैक्टर 15,14, 12 और सैक्टर 23 में हैं उन सड़कों की हालत काफी खस्ता है इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इन सड़कों को भी दुरुस्त करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. का भी स्पैशल फण्ड सोनीपत जिले के लिए रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप एक मिनट में वाइंड अप करें।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो जरूरी बातें कहना चाहती हूं। विकलांगों और विधवाओं के लिए बी.पी.एल. कार्ड बनाने की नीति बनाई जाए।

Mr. Speaker : You have already spoken the same things on the Governor's Address. Don't repeat same things. What is the distinction of your speech made on the Governor's Address and between the Budget Estimates? I am giving you special favour because you are from Sonepat.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रही हूं बल्कि मैं सरकार को सुझाव दे रही हूं। मेरी आधे मिनट की बात रह गई है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप आधे मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, विकलांगों का जब मैडीकल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें 75 परसैंट विकलांग होने पर उनको सुविधाएं दी जाती हैं इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगी कि यह लिमिट 50 परसैंट की जाए। इसके अलावा इनको 2 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के देने की नीति बनाई जाए ताकि वे कोई रोजगार अपना सकें। इसके इलावा विकलांगों को भी 100-100 गज के प्लॉट देने की कोई नीति बनाई जाए।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप जल्दी वाइंड-अप करें।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यूनिवर्सिटी और पत्रकारों की बात जरूर करना चाहूंगी। (विघ्न) दीनबंधू यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले कई दिनों से छात्र हड़ताल पर गए हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस प्वायंट को जीरो आवर में उठाऊं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उस यूनिवर्सिटी में 2010 में वीकएंड टैक्नीकल कोर्सिज शुरू किए गए थे जिसके माध्यम से यह था कि जो आलरेडी डिप्लोमा होल्डरर्ज हैं वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें यानि उनको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मिल सके। मैं उनको बच्चे तो नहीं कहूंगी क्योंकि all are working. उन लोगों ने फोरथ इयर में प्रवेश भी ले लिया है और अब उन बच्चों को पता चला है कि अभी तक उनके कोर्सिज को AICTE ने मान्यता नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में उन्हें जो डिग्री मिलेगी वह केवल मात्र कागज का टुकड़ा होगी। इस बात को लेकर उन्होंने वाइस चांसलर को भी लिखा और वी.सी. साहब ने आल इंडिया कौंसिल ऑफ टैक्नीकल एजूकेशन को भी लिखा लेकिन अभी तक इसकी एप्रूवल नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इसको परसयू करे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पत्रकारों की जरूर करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप बैठें।

Chief Parliamentary Secretary (Rao Dan Singh) : Speaker Sir, Thank you very much for giving time to me for taking part on the discussion of the Budget Estimates. The Budget is quite difficult to understand though its most important and integral part on without which no Government, no institution, even though House can progress. Sir, whatever I can gather from the speech of the Hon'ble Finance Minister, the Budget is an annual financial

[Rao Dan Singh]

statement of the Government which includes estimates receipts and expenditure of the year which commence from 1st of April, 2013 to 31st March, 2014. Sir, it mainly comprises three divisions; the capital accounts, the revenue accounts and public accounts. Before I come to subject-wise allocation of the Budget, I must appreciate and congratulate the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Finance Minister for making their hard efforts and leaving no stone unturned to provide us a very pro-development and pro-poor budget without imposing additional burden of taxes. Sir, if you look at the size of the budget, this plan budget is much higher and bigger than the budget of 2004-05. The revenue deficit is less, fiscal deficit is less that means everything has been taken care of properly and considered properly to make Haryana No. 1. It was pledged by the Hon'ble Chief Minister to make at the time of his youth. Ch. Bhupinder Singh Hooda is a man of strong conviction and commitment. Whatever he says he does not merely say, he meant by it and stand by it and that's why he has rightly been said इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, बजट तीन शब्द का एक अक्षर है जिसके महत्व को हर सरकार, संस्था यहां तक कि गृहणी भी समझती है । सर, दुनियां के अंदर अमृत्यसैन व कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सब लोग जानते हैं । कल मेरे काबिल दोस्त श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने यहां पर कहा कि कब तक मीठे के खारे के साथ मिलाते रहेंगे । उनकी बात की ताईद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम इसकी तुलना किसी मधुमक्खी से करें तो इसमें गलत नहीं है । जो अपनी धुन के साथ अपने परिश्रम से सर्दी गर्मी सुबह से शाम तक ठंड व बरसात की परवाह किए बगैर हवाओं से लड़ते हुए उन पुष्पों के पास जाती है । वहां से उनकी खुशबू लेती है और उस खुशबू को बिगाड़े बगैर मकरंद चुराकर शहद बनाती है और उस शहद से स्वयं भी आनंद लेती है तथा लोगों को भी आनंद देती है । ठीक उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के इस बजट को तैयार किया है जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर विभाग का ख्याल रखा गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा सदन के सभी सम्मानित साथियों को कि आज से ठीक 8 वर्ष पहले इसी सदन में शपथ लेने के बाद माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि हरियाणा के लोगों आपने मुझे विश्वास और मत देकर यह जिम्मेवारी सौंपी है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप काम करूंगा और हरियाणा के विकास और तरक्की के अंदर इतना साथ दूंगा कि इसको हिंदुस्तान का नम्बर-1 प्रदेश बनाया जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि किसी चीज के कहने मात्र से कोई काम नहीं हो सकता, प्रदेश को नम्बर-1 रखने के लिए उन्हें बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का, हर पेट को रोटी देने का, हर गरीब व्यक्ति को छत देने का है । ये सारी बातें तब हो सकती हैं जब एक अच्छा बजट प्रदेश की जनता को दिया जाये क्योंकि किसी भी ताकत को अगर सरकारी है, संस्था की है, व्यक्ति की है तो उसकी सामरिक ताकत को आर्थिक ताकत के साथ नापा जाता है । आर्थिक स्थिति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब सदन में

वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया जा रहा था तब मैंने 2004-2005 के आंकड़ों को कम्पेयर करके देखा कि 2004 में 2108 करोड़ रुपये का प्लान बजट था जिसका साईज आज बढ़कर 18000 करोड़ रुपये हो चुका है। अगर इसमें केन्द्र प्रायोजित स्कीम्ज को भी लगाते हैं तो हमारा बजट 20532 करोड़ रुपये हो जाता है, जो तकरीबन 2004 से 10 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का द्योतक है कि कितना बजट मुख्यमंत्री जी ने संभाल करके और वित्त मंत्री जी ने मेहनत करके इस प्रदेश की जनता के लिए बनाया है। माननीय अध्यक्ष जी, जी.एस.डी.पी. का कंपैरीजन कंसटैंट और करैंट रेट्स के आधार किया जाता है। यदि आप 2005-06 का बजट देखें उसमें कंसटैंट जी. एस.डी.पी. 104608 रुपये था जो 2013-14 के अंदर 206638 रुपये हो चुका है। इसी तरह से अगर 2005 का करैंट प्राईस पर देखें यह 108885 रुपये था जो 2013-14 के अंदर 411429 रुपये हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यदि पर-कैपिटा इनकम का हिसाब लगाते हैं जहां से आर्थिक मजबूती को नापा जाता है। 2004-05 में प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम 40627 रुपये वार्षिक थी जो अब हमारे समय में 2013 के अंदर 70464 रुपये वार्षिक है और करैंट प्राईस पर यह 42309 रुपये से बढ़कर 141540 रुपये हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि बहुत ज्यादा अंक और आंकड़ों का मैं जिक्र करूंगा तो मैं समझता हूं कि बहुत समय लग जायेगा। मेरे से पहले बोलते हुए मेरे बहुत से काबिल दोस्तों ने इस बारे में विस्तार से अपने विचार रखे हैं परन्तु इस बजट के कुछ बिन्दु हैं जिन पर मैं अपने विचार निश्चित तौर पर रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सबसे ज्यादा बजट अलोकेशन शिक्षा के लिए की गई है क्योंकि शिक्षा के महत्व को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। सबको मालूम है कि अज्ञानता अभिशाप है और अनपढ़ नर पशु समान यह बहुत पुरानी कहावत है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा पैसे का प्रावधान करके यह दर्शा दिया है कि हम सभी व्यक्तियों को शिक्षा देकर सम्पूर्ण व समृद्ध करना चाहते हैं और उसी के आधार पर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं, शिक्षा से बड़ी कोई रोशनी नहीं जो सूर्य की तरह फैलती है, शिक्षा से बड़ा कोई त्याग नहीं जो सूई की तरह खुद वस्त्रहीन रहते हुए भी दूसरों के कपड़े सिलती है, शिक्षा से बड़ा कोई दीपक नहीं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो सबसे पहले मैं शुरुआत अपने आप से ही करना चाहूंगा क्योंकि यह कहा जाता है कि charity begins at home. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के माननीय साथियों को एक बात विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं कि वे अपने समय को याद करें जब "सरकार आपके द्वार–प्रगति का आधार" की बातें की जाती थी उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में कनीना के अंदर जनता के गाढ़े खून-पसीने की कमाई से एक भवन बनाया गया था वह भवन मात्र सरकार की एन.ओ.सी. न मिलने के कारण वह इमारत ऐसी ही खड़ी रही लेकिन तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री ने उसको एन.ओ.सी. नहीं दी। हम आभार व्यक्त करते हैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का जिन्होंने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा को दिलवाया और जिसकी स्थापना के लिए महेन्द्रगढ़ को चुना गया। दूसरा एक आयुर्वेदिक मैडीकल कॉलेज भी हरियाणा प्रदेश को मिला जिसकी स्थापना नारनौल में की गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर सतनाली

[राव दान सिंह]
और महेन्द्रगढ़ के अंदर दो महिला महाविद्यालय दिये। इसके अतिरिक्त एक किसान मॉडल स्कूल भी दिया और एक आरोही मॉडल स्कूल भी मेरे क्षेत्र के लोगों को दिया। इसके साथ-साथ एक संस्कृति मॉडल स्कूल भी हमें दिया गया। इस प्रकार से 6-6 संस्थान एक जिले के अंदर मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए दिये गये। मेरे क्षेत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में मेरे पड़ौस में लगते हुए सैनिक बाहुल्य क्षेत्र रेवाड़ी के बारे में बात करना चाहूंगा जहां कि रणबांकुरों ने जंग-ए-आज़ादी से लेकर देश की आजादी के बाद भी देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राणों की आहूति देकर देश का इतिहास लिखा। अब मैं सैनिक स्कूल के बारे में बात करना चाहूंगा। सर, एक नहीं दो-दो रक्षा मंत्री हमें यह वादा करते रहे कि आपके यहां सैनिक स्कूल बनेगा लेकिन हरियाणा के किसी भी मुख्यमंत्री ने इस बात की चिंता नहीं की। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से पहले अनेकों मुख्यमंत्री आये और चले गये, कुर्सियां बदलती रही और नेता भी बदलते रहे लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस सैनिक स्कूल के शुभारम्भ का कार्य करने का जोखिम नहीं उठाया। ये तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी थे जिन्होंने वहां पर सैनिक स्कूल की स्थापना की। इस प्रकार से आठ स्कूल और कॉलेज मेरे हल्के/जिले में बने हैं और उनमें से पांच कॉलेजों की स्थापना चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के समय में हुई हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के समय में हुई है। गुड़गांव जो कि दुनिया के मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ शहर है वहां पर बिनावा में एक रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है जो हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ पूरे हिन्दुस्तान का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय होगा। भाई आफताब अहमद जी मेवात से आते हैं जिसे हरियाणा के आर्थिक पिछड़े क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वहां पर 800 करोड़ रुपये की लागत से भी ज्यादा का एक मेडीकल कॉलेज बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी क्षेत्र विशेष के विकास करने के आरोप मौजूदा सरकार पर लगाते हैं कि सरकार द्वारा एक क्षेत्र विशेष का विकास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं मानता। सर, आपके पड़ौस में सोनीपत है। मैं अगर शुरुआत करता हूं तो दिल्ली के सबसे नजदीक सोनीपत लगता है जहां पर 2500 एकड़ के अंदर एक एजुकेशन सिटी बनाया जा रहा है जिसमें डेढ़ लाख से ज्यादा लोग पढ़ेंगे। (विघ्न) अर्थात् डेढ़ लाख लोगों के उस कैम्पस में पढ़ने की कैपेसिटी रखी गई है। मैं समझता हूं कि जब वह एजुकेशन सिटी सम्पूर्ण रूप से विकसित हो जायेगा तो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उससे बड़ा कोई एजुकेशन का हब नहीं होगा। स्पीकर सर, श्रीमती कविता जैन जी बैठे-बैठे कुछ बोल रही थी मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि उनके यहां सोनीपत में एक टैक्नीकल कॉलेज होता था जिसको टैक्नीकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। कविता जैन जी स्वयं एक महिला हैं उनको यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह समझा कि अगर एक महिला पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं जबकि अगर एक व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी शिक्षा उस व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहती है। कविता जैन जी के यहां सोनीपत में एक महिला विश्वविद्यालय बनाया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले महिला मैडीकल कॉलेज का लोकार्पण करने के लिए 08 मार्च,

2013 को माननीय सोनिया गांधी जी सोनीपत में आ रही हैं। मैं समझता हूं कि महिलाओं की शिक्षा के चहुंमुखी विकास के लिए इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इसमें 100 एम.बी.बी.एस. की सीटों का कोटा हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र के अंदर नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिफैंस की स्थापना की गई है। रोहतक के अंदर जो मैडीकल कॉलेज था उसको मैडीकल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। इसके साथ-साथ आई.आई.सी.टी. की झज्जर के अंदर स्थापना की जा रही है। इसके अलावा झज्जर जिले में आई.आई.टी. रिसर्च की स्थापना की जा रही है। आई.आई.एम. को रोहतक में बनाया जा रहा है। हिसार के अंदर एक वैटनरी कॉलेज था जिसको वैटनरी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सबसे हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा जगत के अंदर हरियाणा को हब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने काम किये हैं। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद के अंदर एक नहीं दूसरा ई.एस.आई.सी. का मैडीकल कॉलेज बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं शिक्षा जगत की सारी बातें बताऊंगा तो मैं समझता हूं कि इससे सदन का बहुत लम्बा समय चला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में चिकित्सा का जिक्र करना चाहूंगा। जब मनुष्य के पास सब चीज़ें आ जाती हैं, शिक्षित हो जाता है, अपनी तरक्की के और आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ लेता है कि शिक्षित होने के बाद मुझे यह-यह काम करना है तो उसके बाद जब कभी भगवान न करे उसको किसी हारी-बीमारी का सामना करना पड़े अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसे भगवान के बाद डॉक्टर ही नज़र आता है। हरियाणा सरकार ने गरीब आदमी के जीवनयापन को ऊंचा करने और सुधारने के लिए जहां बी.पी.एल. परिवारों को 30-30 हजार रुपये तक की मैडीकल सुविधायें मुफ्त प्रदान की हैं। वहीं जो समर्थ लोग हैं और जो अपना अच्छा इलाज कराने में सक्षम हैं उन लोगों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक नहीं बल्कि 4-4 मैडीकल कॉलेजों की स्थापना हरियाणा में की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के साथी इतिहास उठाकर देख लें तो उनको पता चल जायेगा कि आज से आठ साल पहले हरियाणा में कितने मैडीकल कॉलेज थे और कितनी मैडीकल यूनिवर्सिटीज थी। आज के दिन 4 मैडीकल कॉलेज हमारे पास हैं। जैसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, गिरे शरीर तो साथ छोड़ दे छाया, इससे बुरा क्या हो सकता है? इसका ध्यान रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैडीकल कॉलेज खोलकर आम आदमी के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रखने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिला एवं बाल विकास की बात आती है। महिला की भूमिका महान है, मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। कहा भी जाता है कि there is a woman behind every great man. हर महिला की विविध भूमिकाएं रहती हैं। कहीं पर वह मां बन कर आशीर्वाद देती है, कहीं बहन बनकर प्रोत्साहन और साथ देती हैं, कभी पत्नी बन कर धर्म निभाती है, कहीं दोस्त बनकर आपका साथ निभाती है। लेकिन एक बात मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं जिससे पूरा सदन चिंतित है और वह है कन्या भ्रूण हत्या। जहां आज हम देश में नम्बर एक प्रदेश बनने की बात करते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या और सैक्स रेशो की बात आने पर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए यह बात हम सबके लिए चिन्तनीय है और सबको इस बारे में सोचना और विचार करना है। खास तौर पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि जो

[राव दान सिंह]
9 महीने अपने गर्भ में खून से पल्वित और पुष्पित करके अगर उसकी आवाज नहीं सुन सकती तो उनको उसकी आवाज सुननी चाहिए जो उनकी उनके पेट से आवाज देती है :

ओ मां मत प्यार देना, मत दुलार देना,
न सम्पति का अधिकार देना पर मुझे
जन्म से पहले मत मार देना।

इन भावनाओं के साथ जो बात करती हैं तो हम सबको उनका ख्याल रखना है। एक बहन जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। एक शिशु अगर कुपोषण की वजह से जान से चला जाता है तो जीवन में आंखें खोलने से पहले ही बंद हो जाती हैं वह अपने आप ही नहीं जाता बल्कि उस परिवार में निराशा छोड़ कर जाता है। इस सरकार ने उनके पोषण के लिए, उनकी अच्छी दवाईयों के लिए, उनकी अच्छी सुविधाओं के लिए बहुत सारे काम किये हैं। जहां तक कृषि का संबंध है तो यह प्रदेश कृषि पर आधारित प्रदेश है। कहा जाता है कि there is no culture in Haryana except Agriculture. और वह हमने दिखा भी दिया है कि जब अवार्ड की बात की जाती है कि गेहूं सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है तो हरियाणा में होता है। सबसे ज्यादा चावल की एक्सपोर्ट कहां होती है तो वह भी हरियाणा ही है। इस काम के लिए राष्ट्रपति महोदय ने कृषि कर्मण अवार्ड देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किया है। माजरा जी कहेंगे कि इनके हलके में गन्ना सबसे ज्यादा होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने के भाव सबसे ज्यादा देकर किसान का गौरव बढ़ाया है। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : सबसे ज्यादा कहां दिया है?

राव दान सिंह : माजरा जी, अगर हलवाई से दुश्मनी हो तो मिठाई खराब नहीं बतानी चाहिए। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : जब सबसे ज्यादा नहीं है तो कैसे मान लें?

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात आती है, हमारे काबिल दोस्त पंवार साहब बिजली के मामले में अपने आपको एक्सपर्ट मानते हैं, शायद ये वहां पर नौकरी करके आये हैं। हर बिजली की बात पर इनकी टैक्नीकल बातें सामने आती हैं। मैं समझता हूं कि सदन में अच्छी बातें पेश करते हैं तो वह खुशी की बात है, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि तथ्य पर आधारित बात ही कहनी चाहिए, असत्य बात सदन में कही जाये तो वह उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने सत्ता सम्भालने के बाद बिजली के लिए जो प्रयास किये हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। आज हम बिजली पर निर्भर हो चुके हैं, बिना बिजली आज हम कुछ भी नहीं हैं। बिना बिजली तो आज के दिन घरों में मधानी से दूध भी नहीं बिलोया जा सकता। हर व्यक्ति बिजली की सप्लाई पर निर्भर करता है। हरियाणा को बने हुए 40 साल हुए, उन 40 सालों में 2005 तक 1567 मैगावाट बिजली पैदा होती थी और आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने 3700 मैगावाट बिजली बनाने के कारखानों की शुरुआत की है। इसके अलावा फतेहाबाद के गोरखपुर में 2800 मैगावाट न्यूक्लियर पॉवर

के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। आगे के समय को देखते हुए भूटान की अडानी कम्पनी से हमने एक अनुबन्ध किया है और बिजली की कोई कमी नहीं रहने देंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं तो हम बिजली की कमी नहीं रहने देंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेलों की बात है तो हरियाणा की खेल नीति के कारण ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना, अपने प्रांत और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम है हरियाणा की खेल नीति। जब अन्तर्राष्ट्रीय खेल होते थे चाहे ओलम्पिक का हो, चाहे कॉमनवैल्थ का हो, चाहे एशियन गेम्ज हों, और उस समय जब भारत की 121 करोड़ की जनता अंक तालिका की तरफ देखती थी तो शर्म से नीचे मुंह कर लेती थी लेकिन आज हम गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : लेकिन राव इन्द्रजीत जी तो कुछ और ही कह रहे हैं।

राव दान सिंह : सर, सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता। सच्चाई ये है कि 38 में से 22 मैडल हरियाणा ने लिए और 5 गोल्ड मैडल में से 4 मैडल हरियाणा ने लिए। हरियाणा की खेल नीति में कहा है कि पदक लाओ पद पाओ। सरकार की तरफ से अब ओलंपिक गेम्ज में जो गोल्ड मैडल लेकर आएगा उसको सरकार 5 करोड़ रुपये, सिलवर मैडल वाले को 3 करोड़ रुपये और ब्रांज मैडल वाले को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker : No, running commentary, please.

राव दान सिंह : रामेश्वर जी, आपके हलके में तो मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास किया है कि जितना कभी कोई नहीं कर सकता। सब डिविजन बना दी, सब तहसील बना दी, स्टेडियम बना दिया, ऑडिटोरियम बना दिया व अनाज मण्डी बना दी। आपके हलके में तो सी.एम. साहब ने बहुत कुछ दिया है।

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर जी, आप जितनी देर बोले हैं मैं सोचूंगा कि आप बजट पर बोले हैं। ठीक है बोलिए। ये क्या मतलब हुआ? जब मैं कह रहा हूं कि आप बैठिए तो आपको बैठना चाहिए। No, interruption, please. (Interruption). Rameshwar Dayal ji, don't interrupt, please. Rao Sahib, Just ignore him. (Interruption) Dan Singh ji, don't notice him. He is not listening the Chair.

राव दान सिंह : सर, हम तो किसी को छोड़ते नहीं अगर कोई हमें छोड़ कर जाए तो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रदेश की तरक्की की बात है तो जब तक सड़क, रेल और परिवहन व्यवस्थाएं न हों तो मैं समझ सकता हूं कि जो हमने हरियाणा को नं. 1 बनाने का स्वप्न देखा हुआ है वह अधूरा नजर आता है। मैं हरियाणा प्रदेश के इन सम्मानित सदस्यों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र जो राजस्थान के अन्तिम छोर से सटा हुआ है वहां पर एक एक्सप्रैस-वे जो 1700 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा जो कोटपुतली से भिवानी होकर चण्डीगढ़ को जोड़ेगा। इसका आई.बी.आर. सी.एल. कम्पनी के साथ अनुबंध भी हो चुका है और सरकार ने 400 करोड़ रुपये का मुआवजा भी आबंटित कर दिया है। इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। सर, दूसरा एक्सप्रेस-वे 71-बी जो रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक होता हुआ पानीपत को जोड़ेगा इसका काम 85% पूरा हो चुका है। सर, महेन्द्रगढ़ विकास के मामले में जहां पर पहले

[राव दान सिंह]

था आज उससे चार गुना नहीं बल्कि 50 गुना आगे पहुंच चुका है। जब फरीदाबाद को मिनी मानचेस्टर कहा जाता था उस समय गुड़गांव और फरीदाबाद को जोड़ने का कभी प्रोग्राम था क्योंकि उनके रास्ते का जो लिंक रोड़ था वह बहुत बुरी अवस्था में था लेकिन उसको कभी किसी ने ठीक करने की नहीं सोची। अब माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी उसको बी.ओ.टी. बेस पर एक्सप्रैस-वे बनवाएंगे। सोहना से लेकर बल्लभगढ़ को जो जोड़ने का मात्र 15 मिनट का रास्ता है यह रास्ता भी बी.ओ.टी. बेस पर बना दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र से हमारे भाई आफताब जी बैठे हैं इनको पता है कि गुड़गांव से लेकर फिरोजपुर झिरका तक फोर लेन से जोड़ दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please sit down, Naseem Ji, don't interrupt. Let him complete. This is not the culture.

राव दान सिंह : सर, जिस मेवात में कभी रेल का स्वप्न ही देखा जाता था आज उस मेवात में रेल की सीटी बजाने का काम कर दिया गया है। इससे ज्यादा और क्या विकास करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऊपरगामी पुलों का सवाल आता है मुझे याद है कि भाई दीपेन्द्र जी के साथ एक बार हम कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि दान सिंह जी, हमें हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या-क्या करना चाहिए? मैंने उनको एक सुझाव दिया कि एम.पी. महोदय, जब धरती से ऊपर कोई चीज आती है तो सबको नजर आती है लेकिन अगर धरती में सोना गढ़ा हुआ होता है तो हर मनुष्य को इसका एहसास नहीं होता। दिल्ली के अन्दर जो मैट्रो चल रही है तो शायद हमें पता भी न हो कि वह यहां से जा रही है इसलिए अगर यहां पर रोडों का जाल बिछाएंगे, ऊपरगामी पुलों का जाल बिछाएंगे, मैट्रो लेकर आएंगे तो मैं समझता हूं कि दुनिया के लोगों को यह याद रहेगी और वह दिखेगी भी। वह बात आज सच हो रही है। चारों तरफ से रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बल्लभगढ़ तक मैट्रो चलाई जा रही है, दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक मैट्रो चलाई जा रही है, दिल्ली से लेकर बहादुरगढ़ तक मैट्रो चलाई जा रही है। आने वाले समय में दिल्ली से लेकर आपके सोनीपत एजुकेशन सिटी तक मैट्रो चलाई जाएगी। एक और नई रेल लाईन यमुनानगर से वाया नारायणगढ़ होते हुए चण्डीगढ़ तक पहुंचेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इससे ज्यादा तरक्की और विकास के कोई रास्ते हो ही नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योग की बात आती है हमारा हरियाणा प्रदेश हमेशा से ही एक कृषि प्रधान प्रदेश रहा है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को उद्योग से जोड़कर इसकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का और उभारने का बहुत सजग प्रयास किया है। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन उन्होंने एक लक्ष्य अपने सामने रखा था कि हम 200 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे और उस 200 करोड़ के निवेश से 20 लाख लोगों को यहां पर रोजगार देंगे। आज इतिहास साक्षी है कि उसमें से 61 हजार करोड़ रुपया हम हकीकत में निवेश कर चुके हैं और 97 हजार करोड़ का निवेश पाईप लाईन में है। उसके लगने के बाद बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो उद्योग इनके समय में हरियाणा से पलायन कर गये थे आज वे यहां पर रुककर काम कर रहे हैं जिससे यहां

के लोगों को रोजगार मिल रहा है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : राव साहब, महेन्द्रगढ़ से दादरी रोड जो इतना बुरी तरह से खराब है उसको तो ठीक करा लो? जहां चलने से ही पसलियों में दर्द हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंह : अरोड़ा जी, उसके बारे में भी बात हो गई है आप क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हो। आपको सरकार की उपलब्धियों को ध्यान से सुनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि आई.बी.आर.सी.एल. कंपनी के साथ एक अनुबंध हो चुका है। सरकार ने पेड़ों की कटाई के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और जिस दिन ये सारे पेड़ कट जायेंगे हम उनको यह पैसा ट्रांसफर कर देंगे और रोड बनना शुरू हो जायेगा (शोर एवं व्यवधान) दो महीने की तकलीफ और रहेगी। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी, जो तकलीफ उससे आपको आती है, वह आपके साथ-साथ हम सबको भी आती है और मैं भी मानता भी हूं कि it is a national loss. उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है। अध्यक्ष महोदय, आज का समय आई.टी. का है। चारों तरफ से उद्योग तरक्की कर रहे हैं। दुनिया के लोग तरक्की कर रहे हैं। अगर ऐसे माहौल में हम आई.टी. में पीछे रह जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हम आज के दौर में पिछड़े हुए हैं। यह आई.टी. का स्वप्न अगर किसी ने दिखाया था तो वह ऑनरेबल स्वर्गीय राजीव गांधी जी ही थे। उन्होंने 20वीं सदी में रहते हुए भी 21वीं सदी का एक स्वप्न दिखाया था। जब शुरू में कंप्यूटराईजेशन और मोबाईल क्रांति आने की बात हुई थी तो आम आदमी इस बात पर भ्रमित था यह इतना बड़ा देश जो पहले से ही बेरोजगार है अगर यहां पर कंप्यूटराईजेशन हो गया तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जायेगी लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है कि जिस दिन से कंप्यूटराईजेशन का काम शुरू हुआ है तब से न केवल हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि दुनिया में हमारा देश नम्बर एक गिना जाता है। अमेरिका जैसे देश में भी जब टू.के. की प्रॉब्लम आई तो वह हिंदुस्तान की तरफ देख रहा था। अमेरिका की जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कम्पनी है वहां पर 56 प्रतिशत इंजीनियर हिंदुस्तान के ही काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के लोगों ने वहां पर एक बहुत बढ़िया एसैट आई.टी. के माध्यम से ही तैयार किया है। आज शहर से लेकर गांव तक मोबाईल क्रांति का युग शुरू हो चुका है। एक रिक्शा चलाने वाला भाई भी एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले चार बार फोन करके पूछता है कि एक सही सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है? (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : राव साहब, सैंटर में आपकी कांग्रेस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने तो 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का टेलीफोन घोटाला कर दिया था? (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में केवल एक बात ही कहना चाहूंगा कि "अजीब शख्स है जो बोलता न कभी जहां-जहां से गुजरता है वो मुकाम बोलते हैं" (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष : कर्नल रघुबीर जी, अब आप बोलिये।

श्री धर्मपाल ओबरा : स्पीकर सर, जो एक बार बनकर आये हैं उनको भी तो बोलने का मौका दो? (विघ्न)

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, हमें भी बोलने का मौका दीजिये?

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, एक को बोलने के लिए तो मैंने अलाऊ कर ही दिया है और अगर आप भी चाहते हो तो आप भी बोल सकते हैं?

Col. Raghbir Singh (Badhra) : Speaker Sir, I thank you for giving me chance to speak on the Budget for the year 2013-14. Before me, one my fellow member was speaking on Power Sector. It is a very important sector because the agriculture, industry and also every sector depends upon the Power Sector. Speaker Sir, I am going to give certain suggestions and I hope that the Finance Minister would have been here but anyway Hon'ble Finance Minister and other Ministers are here in the House. So, they will definitely note my valuable suggestions and bail out this Power Sector. Speaker Sir, I wish to draw the attention of the House towards un-sustainable state of affairs in the Power Sector that require immediate attention of the Government, lest losses of the DISCOMS leading to loan default, non payments of dues to HVPNL and HPGCL spills over to State Finances. As per Fiscal Responsibility and Budgetary Management (FRBM) Act, the State is required to rein in their fiscal deficit in Financial Year 2011-12 below 3%. But Speaker Sir, in Haryana Fiscal Deficit below 3% is very difficult. (Interruption)

बैठक का समय बढ़ाना

14.00 बजे

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

Col. Raghbir Singh : In Haryana, with Discoms losses, the fiscal deficit would be in excess of 4% *i.e.* without considering Discoms losses the borrowings would be about Rs. 80 billion and with Discoms losses the same amount would be Rs. 105 billion. Hence unless the power sector is turned around swiftly neither the Central Government nor the State Government would have financial means to bail out the sector. (विघ्न) 2013-14 में जो टैरिफ डिस्कॉम प्रपोजल ने रिवेन्यू अप्रूवल के लिए भेजी है उस टैरिफ प्रपोजल में जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए कुछ नहीं किया गया है। उसमें आज के दिन रिवेन्यू गैप 5836.75 करोड़ रुपये दिखाया गया है और उसकी टैरिफ प्रपोजल बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। इसमें जो FSA क्लेम किया गया है 2011-12 के अंदर वह 2446.37 करोड़ रुपये है और उसको रैगुलराइज करने के लिए उसका अमाउंट देखा जाए तो

2343.55 करोड़ रुपये है। वर्ष 2013-14 के अंदर डिस्कॉम ने जो प्रपोजल भेजी है इस पैसे को रिकवर करने के लिए 27 पैसे पर यूनिट के हिसाब से मांगा है उसको हम देखें तो पिछले 2011-12 का जो एफ.एस.ए. है वह 2446.37 करोड़ है और उसको अभी ऐड कर दिया जाए तो दो साल में 48 पैसे रिकवर करने के लिए सजेशन दी गई है लेकिन फाइनैंशियल लौसिज जो इस कंपनी के थे वह 31.3.2012 को 10138 करोड़ रुपये हैं जबकि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वह 2682.37 करोड़ रुपये बनता है इस प्रकार एंटायर नैटवर्क की बहुत ही इरोडेड हालत है। यदि सरकार इस डिस्कॉम को फ्रैश ऐक्टिविटी के अंदर नहीं ले जाती तो सरकार इसको बेलआउट नहीं कर सकेगी। यदि मैं इस बजट के पैरा 118 को आब्जर्व करता हूं तो पाता हूं कि उसके अंदर सरकार यह क्लेम कर रही है कि 1 हजार 68 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन सप्लाई की जबकि 2004 के अंदर 538 लाख यूनिट बिजली सप्लाई होती है। इस क्लेम को भी मैं सही नहीं मानता हूं। यदि आप 2012-13 तक देखें उत्तर हरियाणा में अप्रैल से सितम्बर तक 64 हजार 1 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की गई है, इस दौरान में 183 दिन होते हैं। 183 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यह 350 लाख यूनिट बनता है। यदि दक्षिणी हरियाणा को देखें तो इतना ही 350 से 400 लाख यूनिट होती है तो आपकी जो सप्लाई है वह कुल मिलाकर 700 से 800 लाख यूनिट के करीब बैठती है न कि 1068। इस प्रकार यह एक मिथ है, इसको करैक्ट करने की जरूरत है। इसी हालात के अंदर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 802 लाख यूनिट बिजली दूसरी स्टेट को बेची गई और जिस हिसाब से बिजली खरीदी गई थी उससे 20-30 परसैंट लौस पर बेचा गया है। इस लौस के लिए डिस्कॉम जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? इसकी आपको जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए कि इस लौस का जिम्मेदार कौन होगा? यदि पैरा 120 की हम बात करें तो सरकार उसमें यह क्लेम करती है और क्रेडिट लेती है कि 3712.80 मेगावाट हमने ऐड किया है। इसके अंदर भी मैं मानता हूं कि ये मिसलीडिंग है। यदि हम इसका पूरा हिसाब लगाएं तो स्टेट में माइक्रो और हाइड्रो से जो बिजली आज के दिन बनती है वह 3230.5 मेगावाट बनती है, इसलिए इसको भी करैक्ट करने की जरूरत है। यदि आज हम अंदाजा लगाएं तो 600 मेगावाट क्षमता का यमुनानगर का प्लांट है या 1200 मेगावाट क्षमता का हिसार का प्लांट है जो कि टैक्सपो पावर प्लांट लगाया गया है यदि हम चाइनीज प्लांट्स और उनके इक्विपमैंट्स को देखें तो जो यमुनानगर का प्लांट या उसको 4767.6 मेगावाट बिजली पैदा करनी चाहिए थी, जबकि जनरेशन पैदा की है 3229.8 मेगावाट। इस प्रकार जनरेशन लौस 1237.78 मेगावाट हो गया जबकि वर्ष 2012-13 में सितम्बर महीने तक यमुनानगर प्लांट से कोई बिजली जनरेट नहीं की गई। अगर हम हिसार वाले प्लांट की बात करते हैं जो 1200 मेगावाट का है उसके अन्दर जो बिजली पैदा की गई है वह 3315 मिलियन यूनिट जबकि उस प्लाट से 8935 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जानी चाहिए थी। इस प्रकार हिसार के प्लाट में जो बिजली जनरेशन का लौस हुआ है वह 5620 मिलियन यूनिट है। इस प्लांट को 7200 करोड़ ₹ की लागत से तैयार किया गया है जिसमें से 2160 करोड़ ₹ स्टेट गवर्नमैंट ने इक्विटी के रूप में खर्च किए हैं बाकि का पैसा डिस्कॉम ने खर्च किया है जोकि एच.पी.जी.सी.एल. ने लोंग टर्म ब्याज पर लिया हुआ पैसा है। इस प्रकार से अपने प्लांट में बिजली पैदा न करके दूसरे स्टेट्स से बिजली ज्यादा रेट पर

[कर्नल रघुबीर सिंह]

खरीदकर 2390 करोड़ ₹ का स्टेट के कंज़्यूमर्ज पर एक्स्ट्रा बोझ डाला गया है। राज्य सरकार कहती है कि हमने बिजली परचेज की है उसके बारे में मैं बताता हूं। जो सरकार आज क्लेम कर रही है कि हमने कम मूल्य में बिजली खरीदी है यह बिल्कुल मिथ है। सरकार ने PTC (GMR), PTC (Lanco Babandh), PTC (Lanco Amarkantak), Lanco Budhil, J.P. Karcham Wangtoo आदि से जो कान्ट्रैक्ट किया है ये सारे कान्ट्रैक्ट्स फिलहाल लिटीगेशन में हैं। आज भी इन कम्पनियों से हरियाणा को एक भी यूनिट बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। अगर कुछ कम्पनियां बिजली बना भी रही हैं तो वे दूसरी स्टेट्स को बेच रही हैं न कि हरियाणा को बिजली दी जा रही है। यदि बजट का पैरा 123 की हम बात करें तो उसमें सरकार यह क्रेडिट ले रही है कि एग्रीकल्चर पम्प सैट्स पर 5129.13 करोड़ ₹ की सब्सिडी दी गई है। इस बात पर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 31 मार्च 2012 को 1333 करोड़ ₹ की सब्सिडी आऊटस्टैंडिंग थी जोकि डिस्कॉम कम्पनी को देनी चाहिए थी। जोकि आज तक नहीं दी गई है। अगर यह सब्सिडी लगातार नहीं दी जायेगी तो यह डिस्कॉम को लैप्स हो जायेगी। आगे अगर हम वर्ष 2013-14 की बात करें तो जो वित्त मंत्री जी ने ईयर मार्क किए हैं वे 4260.25 करोड़ ₹ की सब्सिडी है। इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में जो सब्सिडी की रिक्वायरमैंट है वह 3974.64 करोड़ ₹ की बनती है। इसमें अगर दस प्रतिशत बिजली ज्यादा दी जायेगी तो इसकी सब्सिडी 4371 करोड़ ₹ बनती है। अगर 1333 करोड़ ₹ की सब्सिडी जोकि पहले ही बकाया है वह इसमें जोड़ दी जाए तो कुल सब्सिडी 5704 करोड़ ₹ बनती है। अगर इससे आगे 35 प्रतिशत फ्यूल चार्ज जो डिस्कॉम कम्पनी ने क्लेम किया है अगर इस फ्यूल चार्ज को भी जोड़ लेते हैं तो यह सब्सिडी 6560 करोड़ ₹ हो जाती है। अगर समय रहते इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आप पॉवर सैक्टर को बेल आऊट नहीं कर पाओगे। अगर हम बजट के पैरा 124 के बारे में बात करें जिसमें राज्य सरकार ने यह कहा है कि पॉवर सैक्टर को बेल आऊट करने के लिए हरियाणा सरकार भारत सरकार के वित्तीय रि-स्ट्रैक्चरिंग प्रोग्राम को ज्वॉयन कर रही है तो यह भी एक आई वॉश है। अगर हम डिस्कॉम का वित्तीय घाटा देखें तो वह आज के दिन 18125 करोड़ ₹ है। अगर यह एक अच्छी वित्तीय स्थिति होती तो अपने पड़ोसी राज्य पंजाब द्वारा आज के दिन एफ.आर.पी. रिजैक्ट नहीं की गई होती। पंजाब ने यह इसलिए रिजैक्ट कर दी है क्योंकि उसने यह कहा है कि ये सोशल सैक्टर जैसे कि हैल्थ, एजुकेशन, रोडज आदि में करने के लिए वॉयबल नहीं है। इन्हीं कारणों से हमारे पड़ोसी राज्य ने यह एफ.आर.पी. रिजैक्ट कर दी है। एफ.आर.पी. इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको वर्ल्ड बैंक ने कर्जा देने से मना कर दिया था ताकि डिस्कॉम वगैरह इनसे लोन ले सकें और लोन ले कर ये कन्टीन्यू कर सकें। परन्तु इनसे भी आप दो या तीन साल के लिए लोन ले सकते हैं उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं माननीय साथियों को बताना चाहता हूं आज वित्त मंत्री जी ने पॉवर सैक्टर के लिए जो बजट में एलोकेशन की है। (विघ्न) माननीय वित्त मंत्री जी ने पॉवर सैक्टर के लिए 5239.97 करोड़ ₹ की जो एलोकेशन की है इस बजट को अगर इन्क्रीज करके दस हजार करोड़ ₹ तक ले जायेंगे तभी सरकार इस सैक्टर को बेल आऊट कर सकती

है। जहां तक मेरे विधानसभा क्षेत्र बाढ़ड़ा के विकास की बात है। सरकार ने कहा है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में समान विकास किया जा रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में विकास हो रहा होगा लेकिन जब से मैं विधान सभा क्षेत्र बाढ़ड़ा से एम.एल.ए. बन कर आया हूं, तब से लेकर आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कोई सड़क नहीं बनाई गई है, कोई माइनर नहीं बनाया गया है, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है और कोई कॉलेज नहीं बनाया गया है। मैंने किसी भी प्रोजैक्ट को बनाने के लिए डिमाण्ड की है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव रहा है। इससे मुझे नहीं लगता कि राज्य में जो समान विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं वह ठीक हैं, यह नहीं पता कि कहां पर विकास हो रहा है लेकिन मेरे हल्के बाढ़ड़ा के अन्दर पिछले साढ़े तीन सालों से एक भी चीज का कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। सड़कें सारी की सारी टूटी पड़ी हैं।

सदन का स्थगन

Mr. Speaker : Thank you, Hon'ble Members, now the House is adjourned for lunch for 30 minutes.

(The Sabha then adjourned at 2.10 P.M. and re-assembled at 2.40 P.M.)

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Before I invite an Hon'ble Member to speak on Budget Estimates, I would like to inform you that I want to terminate the discussion on Budget Estimates at 4.00 P.M. so that the Hon'ble Finance Minister can give his reply and the rest of the legislative work following the Budget Estimates can be undertaken.

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, 2013-14 का बजट इस सदन में रखा गया है। जिस प्रांत ने पिछले साढ़े 7-8 वर्षों के दौरान अनप्रैसीडैंटिड तरक्की की है लेकिन सबसे बड़ी एक विडम्बना सी लगती है कि जो प्रतिपक्ष है उसको हरियाणा प्रांत की तरक्की गले से नहीं उतर रही या फिर ये प्रांत की तरक्की नहीं चाहते तभी तो धन्यवाद नहीं करते। When it is a progressive State then it is natural that the economic condition and situation of the State have been counted for that. कोई प्रदेश इतनी ऊंचाईयों को छू रहा हो और सब जगह उसका नाम हो तो यह ऐसे नहीं बनता बल्कि उसकी इक्नोमिक कंडीशन देखी जाती है और बजट का हिस्सा उसका मेजर पार्ट होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पॉवर सैक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत सी डिफरैंट डिफरैंट अनट्रयू फीगर्ज यहां रखे जाते हैं परन्तु जो एडमिटिड फैक्ट्स हैं उसके लिए कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है कि वर्ष 2004-05 के अंदर इस प्रांत की कितनी पॉवर जनरेशन की कैपेसिटी थी। उस समय हम अपनी कितनी पॉवर जनरेट करते थे और कितनी पॉवर बाहर

[श्री भारत भूषण बतरा]

से आती थी। उस समय 4033.30 मैगावाट की कैपेसिटी हमारी थी और आज के दिन में जो हमारी कैपेसिटी है वह 9786.46 है और यह रिकॉर्ड है। इस दौरान हमारी पॉवर प्रोडैक्शन बहुत बढ़ी है। हमारी कोई फैक्ट्री, कोई पॉवर प्लांट या कोई और प्लांट 5 दिन के लिए ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये उसका एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। साढ़े सात साल के अंदर पॉवर की डिमांड कितनी बढ़ी है इसको सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि 83 परसैंट हमारी डिमांड बढ़ी है। इस स्टेट के अंदर पॉवर क्राइसिस तो नहीं हैं। यमुनानगर के पॉवर प्लांट की बात आती है और उसमें किसी एक मशीनरी का कोई स्नैग्स है तो ये तीन साल से उसी मशीनरी के स्नैग पर प्वायंट आउट करेंगे। पॉवर में self-sufficiency होकर हम कहां तक पहुंच गए हैं, कितने हमारे एफर्टस हैं और कितनी हमने पॉवर में प्रोग्रैस की है और कितने हमने थर्मल पॉवर प्लांट्स लगाए हैं इस बात का ये लोग क्रेडिट नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि 6.7.2012 को हमारी 5832 मैगावाट की रिकॉर्ड प्रोडैक्शन थी और उस दिन डिमांड 6780 यानि 85 प्रतिशत हाईयस्ट रिक्वायरमैंट थी जो कि हमारे प्रांत में पूरी थी। आज के दिन हमारी पॉवर की प्रोडैक्शन 4412 मेगावाट रिकॉर्ड पर है। सिर्फ टैक्नीकल्टीज देखना और बात करना अधिकारियों का काम है। हमारे सामने यह मकसद है कि किसानों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और प्रदेश के आम आदमियों को बिजली की पूरी सप्लाई मिले। विपक्ष के साथी जो बिजली की चोरी होती है या लोग बिल नहीं भरते उस बारे नहीं सोचते। कुण्डी लगाकर बिजली की चोरी होती है। ये लोग नारे लगाते थे कि बिजली के बिल मत भरो जिसकी वजह से आगे आने वाली सरकारों को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा रहा है। यदि आज के दिन प्रदेश में लाईन लोसिज और बिजली की चोरी न हो तो स्टेट में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्री यहां बैठे हुए हैं उनको मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि बिजली की प्रोडैक्शन बढ़िया है लेकिन बिजली में थैफ्ट के रैगूलेशंज को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। आज एक जे.ई. या एस.डी.ओ. बिजली के थैफ्ट को चैक करने जाता है और उसके बाद वह जो कुछ करता है उसकी कहीं कोई अपील या दलील नहीं है। यह बहुत अन जस्टिस की बात है और इससे आम आदमी पीड़ित है। बिजली चोरी के पूरे रैगूलेशन को स्टैडी करना चाहिए। मैं मानता हूं कि चोरी पकड़ना ठीक है परन्तु प्रजातंत्र के अंदर परि रैमेडी होनी चाहिए। बगैर सुने किसी को थोड़ी ही फांसी दे देंगे। जे.ई. चोरी पकड़ने के लिए जाते हैं उनका इनसैंटिव रखा हुआ है जिसके लालच में वे ज्यादा से ज्यादा लोड दिखा देते हैं। मैं कैप्टन साहब से गुजारिश करूंगा कि आफिशियल लैवल पर जो रिक्वीजेशन है इसको बकायदा अवल्यूवेशन करवायें। उसमें कंज़ूमर को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। लोड वैरीफिकेशन के बाद में किसी अधिकारी से वैरीफाई भी करवाने चाहिए लेकिन आज इसमें कहीं कोई सुनवाई की गुंजाइश नहीं है। यह मैटर बड़ा गंभीर है और हर नागरिक के हक में जाता है इसलिए इस पर मंत्री जी विचार करें। अध्यक्ष महोदय,

अब रिसोर्सिज मोबलाईजेशन की बात आती है। (विघ्न) हमारी सोच है कि आम आदमी को, किसान को, व्यापारी को और उद्योगों को सही रेट पर बिजली मिलती रहे और इस समय सरकार सही बिजली उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ-साथ बिजली की प्रोडैक्शन भी हो रही है इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी इतनी बढ़ी प्रोडैक्शन कभी सोच नहीं सकते थे यदि इतने पावर प्लांट हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं लगवाते। ये लोग इस बात का क्रेडिट भी नहीं देते हैं। सोचना चाहिए कि इनको आज बिजली कहां से मिल रही है। (Interruption) I am speaking according to the record. अध्यक्ष महोदय, जो पंवार साहब ने रिकार्ड रखा है उससे 2-4 मेगावाट का फर्क हो सकता है यह भी मैं एडमिट करता हूं। (विघ्न) मैंने आपका नाम नहीं लिया। यह तो मैं रिकार्ड की बात बता रहा हूं। I do not need any explanation from you. स्पीकर सर जब कोई प्रान्त तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके सभी क्षेत्रों में विकास होता है। मैं रिसोर्स मोबलाईजेशन की बात करना चाहता हूं। सर, वर्ष 2007-12 के पंचवर्षीय प्लान के अंदर जब स्टेट की ओन रोड रिसोर्स मोबलाईजेशन की बात आती है। अगर हम इससे संबंधित आंकड़ों को उठाकर देखें तो हम पायेंगे कि जो हमारे रिसोर्सिज हैं उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश सबसे ऊपर है और 192.1 परसैंट हमने रिसोर्सिज मोबलाईजेशन की है। चाहे हम हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश से हरियाणा का कम्पैरीजन कर लें हमारा रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन रेट सबसे ज्यादा मिलेगा। सर, भाजपा के माननीय सदस्य यहां पर हर मामले में गुजरात का जिक्र करते हैं इसलिए मैं भी इस मामले में गुजरात का जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर 95.6 परसैंट रिसोर्सिज मोबलाईजेशन है। देश के बाकी प्रदेशों जैसे कर्नाटक इत्यादि की भी हमसे बहुत कम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिसोर्स मोबलाईजेशन हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश की हमसे ज्यादा नहीं है। अगर रिसोर्स मोबलाईजेशन की हम बात करें तो it is the maximum resource mobilization. स्पीकर सर, हमारे आदरणीय फाईनैंस मिनिस्टर श्री चट्ठा ने जो बजट पेश किया है वह बहुत अच्छा बजट है। हमारे विपक्ष के साथी यहां पर यह जिक्र कर रहे थे कि सरकार ने बजट में अनावश्यक रूप से यहां खर्च का प्रावधान कर दिया, वहां खर्च का प्रावधान कर दिया और बजट का ज्यादातर कर्जे के इंट्रेस्ट में चला गया, जैसे स्टेट बैंक के कर्जे में चला गया और ऐसे ही और भी बहुत कुछ उनके द्वारा यहां पर कहा गया है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह इस बारे में कभी केलकूलेशन तो करके देखें। अगर वे इसकी केलकूलेशन करके देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि रिकॉर्ड में वास्तव में क्या है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य इस बजट को सिर्फ अपोज़ करने के लिए अपोज कर रहे हैं। जो हमारे ऑनरेबल फाईनैंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है अगर उसमें टोटल केलकूलेशन की जाये तो हम पायेंगे कि इसमें 70.67 परसैंट हमारे जनरल डवैल्पमैंट और जनरल आवश्यक सेवाओं के ऊपर खर्च होगा। इससे फालतू किसी भी हालत में खर्च नहीं होगा। इसके अलावा जहां तक कर्जे के इंट्रेस्ट की पेमैंट और गवर्नमैंट के लोन की पेमैंट की बात है उस पर बजट का मात्र 29.33 परसैंट ही खर्च होगा। चाहे वह

[श्री भारत भूषण बतरा]

स्टेट बैंक के लोन की बात हो या फिर गवर्नमेंट के लोन की बात हो। चाहे नाबार्ड की बात हो या फिर मार्किट लोन की ही बात हो या एन.सी.आर.एफ. की बात हो, चाहे वेज एण्ड मीन्ज की बात हो इन सब मदों पर बजट का केवल मात्र 29.33 परसैंट ही खर्च होगा लेकिन विपक्ष के साथी कह देते हैं कि बजट का 65 परसैंट हिस्सा अनावश्यक रूप से खर्च हो जायेगा और उससे कोई डवैल्पमैंट नहीं होगी। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी बजट के दो इम्पोर्टैंट फैक्टर्ज होते हैं। एक प्लान साईड और दूसरा नॉन प्लान साईड। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पंचवर्षीय प्लान के अंदर जो प्रोग्रैस की ओवरऑल डवैल्पमैंट की बात है, सभी प्रोजैक्ट्स की बात है। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और रिफार्म्स की बात है। मैं समझता हूं कि एक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नॉन प्लान बजट का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है जितना कि प्लान बजट का। आज टीचर्ज की सर्विस को देखें, डॉक्टर्ज की सर्विसिज़ को देखें और पुलिस वालों की सर्विसिज़ को देखें। इसके अलावा हमारे दुनिया भर के कारपोरेशंज और दूसरी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं इन सबमें जो पैसा खर्च होता है वह लोगों को मूलभूत और आधारभूत सुविधायें देने के लिए होता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक भी है। अगर ये सब नॉन प्लान में से खर्च होता है तो फिर हम प्लान की बात करेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नॉन प्लान का भी उतना ही इम्पोर्टैंट रोल है जितना कि प्लान बजट का। (विघ्न)

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in the V.V.I.P. Gallery, we have Dr. Charanjeet Singh Atwal, Hon'ble Speaker, Pubjab Vidhan Sabha. We also have Shri Harbans Lal Kapoor, Ex-Speaker, Uttrakhand Vidhan Sabha and his son. On behalf of Haryana Vidhan Sabha, I welcome them.

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, we stopped comparing with the rule of INLD. We stopped now that what they did in their rule. अब तो हम डैटाज़ की प्रोग्रैस में वर्ष 2005 के बाद अपने ही राज से कम्पैरीज़न करते हैं। हम यह कम्पैरीज़न करते हैं कि हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे कितनी प्रोग्रैस कर रहे हैं। जब टोटल बजट की बात आती है तो वर्ष 2011-12 के अंदर हमारे प्रान्त का कुल 43025.70 करोड़ रुपये का बजट था जिसमें प्लान और नॉन प्लान दोनों प्रकार का बजट था। इसमें प्लान बजट 12510 था। अकार्डिंगली जब वर्ष 2012-13 आया इसके अंदर जो प्लान बजट था that was 56962.11 करोड़ रुपये और इसके अंदर फिर नॉन प्लान बजट था जबकि वर्ष 2004-05 में यह बजट सिर्फ 2200 करोड़ रुपये ही था। आज के दिन हम प्लान की बात करें तो वह 20352 करोड़ रुपये है। It is 10 times, and

they don't give the credit. इस सरकार के समय में कितने रिसोर्सिज़ बढ़े हैं और कितना हमारा सेल्स टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है और हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जिज़ भी आ रहे हैं। इस प्रकार के जो दूसरे चार्जिज हैं वे भी आ रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथी इस बात का सरकार को कोई भी क्रेडिट नहीं देते हैं। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : बतरा जी, आपकी सरकार ने VAT हटाने की भी बात की थी आप VAT को कब हटवा रहे हो।

श्री भारत भूषण बतरा : अरोड़ा जी, VAT हटाने की बात नहीं है। VAT के बाद हम G.S.T. भी लायेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा साहब, आप कन्कन्यूड कीजिए।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर फिस्कल डेफिसिट की बात की जाती है। पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी नॉर्म्स को मिलाकर फिस्कल डेफिसिट 2.2 परसैंट है। इसी प्रकार से शिक्षा की बात आई। शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमने शिक्षा के लिए टोटल बजट का 14.77% एलोकेट किया है। प्लान और नॉन प्लान सैक्टर में 9118.68 करोड़ रुपये है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि जिस प्रदेश में शिक्षा का विस्तार होगा उस प्रदेश में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता अच्छी होगी और वह प्रान्त सबसे आगे जायेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के लिए इस बजट में सबसे ज्यादा ऐलोकेशन की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा में चार-चार मैडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली गई हैं और अगर मैं उनके नाम भी गिनाने लग गया तो मेरा सारा टाईम खत्म हो जायेगा। शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं मैं दो सुझाव उनको अवश्य देना चाहूंगा। पहला सुझाव है कि जो प्राईवेट यूनिवर्सिटी बिल और एक्ट है उसमें कोई ऐसा प्रावधान किया जाये जिससे इनके ऊपर कोई चैक लग सके। If you will not give the Government full teeth तो शिक्षा की गुणवत्ता आगे नहीं बढ़ेगी। इनकी अपनी यूनिवर्सिटी हैं और ये सब काम अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए इनके ऊपर कुछ लगाम लगाई जानी चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है, यहां पर कई माननीय साथियों ने भी जिक्र किया था मैं अपने आपको भी उससे जोड़ता हूं कि 'असर' की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाये जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा सके। माननीय मंत्री जी उसमें देख लें आर.टी.ई. (Right to Education) में हरियाणा में क्या-क्या करने की जरूरत है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमैंट की है कि इस बार के बजट में साढे तीन लाख एफोरडेबल हाउसिज बनायेंगे तथा उसके लिए 350 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है जो बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से जो लाभार्थी इस दायरे में आते हैं अगर वह 100 गज के प्लॉट में मकान बनायेगा उसको हरियाणा सरकार की तरफ से 87 हजार रुपये की ग्रांट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से हमारे विपक्ष के साथी डैट की बात कर रहे थे इस बारे में एक हरियाणवी कहावत है कि जमींदार तो तगड़ा वही होता है जिसके सिर पर ज्यादा कर्जा हुआ करता है। इस बात का सबको पता है। स्टेट के सिर पर कर्जा है लेकिन सभी काम अच्छी तरह से चल रहे हैं। प्रांत भी अच्छा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज हैं। आज गुड़गांव को देखो तो सिंगापुर ऑफ इंडिया की बात कही जाती है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जमींदार तो तगड़ा वही होता है जिस पर कर्जा होता है लेकिन मैं बतरा साहब को बताना चाहता हूं कि जिसके सिर पर कर्जा ज्यादा होता है उसकी धरती बिक जाया करती है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting of the House be extended for one hour.

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : O.K. The time of the Sitting of the House is extended for one hour.

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, खास वही होता है जिस पर कर्जा होता है और उसकी धरती बिका करती है।

श्री भारत भूषण बतरा : सर, जो काम नहीं करते उनकी बिकती होगी। चलो कोई बात नहीं अगर इस तरह बहस करेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा जिसकी स्पीकर सर इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर सर, अगर मैं डाटाज में जाऊं तो हमारे साथ में पंजाब प्रदेश है, अगर हम पंजाब प्रदेश के डैट के साथ अपने प्रदेश का डैट कम्पेयर करें तो आप देखेंगे कि हमारे देश का डैट 40% पर है और पंजाब प्रदेश का डैट 60% पर है। पंजाब प्रांत का पिछले साल तक का डैट अब तक बकाया पड़ा है, लेकिन हमारे प्रदेश में एक मैंबर भी यहां खड़ा होकर कहे कि हमारे प्रदेश के अन्दर किसी इम्पलाई को समय पर सैलरी नहीं मिली तब बात है। (शोर एवं व्यवधान) सर, मैं आदर सहित सविनय निवेदन करता हूं कि एक मिनट और रहती है और उसमें मैं अपनी लास्ट लाईन में कहना चाहता हूं कि सैलरीज की बात तो यहां पर आती है जब इम्पलाई रिटायर होता है क्योंकि उस वक्त उसके लिए पैंशन जरूरी है, सैलरी बहुत जरूरी है। सर, इस सरकार में सिक्स्थ पे कमीशन की इम्पलीमैंटेशन देने के बाद भी सैलरीज की रेशो सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ी है। आपकी सरकार के टाईम में रेवैन्यू के हिसाब से सैलरीज की जितनी रेशो थी उससे सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ी है। सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से हमारी सरकार ने इम्पलाईज की सैलरीज में काफी बढ़ोतरी की है लेकिन अगर इनकी सरकार होती तो सरकार का दिवालिया निकल गया होता। इन्हीं शब्दों के साथ स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान) मैं बजट के ऊपर प्रतिक्रिया दूं तो काफी विकास की बात सुनी है और यहां पर काफी बातें आई हैं। मैं एक मिशाल देना चाहूंगा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा कि ऐसा कारीगर लाओ जो छत से इमारत बनाकर नीचे तक लाए। बीरबल ने कहा कि मैं कोशिश करता हूं। दिन फिक्स हो गया, बादशाही भी पहुंच गए, मजदूर भी आ गए, सामान भी आ गया। बादशाह ने बीरबल

को कहा कि कारीगर कहां है। बीरबल अपने पिंजरे लेकर चले गए, सभी आदमी पिंजरों की तरफ देखते रहे। उन्होंने पिंजरे खोले तो कबूतर ऊपर घूमने लगे। बादशाह बोले कारीगर कहां है। बीरबल कहने लगा कि ईंट लाओ गारा लाओ, ईंट लाओ गारा लाओ। सर, इस तरह से विकास का कबूतर तो सभी जगह पहुंच रहा है लेकिन पता नहीं उस विकास ने हमारे जिले की तरफ तो अब तक दर्शन नहीं दिए। अध्यक्ष महोदय, बजट से ये उम्मीद होती है कि बजट विकास का होगा, किसान के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, लेकिन बजट का गहराई से अवलोकन करने से पता चलता है कि कहीं भी विकास की बात नहीं है। इसलिए ये बजट विकासोन्मुख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बजट को टैक्स फ्री बताया गया है। मैं वित मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सदन को अपने जवाब में यह आश्वासन दें कि यह बजट पेश करने के बाद प्रदेश की जनता पर अगले साल कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत खर्च जो है वह 1.56 दिखाया गया है। इससे विकास के इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो पिक्चर पेश की जा रही है वह पूरी नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी पी.पी.पी. यानि पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप पर जा रहे हैं जो प्राइवेट इन्वैस्टमैंट होती है वह अपने फायदे के लिए इन्वैस्ट करते हैं, वह उस का कोई ऑडिट नहीं कराते। अब प्रदेश में टोल टैक्स लगे हुए हैं। वो अपनी मर्जी से आये दिन बढ़ाते हैं जनता के सामने उनकी कभी असलियत नहीं आती है। आज इसकी तरफ भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं खेलों की तरफ सदन का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा। कुश्ती हरियाणा का सबसे प्रिय खेल है। दुर्भाग्य की बात है कि आज कुश्ती को ओलम्पिक खेलों से बाहर किया जा रहा है। प्रदेश के लोगों की कुश्ती से भावनायें जुड़ी हुई हैं। अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ पूरे सदन से अनुरोध है कि एकजुट होकर के कुश्ती को ओलम्पिक में दोबारा से शामिल करवाने के प्रयास किये जायें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो बात हमारे साथी ने अभी कही है उसके बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि पूरा स्टेट आज कुश्ती के खेल को दोबारा से ओलम्पिक में शामिल करवाने के बारे में कंशर्न है। मैं भी इस विषय को लेकर पर्सनली तौर पर कंशर्न हूं। मैंने इस बारे में केन्द्र में खेल मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि वे ओलम्पिक में इस खेल को दोबारा से शामिल करवाने के लिए जितनी लंबी लड़ाई हो लड़े हमारा उनको पूरा समर्थन है। हम कुश्ती को दोबारा से ओलम्पिक में शामिल करवाने के लिए पूरे जोर-शोर से लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि यह हमारा सबसे पुराना और प्रिय खेल है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, इस विषय पर हाउस की तरफ से एक रैजोल्यूशन पास होना चाहिए और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजा जाये।

Mr. Speaker : You want to say that a Resolution of the House in this regard may be sent to the Union Government. All right we will pass it and send to the Union Government.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अगर कुश्ती पर रैजोल्यूशन आयेगा तो हम भी उसका स्वागत करेंगे।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले साथियों ने कर्जे का जिक्र करते हुए कर्जे के बारे में अपने विचार प्रकट किए। बजट में बताया गया है कि 8100 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार से वसूल करने हैं। वित्त मंत्री जी बतायें कि अगर हरियाणा सरकार अपने 8100 करोड़ रुपये जो उन्होंने वसूल करने हैं वो किस कारण से वसूल नहीं हो पाये हैं। अगर यह 8100 करोड़ रुपये वसूल हो जाते हैं तो प्रदेश को कर्जा कम लेना पड़ेगा और विकास की दृष्टि से हम आगे चल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर भी बहुत लंबा विचार-विमर्श किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा सबसे बड़ा विषय बन चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के दो अहम दायित्व हैं। शिक्षा के ऊपर काफी चर्चा हुई लेकिन प्राईमरी से लेकर के कॉलेज लैवल तक शिक्षकों के या नॉन-शिक्षकों के सहायक पदों के लगभग 40000 पद खाली पड़े हैं। मंत्री जी ने बताया था कि भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन 8500 पी.जी.टी. टीचरों के पद ऐसे हैं जो प्रमोशन कोटे से आने हैं लेकिन प्रमोशन न होने के कारण यह पद अभी भरे नहीं जा सके हैं। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन 8500 पी.जी.टी. टीचरों के पदों को भी प्रमोशन के द्वारा जल्दी भरा जाये ताकि इनका भविष्य भी उज्जवल हो सके और ये अच्छी शिक्षा भी दे सकें।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी ने प्रश्न काल में भी इसके बारे में पूछा था। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि जहां कॉलेज लैक्चरर की 14000 से ज्यादा टीचर्ज़ की भर्ती प्रक्रिया चल रही है वही 9800 से ज्यादा की जे.बी.टी. टीचर्ज की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। प्रमोशंज को लेकर इन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं इनकी चिंता को समझ सकती हूं। प्रमोशन की चिंता में इनका कुछ पर्सनल मैटर भी है क्योंकि इनकी वाईफ का भी प्रमोशन इसके अन्दर आता है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरीवश कहना पड़ रहा है। (हंसी) मैं इनको आश्वासन देना चाहती हूं कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया है हम उसको समय रहते अति शीघ्र पूरा करेंगे और साथ ही इनकी वाईफ को उनकी ही च्वॉईस का स्टेशन भी देंगे। (हंसी)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि शायद माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं है कि मेरी पत्नी पी.जी.टी. टीचर पद के लिए योग्य नहीं है। मेरी पत्नी पी.जी.टी. टीचर लैवल में नहीं आती है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : ढुल साहब, आप चिंता न करो उनकी प्रमोशन हो जायेगी।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : दांगी साहब, प्रमोशन होगी या न होगी कोई बात नहीं है, मैं तो नौकरी भी छुड़वा दूंगा? (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : ढुल जी, हम प्रमोशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं और जल्दी ही इन प्रमोशंज को करवा भी देंगे।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हैड मास्टर की प्रमोशन से हाई स्कूलों के टीचर्ज के 1200 पद खाली पड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि इनकी प्रमोशन पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रमोशन चैनल में एक और विसंगति भी है। मान लो कि मैं साईंस मास्टर हूं और मैंने साईंस मास्टर रहते हुए एम.एस.सी. मैथेमैटिक्स कर ली तथा एम.ए. कर ली है तो भी मैं प्रमोशन के लिए लायक नहीं माना जाता हूं जबकि यदि मैं डॉयरेक्ट एम.एस.सी. मैथ करके आता हूं तो प्रमोशन के लायक माना जाऊंगा, यह एक

बहुत बड़ी विसंगति है। माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बैंच ने वर्ष 2006 में यह फैसला दिया है कि there cannot be two sets of qualifications. अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस एनोमली को भी दूर किया जाये ताकि शिक्षकों के साथ अन्याय न हो। सर, मैं अपने हल्के की डिमांड के बारे में कहना चाहूंगा।

Mr. Speaker : Dhull ji, last minute please.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : सर, मुझे बोलते हुए तो अभी 5 मिनट हुए हैं। तीन बजकर 5 मिनट तक तो बतरा जी बोले थे। सदन में आश्वासन दिया गया था कि मेरी बिरोड़ी माईनर बनाई जायेगी और किला जफरगढ़ माईनर की कैपेसिटी भी 34 क्यूसिक्स से बढ़ाकर 54 क्यूसिक्स की जायेगी। आज तीसरा साल शुरू हो चुका है लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सदन में आश्वासन दिया गया था अतः मैं चाहता हूं कि उस पर भी काम जल्द से जल्द हो।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमारे माननीय साथी जो कह रहे हैं उसे कोई भी मिनिस्टर नोट तक भी नहीं कर रहा है?

श्री राम पाल माजरा : विपक्ष की बात को तो कोई सीरियसली ही नहीं लेता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हमने आलरेडी माननीय सदस्य की डिमांड नोट कर ली है, मुझे लगता है कि इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। There are two Ministers who are noting it. अरोड़ा जी, आप प्लीज ध्यान दीजिये, ऐसे एलीगेशन मत लगाईये?

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : स्पीकर सर, मेरे इलाके में जुलाना के अन्दर 2200 से 2500 एकड़ में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का भारी नुक्सान हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां के किसानों को 30 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये ताकि उनकी आगे की भी आशा बनी रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अंदर कुछ सड़कें हैं जैसे नंदगढ़ से लेकर ढिगाना, ढिगाना से पढ़ाना, मैरूखेड़ा से ढिगाना, निदाना से निदानी होते हुए बिरौली। ये सड़कें बना दी जाएं तो लगभग 26 गांवों के किसानों को मंडी जाने के लिए जींद होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, न ही फाटक क्रॉस करना पड़ेगा और न ही जींद शहर क्रॉस करना पड़ेगा। यदि रामराय से बीमरू सड़क बना दी जाए तो हमें डायरैक्ट अनाज मंडी आने के लिए शहर में से नहीं जाना पड़ेगा। इन सड़कों की मैं मांग करता हूं। इन सड़कों के न बनने के कारण जींद शहर पर भारी बोझ पड़ा हुआ है। न वहां बाईपास है और न ही कोई ब्रिज है। अगर ये सड़कें बन जाएं तो अगले 8-10 साल तक शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से बचाया जा सकता है। सर, इसके अलावा मेरे हल्के की कुछ सड़कें हैं जिनके बारे में मैंने पिछली बार के बजट सत्र में मांग उठाई थी और मुझे आश्वासन दिया गया था कि ये सड़कें मार्च, 2013 तक दोबारा से बन जाएंगी। सर, ये सड़कें पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं जैसे घड़वाली से खरेंटी, घड़वाली से खेड़ा बख्ता होते हुए झमोला, गनाड़ा से बराड़, गुनाना से इगरा, सुन्दर बराड़पुर से बराकलां, सामलोंकला से ढिगाना, निदाना से गोहाना रोड, गोहाना रोड से भावरी और इसी तरह से खरक राम जी। इन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, इनको ठीक किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बराड़खेड़ा माइनर बहुत ही पुरानी माइनर है और इसके

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]
आउटलेट जो 1966 में थे वही आज हैं और वहां तीन नई माइनर बना दीं उनमें से एक बुआना सब माइनर है। बड़े अफसोस की बात है कि पांच साल के बाद भी बुआना सब माइनर में एक बूंद भी पानी नहीं गया। अधिकारियों को इस बारे में पता भी है और हमने भी बार-बार कह कर देख लिया लेकिन इसके बावजूद भी बुआना सब माइनर में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से रजबाहा नम्बर 3 जो कि 65 गांवों को इरीगेशन की सुविधा प्रदान करता है लेकिन उस पर धिमाणा, बहबलपुर, बिशनपुरा, अनूपगढ़, सामलोंकला, लदाना और खरकराम जी ये टेल के गांव हैं और इन पर अब तक साल में एक आध बार पानी बारिश के दिनों में ही आता है, वैसे नहीं आता है। मेरा अनुरोध है कि रजबाहा नम्बर 3 की कैपेसिटी बढ़ाकर इसमें पानी दिया जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए। आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मांग और एक निवेदन और रहता है। इसको जरूर सुन लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका भी ध्यान करके उनको पंजाब के बराबर तनख्वाह दी जाए और मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ को भी पंजाब के बराबर तनख्वाह दी जाए। इसके अलावा सभी सदस्यों के लिए मेरी एक मांग है कि जो पैटी ग्रांट हमें दी जाती है उसके लिए पहले यह सिस्टम था कि खर्च करके हम आपको बताते थे। सर, इस पैटी ग्रांट के बारे में कई स्टेट्स में यह नियम है कि इसे तीन हिस्सों में बांटकर मैंबर के अकाउंट में डाल दी जाती है। मैंबर्ज उसकी यू.सी. सबूत के साथ बाकायदा चैक नंबर के साथ दे देते हैं तो अगली ग्रांट उनके खाते में डाली जा सकती है और सारी अव्यवस्था से ही बचा जा सकता है। सर, मेरी इस बारे में प्रार्थना है कि मैंबर्ज के खाते में 1-1 लाख रुपया डाल दें और जब एक लाख रुपया खर्च हो जाए और उसकी यू.सीज. दे दें तो अगला एक लाख रुपया डाल दें। यह मेरा निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार (बादली) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी के द्वारा जो इस सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलने के लिए मुझे जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में प्रधान मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी तथा जननायक विकास पुरुष, 36 बिरादरी के मान सम्मान एवं स्वाभिमान के प्रतीक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में मंत्रीमण्डल ने इस गरिमामय सदन के सदस्यों के सहयोग से यहां पर बजट पेश किया है, इस पर मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी एवं वित्त मंत्री श्री चट्ठा जी को बधाई देता हूं कि ऐसा बजट जो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, अधिकारियों और हर वर्ग को 36 बिरादरी के भाइयों की भावनाओं और हितों का भी ध्यान इस बजट में रखा गया है। समाज के कमजोर वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इस पर गरीबों को आवास देने के लिए ध्यान रखा गया है। दलित भाइयों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। वर्ष 2013-14 के बजट

में प्रिय दर्शनी आवास योजना की एक महत्वाकांक्षी आवास योजना शुरू करने का प्रयास इस योजना में किया है। 100 गज के प्लॉट आबंटित किये हैं और जिनके पास कोई मकान नहीं है या कच्चा मकान है उन सभी गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस वित्त वर्ष में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान दो लाख भवन बनाने का लक्ष्य किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूं और हमारा परिवार पतरा भी देखता है। जन्मपत्री भी बनाता है। मैं बहुत कम पढ़ा-लिखा हूं लेकिन जितने भी पक्ष और विपक्ष के साथियों ने अपने विचार बजट के बारे में सदन में प्रस्तुत किए वे मैंने बड़े ध्यान से सुने हैं क्योंकि आज मैं सदन में बहुत कम बोला हूं। मैंने इस बजट को बड़े ध्यान से पढ़ा है और कोई बात मेरे समझ में नहीं आई तो मैंने अपने साथियों से उस बात को समझा है। मैंने यह पाया है कि इस बजट के माध्यम से माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम किया है और भारत में हरियाणा ने नम्बर एक का अपना स्थान कायम रखा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों की तो जन कल्याणकारी नीतियों में भी विरोध करने की पुरानी आदत है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। ये मेरे बड़े भाई और पिता समान हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को कभी भी मंत्रिमण्डल में शामिल न किया जाए वरना यह हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। ऐसा पहले की सरकारों की परिपाटी के लिहाज से शुरुआत हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को बड़े ध्यान से पढ़ा है यह एक जनकल्याणकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सबल और सफल नेतृत्व और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला बजट और हरियाणा को नम्बर एक के मार्ग को प्रस्तुत करता हुआ दिखाया गया है। जो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ पहले धोखाधड़ी करते थे और झूठे वायदे करके उनके वोट हासिल करते थे वे लोग इस बजट के माध्यम से मुंह की खाते हुए और जनता का खून पीते दिखाई देते थे आज वे दाल पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी सशक्तिकरण अभियान योजना के तहत चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पंचायतों के सशक्तिकरण का काम किया गया है। पूरे प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने का लक्ष्य हासिल किया गया है जिससे ग्रामीण पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, ये लोग ग्रामीण पंचायतों का शोषण करते थे। जनता द्वारा चुनी हुई पंचायतों पर माफिया गिरोह के लोगों को थोपते थे। आज माफिया दल हरियाणा प्रदेश की सत्ता से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी का नेता नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता हूं। मेरी उपलब्धि यह है कि मैं कई बार एम.एल.ए. चुनकर आ रहा हूं। मुझे लोग यह समझते हैं कि ये चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जननायक का वफादार सिपाही है और यही मेरी उपलब्धि है। सोनीपत में नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रिवाड़ी और झज्जर में नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए वर्ष 2013-14 में 16 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह प्रदेश के जनहित में और सफल नेतृत्व का लक्षण है। मुंडका से बहादुरगढ़ तक दिल्ली मैट्रो का विस्तार जिसकी लम्बाई 11.182 किलोमीटर है और लागत 1991 करोड़ रुपये है। दो फरवरी, 2013 को यह स्वीकृत किया गया। हरियाणा सरकार मार्च 2016 तक

[श्री नरेश कुमार]

पूरी होने वाली इस परियोजना के लिए 787.96 करोड़ रुपये की राशि का योगदान करेगी। इस बजट से मुझे चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की अगली भावना दिखाई दी और मैं बेताबी से इंतजार कर रहा हूं कि कब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मैट्रो में बैठकर वाया बादली झज्जर जाएंगे और लाखों की संख्या में हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यह चीज आने वाले समय में स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा है और 2010-11 के लिए गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता हासिल करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया है। किसान का बेटा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अवार्ड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो साथी जनता के साथ कुठाराघात करते थे और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, और जनता की भावनाओं को कुचल देते थे, उनके तो बनाए हुए बोर्ड राष्ट्रपति द्वारा भंग करते हुए मुझे दिखाई दिए। केन्द्रीय खाद्यान भण्डारण में 60 प्रतिशत निर्यात बासमती का अकेले हरियाणा प्रदेश से हो रहा है जोकि प्रदेश को एक नम्बर पर कायम रखने का मुख्य स्रोत है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से किसानों को फायदा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के गन्ने के भाव 45 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाये हैं जोकि किसान हित में उठाया गया जनहित का कार्य है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं बड़े हर्ष के साथ सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा एक नौजवान साथी जो रोहतक लोक सभा का एम.पी. के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं उनके सफल और अथक प्रयासों से गांव बाढ़सा, झज्जर में एम्ज बना दिखाई दिया जोकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर राज्य का मुख्यमंत्री और नेता चाहता है कि उनके राज्य में एम्ज बनें लेकिन हमारे कर्मयोगी चौधरी दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिलती दिखाई दी है। जबकि एक समय कुछ ऐसे लोगों की सत्ता थी जो जनहित के बारे में सोचते ही नहीं थे और हरियाणा प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करने की आदत हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, आज जहां हमें यह मैडीकल इंस्टीच्यूट बनता दिखाई दे रहा है उसी जमीन के साथ वे लोग डीजनी लैंड कसीनो बनाना चाहते थे। यदि वहां कैसीनो बन जाता तो क्लब बनता जिसमें शराब माफिया सक्रिय होता और कुछ पार्टियों का माफिया भी सक्रिय हो जाता और वहां पर संसार का सबसे बड़ा जूवे का अड्डा बन जाता। जहां चरित्रहीनता का प्रदर्शन होता। मुझे इस बजट के माध्यम से जहां कुछ लोग चरित्रहीनता का नंगा नाच करना चाहते थे वे भागते नजर आ रहे हैं और जनता द्वारा फिर से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट 36 बिरादरी का बजट है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please wind up.

श्री नरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है (विघ्न) लेकिन मैं आपके आदेशों की पालना करूंगा। मैं कह रहा था कि एम्स-2 नई दिल्ली के विस्तार के लिए गांव बाढ़सा, झज्जर में 300 एकड़ जमीन आबंटित की है जिसकी आउटडोर ओ.पी.डी. 20 करोड़ रुपये की लागत से 24 नवम्बर, 2012 को शुरू हो गई है। स्पीकर सर, 1800 करोड़ रुपये की लागत से 600 बिस्तरों वाला कैंसर संस्थान स्थापित करने

के बारे में सरकार के स्तर पर सक्रियता से विचार-विमर्श हो रहा है। मैं आपके माध्यम से विकास पुरुष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि मेरे गांव बादली में फुटबाल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुए हैं और इस समय भी बादली गांव के 3-4 खिलाड़ी खेलने गये हुए हैं इसलिए मेरे गांव बादली में फुटबाल अकादमी खोलने की बहुत सख्त जरूरत है। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि मेरे गांव में फुटबाल अकादमी शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करवाने का कष्ट करें। सर, इसके अलावा मेरी एक और डिमाण्ड है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए फरूखनगर तक रेल लाईन जाती है। वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रोज़ाना ही बड़े-बड़े इतिहास रचते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस रेलवे लाईन को फरूखनगर से वाया बादली झज्जर तक बढ़ा दिया जाये तो इससे भिवानी तक के नागरिकों को लाभ मिल सकता है। हमारा यह भी विश्वास है कि हुड्डा साहब मैट्रो रेल सेवा भी दिल्ली से बादली तक अवश्य लायेंगे और जब हुड्डा साहब उसमें बैठकर बादली आयेंगे तो उस समय हमारे हल्के की जनता लाखों की संख्या में उनका दिल से स्वागत करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने गांव-गांव में घूमकर जो जन भावनायें देखी हैं उनके आधार पर मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बात 100 परसैंट निश्चित और सुनिश्चित है। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझसे जाने-अनजाने में कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। इसके साथ ही आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री गंगा राम (पटौदी) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट को पढ़ने और देखने से पता चला है कि यह बजट दिशाहीन होने के साथ-साथ निराशाजनक भी है। स्पीकर सर, किसी भी प्रदेश के बजट से लोगों द्वारा यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह 100 परसैंट जनता के हक में होगा क्योंकि बजट को बनाते समय हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाता है और बजट में यह कोशिश निहित होती है कि वह प्रदेश की सारी जनता के लिए सुख और सुविधाओं के साथ रोजगारपरक भी होगा लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस बजट में महंगाई को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा वर्ष 2005 के बाद से प्रदेश का कर्ज 45000 करोड़ रुपये से बढ़कर 68000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस प्रकार से प्रदेश का प्रत्येक आदमी 27000 का कर्ज़दार है। कमज़ोर वर्ग के लोगों के विकास का जहां तक संबंध है। देहातों में अनुसूचित जाति की कालोनियों में तो कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास के बड़े-बड़े दावे महज़ दिखावा और बहकावा हैं। 100-100 वर्ग गज के प्लॉट नहीं तो फिर मकान कहां? जहां तक कृषि का सवाल है। कृषि उत्पादन में हरियाणा को नम्बर एक प्रदेश बताया गया है और फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन भी बताया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन कहां से होगा जब प्रदेश में किसानों को समय पर न तो पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, न ही सही खाद व बीज़ मिलते हैं और न ही दवाईयां मिलती हैं। यह बात स्वयं सरकार ने भी मानी है कि हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब पानी की कमी है तो फिर सिंचाई कहां से होगी और अगर सिंचाई ही नहीं तो फसलों

[श्री गंगा राम]
का रिकॉर्ड उत्पादन कहां से होगा। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जो गुड़गांव जिले में ट्यूबवैल्ज के माध्यम से फसलों को पानी दिया जाता था सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी है जिससे फसलों का उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है और जो किसान अपना खून-पसीना बहाकर कुछ फसल पैदा कर भी लेता है तो उसको उस फसल का भी उचित मूल्य नहीं मिलता है। जहां तक शिक्षा के स्तर की बात है वह भी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि आज ज्यादातर बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वह प्राईवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता इसलिए गवर्नमैंट स्कूलों में छात्रों की संख्या भी निरंतर घटती जा रही है। इसी कारणवश स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है तो हरियाणा में स्वास्थ्य के मामले में बहुत बुरा हाल है। हॉस्पीटल्स में स्टाफ की बहुत कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भौड़ाकलां गांव है जहां पर लगभग 40 साल पहले से सी.एच.सी. बनी हुई है लेकिन पी.एच.सी. ही वहां पर कार्य कर रही है। वहां पर एस.एम.ओ. की सीट है लेकिन एस.एम.ओ. पटौदी में बैठते हैं। अध्यक्ष महोदय, सड़कों का जहां तक सवाल है मेरे क्षेत्र में बार-बार विधान सभा में प्रश्न लगाने के बाद भी सड़कों का बुरा हाल है। रोजाना के एक्सीडैंट्स से बचने के लिए लोग कच्चे रास्ते पर चलना ज्यादा उचित समझते हैं। इसी तरह से कानून व्यवस्था के बारे में सभी जानते हैं कि कैसी कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में है। हर दिन कोई न कोई नया कांड हो जाता है। जहां तक युवाओं का सवाल है और रोजगार का सवाल है तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उनके साथ धोखा है इसलिए इस बजट में रोजगार देने का भी कोई प्रावधान किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुये हैं उस तरफ भी ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे बजट पर बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी सरकार का जो 9वां बजट पेश किया है यह एक बहुत ही प्रगतिशील और हर वर्ग की भलाई के लिए हर तरह से प्रदेश की वैभूति के लिए जिसे हम कह सकते हैं आइडियल और डायनामिक बजट पेश किया है। यह तो एक रीत है कि विरोधी कहीं भी हों वह अच्छे को बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि आज हरियाणा प्रदेश का मानचित्र दर्शाता है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश ने आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में हर फील्ड में तरक्की की है और प्रदेश की उन्नति, मान-सम्मान और इज्जत पाई है वह किसी से छिपी नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान के मानचित्र पर सबसे ऊपर उभरकर आया है मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रदेश का बजट पेश किया यह बहुत ही सराहनीय है। 2004 में जहां 2200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था वहीं आज लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस बजट से पता चलता है कि हमारे प्रदेश ने कितनी तरक्की की है। अध्यक्ष महोदय, हर फील्ड में, हर लाईन में जिस तरह से कार्य

प्रगति पर आकर इस प्रदेश का नाम उभरा है, वह सराहनीय है। उसके साथ-साथ मैं ज्यादा लम्बी बात न करते हुए न आंकड़ों में जाकर एक ही बात कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने और विरोधी पार्टियों ने भी बजट पर और आंकड़ों पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा पर बोलना चाहता हूं। शिक्षा ऐसी चीज है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है और कहा भी जाता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं भाषण देते हैं तो यही बात कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है। भविष्य खाली बातों से नहीं बनता। आज हरियाणा प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो शिक्षा का सिस्टम है मेरी राय उससे अलग है। शिक्षा के बारे में हमारी केन्द्रीय सरकार की भी पॉलिसी बनी है लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो शिक्षा का वर्तमान सिस्टम है कि पहली कक्षा से लेकर आठवीं तक न कोई इग्जाम न कोई हाजरी और उन बच्चों को पास कर दिया जाता है, मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। हम मकान बनाते हैं, अगर हमारे मकान की नींव ही ठीक नहीं होगी तो वह मकान ज्यादा दिन तक नहीं चलता। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारी शिक्षा मंत्री जी, जब भी सैंटर में डिपार्टमैंट की मानव संसाधन मंत्री जी के साथ कोई मिटिंग हो तो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये सारी बातें हमारे देहात से जुड़ी हुई हैं। पूरे हिन्दुस्तान की 70% आबादी देहात में रहती है और जो 30% आबादी शहरों में रहती है उसमें भी 10 या 15 प्रतिशत आबादी गांव से शहर में जा कर बसी हुई है। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, मुम्बई है, वे लोग अपने बच्चों को यहां न पढ़ा कर बाहर विदेशों में भेज कर पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी क्षमता होती है। चाहे हम कितनी ही बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटिज में अपने बच्चों को पढ़ाएं लेकिन जो हमारा नीचे का मूलभूत ढांचा है उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमारे बच्चों के भविष्य की जो बात है उसके लिए हम शुरू से ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि हमारे बच्चों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। हम जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी, आपके जमाने में भी जिस वक्त हमने प्राईमरी की शिक्षा ग्रहण की, उस वक्त एक अच्छा सिस्टम था, एक बहुत बढ़िया सिस्टम था। पहली से एग्जाम शुरू होकर लास्ट तक जो बच्चा फेल हो जाता था वह पीछे जाता था। अगर बच्चा पढ़ेगा अच्छा रिजल्ट आएगा तो वह पास होगा और तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन आज इस सिस्टम ने ऐसे हालात बना दिए कि अगर आज कोई भी नौकरी पेशे की बात आती है या कोई सर्विस की एडवरटाइजमैंट होती है तो लाखों की संख्या में हमारे देहाती बच्चे बेलदार की पोस्ट के लिए, चौकीदार की पोस्ट के लिए, कंडक्टर और पटवारी की पोस्ट के लिए, पुलिस भर्ती के लिए फार्म एप्लाई करते हैं इससे आगे हमारे बच्चे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो देहाती एजुकेशन है वह हमारे बच्चों के ऊपर एक किस्म से कुठाराघात करने वाली है। यह मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने प्रदेश में तो इस सिस्टम को ठीक करें। रोजाना क्वैश्चन ऑवर में भी शिक्षा के ऊपर सवाल उठते हैं और हमारी माननीय बहन उनके जवाब भी देती है। शिक्षक भर्ती के बारे में, स्कूलों में स्टाफ देने के बारे में कई तरह की डिफरैंट बातें आती हैं। परसों जैसे एक प्रश्न के जवाब में आया शायद वह श्री रामपाल माजरा जी का सवाल था। एक गांव में 13 टीचर हैं और पढ़ने वाले 13 बच्चे भी नहीं हैं और जहां

[श्री आनन्द सिंह दांगी]
पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां टीचर नहीं हैं। इस सिस्टम को एक बार अच्छी तरह से चैक करके उसके हिसाब से टीचरों की अप्वायंटमैंट देने की आवश्यकता है। ठीक है वह मेरी बहन का गांव हो सकता है उसमें इनको जाना-आना भी पड़ता है, लोगों की शिकायत भी सुननी पड़ती है, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां 13 पोस्टें हैं और वहां 13 की 13 पोस्टें फिलअप कर दी जाएं, और जहां बच्चे हों वहां खाली छोड़ दी जाएं। इसलिए यह एक अच्छे ढ़ंग से पूरे सिस्टम के साथ सारा चैक करके पूरे प्रदेश के सिस्टम को इसकी सैटिंग और एडजैस्टमैंट करने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और एक बढ़िया ढंग से हम अपने बच्चों की नींव बनाकर उनको आगे बढ़ने का रास्ता दें। आज चाहे वह खेल की बात हो, चाहे कोई भी फील्ड की बात है अगर हमारे बच्चे की नींव ठीक से चलेगी तभी वह आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, खेलों में भी आएगा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सिस्टम के अनुसार जो खेल नीति बनाई है और उस खेल नीति से हमारे बच्चों ने हमारे नौ जवान भाईयों ने, साथियों ने, देश का नाम दुनिया में रोशन किया है वह यहीं से शुरू होता है। वह नीचे से शुरू होता है अगर हमारी नींव ठीक नहीं है तो सारा मामला खराब हो जाता है। मैं ज्यादा लम्बी बात न करते हुए यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में सुधार किया जाए ताकि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल) : स्पीकर सर, कुछ रिस्पोंड करना चाहती हूं।

Mr. Speaker : Madam ji, why do you respond when you gave your clarification earlier also.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल : सर, श्री दांगी साहब ने बहुत गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है इसलिए इसकी क्लैरीफिकेशन बहुत जरूरी है। सर, दो मिनट में बताना बहुत जरूरी है कि सम्मानित सदस्य ने शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिन्ता व्यक्त की है। ये चिन्ता का विषय भी है और इसके प्रति सरकार भी बहुत ज्यादा गम्भीर है। शिक्षा का अधिकार का जो कानून बनाया है वह भारत सरकार ने बनाया है और उसके बाद सभी राज्यों को कहा गया कि आप अपने हिसाब से अपनी-अपनी स्टेट्स में शिक्षा के अधिकार के जो रूल्ज हैं वह आप खुद बनाएं। सभी राज्यों ने अपने-अपने रूल्ज बनाए। हरियाणा ने अग्रणी हो कर बनाए और जिस समय ये रूल्ज बनते थे उस समय हमने सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, चिट्ठी लिख कर सारे रूल्ज की कॉपी उनके पास भेजी और अपने वैबसाईट पर भी हमने डाला कि रूल्ज के मुताबिक किसी का भी कोई भी सुझाव हो तो आप उसमें जरूर दें ताकि उसमें हम किसी तरह से और अमैंडमैंट कर पाएं। क्योंकि जो यह शिक्षा का अधिकार कानून है इसकी आज के समय में बहुत जरूरत है। आजादी के इतने साल बाद आज शिक्षा का अधिकार कानून एक डॉयरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक अधिकार बन गया है और अब शिक्षा देना सरकारों की जिम्मेदारी बन गई है। (विघ्न) स्पीकर सर, जो हम शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आये हैं इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने यहां 30 मार्च, 2013 तक इसको लागू करें। इसको लागू करने में हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एच.आर.डी., सैंट्रल एडवाईजरी बोर्ड ऑफ ऐजुकेशन की मीटिंग हुई। भारत वर्ष

के सभी शिक्षाविद्व, शिक्षा मंत्री, वाईस चांसलरज और यहां तक की एच.आर.डी. मिनिस्टर स्वयं भी इसके मैम्बर हैं। इस मीटिंग में सभी राज्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके अंतर्गत हम बच्चों को फेल नहीं कर सकते कहीं भविष्य में बच्चों के लिए यह अहितकर तो साबित नहीं हो जायेगा? या कहीं यह कानून हमारी ऐजुकेशन प्रणाली को नीचे तो नहीं ले जायेगा? जैसा कि हमारे भाई दांगी साहब ने भी चिंता व्यक्त की थी, तो वहां पर मीटिंग में इन बच्चों को फेल न करने संबंधी विषय पर चर्चा की गई और बातचीत के बाद सी.सी.ई. को इंट्रोड्यूज किया गया। सी.सी.ई. का मतलब है Continuous and comprehensive evaluation जिसका प्रयोग हमारे प्राईवेट स्कूल्ज और कॉन्वैंट स्कूल्ज में किया जाता है। बच्चों को फेल न करने का मतलब यह नहीं है कि हमारे टीचर्ज को एग्जाम्ज बंद करने पड़ेंगे बल्कि बच्चों का लगातार और सतत् मूल्यांकन करना ही इस कानून का उद्देश्य है। इसके लिए हमने टीचर्ज को ट्रेनिंग भी दी है लेकिन दुर्भाग्यवश आज इसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि फ्री एंड कंम्लसरी ऐजुकेशन का मतलब है there will be no exams but it will be a continuous process of evaluation लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं से यह बात निकलकर सामने आई कि बच्चे इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और विशेषतौर से जो हमारा शिक्षक वर्ग है उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। ऐसा हमने देखा है कि जो वोकल ग्रुप होता है जिसकी प्रतिशतता मात्र 10 प्रतिशत ही होती है उसकी आवाज को ही ज्यादा सुना जाता है और यही इसमें भी हुआ। लेकिन मैं सदन को बताना चाहती हूं कि 90 परसैंट ने इस बात को समझा है कि जो शिक्षा का अधिकार आया है यह एक अच्छा कानून है और इसे हमने अच्छे ढंग से लागू करना है। स्पीकर सर, जब इस बात को लेकर कई राज्यों ने हल्ला किया तो कैग की सब कमेटी कांस्टीच्यूट की गई जिसका चेयरमैन स्टेट एच.आर.डी. मिनिस्टर को बनाया गया, और फिर इस विषय पर कि क्या हमें दोबारा से एग्जॉम्स लेने चाहिएं और क्या सी.सी.ई. को कांटीन्यू करना चाहिए एक और कमेटी बनी और मेरा भी यह सौभाग्य है कि इसका चेयरपर्सन नैशनल लैवल पर मुझे खुद बनाया गया। हमने सभी राज्यों में एक निर्धारित प्रोफार्मा भेजा है और उनकी इस विषय पर राय मांगी है, सभी एसोसिएशंज से भी राय मांगी गई है कि आप हमें जरूर बतायें कि क्या हम इस प्रोसिजर को एडॉप्ट करें या इसमें कुछ अमैंडमैंट्स लेकर आयें। बहुत से राज्यों ने इस बारे में सुझाव भी दिये हैं। आज सदन में जब इस बारे में चिंता व्यक्त की गई है तो मैं जरूर इस बारे में पूरा मैंशन करूंगी। हरियाणा में भी पूरी तरह से इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है। स्पीकर सर, मैं केवल आधे मिनट में और बात कहूंगी कि शिक्षा का अधिकार कानून जो पहली क्लास से लेकर आठवीं तक हम लेकर आ रहे हैं, भारत सरकार ने यह भी आगे प्लानिंग की है कि इसको दसवीं और बाहरवीं तक भी लेकर आया जाये। आज छह साल का बच्चा स्कूल में आता है लेकिन समय की मांग है कि चार साल का बच्चा भी स्कूल में आये अतः इसको लेकर भी कैग की कमेटीज बनी हुई हैं और उस पर कार्य चल रहा है and extension of RTE to 10th and 10+2 के बारे में जो कैग की सब कमेटी है मैं हमारे सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्तर पर मुझे ही उसका चेयरमैन बनाया गया है और उसकी काफी बार मीटिंग्ज भी हुई हैं। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : मैडम, जो आपके डिपार्टमैंट में टीचर्ज की एप्वॉयंटमैंट की एनोमलिज हैं आप पहले उनको ठीक करिये?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : दांगी जी, जो बात आपने कही है मैंने उसको नोट कर लिया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे सुझाव देते रहें ताकि हम इसमें सुधार करते रहें (विघ्न) एक मिसइंट्रप्रिटेशन आरोही स्कूल्ज को लेकर हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) रामपाल माजरा जी कलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं पहले मैं भी वहां से विधायक रही हूं। भारत सरकार के द्वारा यह क्षेत्र ऐजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर किया गया है। भारत सरकार ने 36 बैकवर्ड ब्लॉक्स डिक्लेयर किये हैं जिनमें हमने आरोही मॉडल स्कूल्ज बनाये हैं। अब किसी भी चीज की जब नींव रखी जाती है तो नींव रखने के बाद उसकी शुरुआत करने में समय तो लगता ही है, केवल उसकी निन्दा करने से ही बात नहीं बनेगी (विघ्न) इसमें जब आरोही मॉडल स्कूल्ज हमने खोले (शोर एवं व्यवधान) तो जो हमारे आलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्ज थे उनमें हमने यह आरोही स्कूल्ज चलाने शुरू किये और इनमें हमारे शिक्षा विभाग से डेप्यूटेशन पर टीचर्ज लगाये गये। सभी मैरीटोरियस स्टूडैंट्स इनमें पढ़ते हैं इसलिए पिछले साल एग्जाम के माध्यम से इन 36 आरोही मॉडल स्कूल्ज के लिए अलग से टीचर भर्ती बोर्ड के परव्यू से भी बाहर हाईली क्वालीफाईड टीचर्ज की भर्ती नॉन-ट्रांस्फरेबल आधार पर की है क्योंकि यह समय की जरूरत थी और हमने वह भर्ती की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन देती हूं कि सभी स्कूलों में निर्माण कार्य चल रहा है और 15 मार्च या 17 मार्च हमने ऐग्जाम की तिथि भी रख दी हैं। जहां हमने हाईली क्वालिफाइड टीचर्ज दिए हैं वहां उन स्कूलों में सारे मेरीटोरियस बच्चे आरोही स्कूलों में आते हैं। हमारी कोशिश है कि जहां-जहां ऐजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं इस सत्र से ही हम वहां सुधार करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) और शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I will allot just five minutes to each Member.

श्री रामपाल माजरा : आपका उद्देश्य क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन में सुधार का है आप इस बात को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास न करें। (विघ्न) मैं मंत्री महोदया का ऑनर करता हूं और मुझे खुशी है कि ये वहां से विधायक रही हैं। मैंने इनसे दो बातें कहीं थी कि क्या कपिल मुनि महाविद्यालय को आप अंडरटेक करेंगे इन्होंने कहा कि 'नो', मैंने कहा कि स्कूल का दर्जा बढ़ायेंगे तो इन्होंने कहा कि 'नो'। (विघ्न)

श्री नरेन्द्र सांगवान (घरौण्डा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट यहां पेश किया गया है वह न्याय की कसौटी पर कतई खरा नहीं उतरता। जैसा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 60 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है जबकि वर्तमान बजट में कृषि के लिए 1854.29 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जबकि कला एवं संस्कृति के लिए बजट में 9118.68 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। स्पीकर सर, मेरे विचार में 9118.68 करोड़ रुपये कृषि के लिए रखे जाने चाहिए थे तभी हरियाणा प्रदेश के किसान को न्याय मिलता। कृषि में अनाज,

दलहन, तिलहन, फलों एवं सब्जी के साथ-साथ बागवानी और फ्लोरिकल्चर और औषधिय पौधों की खेती को बढ़ावा देना आज के दिन आवश्यक है। बागवानी के लिए बजट में मात्र 41 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इतना पैसा तो विभाग द्वारा प्रदर्शनी आदि लगाने पर ही खर्च हो जाता है इस प्रकार यह 41 करोड़ रुपये की राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि मंडी बोर्ड ने करनाल में किसानों के लिए 4 करोड़ रुपये की लागत से 3 वर्ष पूर्व कोल्ड स्टोर बनाया था जो कि आज तक नहीं चला। पिछले वर्ष आलू का भाव किसान को 1 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो दिया गया जिससे किसान लुट गया। मंडी बोर्ड ने किसानों का आलू कोल्ड स्टोर में नहीं रखा। इसकी मशीनरी जो थी, वह कंडम थी। बाद में मंडी बोर्ड ने यह कोल्ड स्टोर एक ठेकेदार को किराए पर दे दिया जिसका एक ट्रक केला सड़ गया था और वह कोल्ड स्टोर को छोड़ गया। इसके बाद मंडी बोर्ड ने हरियाणा के अंदर बनाए गए सभी कोल्ड स्टोरज बंद कर रखे हैं, मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। (विघ्न) स्पीकर सर, इस प्रकार से मंडी बोर्ड करनाल, पानीपत, रोहतक, पंचकुला जैसे दर्जन भर शहरों में किसान मेलों के नाम पर खरबों रुपये की राशि खराब कर रहा है। प्रथम दृष्टि से वर्ष 2005 में प्रत्येक बड़ी मंडी में तीन गोदाम किसानों के लिए बनाए गए थे जिसमें खाद, बीज और कृषि संबंधित दवाइयां उचित रेट पर कमेटी द्वारा किसानों को बेचे जाने का बजट में प्रावधान किया गया था ताकि किसानों को बाजार में बिकने वाले डुप्लीकेट खाद, बीज और दवाइयों से बच सकता।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आपका बोलने का टाईम समाप्त हो गया है। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं। मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट हुए हैं मुझे बोलते हुए। श्रीमान् जी, बजट में ऊर्जा के हैड में 5232.97 करोड़ ₹ और स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए 2044.88 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है जोकि बहुत ही कम है। हरियाणा प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनता मध्यम वर्ग और गरीब है इसलिए गरीब जनता को जितना हो सके सरकार को फ्री दवाइयां देनी चाहिए। (घण्टी) बड़े-बड़े गांवों में डिस्पैंसरीज खुल जायें तो जनहित का काम होगा। (घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और अपने जिले के बारे में बोलना चाहता हूं। हरियाणा में ऐसा लगता है कि जिला अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले तो जैसे हरियाणा में हैं ही नहीं। इन जिलों को तो बच्चे को मीठी गोली देकर खुश करते हैं ऐसा बजट में इन जिलों के साथ किया गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए वर्ष 2013-14 में कितने करोड़ रुपये दिए जायेंगे इस बारे में बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2004-05 और वर्ष 2007-08 तक हरियाणा प्रदेश के खजाने में 1148 करोड़ ₹ सरपल्स थे लेकिन आज 2012-13 और 2013-14 में पहले का घाटा लगाकर 3163 जमा 2443 करोड़ ₹ का घाटा है। आज हरियाणा सरकार पर 58334 करोड़ ₹ से बढ़कर 67772 करोड़ ₹ कर्जा हो गया है। (घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आपका टाईम ओवर हो गया है। मैं आपको पांच मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगों के बारे में बोलना चाहता हूं। मैंने आपके माध्यम से पिछले सैशन में 38 सड़कों के बारे में प्रश्न भी लगाये थे और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक साल के अन्दर-अन्दर सारी सड़कें ठीक कर दी जायेंगी। लेकिन किसी भी सड़क पर काम नहीं किया गया है। इसी के साथ मैंने रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर बनाने के लिए डिमाण्ड की थी लेकिन वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज भी नहीं बनाया गया। एक लड़कियों का कॉलेज खोलने के लिए मांग की थी लेकिन लड़कियों का कॉलेज भी नहीं खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : आपके हल्के के अन्दर सरकारी कॉलेज नहीं है?

श्री नरेन्द्र सांगवान : स्पीकर सर, वह कॉलेज तो झालपुना गांव में है जो शहर से बाहर दो किलोमीटर की दूरी पर है। शहर से बाहर एक गांव में पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : दो किलोमीटर की दूरी मानते हो।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाने की बात की थी लेकिन हॉस्पिटल का दर्जा भी नहीं बढ़ाया गया है। बस स्टैण्ड बनाने की बात की थी और श्री ओमप्रकाश जैन जी जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि बना दिया जायेगा लेकिन आज तक कोई बस स्टैण्ड नहीं बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों करनाल में गए थे उस समय इन्होंने नई अनाज मण्डी से घोघड़ीपुर गांव तक यह सड़क जाती है उसको बनाने की घोषणा वर्ष 2008 में की थी लेकिन आज वर्ष 2013 होने के बावजूद भी किसी भी सड़क का काम शुरू नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, विपक्ष के अब तक 11 सदस्य बजट पर बोले हैं जबकि ट्रेजरी बैन्चिज के 8 सदस्य ही बजट पर बोल पाये हैं।

16.00 बजे

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप टाइम देख लीजिए कि कौन कितना टाइम बोला है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भारतीय जनता पार्टी के मैम्बर्ज 99 मिन्ट्स बोले हैं, रामपाल माजरा जी 37 मिन्ट्स बोले हैं। अपोजीशन के मैम्बर्ज को जो टाइम दिया गया है वह आलरेडी ट्रेजरी बैंचिज से कहीं ज्यादा है। (विघ्न) टोटल टाइम विपक्ष का काउंट किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आपने टाइम के बारे में बताया कि कौन सी पार्टी कितना टाइम बोली है। आपने बताया कि अपोजीशन ट्रेजरी बैंचिज से दो गुना टाइम ज्यादा बोल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, हम भी विपक्ष में रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये हाउस में रहे ही कितना टाइम हैं। ये हाउस में रहते नहीं हैं और वाक आउट करते रहे हैं।(विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम भागते नहीं बल्कि हमें निकाला जाता है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, आप को 5 मिनट बोलने के लिए दिए गए थे लेकिन आपने 12 मिनट ले लिए। इस प्रकार कैसे चलेगा? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस साईड से भी कई सदस्य बोलने के लिए रह गए हैं। आपने बताया कि अपोजीशन दो गुना टाइम ज्यादा बोल चुकी है। हमारे इधर के विधायक भी चुनकर आए हैं इसलिए इनको भी बोलने के लिए टाइम चाहिए। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य पहली बार बोल रहा है इसलिए उनको बोलने देना चाहिए। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने बोलना होता है तो ये वाक आउट करके तो न जाएं। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम वाक आउट नहीं करते बल्कि हमें निकाला जाता है। (विघ्न)

श्री जयतीर्थ (राई) : अध्यक्ष महोदय, देर से सही परन्तु आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह हाउस पहले ही रेलवे कोच और रेलवे लाइन पर धन्यवाद प्रस्ताव पास कर चुका है लेकिन मैं अपनी तरफ से और अपने इलाके की ओर से रेल मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी का सोनीपत में जो रेल कोच फैक्ट्री की बजट में घोषणा की गई है उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। यह मेरे इलाके के लिए और सारे प्रदेश के लिए एक सौगात है जो केन्द्र सरकार ने हमें दी है। एक बात मैं मुख्यमंत्री जी से इस रेल कोच फैक्ट्री के बावत कहना चाहूंगा कि इस फैक्ट्री में एक प्रावधान और करवा दें कि इसमें 75 परसैंट रोजगार हमारे हरियाणा के लोगों को मिले। ऐसा न हो कि इसमें दिल्ली या कहीं दूसरी जगहों के लोग लग जाएं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के लोगों को इसमें रोजगार मिले इस चीज का प्रावधान पहले से ही कर दिया जाए। क्योंकि बजट पर काफी साथी बोल चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं वित्त मंत्री जी सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी का ओर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आम आदमी के लिए खासतौर पर गरीब आदमी के लिए यह कर मुक्त बजट पेश

[श्री जय तीर्थ]

किया है। इसी के साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने सोनीपत के राई हल्के में राजीव गांधी ऐजुकेशन सीटी बनाकर उपकार कर रखा है और अब बजट में नैशनल लॉ कॉलेज का प्रावधान भी सोनीपत में किया गया है। इसी के साथ-साथ मैं वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आई.आई.टी. दिल्ली का जो एक्सटैंशन काऊंटर सोनीपत में बनाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश को ऐजुकेशन हब बनाने के लिए कटिबद्ध व वचनबद्ध हैं उसमें आई.आई.टी. दिल्ली का एक्सटैंशन काऊंटर सोनीपत में लाना बहुत ही बड़ी बात है और प्रदेश ऐजुकेशन हब में एक कदम आगे बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने राई हल्के के खरखल को ब्लॉक का और राई को उप तहसील का दर्जा दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ आंकड़ों की बात बताना चाहूंगा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1854.29 करोड़ रुपये, रोड्ज के लिए 4471 करोड़ रुपये, पब्लिक हैल्थ के लिए 2307 करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 2244.96 करोड़ रुपये, और प्रदेश के लोगों को सही बिजली देने के लिए बिजली क्षेत्र के लिए 5232.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बजट का 14.77 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है जो कि बहुत खुशी की बात है इस बारे में हमारे माननीय सदस्य श्री बत्तरा जी ने भी जिक्र किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि वह इलाका, प्रदेश या देश आगे होगा जो शिक्षा में आगे होगा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए रखा है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ग्रामीण विकास के लिए 1898 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाये गये हैं जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में या इलाके में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अपराधियों को इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू जल्दी सजा दी जायेगी और अपराधों में कमी भी आयेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सोनीपत और पानीपत के लिए सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की सुविधा का प्रावधान रखा है। इसमें दो योजनाएं शुरू की गई हैं उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, फाईनैंशियल रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन के बारे में बत्तरा जी ने भी जिक्र किया मैं भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि देश में इस क्षेत्र में हमारा प्रदेश सबसे आगे है। उन्होंने गुजरात का हवाला दिया कि वहां रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन 95.6 प्रतिशत है जबकि हमारे प्रदेश में 192 प्रतिशत है। पंजाब की 87.5 परसैंट है, आंध्र प्रदेश की 87.8 परसैंट है, महाराष्ट्र की 92.3 परसैंट है, मध्य प्रदेश की 95.8 परसैंट है, राजस्थान की 105.8 परसैंट है, कर्नाटक की 107.2 परसैंट है, उड़ीसा की 122.9 परसैंट है और हरियाणा की इन तमाम स्टेटों से ऊपर 192.1 परसैंट है। इस प्रकार से हमारी सरकार फाईनैंशियल रिसोर्सिज जुटाने में देश के सभी प्रदेशों से आगे है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देता हूं। योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित फाईनैंशियल

रिसोर्सिज जुटाने में हरियाणा सैंट्रल गवर्नमैंट की रेशो 92.5 परसैंट से भी आगे है। आर्थिक मंदी के बावजूद हमारी सरकार नये बजट के मुताबिक वैट अधिनियम में, सी.एस.टी. एक्ट में, एंटरटेन टैक्स में, एक्साईज टैक्स में और पैसेंजर टैक्स के तहत निर्धारित 19962 करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं और वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सरोज (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि बजट के माध्यम से विकास की जो तस्वीर पेश की गई है और जो असलियत में विकास हुआ है अगर उसका मिलान किया जाये तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह झूठा है और पक्षपातपूर्ण है। सर, अब मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछेक समस्यायें सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पिछले काफी सालों से उसमें कोई भी विकास नहीं करवाया गया। अध्यक्ष महोदय, नारनौंद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्टाफ नहीं है जबकि बिल्डिंग दो साल पहले बन चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्टाफ न होने की वजह से चार महीने पहले नारनौंद के व्यापारी श्री धर्मपाल मित्तल जी के यहां आग लगने की वजह से लगभग 25 लाख रुपये का नुकसान हो गया था। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि नारनौंद नगरपालिका की सीमा को बढ़ाया जाये क्योंकि पिछले काफी सालों से इसका जितना क्षेत्र था आज भी उतना ही है। नारनौंद में एक सार्वजनिक पार्क की भी सख्त जरूरत है इसलिए नारनौंद में एक सार्वजनिक पार्क शीघ्रातिशीघ्र बनवाया जाये। नारनौंद में सीवर व्यवस्था भी नहीं है जिसकी कि वहां पर सख्त जरूरत है। इसलिए नारनौंद में सीवर लाईनें बिछाई जायें। नारनौंद हल्के में महिला कॉलेज भी नहीं है जिसकी सख्त जरूरत है क्योंकि कोई महिला महाविद्यालय न होने के कारण क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जींद से हांसी वाया नारनौंद रेलवे लाईन बिछाई जाये यह हल्के की जनता की वर्षों पुरानी मांग है जिसको हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। गांव बास की उप तहसील में 19 गांव आते हैं। न तो उप तहसील का अपना भवन है और न ही स्टाफ है। इस उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाये और इसका भवन भी बनाया जाये। इस समय यह उप तहसील किराये के मकान में चल रही है। गांव बास के अस्पताल में डॉक्टरों के आवास की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से डॉक्टर रात को वहां पर नहीं ठहरते। एमरजैंसी की हालत में डॉक्टरों की उपलब्धता न होने के कारण अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांव बास के अस्पताल में डॉक्टरों एवं स्टाफ के आवास की व्यवस्था भी की जाये। अध्यक्ष महोदय, दूसरे गांवों के अस्पतालों में भी डॉक्टरों व स्टाफ नर्सों की बड़ी भारी कमी है उसको भी जल्दी से जल्दी दूर किया जाये। मिर्चपुर, खाण्डा, सिसाय, राखी शाहपुर और राखी खास इत्यादि गांवों में पीने के पानी की बहुत भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन

[श्रीमती सरोज]

गांवों में पीने के साफ पानी की सप्लाई के लिए शीघ्रातिशीघ्र कारगर कदम उठाये जायें। इन गांवों में वाटर वर्क्स का पानी ऊंचाई वाले मकानों में बिल्कुल नहीं पहुंचता है इसलिए ऊंचाई पर स्थित मकानों में पीने का पानी समुचित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, खेतों में लोगों के निवास स्थानों, डेरों और ढाणियों में डोमैस्टिक फीडर से बिजली की सप्लाई की सुनिश्चित व्यवस्था सरकार के स्तर पर जल्दी करवाई जाये। मकानों के ऊपर से जो हाई वोल्टेज की तारें जा रही हैं उनको हटाया जाये। सभी गांवों में बिजली की पुरानी तारों को शीघ्रातिशीघ्र बदला जाये। तालाबों में पानी भरने के लिए नहरों से पक्के नाले बनाये जायें। गांवों में गंदे पानी की निकासी की भी व्यवस्था की जाये। इलाके में ज्यादातर नहरों में पानी टेलों तक नहीं पहुंचता इसलिए सरकार द्वारा सभी नहरों के अंतिम छोरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवाई जाये। सुन्दर ब्रांच महीने में कम से कम दो हफ्ते चलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी को भी जल्दी से जल्दी दूर किया जाये। कई गांवों में सड़कें अभी भी कच्ची हैं इसलिए उनको जल्दी से जल्दी पक्का करवाया जाये। जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए उनकी पूर्ण रूप से रिपेयर करवाई जाये। गांव मोला से गांव गालन तक वाया खेड़ा तक पक्की सड़क बनाई जाये। गांव छोटी गोल से गांव मिर्चपुर तक पक्की सड़क बनाई जाये। गांव पेटवाड़ से गांव उगालन तक पक्की सड़क बनाई जाये। गांव डाटा से गांव खानपुर तक पक्की सड़क बनाई जाये। गांव बास से गांव खुराना तक पक्की सड़क बनाई जाये। गांव खेड़ा से गांव बास तक पक्की सड़क बनाई जाये। गांव बकलाना से गांव बास तक पक्की सड़क बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ उम्मीद करती हूं कि सरकार मेरे द्वारा रखी गई समस्याओं पर गौर करेगी और इनका जल्दी से जल्दी समाधान करेगी। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं दुबारा आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री आनन्द कौशिक (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2013-14 के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, महिला एवं बाल विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए और खेलों के विकास के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। किसानों के लिए जिस तरह से पिछले 2 साल, 2010-11 और 2011-12 में हरियाणा ने देश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने किसानों को अच्छे बीज और अच्छा खाद उपलब्ध करवाया और किसानों ने भी उसके अनुरूप मेहनत की और इन्होंने भी संकल्प ले रखा था कि हरियाणा नम्बर एक बनाना है। इसी तर्ज पर किसानों ने भी काम किया और हरियाणा नम्बर एक बना। शिक्षा के क्षेत्र में जो सोनीपत में ऐजुकेशन सीटी बनी है उसमें 25 परसैंट सीटें हरियाणा के लिए आरक्षित होंगी उससे यहां के बच्चों को फायदा मिलेगा। वहां पर ऐजुकेशन हब बनेगा और डेढ़ लाख छात्र इकट्ठे शिक्षा ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हलके की भी कुछ

डिमांड रखना चाहता हूं। कवि सूरदास जी सीही गांव में पैदा हुये थे और हमारी हरियाणा की हिन्दी अकादमी उनका जन्मदिन मनाती है लेकिन वहां पर कोई स्मारक उनके लिए नहीं बना है। ऐसे महान कवि जिनको दुनिया जानती है, उनके लिए एक स्मारक सीही गांव में बनाया जाये। सीही गांव का भी अपना एक इतिहास है जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। सीही गांव में एक स्मारक बनाया जाये ताकि सूरदास के भक्त वहां पर आयें और मन्नत मांग सकें। हमारे चार गांव ऐसे हैं जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आये हुये हैं लेकिन उनको बजट का कोई हिस्सा नहीं मिलता। उन चारों गांवों की जमीनें हुड्डा ने एक्वायर कर ली हैं। उनकी जमीनें बहुत ही सस्ते भाव, 6 से साढ़े 6 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर की हैं। अगर वे आज के दिन 1 गज जमीन भी लें तो 10 एकड़ जमीन के बदले 1 गज जमीन मिलेगी। इतने ज्यादा जमीनों के भाव हैं इसलिए अब तो उनकी समस्याएं भी उनकी नियति बन गई हैं। हुड्डा जमीन लेता है तो उनकी समस्याएं भी वही दूर करता है। उन सभी गांवों में एक-एक कम्यूनिटी सैन्टर, सीवरेज, अच्छी गलियां बनाई जायें। कुछ कॉलोनी हैं जिनमें पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है उनके लिए पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाये क्योंकि नहरी पानी फरीदाबाद को नहीं मिलता। फरीदाबाद एक ऐसा जिला है जो नहरी पानी से वंचित है। सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में तो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत से इसको पटरी पर लाए हैं और पटरी पर ही नहीं लाए हैं बल्कि दौड़ा रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा को नम्बर-1 बनाने की ठान रखी थी ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था चरमरायी हुई थी। इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर लाना और हरियाणा को नम्बर-1 बनाना आसान काम नहीं था। सर, मैं मुख्यमंत्री जी के नाम यह शेर पढ़ना चाहता हूं -

इतना आसान होता जिन्दा रहना तो लोग खुदकुशी न करते,
मरना भी होता आसान तो मौत से यूं न डरते।
आसान तो इस जहां में कहीं भी कुछ नहीं है,
हां, अगर आप ठान लो कुछ कर गुजरने को,
आसान बस वही है, आसान बस वही है।

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी आप बोलने का समय दें।

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आप सिर्फ मांग पर बोलिए। मांग के अलावा कुछ बोलोगे तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

डॉ० बिशन लाल सैनी (रादौर) : स्पीकर सर, मैं बजट पर बोलकर अपने समय को खराब नहीं करूंगा। स्पीकर सर, जैसे कि यमुनानगर में एक बाईपास बनाया जाएगा और उसके लिए सरकार ने वहां के किसानों की जमीन भी ली है। जमीन देने में कोई एतराज नहीं है अच्छा काम है उसके लिए जमीन दी है लेकिन सरकार उस जमीन का प्रति एकड़ के हिसाब से जो रेट दे रही है वह बहुत कम है। स्पीकर सर, शहर से लगती जमीन का रेट वहां डेढ़ करोड़ रुपये प्रति एकड़ से भी ज्यादा है और सरकार उसके 25 लाख रुपये प्रति एकड़ दे रही है। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी जोकि अब यहां पर मौजूद नहीं

[डा. बिशन लाल सैनी]
हैं से मांग है, कि इस काम के लिए डेढ़ करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को जमीन की कीमत दी जाए। स्पीकर सर, मेरी दूसरी मांग यह है कि वित्त मंत्री जी ने जो सहकारिता मिलों की सहायता का जिक्र किया है कि हम उनकी मदद करते हैं लेकिन इन्होंने गन्ना सहकारी समितियों के बारे में जिक्र नहीं किया। स्पीकर सर, यमुनानगर में लगभग 5, करनाल में एक और अम्बाला में एक गन्ना समिति है, उनमें लगभग 300 इम्पलाईज काम करते हैं। उनको जो कमीशन मिलता है वह फ्लैट रेट एक रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है और बहुत सालों से यही रेट चल रहा है। स्पीकर सर, जब सन् 1988 में चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब फ्लैट रेट 25 पैसे प्रति क्विंटल था जो उन्होंने 25 पैसे से बढ़ाकर यह 50 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया था। सन् 2000 में श्री ओमप्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यह 50 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया प्रति क्विंटल कर दिया। लेकिन उसके बाद उन इम्पलाईज का कमीशन नहीं बढ़ा। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि फ्लैट रेट एक रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। सर, बत्रा जी शायद चले गए लेकिन सबसे पहले मैं उनका एक बात के लिए धन्यवाद जरूर करूंगा कि इन्होंने इतनी सुनवाई जरूर करी कि मुस्तफाबाद को-ऑपरेटिव बैंक के अन्दर जो 14% ब्याज पर कर्ज दिया जाता था तो इन्होंने अपने एफैर्ट्स किए, बैंक वालों को, सोसायटी वालों को बुलाकर ब्याज 14% से घटाकर ब्याज 7% करा दिया लेकिन जैसे यह कहा जाता है कि 4% पर लोन मिलता है। स्पीकर सर, मेरी मांग है कि किसानों के कर्ज का 4% वार्षिक दर से ब्याज किया जाए। सहकारिता मंत्री जी को भी मैंने दरखवास्त दी थी इन्होंने तो कोई सुनवाई नहीं की।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। अब आप बैठ जाइये।

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, जब आप भी हमारे यमुनानगर जिले में जाते हैं तो वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं कि यमुनानगर जिला आपका स्वागत करता है। मेरी यह मांग है कि वह बोर्ड हटाकर ये लिखवा दो कि यमुनानगर की सड़कें आपका स्वागत करती हैं अर्थात् वहां की सड़कों के गड्ढे आपका स्वागत करते हैं। स्पीकर सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। (विघ्न)

श्री हरिचंद मिड्ढा : स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्ष : मिड्ढा जी, आप तो बिना परमिशन के ही खड़े हो गये, आप प्लीज बैठिये अभी सैनी साहब बोल रहे हैं, पहले उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मिड्ढा जी तो आपको शेर सुनाना चाहते हैं। (विघ्न)

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, आदरणीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 1 हजार 165 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की मुरम्मत की गई है। हमारे यमुनानगर के अन्दर तो यह मुरम्मत केवल कागजों में ही हुई है। मंत्री जी यहां से चले गये इसलिए स्पीकर साहब मैं आपको ही इस बात का प्रूफ दे सकता हूं कि यह मुरम्मत कागजों के अन्दर ही की गई है। जोणियों से लेकर कलानौर का जो बॉर्डर है उसके आगे उत्तर प्रदेश आ जाता है। वहां के एक इंजीनियर-इन-चीफ ने मुझको 6.12.2012 को एक पत्र लिखा जो मुझे जनवरी 2013 में मिला था। उस पत्र में लिखा था कि हमने आपकी सड़क की रिपेयर

का काम पूरा कर दिया है। पैच वर्क कर दिया है तथा जो खड्ढे वगैरह हैं उनको भी भर दिया है लेकिन जब हमने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी काम नहीं किया गया था। अतः मेरी मांग है कि अगर वह काम किया गया था तो उस पर पैसे भी खर्च हुए होंगे, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस काम पर कितने पैसे लगे तथा किसकी जेब में वह पैसे गये? जब काम हुआ ही नहीं है तो पैसे कैसे खर्च हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी इसकी इन्कवॉयरी जरूर करवायें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आ सके।

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा (बड़ौदा) : अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और वित्त मंत्री जी ने जो वार्षिक बजट वर्ष 2013-14 के लिए पेश किया है यह उनकी विकासशीलता एवं दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। इस बजट को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी एवं हरियाणा सरकार ने बजट तैयार करने से पहले काफी मेहनत की है और आम आदमी को राहत महसूस कराने की हर संभावित कोशिश की है। हरियाणा सरकार ने इस बार भी कोई नया टैक्स न लगाकर आम आदमी की सारी चिंताओं को खत्म कर दिया है क्योंकि हर बजट से पूर्व हर किसी को नए टैक्सों की सम्भावित भार का खतरा बना रहता है। कम से कम इस डर से आम आदमी को काफी हद तक राहत मिली होगी। हरियाणा सरकार ने दो लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लाट उपलब्ध करवाने, प्रियदर्शनी आवास योजना के जरिये डेढ़ लाख लोगों के लिए मकान बनाने की घोषणा करके एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। आम आदमी के लिए बीमे की शुरुआत करने के लिए 37 करोड़ की धनराशि का प्रावधान करना अपने आप में अनूठा कदम है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी एवं राज्य सरकार सराहना की पात्र है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी ध्यान दिया गया है। शिक्षा पर 2491.88 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि देकर शिक्षा में सुधार की उम्मीदों को बल मिला है। स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए डेस्कों की समस्या के निराकरण के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करके मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एवं हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट कार्य किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के लिए चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान सराहनीय कदम है। चिकित्सा शिक्षा पर भी चार सौ करोड़ की धनराशि मुहैया करवाकर मुख्यमंत्री जी ने विद्यार्थियों को बखूबी प्रोत्साहित किया है। औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए दो सौ करोड़ की धनराशि का प्रावधान करने से प्रशिक्षणार्थियों की कौशलता में बढ़ोत्तरी होगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सोनीपत जिले में नेशनल लॉ कॉलेज, कुरुक्षेत्र में नेशनल स्कूल ऑफ डिजायनिंग इंस्टिच्यूट और खानपुर, मेवात एवं करनाल में नए मेडीकल कॉलेज और रेवाड़ी व झज्जर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणाओं से निश्चित तौर पर शिक्षण सेवाओं का विस्तार एवं विकास होगा। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही पता चलता है। हरियाणा सरकार ने बजट में खेलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने खेलों के विकास के लिए 100 करोड़ खर्च करने का मन बनाया है। हॉकी के लिए हिसार में एस्ट्रोट्रफ, फुटबाल के लिए दरियापुर में सिंथेटिक प्ले ग्राउंड और महम में बाक्सिंग रेसलिंग के लिए स्पोर्ट्स

[श्री श्रीकृष्ण हुड्डा]
सैंटर बनाने की घोषणा करके मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का सार्थक प्रयास किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट में 13 प्रतिशत वृद्धि करके 1854.20 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया। सिंचाई के लिए 2240.90 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसानों के लिए इसी लगाव के कारण ही मुख्यमंत्री जी ने 15 जनवरी, 2013 को माननीय राष्ट्रपति से "कृषि कर्मण पुरस्कार" प्राप्त किया। जो निःसंदेह हमारे पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अपने वार्षिक बजट में आम आदमी का पूरा ध्यान रखा है। बजट में कृषि, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य एवं उद्योग के क्षेत्र में भारी भरकम धनराशि का प्रावधान करके राज्य की जनता का पूरी तरह से मन मोह लिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी एवं हरियाणा सरकार का बजट काफी आकर्षक एवं सराहनीय है और निःसंदेह हरियाणा सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद हुड्डा जी, आप बैठ जाइए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम किशन गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच को दर्शाता है और यह बजट आम आदमी और गरीब आदमी का बजट है। मैं इसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आंकड़ों के बारे में हमारे साथी श्री संपत सिंह जी ने बोल दिया है और इस बारे में मैं अपनी आवाज को उनकी आवाज के साथ मिलाता हूं और समर्थन करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने पिछली प्लान में गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट मंजूर किए थे। अभी विपक्ष के साथी कुछ जिक्र कर रहे थे कि प्लॉट मिले नहीं। मैं अपने हल्के की बात बताता हूं। हर पंचायत में जहां पंचायत के पास जगह थी वहां पंचायतों के द्वारा प्लॉट दिये गये हैं। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उसके साथ-साथ इस बजट के अंदर गांव में और शहरी क्षेत्रों में भी समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की प्राथमिकता रखी है। इसके लिए राज्य सरकार गांवों में आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रियदर्शिनी आवास योजना का

बजट में प्रस्ताव है यह बहुत ही अच्छी योजना है। इससे गरीब आदमी को, आम आदमी को जिसके पास मकान नहीं है, उसको मकान मिलेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कल विपक्ष के साथी गन्ने के भाव का जिक्र कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे नारायणगढ़ हल्के में जो शुगर मिल है इनकी सरकार के समय में 1999 से 2005 तक किसानों के साथ बहुत ज्यादती की थी। किसानों को अपने गन्ने के पैसे नहीं मिले थे वे गन्ने के दामों को समय पर देने की मांग कर रहे थे तो इनकी सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए थे उन पर लाठी चार्ज किया गया था, जेलों में बंद किया गया था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने न केवल किसानों को पैसे दिलवाए बल्कि ब्याज समेत पैसे दिलवाए। (शोर एवं व्यवधान) पब्लिक ने तो आपको जितना सुनना था सुन लिया अब पब्लिक ने आपका फैसला कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने थोड़े समय पहले गन्ने के दाम 45 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाये थे लेकिन ये साथी एक ही बात पकड़े बैठे हैं कि सबसे ज्यादा दाम करो। तभी यह धन्यवाद करेंगे। मैं इन विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जो 45 रुपये दाम बढ़ाए हैं क्या इसके लिए ये धन्यवाद नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का गन्ने का भाव अब भी सबसे ज्यादा है। यू.पी. में 1 साल में गन्ने की पेमेन्ट होती है और हमारे यहां किसान की पेमेन्ट 15 दिन में हो जाती है उसका हिसाब लगाएं तो आज भी हरियाणा का रेट सबसे ज्यादा है।

श्री राम किशन गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005 में पहली बार विधायक बना था, उन दिनों जब मैं अपने हल्के में जाया करता था और लोगों से मिलता था तो लोगों का बहुत बड़ा मांग पत्र होता था। तब लोगों की मांगें थीं। स्पीकर सर, मेरे हल्के में 190 गांव हैं और आज 8 साल के बाद भी मैं अपने हल्के में जा रहा हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि विपक्ष के साथी मेरे साथ मेरे हल्के के किसी भी गांव में चलें और चल कर देख लें कि गांव में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं और आज मांग पत्र का साइज एक चौथाई भी नहीं रह गया है। 75 से 80 परसैंट डिवैलपमैंट हो चुकी है। (विघ्न)

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो यह बात मान रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों के काम हो रहे हैं। हमारे काम नहीं हो रहे हैं। (विघ्न)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा क्या कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने यह माना है कि उसके यहां काम हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी ये जिलेवार चर्चा कर रहे थे। (शोर एवं व्यवधान) मैं अनिल विज जी की बात कह रहा हूं वे इस समय बैठे नहीं हैं। वे हर बात पर हाउस में खड़े हो जाते हैं और विरोध करते हैं। मैंने अखबार में थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि अम्बाला कैंट के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत फंड दिए हैं। अनिल विज जी अखबारों के अंदर तो उसका क्रेडिट लेते हैं। वहां जाकर लोगों को कहते हैं कि मैं ये काम करवाकर लाया हूं और यहां आकर सरकार की निन्दा करते हैं। यह मेरे अम्बाला जिले की बात है। (विघ्न) हमारे माननीय विधायक साथी श्री अभय सिंह चौटाला जी सदन में बैठे नहीं हैं वे कल बैठे-बैठे बात कर रहे थे कि इनैलो पार्टी की पार्लियामैंट चुनाव

[श्री राम किशन गुर्जर]
में दस की दस सीटें आयेंगी और हरियाणा में भी आप इधर होंगे और हम उधर होंगे। अध्यक्ष महोदय, जनता ने इनकी पार्टी को दो बार तो रिजल्ट दिखा दिया है और अब भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की दस की दस सीटें आयेंगी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनेगी।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार के साथ हिसार में जो बनी है वह सबने देखा है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, लोकदल पार्टी के साथियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में भिवानी और कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था उस समय चौटाला जी के दोनों पुत्रों को मुंह की खानी पड़ी थी। यह तो जनता का फैसला है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है इसलिए इनको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पांच वर्ष के लिए कांग्रेस की सरकार दोबारा से बनेगी और दो बार पार्लियामैंट और एसैम्बली में दो बार लगातार कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुनकर भेजा है। यह शुक्र करें कि दोबारा से चुनकर आयें।

श्री राम किशन गुर्जर : सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पिछले पांच साल से एक बात देख रहा हूं कि सैनी साहब हर बात पर खड़े हो जाते हैं। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपा करके इनको माननीय सदस्य की बात सुननी चाहिए।

श्री राम किशन गुर्जर : सर, मैं एक मिनट के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे इलाके की बहुत पुरानी मांग रेलवे लाईन की थी उसको इन्होंने भारत सरकार से मन्जूर करवाया है। दूसरा सुझाव मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं उन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से बनाया जाए और जो मार्केटिंग बोर्ड का फण्ड है वह पी.डब्ल्यू.डी. को दे दिया जाये। इसी प्रकार से हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर डेपुटेशन पर चले जाते हैं और वहां पर वह पोस्ट भरी हुई दिखाई जाती है इसलिए डेपुटेशन प्रणाली को खत्म किया जाये। तीसरी बात मैं पंचायत मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो गांव की पंचायतों को सरकार की तरफ से विकास के लिए पैसा भेजा जाता है उस पैसे के लिए विकास कार्यों के लिए समयबद्ध किया जाए अगर उतने समय में वह विकास कार्य नहीं होता है तो उस पैसे को वापिस लेकर विभाग द्वारा यह कार्य किया जाये। इस काम के लिए समय जरूर तय किया जाए।

Mr. Speaker : It is a good suggestion.

श्री राम किशन गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय जी हर मामले में दरियादिली दिखाते हैं। बहुत से एम.एल.एज. ने कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में कहा तथा लोग भी इस बारे में हमसे मिलते हैं। पुलिस के स्टाफ की बात हो, क्लर्कों और ड्राइवर्ज की बात हो तो मैं कहना चाहता हूं कि

इनकी जितनी भी तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती हों, जरूर बढ़ाई जाएं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जगदीश नायर (होडल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं बजट पर न बोलकर अपने हल्के की मांगें रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र होडल में एक सी.एच.सी. है जिसकी हालत बहुत बुरी है और उसकी बिल्डिंग टूटी पड़ी है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस हॉस्पिटल के लिए फण्ड अलॉट किए जाएं, इसका नया भवन बनाया जाए और इसको जी.टी. रोड पर लाया जाए क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र जी.टी. रोड पर है जिस कारण वहां बहुत से एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। यह हॉस्पिटल आबादी के बीच में है इसलिए वहां जाने के लिए कई बार रास्ता नहीं होता। मेरा अनुरोध है कि इस हॉस्पिटल का नया भवन बनाकर इसको जी.टी. रोड पर लाया जाए। यहां एक ट्रॉमा सैंटर बनाया जाए, एक्स-रे मशीन लगाई जाए तथा स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, गांवों में डिस्पैंसरीज की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। गांवों में डिस्पैंसरीज खोलकर गांव के लोगों की दिक्कत को दूर करने का काम किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हसनपुर में एक पुराना हॉस्पिटल है उसकी हालत भी बहुत बुरी है इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां एक्स-रे मशीन लगाई जाए और स्टाफ पूरा किया जाए और इसकी बिल्डिंग को बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने दो गांवों की मांग रखना चाहता हूं। कामपुर जोकि हमारे मेव समाज का गांव है, यहां के बच्चे पहले तो बहुत कम पढ़ते हैं और दूसरा यहां का स्कूल सदियों से 8वीं तक का है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको 10वीं क्लास तक किया जाए। पेंगुल-II का एक स्कूल है उसको भी 8वीं से 10वीं क्लास तक किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक महिला यूनिवर्सिटी बनाने का मैं अनुरोध करता हूं। गांव-गांव में मवेशी हॉस्पिटल्ज पर ध्यान दिया जाए क्योंकि गांव के अधिकतर लोग पशु पालन पर अपना गुजारा करते हैं। आजकल पशुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं यदि उनके पशु मर जाते हैं तो उनकी बहुत बड़ी क्षति होती है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पशु अस्पतालों के लिए डॉक्टरों का चयन करने की तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं नहरों की बात करना चाहूंगा। नई नहरों की खुदाई की जाए क्योंकि सिंचाई विभाग का वही पुराना ढांचा चला आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़े-बड़े गांव हैं, सोंद, बंचारी, डाढका, बोराखा, गढी और होडल, इन गांवों में नहरों के अलावा सिंचाई का कोई और साधन नहीं है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां एक नई नहर खोदकर लोगों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी नहरें हैं जैसे होडल रजवाहा, हसनपुर रजवाहा, गोच्छी ड्रेन और खटेला माइनर और उजीना माइनर, इनकी सफाई करवा कर इन नहरों को दुरुस्त किया जाए क्योंकि बहुत दिनों से इन नहरों की सफाई नहीं हो रही जिसके कारण किसानों को सिंचाई की दिक्कतें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मैं बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये सारी जन समस्याएं हैं और ये हमारी अपनी समस्याएं नहीं हैं। हमारे इलाके में बिजली की तारों की वजह से कई एक्सीडैंट्स हो चुके हैं। मैंने इस बारे में कई बार प्रश्न भी लगाए कि हमारे यहां के

[श्री जगदीश नायर]
इलाके में बिजली की तारें काफी पुरानी हैं इसलिए इनको बदला जाए। इन तारों को हटाकर नई तारें लगाने बारे हम बिजली विभाग के अधिकारियों से मिले भी हैं लेकिन वे इसके बारे में एक ही बात कहकर हमें टाल देते हैं कि तारें नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, होडल विधान सभा क्षेत्र का एक शहर होडल है, उस शहर की बहुत बुरी हालत है। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप काम करवाएं यह बात ठीक है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा लेकिन 8 सालों से उस शहर में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। वहां न नालियां हैं और न स्ट्रीट लाइटें हैं। होडल का गंदा पानी गलियों में घूमता रहता है। सीवरेज के काम तो किए गए हैं लेकिन वह सीवरेज पानी को नहीं खींचता है और वह सीवरेज ठप्प पड़ा है जिसकी वजह से होडल शहर सड़ रहा है इसलिए इस ओर जरूर ध्यान दिया जाए। होडल शहर की कॉलोनियों में भी विकास की बहुत जरूरत है। चरण सिंह कॉलोनी, बड़ोता रोड, श्याम कॉलोनी, लोहाकंड कॉलोनी, कुंडा कॉलोनी, अग्रसेन चौक कॉलोनी, होडल बस स्टैंड कॉलोनी, रोहता, बारा, अंधुआ, राविया, तेविया, बक्सुआ पट्टी आदि गांवों की सभी मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Those who obey the Chair, they will get preference.

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे वहां बृज परिक्रमा पर देश से करोड़ों लोग गुजरते हैं इसलिए उसको पक्का करवाया जाये, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। इसके अतिरिक्त हसनपुर में ओवर ब्रिज बनाने का काम भी जल्दी शुरू करवाया जाये। धन्यवाद!

श्री जिले राम शर्मा (असंध) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के वित्त मंत्री जी ने विधान सभा में 2013-14 को जो बजट प्रस्तुत किया है उससे यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस की सरकार वास्तव में आम आदमी की पार्टी है और इसकी नीतियां हमेशा जन हितैषी रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह कर मुक्त बजट प्रस्तुत किया है इससे प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस प्रगतिशील, विकासमुखी एवं जनहितैषी बजट की जितनी तारीफ की जाये वह कम है। इस बजट में हर वर्ग को राहत देने का काम किया गया है। जो बी.पी.एल. और गरीब परिवार हैं उनको मकान देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह से इस बजट के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन, पैकेज बढ़ोत्तरी करना, आधारभूत संरचना के विकास को विशेष बढ़ावा देने, आम आदमी की बीमा योजना शुरू करने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान जैसी योजनाएं शुरू करने का सराहनीय कार्य किया गया है। स्पीकर सर, जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से अब आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में असंध क्षेत्र का और करनाल जिले का चहुंमुखी विकास हुआ है। असंध के अंदर 80 करोड़ रुपये की लागत से शुगर मील लगाई गई है। 220 के.वी. के सब स्टेशन पर मूंड में कार्य प्रगति पर है जिस पर 55 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी तरह से 132 के.वी. का सब स्टेशन बलाह के अंदर बनाया जा

रहा है। इसी तरह से 33-33 के.वी. के साहपुर, चौचड़ा, शेखपुर, बड़ौता और पिचोलिया में बिजली घर बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त असंध आई.टी.आई. की क्लासिज भी शुरू हो चुकी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि असंध आई.टी.आई. की जल्द से जल्द बिल्डिंग बनवाई जाये। इसी तरह से करनाल जिले और असंध हल्के में सड़कें भी बनवाई गई हैं तथा दूसरे विकास कार्य भी करवाये गये हैं। हमारे यहां 40 साल में इतने विकास कार्य नहीं हुये जितने हुड्डा साहब की सरकार बनने के बाद हुए हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से और अपने हल्के की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से करनाल जिले में कई सौ करोड़ रुपये की लागत से कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज खोला जायेगा जोकि एक पंजाबी महिला के नाम से है। इसका कार्य शुरू हो चुका है। अभी हमारे घरोंडा के विधायक मेरे मित्र बोल रहे थे कि इंडो-इजराइल फार्म के तहत विदेशों की सब्जी की तकनीक लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, करनाल का आप ऑन रिकॉर्ड किसी चीज का देख लें, चाहे डी-प्लान का देख लें सभी 5 के 5 हल्कों में करनाल जिले में बराबर खर्चा करके विकास कार्य किए गए हैं। जैसा कि विपक्ष के साथी कह रहे थे कि भेदभाव हो रहा है और रोहतक में ज्यादा विकास कार्य हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सभी जगह बराबर विकास कार्य हो रहे हैं और प्रदेश में चहुंमुखी विकास कार्य चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने करवाये हैं। आज प्रदेश में गरीब लोगों को आवास उपलब्ध करवाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और इसके लिए बजट में बहुत मकान बनाने का प्रावधान किया गया है जोकि बहुत बड़ी बात है। गरीबों ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी कि उन्हें इस तरह से सरकार मकान बनाकर देगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के असंध के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, आप भी वहां जाते हैं। असंध के अंदर डिवाइडर करके सड़क को फोर लाईन करना बहुत जरूरी है। वहां शहर में घंटों-घंटों जाम लगा रहता है। इस जाम के कारण दुर्घटनाएं होने पर वहां 3-4 मौतें भी हुई हैं। इसके अतिरिक्त असंध शहर में सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी बनवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप वाईंड अप करें।

श्री जिले राम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पक्का खेड़ा करनाल रोड से मुनक वाया बालपबाना की सड़क, बालपबाना से ऐंचला की सड़कों की बहुत बुरी हालत है इनको जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। आई.टी.आई. की जो बिल्डिंग बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर निवेदन करना चाहूंगा। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, ...(विघ्न)

Mr. Speaker : Shri Dharampal Obra is the last speaker from the Opposition side. (Interruption) ओबरा जी आप बोल रहे हैं या मैं अगले स्पीकर को अलाऊ करूं।

वॉक-आऊट

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, मुझे बजट पर बोलना है। इसलिए आप कृपया मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दें। यदि आप मुझे बजट पर बोलने के लिए समय नहीं देंगे तो फिर इसके विरोध में मुझे सदन से वॉक-आऊट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : सुभाष जी, जब मैंने आपको बोलने के लिए समय दिया था उस समय आपकी पार्टी के कुछ सदस्य इक्ट्ठे बोल रहे थे लेकिन आपने उस समय बोलना शुरू नहीं किया। अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाईये।

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, मुझे बजट पर बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं इसके विरोध में एज-ए-प्रोटैस्ट सदन से वॉक आऊट कर रहा हूं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री सुभाष चौधरी बजट पर बोलने के लिए समय न दिये जाने के विरोध में सदन से वॉक आऊट कर गये।)

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

मास्टर धर्म पाल ओबरा : स्पीकर सर, ...(विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आपके द्वारा श्री सुभाष चौधरी को यहां पर बोलने के लिए बराबर इजाजत दी जाती रही है (शोर एवं व्यवधान) उन्हें यहां पर इस प्रकार की अनुचित बातें नहीं करनी चाहिएं। इनकी इस प्रकार की बातें न केवल निंदनीय हैं बल्कि इनका इस प्रकार बोलना संसदीय प्रणाली के भी विरूद्ध है। (शोर एवं व्यवधान)

मास्टर धर्म पाल ओबरा : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आपने विपक्ष की तरफ से 14 माननीय सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए मौका दिया और सत्ता पक्ष के सिर्फ 11 माननीय सदस्य ही बजट पर बोल पायें हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अब तक बजट पर बोलने के लिए कुल 8 घंटे का समय अपोजिशन को दिया गया है और ट्रेजरी बैंचिज को अभी तक बजट पर बोलने के लिए 3.40 घंटे का समय मिला है। (शोर एवं व्यवधान)

मास्टर धर्म पाल ओबरा : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं क्योंकि जितने माननीय सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए आपने मौका दिया है इतने माननीय सदस्य हरियाणा के इतिहास में बजट पर कभी भी नहीं बोले हैं। आपने यह भी एक रिकॉर्ड ही स्थापित किया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : About 1/3rd members have spoken.

मास्टर धर्म पाल ओबरा (लोहारू) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में 7-8 सी.एच.सी. और पी.एच.सी. हैं इनमें से किसी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. में महिला डॉक्टर नहीं है। स्पीकर सर, सी.एच.सी. और पी.एच.सी. में जच्चा-बच्चा के लिए महिला डॉक्टर न होने के कारण इससे महिलाओं को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें महिला डॉक्टरों की कमी बहुत ज्यादा खल चुकी है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में जो सी.एच.सी. और पी.एच.सी. हैं उनमें महिला डॉक्टरों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी और एक बात और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कई बार एक्सीडैंट्स में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है लेकिन हॉस्पिटल में उनके पोस्ट मार्टम के लिए डॉक्टर नहीं मिलते हैं जिसके लिए हमें टेलीफोन करके भिवानी से डॉक्टर मंगवाने पड़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तो उनका पारिवारिक सदस्य की जान चली जाती है और ऊपर से इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। किसी भी पी.एच.सी. में अमला रिपोर्ट भी नहीं काटी जाती है। पहले यह सुविधा थी लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। इस काम के लिए भी मेरे हल्के के लोगों को 40 किलोमीटर दूर भिवानी जाना पड़ता है। मेरे हल्के में तीन तहसील हैं। इन तीन तहसीलों में से डेढ़ तहसील में जमीन के नीचे का पानी खारा है। वहां पर नहरों का पानी भी नहीं पहुंचता। लोगों को पीने का पानी टैंकरों से मंगवाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री महोदया जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जाये। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदया जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षायें बंद कर दी गई हैं उन्हें दोबारा से शुरू किया जाये। वैसे तो इस बारे में माननीय सदस्य दांगी जी ने जिक्र कर दिया था लेकिन क्योंकि मैं एक अध्यापक रहा हूं इसलिए अध्यापक होने के नाते मैं यह कह रहा हूं कि पांचवीं और आठवीं की कक्षाओं के लिए बोर्ड की परीक्षायें दोबारा से शुरू की जायें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पायेंगे। इसी प्रकार से महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी ने डिस्टैंस ऐजूकेशन की क्लासिज बंद कर दी हैं उनको दोबारा से चालू करवाया जाये। जहां तक सड़कों की बात है तो सड़कों को देख कर ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे न हो कर गड्ढों में सड़क हो और रोजाना एक्सीडैंट्स होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने ओलावृष्टि पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था लेकिन नेम होने के कारण मैं उस प्रस्ताव पर नहीं बोल सका। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसानों को अच्छा मुआवजा दिया जाये।

श्रीमती शकुन्तला खटक (कलानौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। सरकार ने 2013-14 के लिए जो बजट सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है वह सराहनीय बजट है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि ही प्रत्येक राज्य की समृद्धि की कुंजी होती है। प्रदेश की खुशहाली

[श्रीमती शकुन्तला खटक]

व समृद्धि इस बात का प्रतीक है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को 2010-2011 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता हासिल करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। स्पीकर सर, आज शिक्षा मनुष्य का एक अंग बन चुकी है, जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 750 रुपये की दर से 12 हजार विद्यार्थियों को वजीफे का लाभ मिल रहा है। स्पीकर सर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और पिछड़ा वर्ग के 7.47 लाख विद्यार्थियों तथा अनुसूचित जाति के 8.45 लाख विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। स्पीकर सर, यह बड़े ही गर्व और सम्मान का विषय है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में नैशनल लेवल का लॉ कॉलेज तथा झज्जर, रेवाड़ी आदि में नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे। इससे हमारे प्रदेश के बच्चों का भविष्य उभर कर आयेगा। यह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की दूरगामी सोच है। पहले हमारे प्रान्त के बच्चे हॉयर ऐजूकेशन लेने के लिए विदेशों में धक्के खाते थे लेकिन अब हरियाणा प्रदेश में ऐजूकेशन के इंस्टीच्यूट इतने खुल गये हैं कि विदेश के लोग हरियाणा में ऐजूकेशन लेने के लिए आते हैं। स्पीकर सर, खानपुर कलां, सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना अपने आप में एक बेमिसाल स्थापना है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में भी हमारी सरकार गंभीर है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में खानपुरा कलां, सोनीपत में एम.बी.बी.एस. की 100 सीटों तथा 500 बिस्तरों के अस्पताल के साथ महिला चिकित्सा महाविद्यालय खोला है, जो आजादी के बाद सरकारी क्षेत्र का देश में पहला महिला चिकित्सा महाविद्यालय है। एम्स-2 के विस्तार के लिए गांव बाढ़सा, जिला झज्जर में 300 एकड़ जमीन आबंटित की है। जिस प्रकार हमारे भाई नरेश शर्मा कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपये की लागत से इसकी ओ.पी.डी. शुरू हो गई है। 1800 करोड़ रुपये की लागत से 600 बिस्तरों का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित करने पर सक्रियता से विचार हो रहा है। स्पीकर सर, हर सिर को छत मिले इसके लिए सरकार ने 2 लाख परिवारों को घर देने का लक्ष्य रखा है। मैं महिला होने के नाते सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के विकास के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के लिए 891.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

श्रीमती शकुन्तला खटक : हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है । बाकी स्टेट्स से पहले कदम उठाने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने जो गरीब परिवारों को बी.पी.एल. की स्कीम के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए, वह भी उन्होंने सबसे अच्छा स्टैप उठाया है । स्पीकर सर, इस योजना के तहत हमारे हरियाणा प्रांत में 3 लाख 88 हजार परिवारों को सुविधा मिल चुकी है । स्पीकर सर, जहां तक पानी की बात है स्वच्छ पेय जल की बात है, वह भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही सबसे पहले स्टैप उठाया था । हमारी सरकार द्वारा हर गरीब घर को पानी की टैंकी, कनैक्शन, पानी की पाईप उनके घर तक पहुंचाई जाती है । सर, इस सुविधा से 9 लाख 99 हजार 471 परिवारों को लाभ हो रहा है । सर, इस सुविधा पर 433 करोड़ रुपये की लागत आई है । सर, आप सभी जानते हैं कि 2005 से पहले खिलाड़ियों के लिए क्या किया जाता था? स्पीकर सर, अगर वर्ष 2005 से पहले का मैं वर्णन करूं तो ऐसे खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम रोशन करते थे उनके स्वागत के लिए गांव के लोग पैसे इक्ट्ठे करके एक टूटी सी जीप, उन्हीं की माला डालकर अपने घर में घुस जाते थे । स्पीकर सर, वर्ष 2005 के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जब बागडोर सम्भाली तो खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं । आज गाड़ी के साथ-साथ खिलाड़ियों की जेब में करोड़ों रुपये की राशि डालकर स्वागत किया जाता है । मुख्यमंत्री जी ने खेल कोटे के तहत 424 खिलाड़ियों को नौकरियां दी हैं । इनमें से 17 खिलाड़ी डी.एस.पी. बनाए गए हैं । इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं । मैं एक बात और बताना चाहूंगी । जो 2016 के अन्दर ओलम्पिक गेम होने हैं उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर आएगा उसको 5 करोड़ रुपये, जो रजत पदक लेकर आएगा उसको 3 करोड़ रुपये और जो कांस्य पदक लेकर आएगा उसको 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे । यह एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी सोच है, आज हमारे खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जी ने जो मान सम्मान दिया है मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करती हूं । स्पीकर सर, ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चौथी बार सर्वोतम पुरस्कार मिलना अपने आप में एक मिसाल है । स्पीकर सर, यह सब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के विकास कार्यों से ही सम्भव हो सका है । सर, वर्ष 2005 से पहले की राजनीति भी हमने देखी है उस समय जो भी नेता रहे हैं मैं यहां सदन में किसी का नाम नहीं लूंगी लेकिन ये जरूर कहूंगी कि एक हमारी बिरादरी का लड़का पुलिस में भर्ती हुआ और उन्होंने चाव में विपक्ष के किसी विधायक मुख्यमंत्री के बेटे को अपने घर बुलाया तो जो आज हमारे विपक्ष के विधायक है और उस समय के मुख्यमंत्री जी के बेटे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगी, उसको शादी में बुलाया गया तो जैसे सब मान-सम्मान देते हैं उसी तरह मुख्यमंत्री के बेटे को भी मान-सम्मान दिया गया । जैसे गांव में शादी समारोह में पाटड़े के ऊपर बच्चे को बिठाते हैं, फिर वार-फेर की रस्म अदा की जाती है तो जिस बच्चे की शादी होती है (शोर एवं व्यवधान) उस पर पैसे वारे जाते हैं और सब चाव में ज्यादा से ज्यादा रुपये उस बच्चे पर वारने लगते हैं जिसको तोलिये से बनी एक पोटली

[श्रीमती शकुन्तला खटक]

में इक्ट्ठा कर दिया जाता है (शोर एवं व्यवधान) और उन लोगों ने जिनके घर शादी थी उस पैसों से भरी पोटली को अपने घर बुलाये हुए नेता का मान रखने की खातिर उसकी झोली में डाल दी। उस नेता ने उस पैसों की पोटली को अपने पीछे बैठे गनमैन को दे दिया और पैसा गायब हो गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : खटक जी, क्या सारे पैसे आपको ही पकड़ा दिये?

श्रीमती शकुंतला खटक : अरोड़ा जी, मैं कानों सुनी बात ही सदन में कह रही हूं। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो केवल अपनी बिरादरी के लोगों की ही बात कर रही हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, यह तो बहुत गलत बात हुई, खटक जी आपको उस विधायक का नाम सदन में अवश्य लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट सत्र पर बोलने का जो मौका दिया है तथा जो मुझ में जोश तथा उत्साह भरा उसके लिए मैं आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के साथ-साथ आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Finance Minister will give reply on the Budget Estimates for the year 2013-2014. (Interruption) (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मान लो आपने किसी एक मैम्बर का नाम आपने बजट पर बोलने के लिए बुलाया है और सदन में उपस्थित नहीं है तो आप दूसरे सदस्यों को जोकि इस इंतजार में बैठे हुए हैं उनको बोलने का भी मौका दे सकते हैं यह मेरा आपसे निवेदन है। दो मिनट से ज्यादा तो आप किसी को बोलने के लिए इजाजत नहीं दे रहे हो? अपनी हल्के की मांग से ऊपर तो आप हमको जाने नहीं देते हो। आपने तो पूरे दिन से दो मिनट से ज्यादा न बोलने की पाबंदी लगाई हुई है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मैं आप लोगों को 11 तारीख को कट मोशन पर बुलवा दूंगा। जो एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा उस पर भी आप बोल लेना।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : स्पीकर सर, आज सारे मैम्बर साहेबान को बजट पर बहस करते हुए ढाई दिन के लगभग हो गया है। लगभग 30 से ज्यादा सदस्यों ने सदन में अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी बातें कहनी थी यहां सदन में अपनी बात रखी। लेकिन इस बजट सत्र में प्रो० संपत सिंह जी ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने बजट में जितनी फिगर्ज का जिक्र किया है उन सारी की सारी फिगर्ज को यहां सदन में कोट कर दिया है तथा एक-एक फीगर को पढ़ कर भी सुना दिया है। बाकी तो बजट पर बहस चल ही रही है कि मेरे हल्के में यह काम हो, मेरे हल्के में वह काम हो लेकिन बजट की बात जो प्रो० संपत सिंह जी ने की है वह वास्तव में बहुत सराहनीय है और इसके साथ ही साथ मैं अपने अपोजीशन के सदस्यों का जो उन्होंने आज चुप बैठकर

सदन की कार्यवाही को चलाने में जो सहयोग दिया है उसके लिए उनका भी धन्यवादी हूं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : चट्ठा साहब, हम तो इंतजार में हैं कि आपके पिटारे से कुछ निकले? (विघ्न)

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अरोड़ा जी, पंजाबी में एक कहावत है कि "यारा तेरा घुट भर ल्यां, मैनू वेख्यां सबर ना आवे" (हंसी)। इस बजट को मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट के मिनिस्टर्ज और ऑफिसर्ज की गाईडैंस में ही बनाया गया है। इस बजट को बनाने के बाद मुख्यमंत्री जी और सदन के दूसरे सदस्यों ने भी यह बात कही है कि यह बजट पहले बजटों से यानी कि वर्ष 2005 से ऑनवॉर्डस जो बजट आये हैं, उनसे कम नहीं है बल्कि उनसे भी बैटर है। मैं हमारे ऑफिसर्ज का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके यह बजट बनाया है और इसके साथ आप सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बजट पर चर्चा करने में ढाई दिन का समय लगाया है बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्रो० सम्पत सिंह जी ने तकरीबन सारी ही फिगर्ज कोट कर दी हैं। फिगर्ज वाली कोई बात रह ही नहीं गई है जो आपने न सुनी हो लेकिन फिर भी जो आप यह कहते हो कि इतना कर्जा है, इतना कुछ है। आप कहीं से पढ़ लो, किसी गाइड से पढ़ लो, किसी इंटरनेशनल इकोनोमिक ऐक्सपर्ट से पूछ लो कि Haryana is best managed State in the finances in the Country. हमारी स्टेट इकोनोमी की जो ग्रोथ है, दूसरों से बैटर है। हमारी पॉपुलेशन एरिया 1.3 है, और हमारी कंट्रीब्यूशन इंडिया में 3.4 है। यही साबित करता है कि Haryana Government under the guidance of the Hon'ble Chief Minister कितना बढ़िया काम कर रही है। इसी तरह हमारी ग्रोथ रेट 7.8 से 7.7 परसैंट हुई है this is also the best. वैसे मैं यह चाहता नहीं कि किसी स्टेट के साथ अपना मुकाबला करूं। सारी स्टेट्स अपनी तरफ से अच्छी हैं। अभी ये बात आई थी कि डैब्ट की सी.ए.जी. की रिपोर्ट दी है कि उसने यह कहा है कि its sustainable, well sustainable. इसके साथ-साथ इसमें एक मुकाबले की बात है कि पंजाब में 33.4 परसैंट है और हमारे यहां 16.48 परसैंट है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय वित्त मंत्री जी ने उठाया है। जैसा सभी साथियों ने कर्ज के बारे में कहा है। हमारे बी.जे.पी. के साथियों ने भी एक बहुत बड़ी पिक्चर पेंट की हुई है और बी.जे.पी. से पूछें तो वे गुजरात का उदाहरण देते हैं। मैं किसी स्टेट से मुकाबला नहीं करना चाहता। जो डैब्ट है जो जी.एस.पी.डी.सी. की रेशो से देखा जाता है। वह गुजरात का जो जी.एस.पी.डी.सी. रेशो है वह 19.89 परसैंट है हमारे यहां 16.47 परसैंट है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट की बात कही, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वह गुजरात में 2.57 परसैंट है और हमारे यहां 2.20 परसैंट है।

श्री अनिल विज : ग्रोथ रेट भी बता दीजिए। बी.जे.पी. शासित सभी राज्यों में यह 10 परसैंट से ऊपर है। (विघ्न)

Sardar Harmohinder Singh Chattha : Deputy Speaker Sir, in 12th Five Year Plan, it is set to be sustainable. इसके साथ एक साथी ने बोलते हुए डायरैक्शनलैस लफ्ज दे दिया और साथ में दस बारह सदस्यों को पढ़ा भी दिया कि ये लफ्ज कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात ही कहता हूं कि वह सरकार डायरैक्शनलैस कैसे हो सकती है जो सरकार गरीबों के लिए दो लाख मकान गांवों में बना दे और डेढ़ लाख मकान शहरों में बना दे और अपने आप उसमें पूरा कंट्रीब्यूट करे। अब मैं कहना चाहूंगा कि एस.सीज. की आबादी 19.35 परसैंट है और हिस्सा हम उनको 20.90 परसैंट दे रहे हैं। बजट में इससे ज्यादा डायरैक्शन वाली बात और क्या हो सकती है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप आगे का बता रहे हैं कि साढ़े तीन लाख मकान बना देंगे। पिछला बताएं कि साढ़े आठ साल में कितने मकान बनाए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : प्रधान जी, अब तो आप ही प्रधान हो। मेरा हल्का तो आपने देखा ही हुआ है। सारसे गांव में आप गए थे, गुमथलागढू गांव में गए थे। आपने देखा होगा कि प्लॉट काटे हुए हैं। उनके लिए उन लोगों को लोन मिलेगा ताकि उन प्लाटों में वे लोग अपने मकान बना सकें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं कि सिर्फ प्लॉट ही काटे हैं। हमारी सरकार ने बाकायदा पंचायत की उस जमीन को डिवैल्प करके उसके बाद ही ये प्लॉट काटे हैं। इनकी पार्टी की सरकार कितने साल सत्ता में रही थी तब इन्होंने कितने प्लॉट गरीब आदमियों को काट कर दिए थे। इनकी पार्टी के समय में कोई प्लॉट नहीं काटे गये जबकि हमने तो लाखों प्लॉट गरीब आदमियों को दिए हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, प्लॉट तो जो पहले की सरकार थी उसने भी काटकर दिए थे।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : उपाध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी भी आप भी उस गांव को जानते हैं और मैं भी उस गांव को जानता हूं। उस गांव की पंचायत ने इकट्ठी होकर इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के लीडर को कहा कि हमारा एक 6 किलोमीटर का रास्ता है जो 25 ढाणियों को जोड़ता है। वहां पर नहर का रास्ता कच्चा है जब बारिश हो जाती है तो उस रास्ते से जा नही सकते। जब कोई औरत या आदमी बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में ले जाने में दिक्कत होती है और बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। तब इनके लीडर ने पंचायत ने जो कागज दिया था वह तो फैंक दिया और पंचायत को यह कहा कि कभी ढाणियों पर भी सड़क बनाई जाती है ओर कभी नहर पर भी सड़क बनाई जाती है ऐसा कानून में नहीं है। जिस बात को विपक्ष के माननीय सदस्य हर बात पर यह कह रहे थे कि यह बजट डायरेक्शन लैस है उस बात ने हरियाणा का नक्शा बदल दिया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने न केवल फण्ड दिया है बल्कि वहां की सड़क को भी बनाया है और हरियाणा का नक्शा ही बदल दिया है। माननीय अरोड़ा जी अपने शहर की गलियों को ही देख लें और ईमानदारी से बतायें कि वे बनी हैं या नहीं। वहां पर काम हुआ है या नहीं। इसलिए लोगों ने भी इनका काम देखकर

बुल्लेशाह जी वाली बात कर डाली । बुल्लेशाह जी से किसी ने पूछा कि मन को कैसे काबू करें तो बुल्लेशाह जी ने कहा कि मन का क्या इधर से पाटना उधर लाना । इसी प्रकार जनता ने भी इनकी सरकार को पाटकर कांग्रेस की सरकार को ला दिया । जब इनैलो की सरकार के समय में इनके नेता मेरे हल्के में जाते थे तो उनके पास पहले ही टेलीफोन पर मैसेज चला जाता था कि आपको 21 हजार रुपये की माला पहनानी है और आपको 25 हजार रुपये की माला पहनानी है तो वहां के लोग छुपते फिरते थे कि हम तो मारे गये । वे हर गांव से नोट इक्ट्ठे करते थे और कारें बड़ी होती थी और कारों की डिग्गी में बोरियां भर कर पैसे लेकर आते थे । अब उसका उल्ट हो गया है क्योंकि न तो कभी हुड्डा साहब ने आज तक एक रुपये का भी हार पहना है और न ही चट्ठा ने कभी एक रुपये का हार पहना है ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अरोड़ा ने भी एक रुपये का भी हार नहीं पहना ।

Sardar Harmohinder Singh Chatha : Deputy Speaker Sir, very good, on this thing I am very happy. ताहिं तो मैं कह रहा हूं यारा तेरा घुट भर लां मैनू वेख्यां सब्र न आवें । तां ही तो मैंने यह बात कही है । अब लोगों से वह पैसा आना नहीं । इसलिए इनको हुड्डा साहब की इस बात के लिए दिक्कत जरूर हुई है कि इन्होंने तो प्रथा ही बदल दी और वह जो वह लूट खसूट वाली पहले बात थी वह तो खत्म हो गई ।

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो कहा है कि ग्राम पंचायत एक्ट के तहत 75 गज के प्लॉट गरीबों को काटकर दिए हैं । ऐसे प्लॉट तो मैंने भी काटे हैं क्योंकि मैं गांव का सरपंच रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि बड़ा भारी स्कीम लेकर आये हैं । एक साल में एक लाख और दूसरी साल में एक लाख मकान बनाये जायेंगे । यह सिर्फ चुनावी स्टंट है किसी ने कुछ नहीं करना है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, माजरा साहब, गलत ब्यानी कर रहे हैं हमारी सरकार ने ये प्लॉट डिवैल्प करके दिए हैं ।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सीधा और साधारण सा आदमी मिलने के लिए आया और माजरा साहब को दूर से देख कर उसने कहा कि जो सफेद विग पहनता है वही विधायक माजरा जी हैं क्या? तब मैंने उस आदमी को कहा कि यह तो बहुत बड़ा आदमी है यह विग नहीं पहनता ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछ ले कि हमारी सरकार के समय कहीं गलत प्लॉट कहीं तालाब में या ऊंची जगह पर काटे हों, कहीं पर भी कोई कब्जा नहीं मिला ये सरकार की आत्मा से पूछ लें । चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जाट कॉलेज कैथल में भरी सभा में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कहा कि भाई, इन बातों से काम नहीं चलेगा । प्लॉट किसी को नहीं मिले हैं । वे एक समाजवादी नेता हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी सदन को यह भी बता दें कि इनकी पार्टी के बारे में श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने क्या कहा होगा?

श्री रामपाल माजरा : आप इस बारे में बता देना, यदि सच्ची होगी तो मैं कह दूंगा कि उन्होंने सही कहा परन्तु रणदीप सिंह जी, इतना जरूर बता दें कि उन्होंने कहा था या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(उद्योग मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। एक तो ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। 1972 में आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे प्रदेश में पहली बार गरीबों को प्लॉट दिए। उसके बाद 1982-83 में एक बार फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में गरीबों को प्लॉट दिए और 2005 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आई और दिल्ली में हमारी मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी, यू.पी.ए. की चेयरपर्सन हैं, एक बार फिर गरीबों को प्लॉट दिए गए। ये झूठी बातें कहना बन्द कर दें और किसी व्यक्ति का नाम लेकर मिथ्या प्रचार न करें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनकी पोल एक बार नहीं बल्कि कई-कई बार खुल चुकी है। 4-4 बार ये नकारें हुए लोग हैं और 4 बार नकारे जाने के बाद भी ये सुधरते नहीं हैं यानि पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, रस्सी जल गई पर इनका बल नहीं टूटा। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ये 67 मैम्बर्ज लेकर आए और इस बार इनके 27 हारे और 40 रह गए और अब की बार अगर 27 हार गए तो ये कहां पहुंच जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव के 224 लोग मारे मारे फिर रहे हैं लेकिन उनको ये प्लॉट नहीं मिले।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : मामू राम जी, मैं आपके इलाके के बारे में ज्यादा जानता हूं। आपको इस बारे में भी बता देंगे। मैं बड़ा वहां हुआ हूं, पढ़ा वहां हूं और इलैक्शन वहां से लड़ा हूं इसलिए मैं उस इलाके के बारे में ज्यादा जानता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स की बात मुख्यमंत्री जी ने बताई है। अध्यक्ष महोदय, डायरैक्शनलैस की बात यहां आई। लोकदल वाले बेचारे साथियों को तो डायरैक्शनलैस लफ्ज का पता नहीं परंतु इनके साथ बैठे किसी मैम्बर को पता होगा जिसने डायरैक्शनलैस लफ्ज कह दिया। यह बजट पूरा डायरैक्शनफुल है और यह बजट सीधा जाने वाला है। यह ऐसा बजट है जो हरियाणा

का नक्शा बदल देगा और हुड्डा साहब के बारे में लोग ये कहेंगे कि तीसरी बार तेरा सिद्ध है यह मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा इन्होंने बजट के बारे में कई बातें कहीं। सबसे पहले इन्होंने गन्ने के भाव की बात कही। हमने भी गन्ने के रेट के लिए एजीटेशंज किए थे और हम भी लड़ते रहे थे। एक बार बहन चंद्रावती भी हमारे साथ थी और इन्होंने पानी फैंक कर हमारा बुरा हाल कर दिया गया था। इन्होंने कभी गन्ने के रेट बढ़ाए भी थे तो केवल एक रुपया या दो रुपये ही बढ़ाए थे और इससे ज्यादा इन्होंने कभी नहीं बढ़ाए। जब 5 साल इनका राज था और 5 साल के बाद जब जाते जाते इनको पता था कि हमारा बेड़ा डूबने लग रहा है और जब बेड़ा डूबने लगा तो इन्होंने गन्ने के रेट बढ़ा दिए थे। उस समय भी गन्ने के रेट 7 रुपये ही बढ़ाए गए थे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उस समय पूरे देश में गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज्यादा था।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह रेट उस समय दिये थे जब ये जाने लगे थे और इनको ये रेट देने नहीं थे और हुड्डा साहब ने वे रेट दिए थे। (विघ्न) हरियाणा में इन्होंने पापुलर का सफाया कर दिया। लोगों ने अपने खेतों से पापुलर उखाड़ दिए थे। इसी तरह लोगों ने अपने खेतों से गन्ने उखाड़ दिए थे और लोग कहते थे कि क्या गन्ना हम सिर पर लगा लें। अध्यक्ष महोदय, लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। इन्होंने 5 सालों में गन्ने के रेट एक रुपये या दो रुपये ही बढ़ाए थे। हुड्डा साहब ने आते ही पहली बार गन्ने का रेट हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा 45 रुपये बढ़ाया। उसके बाद 32 रुपये और उसके बाद 40 रुपये यानि तीन-तीन बार हमने गन्ने के रेट बढ़ा दिए। अब पंजाब से भी ज्यादा गन्ने का रेट हम दे रहे हैं। यू.पी. से तीन चार रुपयों का ही हमारा फर्क है। यू.पी. में बात यह है कि वहां के किसानों को साल बाद पेमैंट मिलेगी और आप एक साल का सूद लगा लो कितना बनेगा और हम पेमैंट साथ की साथ देते हैं। यू.पी. में किसानों को गन्ने की पेमैंट मिलती ही नहीं है।

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यू.पी. में किसानों के गन्ने की पेमैंट 4 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पैंडिंग है। इस बारे में हमने लिखकर लिया हुआ है।

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, यू.पी. में किसानों को मिलें गन्ने की पेमैंट नहीं देती। साल-साल तो मामूली बात है वहां के किसान फिरते रहते हैं। वहां के किसान मिलों के बाहर आकर बैठ जाते हैं, मालिक मिलते नहीं हैं। यदि साल के बाद 10 रुपये गन्ने का भाव ज्यादा भी दे दें तो उनको क्या फर्क पड़ता है। वहां मिल मालिक इतनी लेट पेमैंट करते हैं कि उनको सूद ही बहुत मिल जाता है। विपक्ष के साथियों ने यदि गन्ने की बात करनी है तो इस तरह से करें कि हरियाणा प्रदेश गन्ने में भी एक नम्बर पर है, नम्बर दो पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गन्ने की पेमैंट टाईम पर होती है यदि यू.पी. वाले भी टाईम पर पेमैंट करें तो हम भी हमारे यहां गन्ने का रेट बढ़ा देंगे। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां उत्तर प्रदेश से गन्ने का रेट कम है।

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल कम नहीं है। जिस हिसाब से ये

[श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]
गन्ना बरतते हैं और साल-साल बाद पेमैंट करते हैं उसको देखें तो हमारे यहां बिल्कुल रेट कम नहीं है। हमारा इलाका यमुना के साथ लगता है आपका नहीं लगता। यू.पी. के यमुना के साथ लगते एरियाज़ की सारी व्हीट, पैडी हमारे प्रदेश की मण्डियों में इसलिए आती हैं क्योंकि वहां कोई मण्डी ही नहीं है। ये लोग यू.पी. की बात करते हैं। वहां किसी तरह का किसानों की फसल खरीदने का सिस्टम नहीं है। वहां किसान खेत से अनाज लाकर अपने घर डाल देते हैं। जब कभी 10-15 या 20 दिन बाद सेठ आयेगा और अपने मन मुताबिक भाव पर वहां के किसानों की फसल खरीद कर ले जायेगा। जबकि हमारे प्रदेश में हम मिनिमम स्पोर्ट प्राईस किसानों की फसल का फिक्स करते हैं और हमारी मण्डियों में बाकायदा इंस्पैक्टर और दूसरा स्टाफ होता है, मजाल है स्पोर्ट प्राईस से एक पैसा भी किसान की फसल नीचे बिक जाये। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है कि कुरुक्षेत्र से चट्ठा साहब भी आते हैं और मैं भी आता हूं। वहां पर किसानों का करोड़ों रुपये जीरी का खाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री जी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करवायें। क्या वित्तमंत्री जी, आप नहीं जानते कि वहां किसानों को कम पैसा जीरी का मिला है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, किसने खाया है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : वित्त मंत्री जी आपको सारी जानकारी है कि किसने वह पैसा खाया है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हाउस की कमेटी बना दी जाये वह इस सारे मैटर को देख लेगी।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : आप मुझे बता देना I will stand on this issue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम तो सदन में ही बता रहे हैं। इससे बड़ी जगह कौन सी होगी।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि हुड्डा साहब ने गन्ने का रेट बहुत बढ़ाया है और हमारा गन्ने का रेट पंजाब से काफी ज्यादा है। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे यहां गन्ने का रेट कम है। क्रिटीसाईज़ करना तो विपक्ष का हक है इसलिए वे करेंगे। इसके अलावा हम किसानों को सबसिडी पर बीज, दवाईयां भी देते हैं। जबकि यू.पी. में तो शायद किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1999 से लेकर 2005 में जब हमारी सरकार बनी उस समय जाते-जाते विपक्ष के साथियों ने 7 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया था। वह पेमैंट भी इन्होंने नहीं की थी जबकि 2005 से लेकर अब तक हमने 159 रुपये गन्ने का भाव प्रति क्विंटल बढ़ाया है। (इस समय मेजें थप-थपाई गई।) (विघ्न)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद है कि जब किसान की बासमती पैडी बढ़े भाव बिक रही थी लेकिन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। उस समय हुड्डा साहब फोरन कंट्री में थे। इनको टेलीफोन किया तो इन्होंने अपना

टूर कैंसील कर दिया और कहा कि मैं कल पहुंच रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने वहां से सरदार मनमोहन सिंह जी से टाईम लिया और सीधे उनके पास गये और पैडी का एक्सपोर्ट खुलवाया। अध्यक्ष महोदय, यह अंतर हमारे हुड्डा साहब और इनमें है। मैं इनका नाम नहीं लूंगा। ये लोग तो और कोशिश करते कि चलो भई नीचे आ गई, नीचे आ गई। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, मैं प्रार्थना कर रहा था कि इसी तरह ही व्हीट के मुतल्लक, व्हीट का रेट तो गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया बढ़ाती है और मिनीमम स्पोर्ट प्राईस तय करती है लेकिन production of wheat के मुतल्लक हुड्डा साहब को, इस स्टेट को नम्बर एक का प्राईज मिलना यह कोई छोटी बात नहीं है। इस बात के लिए विपक्ष के साथियों को भी माननीय मुख्यमंत्री और पूरी हरियाणा सरकार को मुबारकवाद देनी चाहिए कि हुड्डा साहब को बुलाकर नम्बर एक स्टेट का अवार्ड दिया गया लेकिन विपक्ष के साथियों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा कुछ भाईयों ने बिजली की बात की है। मैं भी यह मानता हूं कि जब बिजली की कमी के दिनों में बिजली की डिमाण्ड का प्रैशर बढ़ता है तो बिजली के काफी कट लगते हैं लेकिन सभी माननीय साथियों को एक बात माननी पड़ेगी कि हुड्डा साहब ने जब सरकार के पास बिजली की कमी होती है उस वक्त दूसरे सूबों से महंगी से महंगी बिजली खरीदकर किसानों को 8-8 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई है। यह बिजली उस वक्त दी जाती थी जब बारिश न होने के कारण बिजली की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। इस बार तो सर्दी के मौसम में अच्छी बारिश हो गई इसलिए गेहूं की फसल में ज्यादा पानी नहीं देने पड़े और गेहूं की फसल अपने आप ही पक गई है लेकिन कभी समय यह होता था कि सरकार को पूरा वर्ष ज्यादातर बिजली बाहर से लेनी पड़ती थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने जितने थर्मल पॉवर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन जितना बढ़ाया है इससे पहले इतना उत्पादन किसी भी सरकार के समय में नहीं बढ़ा। विपक्ष के साथी इस बात को भी नहीं मानते हैं। इसके अलावा मैट्रो ट्रेन को हरियाणा में चलाने के लिए हुड्डा साहब ने जो पैसा दिया है विपक्ष के साथी उसे भी नहीं मानते। विपक्ष के साथी तो हरेक मामले में "तो भी ना मन्नूं", "तो भी ना मन्नूं" और "तो भी ना मन्नूं" वाली बात करते

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]
हैं । इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बात का तो हमारे पास कोई भी ईलाज नहीं है । हम कोई भी बात करें वह विपक्ष के साथियों के अंदर नहीं जाती अर्थात् इनकी समझ में नहीं आती । (विघ्न) स्पीकर सर, यहां पर डॉक्टरों के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई थी जिसके बारे में हमारे दोस्त दांगी साहब ने भी जिक्र किया था और भी बहुत से माननीय साथियों ने कहा था कि हरियाणा में डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है । मैं भी यह बात मानता हूं कि सारी स्टेट में लगभग 500 के करीब डॉक्टरों की कमी है । डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक कदम तो यह उठाया है कि इनकी भर्ती की प्रक्रिया को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से निकालकर उसे डॉयरेक्टोरेट के लैवल पर कर दिया गया है इसलिए इनकी भर्ती की प्रक्रिया अब डॉयरेक्टोरेट लैवल पर होती है । इस बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो एम.बी.बी.एस. होता है वह तो यह देखता है कि अगर कोई अच्छा स्टेशन है और शहर के भी नजदीक है तो वह वहां पर ज्वाईन कर लेता है नहीं तो वह एम.डी. या एम.एस. करने के लिए चला जाता है और जो ऑलरेडी एम.डी. या एम.एस. हैं वह गांवों में जाता ही नहीं है । गांवों में वास्तव में यह प्रॉब्लम है । इस बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए । सरकार इस प्रॉब्लम के निदान के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है अगर विपक्ष के साथियों के पास इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई सुझाव हों तो । I will be glad to accept it. (Interruption) कोई भी माननीय साथी मुझे पर्सनली मिलकर इस बारे में अपने सुझाव दे सकता है । मुझे भी इस बात का बेहद दुःख है कि गांवों में डॉक्टर नहीं है और अगर हैं तो एक स्टेशन पर एक या दो लेकिन इससे ज्यादा कहीं पर भी डॉक्टर नहीं हैं और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर डॉक्टर रात को अपनी कार में बैठकर शहर में चले जाते हैं । (विघ्न) यह दिक्कत वास्तव में है और इस दिक्कत को दूर करने के लिए we are very serious and I will request Mr. Ashok Kumar Arora, he is my younger brother that he meet me personally and we will discuss this matter. इसके साथ ही मैं एक बात सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए जरूर बताना चाहता हूं कि अब सी.एम. साहब ने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के अस्पतालों में C.T. Scan और M.R.I. की फैसिलिटी उपलब्ध कराने का फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट लैवल के अस्पतालों में C.T. Scan और M.R.I. की एक-एक मशीन होगी और ये मशीनें चालू हालत में होंगी ऐसा नहीं होगा कि मशीनें वहां पर पहुंच जायें लेकिन वहां पर उस मशीन को चलाने वाला कोई न हो । यह माननीय हुड्डा साहब ने फैसला किया है । इस फैसले के बावजूद भी अगर माननीय सदस्य इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते तो यह बहुत गलत बात होगी क्योंकि अब अगर किसी को M.R.I. करानी हो तो वह चण्डीगढ़ आता है या फिर रोहतक जाता है । इस बारे में हुड्डा साहब ने अस्पतालों की डिवैल्पमैंट के लिए यह कदम उठाया है । मैं श्री दांगी साहब को भी कहूंगा कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनके गांव में डॉक्टर नहीं है । इस बारे में सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ गांव ऐसे होते हैं "नामी" जिनमें कि पढ़े-लिखे लोग नहीं जाना चाहते । I may be excused for this. (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय

को बताना भी चाहता हूं और इनका और पूरी सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इस हाउस में इस बारे में बात होने के तुरंत बाद उसी दिन रात को ही हमारे गांव में डॉक्टर भेज दिया गया था।

Mr. Speaker : Hon'ble Finance Minister please continue.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : दांगी साहब, यह तो बहुत फास्ट सर्विस है कि डॉक्टर रात को ही पहुंच गया। यह बात ठीक है कि वहां डॉक्टरों की जरूरत है। अगर आपके इलाके में कोई योग्य डॉक्टर हो तो बता दो हम उसको सिलैक्ट करके वहीं पर भेज देंगे ताकि वह अपने घर रहे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : मंत्री जी, मेरा कहना यह है कि वहां पर सी.एच.सी. है और डॉक्टरों की चार पोस्ट्स हैं लेकिन वहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं था।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अगर योग्य कैंडिडेट्स होंगे तो चारों ही लगा देंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, यह मेरा काम नहीं है, यह काम सरकार का है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जहां तक टीचर्ज की बात है तो इस बारे में शिक्षा मंत्री ने विस्तार से जवाब दे दिया था लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि हमारा एम.एल.एज. का भी कुछ फर्ज बनता है। जो रिमोट विलेजिज हैं और वहां पर दो टीचर लगे हों तो एक ड्यूटी पर जाता है दूसरा नहीं जाता। इतना फर्ज तो हमारा भी बनता है कि जब कभी स्कूल के पास से निकलें तो यह चैक कर लें कि टीचर आये भी हैं या नहीं। अगर कोई अनियमितता नजर आती है तो शिक्षा मंत्री जी को लिख कर दो या टेलीफोन पर बता दें फिर देखना कि एक्शन कैसे होता है? इसी तरह का एक केस मेरे हल्के का है। मेरे हल्के में एक स्कूल था जिसमें वहां दो टीचर थी जो एक सप्ताह एक आती थी दूसरी दूसरे सप्ताह आती थी। आखिरकार वे पकड़ी गई और दोनों ने आना शुरू कर दिया। इसमें हमारा भी कसूर है, हम स्कूल के आगे से निकल जाते हैं, हम कभी नहीं देखते। जब हम एम.एल.ए. बन जाते हैं तो उस हल्के के बाप का दर्जा मिल जाता है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे हल्के में एक फौजी है, वहां पर 10+2 का स्कूल सी.एम. साहब ने बनाया हुआ है। वह फौजी सुबह ही आकर किसी न किसी क्लास को पढ़ाना शुरू कर देता है और वह भी मुफ्त में पढ़ाता है। उसने स्कूल को टॉप पर पहुंचा दिया है।

श्री रामपाल माजरा : मंत्री जी, बात यह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कैसे पहुंचें, इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : माजरा साहब, आप तो पुठकंडे की तरह उल्टे जा रहे हो। (हंसी)

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, एक सच्ची घटना है, यह मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। जब टीचर भर्ती होते हैं तो वे स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते बल्कि अपनी जगह किसी अपने सहायक को वहां पर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। सरकारी तनख्वाह

[श्री बलबीर पाल शाह]
ज्यादा है और वे दो-तीन हजार रुपये में किसी आदमी को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं और खुद घर पर अपने काम करते हैं। यह एक समस्या है, इसके ऊपर भी चैक होना चाहिए। सभी एम.एल.एज. को इस बारे में अवेयर होना चाहिए।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के अलावा जिस प्रकार से पानी की बात आई थी। हुड्डा साहब ने हर गांव में पानी पहुंचाने की कोशिश की है। अगर कोई गांव रिमोट एरिया में है और वहां पानी नहीं पहुंचता तो वह हमें लिख दें कि पानी नहीं पहुंचता, हम वहां पर स्पैशल इंतजाम करके पानी पहुंचा देंगे। इसके अलावा अरोड़ा साहब ने बहुत अच्छी बातें की। इन्होंने एक कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया था कि कैग की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए थी, उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया था लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि वह हमारे बस की बात नहीं होती। रिपोर्ट देना उनका काम है, जब वे रिपोर्ट दे देंगे हम उसको आगे बढ़ा देंगे, हमें अपने पास रख कर क्या करना है? वह कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उसने अंडे देने हैं या बच्चे देने हैं। सर, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कुछ भाइयों ने ये कहा है कि हमें एपरिहैंसन है कि बजट पास करने के बाद आप फिर टैक्स लगाओगे। हम टैक्स नहीं लगाएंगे। लोगों के हित की बात को सामने रखना पड़ता है। हमारा टैक्स लगाने का कोई ईरादा नहीं है। अगर हमने टैक्स लगाने होते तो हम यहां ले आते पास तो हो ही जाने थे। वह तो ऐमरजैंसी की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने एन.एस.टी. और आरनैस्टी ये लाए हैं। हमारे मन में कुछ नहीं है और दूसरा खाना हमारा कोई नहीं है। हमारा एक ही खाना है जो हमें हुड्डा साहब ने पढ़ाकर भेजा है। जो कांता बहन ने या दूसरे सदस्यों ने बातें की मैं सबको विश्वास देता हूं कि गवर्नमैंट अपने फ्रेम वर्क के बीच में रहेगी, गवर्नमैंट एक्स्ट्रा कर्जा नहीं उठाएगी, कर्जा उठाना भी जरूरी है मेरे ख्याल से जितने यहां बैठे हैं सबने कारों का कर्जा ले रखा होगा, सबने मकानों का भी कर्जा ले रखा होगा, कर्ज के बिना काम तो नहीं चलता लेकिन कर्ज को कन्सट्रक्टिव काम पर लगाना This is the best. आज जो सारे बड़े-बड़े लाट साहब हैं सब कर्जा लेते हैं लेकिन वे कन्सट्रक्टिव काम में लगाते हैं। अगर पैसा लेकर हम थर्मल लगाएं, हम नहर निकालें, कन्सट्रक्टिव वर्क, हस्पताल बनाएं, हम उस कर्ज को लेकर एन्न्याय नहीं करते और उसमें हम लिमिट के बीच में हैं लिमिट के बाहर नहीं हैं ना कभी जाएंगे ना कभी हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की बात के साथ मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे एक अहम पत्र लिखकर यह बताया कि आपके हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी गांव सभ्यता का प्रतीक है। उस गांव को कल्चरल हैरिटेज बनाए रखने के लिए हमें उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। वहां पर जो खुदाई चल रही है उससे प्रतीत होता है और आरकोलोजी डिपार्टमैंट भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वहां पर इन्डसवैली सिवलाईजेशन का सबसे बड़ा भाग नीचे जमीन में दबा हुआ है जो कि मोहन जोदड़ो से भी बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए वर्ष 2013-14 के बजट में 1 करोड़ 75 लाख रुपये रखे गए हैं। इस अमाउंट से राखी गढ़ी गांव में सन् 2013-14 में एक म्यूजियम और इन्टरपटेशन सैंटर बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज ग्रीक में

भी टूरिस्ट वहां पर नीचे दबी सभ्यता को देखने के लिए जाते हैं उसी तरह से आने वाले सालों में राखी गढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट केन्द्र बनने जा रहा है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, हमारा सुझाव भी मान लो।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सर, मैं विनती करता हूं कि इस बजट को पास किया जाए।

वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the Demands for Grants on Budget 2013-2014 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the Demands for Grants (Nos. 1 to 45) on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand and they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding ₹ **51,41,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 1 — **Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding ₹ **75,76,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 2 — **Governor & Council of Ministers.**

That a sum not exceeding ₹ **150,26,25,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 3 — **General Administration.**

That a sum not exceeding ₹ **858,49,76,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 4 — **Revenue.**

That a sum not exceeding ₹ **137,49,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 5 — **Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding ₹ **3880,65,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 6 — **Finance.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding ₹ **546,76,26,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 7 — **Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding ₹ **1122,08,86,000 for revenue expenditure and ₹ 2005,05,57,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 8 — **Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding ₹ **8753,76,57,000 for revenue expenditure and ₹ 27,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 9 — **Education.**

That a sum not exceeding ₹ **373,50,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 10 — **Technical Education.**

That a sum not exceeding ₹ **173,80,77,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 11 — **Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **11,45,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 12 — **Art & Culture.**

That a sum not exceeding ₹ **1936,12,78,000 for revenue expenditure and ₹ 80,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 13 — **Health.**

That a sum not exceeding ₹ **189,00,60,000 for revenue expenditure and ₹ 850,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 14 — **Urban Development.**

That a sum not exceeding ₹ **2073,99,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 15 — **Local Government.**

That a sum not exceeding ₹ **32,97,23,000 for revenue expenditure and ₹ 10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 16 — **Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **78,44,80,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 17 — **Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **180,30,48,000 for revenue expenditure and ₹ 57,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 18 — **Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **420,12,62,000 for revenue expenditure and ₹ 3,53,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 19 — **Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **1821,21,19,000 for revenue expenditure and ₹ 2,83,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 20 — **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **695,87,17,000 for revenue expenditure and ₹ 188,62,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 21 — **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **71,87,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 22 — **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding ₹ **258,13,00,000 for revenue expenditure and ₹ 8350,34,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 23 — **Food & Supplies.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding ₹ **1509,36,65,000 for revenue expenditure and ₹ 639,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 24 — **Irrigation.**

That a sum not exceeding ₹ **112,33,22,000 for revenue expenditure and ₹ 3,16,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 25 — **Industries.**

That a sum not exceeding ₹ **17,46,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 26 — **Mines & Geology.**

That a sum not exceeding ₹ **1071,58,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 27 — **Agriculture.**

That a sum not exceeding ₹ **489,45,00,000 for revenue expenditure and ₹ 20,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 28 — **Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding ₹ **27,42,35,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 29 — **Fisheries.**

That a sum not exceeding ₹ **265,13,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 30 — **Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding ₹ **5,32,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 31 — **Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding ₹ **2171,25,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 32 — **Rural &**

Community Development.

That a sum not exceeding ₹ **202,67,00,000 for revenue expenditure and ₹ 74,95,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 33 — **Co-operation.**

That a sum not exceeding ₹ **1525,43,00,000 for revenue expenditure and ₹ 182,45,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 34 — **Transport.**

That a sum not exceeding ₹ **2,98,95,000 for revenue expenditure and ₹ 24,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 35 — **Tourism.**

That a sum not exceeding ₹ **2028,35,34,000 for revenue expenditure and ₹ 109,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 36 — **Home.**

That a sum not exceeding ₹ **23,33,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 37 — **Elections.**

That a sum not exceeding ₹ **1261,56,00,000 for revenue expenditure and ₹ 1064,93,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 38 — **Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding ₹ **191,78,40,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 39 — **Information & Publicity.**

That a sum not exceeding ₹ **4295,81,52,000 for revenue expenditure and ₹ 475,68,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 40 — **Energy & Power.**

That a sum not exceeding ₹ **30,40,90,000 for revenue expenditure and ₹ 1,00,000 for capital expenditure** be

[Mr. Speaker]

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 41 — **Electronics & IT.**

That a sum not exceeding ₹ **322,65,42,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 42 — **Administration of Justice.**

That a sum not exceeding ₹ **101,29,66,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 43 — **Prisons.**

That a sum not exceeding ₹ **40,44,10,000 for revenue expenditure and ₹ 7,92,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 44 — **Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding ₹ **1083,54,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 45 — **Loans & Advances by State Government.**

No member rose to speak.

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding ₹ **51,41,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 1 — **Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding ₹ **75,76,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 2 — **Governor & Council of Ministers.**

That a sum not exceeding ₹ **150,26,25,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 3 — **General Administration.**

That a sum not exceeding ₹ **858,49,76,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 4 — **Revenue.**

That a sum not exceeding ₹ **137,49,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 5 — **Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding ₹ **3880,65,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 6 — **Finance.**

That a sum not exceeding ₹ **546,76,26,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 7 — **Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding ₹ **1122,08,86,000 for revenue expenditure and ₹ 2005,05,57,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 8 — **Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding ₹ **8753,76,57,000 for revenue expenditure and ₹ 27,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 9 — **Education.**

That a sum not exceeding ₹ **373,50,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 10 — **Technical Education.**

That a sum not exceeding ₹ **173,80,77,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 11 — **Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **11,45,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 12 — **Art & Culture.**

That a sum not exceeding ₹ **1936,12,78,000 for revenue**

[Mr. Speaker]

expenditure and ₹ 80,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 13 — **Health.**

That a sum not exceeding ₹ **189,00,60,000 for revenue expenditure and ₹ 850,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 14 — **Urban Development.**

That a sum not exceeding ₹ **2073,99,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 15 — **Local Government.**

That a sum not exceeding ₹ **32,97,23,000 for revenue expenditure and ₹ 10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 16 — **Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **78,44,80,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 17 — **Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **180,30,48,000 for revenue expenditure and ₹ 57,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 18 — **Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **420,12,62,000 for revenue expenditure and ₹ 3,53,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 19 — **Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **1821,21,19,000 for revenue expenditure and ₹ 2,83,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 20 — **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **695,87,17,000 for revenue expenditure and ₹ 188,62,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in

the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 21 — **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **71,87,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 22 — **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding ₹ **258,13,00,000 for revenue expenditure and ₹ 8350,34,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 23 — **Food & Supplies.**

That a sum not exceeding ₹ **1509,36,65,000 for revenue expenditure and ₹ 639,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 24 — **Irrigation.**

That a sum not exceeding ₹ **112,33,22,000 for revenue expenditure and ₹ 3,16,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 25 — **Industries.**

That a sum not exceeding ₹ **17,46,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 26 — **Mines & Geology.**

That a sum not exceeding ₹ **1071,58,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 27 — **Agriculture.**

That a sum not exceeding ₹ **489,45,00,000 for revenue expenditure and ₹ 20,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 28 — **Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding ₹ **27,42,35,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 29 — **Fisheries.**

That a sum not exceeding ₹ **265,13,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that

[Mr. Speaker]

will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 30 — **Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding ₹ **5,32,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 31 — **Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding ₹ **2171,25,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 32 — **Rural & Community Development.**

That a sum not exceeding ₹ **202,67,00,000 for revenue expenditure and ₹ 74,95,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 33 — **Co-operation.**

That a sum not exceeding ₹ **1525,43,00,000 for revenue expenditure and ₹ 182,45,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 34 — **Transport.**

That a sum not exceeding ₹ **2,98,95,000 for revenue expenditure and ₹ 24,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 35 — **Tourism.**

That a sum not exceeding ₹ **2028,35,34,000 for revenue expenditure and ₹ 109,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 36 — **Home.**

That a sum not exceeding ₹ **23,33,90,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 37 — **Elections.**

That a sum not exceeding ₹ **1261,56,00,000 for revenue expenditure and ₹ 1064,93,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 38 — **Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding ₹ **191,78,40,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 39 — **Information & Publicity.**

That a sum not exceeding ₹ **4295,81,52,000 for revenue expenditure and ₹ 475,68,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 40 — **Energy & Power.**

That a sum not exceeding ₹ **30,40,90,000 for revenue expenditure and ₹ 1,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 41 — **Electronics & IT.**

That a sum not exceeding ₹ **322,65,42,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 42 — **Administration of Justice.**

That a sum not exceeding ₹ **101,29,66,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 43 — **Prisons.**

That a sum not exceeding ₹ **40,44,10,000 for revenue expenditure and ₹ 7,92,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 44 — **Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding ₹ **1083,54,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2013-14 in respect of charges under Demand No. 45 — **Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the House is adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 11th March, 2013.

*17.45 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 11th March, 2013.)

51232—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh *
LIBRARY